Seventh Series, Vol. XII; No. 13

Tuesday, March 3, 1981
Phalguna 12, 1902 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

Fifth Session

(Seventh Lok Sabha)

(Vol. XIV contains Nos. 31 to 40)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 6.00

CONTENTS

No. 13, Tuesday, March 3, 1981/Phalguna 12, 1902 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions:	
*Starred Questions Nos. 207, 211, 213, 214 and 216 to 218	1—32
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 208 to 210, 212, 215 and 219 to 226	32—41
Unstarred Questions Nos. 2001 to 2058, 2060 to 2073 and 2075 to 2200	41—286
Re: Reported Supply of Briefs to Members by Ministries	286—96
Papers Laid on the Table	296—98
Committee on Private Members' Bill and Resolutions—	
Sixteenth Report	298
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Increasing incidence of robberies and dacoitites in Delhi	298—319
Shri Nawal Kishore Sharma	298, 300—303
Shri Yogendra Makwana	299—300
Shri Harish Chandra Singh Rawat	304—307
Shri Zainul Bashar	308—11
Shri Mukunda Mandal	311—14
Shri Harikesh Bahadur	314—18
The Oil and Natural Gas Commission (Amendment) Bill—*Introduced*	319—26
Motion to introduce :	
Shri P.C. Sethi	319, 324—26
Shri Jyotirmoy Bosu	319—22
Shri Mukunda Mandal	322
Shri Ajoy Biswas	322—23
Shri Ananda Gopal Mukhopadhyaya	324

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the questions was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

Matters Under Rule 377—

(i) Refusal to implement Palekar Award by Sakal Papers Private Limited (Maharashtra) :

Shri V.N. Gadgil . . . . . 326—27

(ii) Problems of handloom industry in Kerala :

Shri V.S. Vijayaraghavan . . . . . 327—28

(iii) Steps for improving power supply in Rajasthan :

Shri Ram Singh Yadav . . . . . 328—29

(iv) Reported decision for allowing import of pre-partially oriented yarn for actual users :

Shri Niren Ghosh . . . . . 329—30

(v) Clearance for new six hydro-electric schemes of Kerala:

Shri K.A. Rajan 331

(vi) Reported killing of a person by Meerut Police :

Shri Suraj Bhan . . . . . 331—33

Shri Zail Singh . . . . . 333—35

(vii) Reported terror in Bharatpur (Rajasthan) due to Activities of Dacoits :

Shri Rajesh Pilot 335

Railway Budget, 1981-82—General Discussion . . . . . 336—500

Shri Nityananda Misra . . . . . 336—40

Shri R.P. Yadav . . . . . 340—50

Shri J.C. Barway . . . . . 350—53

Shri Rana Vir Singh . . . . . 353—61

Shri A. K. Roy . . . . . 361—66

Shri Ram Singh Yadav . . . . . 367—72

Dr. B. N. Singh . . . . . 372—78

Shri Atal Behari Vajpayee . . . . . 378—85

Shri Kamal Nath Jha . . . . . 385—89

Shrimati Krishna Sahi . . . . . .

COLUMNS

Shri Pius Tirkey	395—97
Shri Pratap Bhanu Sharma	397—402
Shri Ranjit Singh	402—405
Choudhary Multan Singh	405—409
Shri Mallikarjun	409—15
Shri Ghulam Rasool Kochak	415—17
Shri Krishna Datt Sultanpuri	417—21
Shri Shiv Kumar Singh Thakur	421—24
Shri Chandradeo Prasad Verma	424—31
Shri Kusuma Krishna Murthy	431—38
Shrimati Suseela Gopalan	438—44
Shri Girdhari Lal Vyas	445—51
Shri K. Mayathevar	451—58
Shri K.M. Madhukar	463—66
Shri Era Anbarasu	467—72
Shri Tapeshwar Singh	472—77
Shri Rameshwar Nikhra	477—81
Shri Mundar Sharma	481—85
Shri Harish Chandra Singh Rawat	485—86
Shri Bhola Raut	486—90
Shri Shantubhai Patel	490—92
Shri Kali Charan Sharma	492—94
Shri Uttam Rathod	494—98
Dr. Golam Yazdani	498—500

LOK SABHA

Tuesday, March 3, 1981/Phalguna 12, 1902 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Deep Coal Mining Programme

+

*207. SHRI CHINTAMANI JENA:
SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the plan, if any, in regard to the deep coal mining programmes of the Government;

(b) whether Government have considered their plan for quality control and setting up of coal handling plants at pit-heads to improve quality of coal made available to power plants; and

(c) if so, the details regarding the plan of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The Coal Industry proposes to increase production of coal from underground mines from about 79 MT in 1980-81 to about 96 MT in 1984-85.

(b) Yes, Sir.

(c) During the VIth Plan period 11 coal washeries and 66 coal handling plants are to be taken up for construction.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 31 जनवरी, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल नोट में एडिटर ने चिन्ता व्यक्त की थी कि मुल्क में कोयले की भारी कमी होती जा रही है, सप्लाई डिमाण्ड से कम है, खानों में कोयला नहीं है, बड़े उद्योगों, ट्रेनों और घरेलू कार्यों में कठिनाई उत्पन्न होती जा रही है और आगे चल कर विशेष कठिनाई होने वाली है । इस लिये उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है तथा खानों को डीप तक ले जाना होगा, गहराई तक खोदना होगा । इस के लिये बिजली संयंत्रों की आवश्यकता है । मैंने इसी आधार पर अपना प्रश्न दिया था लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने शायद मेरे क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने उस क्वेश्चन को देखने तक की कोशश नहीं की तथा जिस ढंग से जवाब दिया है, मैं कुछ ज्यादा कहना पसन्द नहीं करता । मेरा प्रश्न था कि सरकार की कोयले को गहराई तक खुदाई कार्यक्रम के बारे में यदि कोई योजना है तो उस का क्या ब्यौरा है, लेकिन उत्तर क्या दिया जा रहा है—कोयला उद्योग का विचार भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन 1980-81 के लगभग 79 मिलियन टन से बढ़ा कर 1984-85 में लगभग 96 मिलियन टन करने का है । मैंने यह नहीं पूछा है कि कोयले का उत्पादन कितना करना है,

मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि गहरी खुदाई कार्यक्रम के बारे में आप की आगामी कोई योजना है ? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ दिया जा रहा है। इस लिये मैं माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं—इस की खुदाई के बारे में, डीप-माइनिंग तक ले जाने के बारे में आप की क्या योजना है ?

श्री विक्रम महाजन : 1980–85 में डीप माइनिंग का जो हमारा कार्यक्रम है, वह यह है कि इस वक्त जो 332 डीप माइन्स हैं, उन को 400 के करीब तक ले जायेंगे । इस वक्त 70 फीसदी कोयला इन से मिलता है । 278 कोल माइन्स हैं, कोल इन्डिया में जो डीप हैं। अन्डरग्राउन्ड माइन्स 72 से ज्यादा करनी हैं कोल इन्डिया में और 1 एस० सी० सी० एल० में करनी है । इस तरह से 73 हो जाऐंगी और इस ढंग से जैसा मैंने जवाब में कहा है हमारा उत्पादन 79 मिलियन टन से बढ़ कर लगभग 96 मिलियन टन हो जाएगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं संयंत्रों के बारे में पूछ रहा हूं कि योजना क्या है ?

श्री विक्रम महाजन : योजना क्या है, इस का जवाब मैंने दे दिया है और प्रोडक्शन कितना है, उस का भी जवाब मैंने दे दिया है । इस के अलावा और क्या आप चाहते हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं यह चाहता हूं कि उस के लिए जो सयंत्र होते हैं और उन को जो आप बढ़ाने जा रहे हैं, वे विदेशों से मंगाने चाहते हैं या नहीं चाहते हैं । उन यंत्रों की टेक्नोलाजी क्या है ? अच्छे से अच्छे यंत्र लिये जायें, इस की कोई योजना आप के पास है और विदेशों से कोई ऐसे यंत्र लेने की आवश्यकता आप समझ रहे हैं जिस से कोल की डीप माइनिंग कर के उस की कमी को पूरा कर सकें । आई वान्ट टू नो एबाउट यंत्र ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक नये यंत्रों का ताल्लुक हैं, दुनिया में जितने भी लेटेस्ट यंत्र हैं, वे सब हम दुनिया से ले रहे हैं और जहां तक मुल्क में एडवान्स्ड टैक्नोलाजी का सवाल है, उस के लिए हम दूसरे विदेशी मुल्कों से कोलाबोरेशन्स कर रहे हैं, जिस से हिन्दुस्तान में जो डीप अन्डरग्राउन्ड माइन्स हैं, वे आवश्यक लेटेस्ट टैक्नोलाजी ले कर डेवलप हो जाएं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बड़ी अच्छी बात है कि आप सारी दुनिया से यंत्र ले रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : 'सारे देश' होगा, सारी दुनिया नहीं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सारी दुनिया से यंत्र ले रहे हैं, इसके लिए आप को धन्यवाद ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : देश कोई दुनिया के बाहर हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सारे वर्ल्ड से ले रहे हैं, सारी दुनिया से ले रहे हैं । ...(व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : इस से तो सारा टाइम ही चला जाएगा । आप सवाल कीजिए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ठीक है, वैसे ही मेरा एक दूसरा प्रश्न और था । उस में मैंने यह पूछा था : क्या सरकार ने बिजली संयंत्रों को उपलब्ध कराये

जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार करने के लिए किस्म नियंत्रण सम्बन्धी कोई कार्यवाही की है । तो उस का हम को यह उत्तर दिया जा रहा है : "छठी योजना की अवधि में 11 कोयला वाशरियों और 66 कोयला रख-रखाव संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा ।" मान्यवर, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि कोयले की किस्म में कोई सुधार, उस की वेरायटीज में कोई सुधार किया जा रहा है और उस का उत्तर यह मिल रहा है कि यह निर्माण किया जाएगा । कृपया आप हम को इस की किस्म के बारे में बताएं ?

अध्यक्ष महोदय : आप का मतलब क्वालिटी कण्ट्रोल से है । इसके बारे में बताइए ।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक क्वालिटी कण्ट्रोल का ताल्लुक है, ये जो कोल हैंण्डलिंग प्लाण्ट्स और कोल वाशरियां हैं, इन से कोयले की क्वालिटी इम्प्रूव होती है । इनके इस्तेमाल से कोयले में एश कण्टेण्ट कम हो जाता है और इस ढंग से कोयला इम्प्रूव होता है, जिससे इंडस्ट्रीज, पावर प्लाण्ट्स और स्टील प्लाण्ट्स को अच्छी क्वालिटी का कोयला दिया जाता है । इसी ढंग से जो कोयले का साइज है, उस को छांटा कर रहे हैं । वह भी इन्हीं मशीनों से होता है । दूसरा जो एक्सट्रेनियस मेटीरियल होता है, एश कण्टेन्ट होता है, वह सब इन्हीं प्लाण्ट्स से साफ होता है । ये हैं बेसिक चीजें हैं और क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश हम कर रहे हैं । इस के अलावा दो-चार बातें और हैं जिन से क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं जैसे इन्सपेक्शन है कोल की क्वालिटी देखने के लिए, ज्वाइण्ट सैम्पलिंग है और मिनिस्टर साहब ने प्रोड्यूसर-कनज्यूमर की मीटिंग के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है । हर जोन के जो कन्ज्यूमर हैं, उन के साथ हमारी कोल कम्पनीज डाइरेक्टर बातचीत करेंगे और जो उन की कम्पलेंट्स हैं, उन को भी देखा जाएगा ।

SHRI KAMAL NATH: The hon. Minister has given some very encouraging figures. Do these figures relate only to deep mines? Or do they also belong to open cast mines?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: These figures relate to deep mines only. At present, there are 343 mines under Coal India and 57 under SCCL. Of them the open cast mines are 65 and 3. For 1980—85, the proposed number of additional open cast mines is 85 under CIL and 4 under SCCL.

"बिजली की चोरी—20 हजार फैक्टिरियां लाइसेंस के बिना" शीर्षक समाचार

*211. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'नवभारत टाइम्स' दिल्ली के 19 दिसम्बर, 1980 के संस्करण में "बिजली की चोरी, 20 हजार फैक्टरियां लाइसेंस के बिना" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली की चोरी के कितने मामले दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government is aware of this news item. Normally, industrial

units are required to obtain industrial power connections before commencement of production. However, in some cases, supply is initially obtained for domestic|commercial use and subsequently, these consumers unauthorisedly use it for industrial purposes, for which no licence is obtained. The Municipal Corporation of Delhi is required to give an industrial licence, and not the DESU. It is estimated that there are about 20,000 such unauthorised factories running without licence in the Union Territory of Delhi which are using domestic connections unauthorisedly for industrial purposes. In such cases of misuse of supply DESU is empowered to disconnect connections after giving consumer due notice. In practice, however, disconnection would cause disruption in production and consequent industrial unrest and unemployment. DESU is, therefore, penalising the offenders by applying the maximum tariff and levying a surcharge of 25 per cent for misuse of power/excess load.

(b) 9 casese of theft of electricity by taking direct supply from poles or using unmetered supply were detected by Delhi Electric Supply Undertaking during 1980-81 upto January, 1981.

(c) Appropriate action, including lodging of FIR with the Police was taken in all such cases.

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो बिजली की कमी है, इसके कारण घरेलू उद्योगों और घरों में काम आने वाली बिजली की अपर्याप्त सप्लाई से भयंकर संकट और हाहाकार मचा हुआ है। इस सन्दर्भ में नवभारत टाइम्स में एक बड़ी ही सनसनीपूर्ण खबर आयी है। जिसमें कहा गया है कि बीस हजार फैक्ट्रियां दिल्ली में स्वीकृत बिजली के लोड से अनधिकृत रूप में अधिक लोड का उपयोग कर रही हैं और इसके कारण घरों में 60 वाट्स वाले बल्ब को 20 से 25 वाट तक बिजली मिलती है और उससे घरों में टी० वी० आदि के उपयोग में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। यह खबर 19 दिसम्बर, 1980 को छपी है। इसके बारे में मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें सूचित भी किया है कि घरेलू और विभिन्न उपयोगों के लिए दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा जो लायसेंस दिए जाते हैं उनमें से 20 हजार कनेक्शन अनअथोराइज्ड तौर पर काम कर रहे हैं। ये विद्युत् प्रदाय संस्थान से सांठगांठ के कारण चल रहे हैं ये या तो खंभों से सीधे बिजली लेकर चलते हैं या अन्य प्रकार से बिजली की चोरी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछिये।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि एक संसद् सदस्य की नजफगढ़ में जो फैक्ट्री चलती है वह अनधिकृत रूप से अधिक लोड पर चल रही थी और उसकी लाइन काट दी गई थी? इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल महोदय से बातचीत की और उन्होंने 14 नवम्बर, 1980 को एक आदेश निकाल दिया कि वे ऐसे फैक्ट्री चला सकते हैं और स्वीकृत लोड से जो लोग अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उन सब को इस प्रकार से छूट दे दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसा आदेश था और क्या ऐसे आदेश के कारण आम-जनता को सफर नहीं करना पड़ रहा है?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक अनअथोराइज्ड फैक्ट्रीज का ताल्लुक है, यह सही है कि दिल्ली में 15-20 हजार फैक्ट्रीज अनअथोराइज्ड काम कर रही हैं। मगर इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनसे ढाई लाख से अधिक आदमी काम करते हैं। अगर

हम सब की बिजली बन्द कर दें तो एक तो मजदूरों की स्थिति खराब हो जाएगी और ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो जाएगी । इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने यह डिसीजन लिया कि मजदूरों को हार्डशिप्स न हों, इसलिए अभी पावर डिसकनेक्ट न की जाए । अगर यह कर दी जाती है तो वीकर सेक्शंस को हार्डशिप्स होंगी और ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो जाएगी ।

जहां तक रेवेन्यू का ताल्लुक है, हम इन फैक्ट्रीज से हायेस्ट रेट पर चार्ज करते हैं । साथ ही साथ 25 प्रतिशत पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। इसलिए हमें इसमें कोई घाटा नहीं हो रहा है । जहां तक डायरेक्ट लाइन से चोरी का ताल्लुक है, हमारे डिपार्टमेंट की विजिलेंस शाखा ने केस-रेड किए हैं । 1980–81 में मीटर टेंपरिंग के 85 केस पकड़े गए और थ्रप्ट डायरैक्ट सप्लाई फ्राम मेन के 9 केस पकड़े गए । इसलिए हम चोरी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि इन्हें कोई अल्टरनेटिव साइट दी जाए ताकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को असुविधा न हो ।

जहां तक किसी एम० पी० का ताल्लुक है, हम इन्फार्मेशन कलैक्ट कर रहे हैं। अभी तक जो इन्फार्मेशन हमारे पास है उसके अनुसार किसी भी एम० पी० या उसके लड़के की फैक्ट्री जो अन-एथोराइज्ड है, बिजली नहीं दी जा रही है ।

जहां तक दिल्ली की पावर-जनरेशन का ताल्लुक है, आपको खुशी होगी कि सन् 1980–81 में 1979–80 से बैटर पोजीशन है और लोड-शेडिंग भी पिछले 3–4 महीने में बहुत कम है। (व्यवधान)।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : प्रैस वालों से पूछें कि अखबार में कैसे छापते हैं। (व्यवधान)।

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): I can assure the House and I can assure you that there was no political interference. What actually happened was that the electric connection of the factory of the gentleman concerned, which appeared in the news item and about which you are mentioning, was disconnected on the 12th November 1980, when consumption of load more than sanctioned was detected. The point at issue is that he was drawing more than what was actually sanctioned. The load detected by the DESU was 172 HP. The factory remained disconnected for a few days. A show-cause notice, as required under the Act, was served on the factory on the 4th November 1980. On receipt of representation dated 4th November 1980 from him that the sanctioned load is about 150 kw, and not 40 HP, as indicated by the DESU, stay orders were granted by the Chief Engineer to enable the party to produce documentary evidence in support of his claim. On verification of the records, the statement of the party concerned was found to be incorrect. Consequently, the supply to the factory was disconnected. So, there was no political interference.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई पोलिटिकल प्रेशर नहीं है, खैर जो भी हो लेकिन ये 20 हजार जो इन्होंने मान लिया है कि 20 हजार फैक्ट्रियां स्वीकृत लोड से अधिक चल रही हैं और इन्हें हाई टैरिफ लेकर नियमित कर दिया गया है और यह देश हित में उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया है, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी तक ये सब इतने दिनों से चल रहा था तब आपके अधिकारियों ने इसको नियमित क्यों नहीं कर दिया । और अब देश हित में रेगुलराइज कानून के तहत 20 हजार में से कितनी फैक्ट्रियों को रेगुलराइज किया गया है ? इसी प्रकार

आपने बताया है कि 9 केस एफ० आई० आर० किए गए हैं तो ये क्वेश्चन करने के बाद हुए हैं या पहले हुए हैं और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है जो मैं पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। ... (व्यवधान)।

MR. SPEAKER: No further supplementaries will be allowed.

श्री विक्रम महाजन : मैंने अपने जवाब में पहले ही साफ कह दिया है कि बीस हजार के करीब फैक्ट्रीज हैं। यह भी मैंने बता दिया है कि इन में ढाई लाख के करीब लोग काम करते हैं। उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला लिया है कि अभी हम ने कोई डिसकोनेक्शन नहीं करना है। जहां तक रेग्युलराइजेशन का ताल्लुक है अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि इस पर विचार करें कि किस ढंग से इस प्राबलैम को साल्व किया जा सकता है।

जहां तक एफ० आई० आर० कैसिस का ताल्लुक है सारे साल की फिगर्ज हैं। मोस्ट आफ दी केसिस आपके सवाल से पहले के हैं। कितने उसके बाद हुए हैं उसकी फिगर्ज मेरे पास नहीं हैं। अगर मिल जाएंगे तो मैं भेज दूंगा।

कितने आफिसर्स इस में इनवाल्व्ड हैं उसकी फिगर्ज मेरे पास नहीं है, अगर मिल जाएगी तो मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली में बीस हजार इलीगल फैक्ट्रीज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनको बिजली का कनैक्शन कैसे मिला ? क्या बिजली का कनैक्शन देने से पहले बिजली डिपार्टमेंट यह वेरिफिकेशन नहीं करता कि व फैक्ट्रीज लीगली इंस्टाल की गई हैं या इलीगली ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: These people have a peculiar *modus operandi*.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN: I am asking about your own department, not that.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Delhi Administration? We have nothing to do. The Energy Department has just nothing to do with it.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN: The Delhi Administration is under the Government of India.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Let him answer the question.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: I am replying. The *modus operandi* is like this. They ask for connection for domestic use and after this, they convert it for commercial and also for industrial purposes.

अध्यक्ष महोदय : उनको जवाब तो पूरा दे लेने दीजिए।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : सवाल का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो उनको देने दीजिए।

SRHI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: The *modus operandi* of such unauthorised users is that initially they obtain a connection for domestic or commercial use and then use it for industrial purposes and in doing so, they do not obtain

the licence. It is the duty of the Delhi Municipality to issue the licence. (*Interruptions*). I do not know Mr. Speaker, Sir, whether the hon. friend agrees with me or not. But whatever facts we have we are presenting them.

श्री मल्लिक एम० एम० ए० खां : मैंने पूछा है कि कनैक्शन मंजूर करने के पहले डिपार्टमेंट वैरिफिकेशन करता है या नहीं करता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता तो दिया है कि पहले डोमैस्टिक ले लेते हैं। जो लाइसेंस इशू होता है वह डोमेस्टिक यूज का होता है।

श्री मलिक एम एम ए० खां : इस्तेमाल फैक्ट्री के लिए कर रहा है तो वेरिफिकेशन क्या करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तब ये रिसपांसिवल हैं।

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Mr. Speaker, Sir, primarily this DESU is under the jurisdiction of Delhi Administration and they should take action because licence for industrial use is granted by the Municipal Corporation of Delhi, but unfortunately this is an unusual situation....

MR. SPEAKER: Take some unusual steps to rectify it.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: We will take necessary steps to rectify it.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I want to know from the hon. Minister (i) whether it is a fact that these over 20,000 factories have been existing for the last 20 years or 15 years or 10 years, (ii) whether it is a fact that DESU is under the control of the Municipal Corporation, and (iii) whether it is a fact that from time to time all the political parties and all the M.Ps. have asked for their regularisation and against this domestic connection, on human considerations the Government has taken this decision. I want to know whether it is a fact that during all this time the Municipal Corporation has been run most of the time by the Janata Party.

श्री विक्रम महाजन : यह सही है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं ये काफी अर्से से चल रही हैं। कुछ 1977 के पहले थीं, कुछ 1977–80 के बीच में भी बनी हैं और कुछ थोड़ी बहुत उसके बाद बनी हैं जिसकी सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन काफ़ी देर से यह फैक्ट्रियां चल रही हैं। यह भी सही है कि यह मामला डी० ई० एस० यू० के अधीन था जो हमेशा दिल्ली म्युनिसिपल कोरपोरेशन के अधीन रहा है, सैण्ट्रल गवर्नमेंट से उसका बहुत कम ताल्लुक रहा है। हमने यह कोशिश की है कि इस प्रोबलम को सॉल्व किया जाय।

और जहां तक पोलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है यह आप सभी जानते हैं कि दिल्ली म्युनसिपल कारपोरेशन को कौन पार्टी चलती रही है।..

श्री एच० के० एल० भगत : दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन कौन सी पार्टी रन करती रही है, इसका जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने।

श्री विक्रम महाजन : मैंने कह तो दिया।

T.V. Centre for Bangalore

*213. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the foundation stone of a T.V. Centre building was laid recently by him in Bangalore; and

(b) if so, the details regarding its cost and when it is expected to start functioning?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir. The foundation stone for the T.V. Centre Bangalore was laid on 4-2-1981.

(b) The estimated cost of the project is Rs. 391 lakhs. The T.V. Centre at Bangalore is expected to be commissioned in 1983-84.

SHRI G. Y. KRISHNAN: It is highly appreciable that during the Sixth Plan, T.V. is going to come to Bangalore. Is it coloured T.V. or Black and White T.V. which is coming to Bangalore?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): First let the T.V. come to Bangalore. The question of colour will be decided after they get T.V.

SHRI G. Y. KRISHNAN: Are we not getting T.V.? The hon. Minister replied—'first let the T.V. come to Bangalore'. Is it still doubtful for us to get T.V.?

SHRI VASANT SATHE: I can assure my hon. Member through you that Bangalore is going to get T.V. I have already laid the foundation stone. Land has been acquired. The State Government has been entrusted their own request with the task of constructing a building as early as possible. I may inform for his benefit that we are also thinking to expedite the arrangement of having a rally antenna set up in the near future within a period of six months so that they can start seeing T.V. from Bombay and Madras.

SHRI G. Y. KRISHNAN: It will be commissioned during 1983-84. Why is so much of long time being taken? If so much of long time is allowed to be taken, the estimated cost which is shown as Rs. 391 lakhs will increase by a few lakhs. Is it not so?

SHRI VASANT SATHE: The estimated cost is with a view to this period. But it is for the State Government to construct. After all the construction of studios and tower is not done overnight. It is for the State Government to take as much time as they feel reasonable. If they do it earlier, I shall be quite happy.

SHRI K. LAKKAPPA: I must congratulate our Minister on having met the long outstanding or pending demand of covering specially beautiful and colourful city of Bangalore. He is not going to give us coloured T.V. I would like to know the estimated cost, construction cost and the financial allocations from the Central Ministry to the State. Because the State has agreed to construct the entire building and other things in a specified time. I would like to know what is the Central assistance provided for. The point of time fixed for 1982-83 is a long one. Therefore, I want to know whether the hon. Minister will expedite the completion of a full-fledged TV centre at Bangalore. We do not want a second-grade TV centre coming up after six months. We want a full-fledged TV centre in the south, at Bangalore. It should be expedited. Will the hon. Minister take up the matter with the Chief Minister in order to expedite it?

SHRI VASANT SATHE: The amount of about Rs. 4 crores provided for construction is going to be given by our Ministry, at the Centre, to the State Government and therefore there is no question of any paucity of funds. The question of expenditing construction work will depend on how fast the PWD of Karnataka does the job. As I said, I will be happy if they do it earlier. As far as six months business is concerned, it is not a full-fledged TV centre. It is only a relay facility to get Madras and Bombay programmes seen in Bangalore so that they will

have something to start with by the time their studio comes up.

SHRI XAVIER ARAKAL: The hon. Minister has stated, that to expedite this matter, a relay equipment will be supplied within six months but the hon. Members from Karnataka have said that they want a full-fledged TV centre immediately. My submission is that Trivandrum TV centre has not yet started functioning. It is only on paper. It will take years to come. Will the hon. Minister, therefore, consider my request to have at least a relay and transmission centre at Trivandrum?

SHRI VASANT SATHE: Like Bangalore, Trivandrum also is included in the Sixth Plan. As soon as the Kerala Government makes land available, I am willing to do the same which I have done for Bangalore.

SHRI C. T. DHANDAPANI: It is not only a question pertaining to Bangalore but it is also relating to transmission from Madras. In that case, I can put a question in regard to Coimbatore also. There is already a tele-communication tower erected in Coimbatore. Enquiries reveal that at the cost of Rs. 30-40 lakhs, a TV station could be erected and constructed at Coimbatore. Will the hon. Minister kindly enquire and promise that he will do it?

SHRI VASANT SATHE: At Coimbatore, what they are having is a microwave tower set up by the P&T. Merely having a microwave tower is not having a television programme producing centre or a studio. What we can do at Coimbatore, with microwave tower being there, is to have a relay programme. That also, to have a relay station, costs about a crore of rupees. If that suggestion is there, we will consider it.

SHRI R. S. SPARROW: One of the most important TV stations which has international significance vis-a-vis Pakistan and other countries has been established at Jullundur. Time and again, it has been promised that it will start working full-blast very shortly. May I take the liberty of asking the hon. Minister to very kindly tell us how the situation stands specially in view of our lagging so many months behind schedule and, in that process, we have been losing so much of our effect?

SHRI VASANT SATHE: As far as Jullundur is concerned, you are perhaps aware that the tower could not be completed due to a dispute. The dispute has now been resolved. The tower will be completed very soon. Now it is only a matter of a few months. As soon as the tower is completed, Jullundur will be a full-fledged television centre.

Per capita consumption of power in Assam

*214. SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the per capita consumption of power in Assam as compared to the country as a whole; and

(b) what is the per capita consumption of power expected to be reached in Assam during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The per capita consumption of electricity in Assam and All India during the year 1979-80 was 35.66 kwh and 130.48 Kwh respectively.

(b) The expected per capita consumption of electricity on the basis of latest information supplied by North Eastern Regional Electricity Board works out to 32.8 Kwh during the year 1980-81.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: The Minister, in his reply gave the figure for the year 1979-80 as 35.66 Kwh against the All India figure of 130.48 Kwh of electricity.

But, in part (b), the Minister has stated that during the year 1980-81, it would come down to 32.8 Kwh and that it was mainly because of higher demand.

In view of this reply and also in view of the Minister's reply to another unstarred question which was put on a previous occasion, in which he said that in Assam out of total villages of about 40,000, only 4,658 villages had been electrified, may I enquire from the Minister what steps the Government of India is taking in the Central Sector to increase power generation in Assam?

May I also know whether it is a fact that the Government of India has since allowed for purchase of some gas turbines for augmentation of power in Assam and, if so, whether they are considering to give more gas turbines for Assam? I understand from the Central Electricity Board that the projects which are in hand will take another four years to be completed.

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): It is true that per capita consumption has come down. It is entirely due to local disturbances in Assam. The per capita consumption of electricity in Assam would be 35.66 units as against the national average of 130.48 units. At the end of the current plan, that means, 1984-85, the per capita consumption in Assam is likely to increase to about 75 units as against anticipated national average of about 200 units. The Government of India has approved a number of projects for the North-Eastern Region as a whole which, after implementation in 1984-85, will increase the present installed capacity of 330 MW to 1,000 MW. That means almost three times more. This three times increase in the present installed capacity will narrow down the gap between the per capita consumption of electricity in the North-Eastern Region and the national average.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: May I enquire from the Minister as to what is the position of the Bongaigaon Thermal Project and the Barakdam Project which are the more important Projects of North-Eastern Region?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: So far as Bongaigaon thermal project is concerned, it is likely to give power during the year 1981-82 to the extent of 60 MW and during 1984-85 to the extent of another 60 MW.

So far as Barakdam project is concerned, the first Unit will give benefit in 1980-81 and the second in 1981-82.

SHRI UTTAM RATHOD: Taking into consideration the backwardness of this particular area and also the fact that they are very much behind in per capita consumption compared to the national level, is the Government likely to give them some special grants for power production?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: The Minister has already said in his main answer that there is going to massive increase in power generation in Assam. In Assam and in the North-Eastern region we expect that, in the year 1984-85, there will be surplus power in this region to the extent of 1303 energy megawatt hours and the peak capacity will be surplus to the extent of 227 megawatts. Special grants are also being given to Assam.

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि आसाम की तरह हिन्दुस्तान की और कौन सी बैकवर्ड स्टेटस हैं बिजली के मामले में और उसके लिए आपने कौन सी कार्यवाही की है जिस के जरिए उनकी बिजली की कमी पूरी हो सके? ... (व्यवधान) ... बिहार भी वैसा ही है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप को नया सवाल करना पड़ेगा।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: From the hon. Minister's statement it is seen that consumption of electricity in Assam is only one-third of the national average. I want to know particularly how much time the Minister will take to improve the situation in Assam; there is an agitation there; for the economic uplift alone...

MR. SPEAKER: He has already said that.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: He has said about the whole north-eastern region. I want to know particularly about this State, Assam, how much time will be taken...

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Assam is also included in that. When we say 'north-eastern region', we mean Assam also.

Alleged violation of company laws by Chowgule Group

†

*216. SHRI DHARAM DAS SHASTRI:

SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is true that a number of companies owned by Chowgule Group are violating company law regulations in the matter of submission of company balance sheets within a statutorily defined period after the end of financial year and if so, particulars thereof;

(b) action taken by Government against this group of companies; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने 'येस सर', 'नो सर' कह कर बात खत्म कर दी । मैं यह कहना चाहता हूं कि वह उन कम्पनियों की सूची बताएंगे जिन कम्पनियों ने टाइमली बैलेंस-शीट सबमिट किया है ? यह जानकारी मैं चाहता हूं ।

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमन चौगुले ग्रुप की 18 कम्पनियां हैं जैसी कि हम को इन्फार्मेशन मिली है और सारी की सारी कम्पनियों ने बैलेंस-शीट जनरल बाडी मीटिंग के 30 दिन के अंदर ही दाखिल कर दिया है । यह दफ़ा 220 के तहत बिल्कुल सही है।

SHRI K. LAKKAPPA: My friend, Mr. Shiv Shankar, the hon. Minister for Company Affairs has stated flatly:

'No. — Does not arise.'

I would like to know this from the hon Minister. The companies owned by Chowgule, he has stated, are about 18. I want to know whether it is a fact that six companies owned by Chowgules have not submitted their balance sheets periodic reports even immediately after the General Body meeting for scrutiny and the completed balance-sheets, even after the end of the financial year. Will the hon. Minister have a probe into this matter and see, because the information supplied by the Ministry to the hon. Minister is not correct.

Therefore, I would like to know whether the Minister will have a second look at the situation prevailing there and see how far the Company Law rules and regulations have been violated by several companies owned by this Chowgule concern.

SHRI P. SHIV SHANKAR: Sir, the question itself related to the vio-

lation of the Chowgule Group of companies...

SHRI K. LAKKAPPA: We should not be too technical. I know it. As a lawyer you should not be too technical.

MR. SPEAKER: He does not want you to juggle around.

SHRI P. SHIV SHANKAR: He is not prepared to listen to my answer.

MR. SPEAKER: He wants an answer according to his norms.

SHRI P. SHIV SHANKAR: Sir, this is with reference to the submission of the Balance Sheets of these companies. Now, he says that there are six companies which have violated the provisions with reference to the submission of Balance-Sheets. I will be glad to receive the information. But when I tried to get the information from the concerned Registrar of Companies, I found that all these companies have filed their Balance-Sheets within time. But, certainly, if my friend could make available some information to me, I assure him that I will certainly go into the investigation of it and I will inquire about the facts. I will do the needful....

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Don't consider this as an inspired question.

SHRI P. SHIV SHANKAR: It is not your repository. Somebody else has put the question. You could wait for some time.

श्री राम विलास पासवान : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौगुले शिपिंग सर्विस को सरकार ने अपने हाथ में लिया, क्या उसका कारण यह भी था कि उन्होंने ला का वायलेशन किया था ?

SHRI P. SHIV SHANKAR: So far as the shipping company is concerned.... (*Interruptions*). If you insist on Hindi, I will certainly speak in Hindi. The point is that so far as the steamship company of Chowgules is concerned, it is called Chowgule Steamship Company. So far as this company is concerned, this company is still retained by this person and this company has not been taken over. I think there is some wrong information that Chowgule Steamship Company has been taken over. There is no information so far as we are concerned.... (*Interruptions*). No, it has not been taken over.

Accelerating rural electrification in Hill States

*217. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to lay a statement showing:

(a) whether the Rural Electrification Corporation has provided enough funds to the State Electricity Boards to accelerate the programme of rural electrification in the hill States and regions like Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Meghalaya, Manipur, Tripura, hill areas of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa and other hilly regions of the other States;

(b) if so, the amount provided to these Boards during the past three years in each case as grant or loan; and

(c) whether any programme for total electrification of the hilly regions has also been drawn up for the financial year 1981-82 and the 6th Five-Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Rural Electrification Corporation has been providing financial assistance for rural electrification schemes in the hill States and also in the the hill regions of other States i.e.

areas defined as hilly areas in the Census Records. In these areas, the Corporation has sanctioned up to 31-1-1981, 506 rural electrification schemes for a total financial assistance of Rs. 218.34 crores. State-wise details of the schemes sanctioned, number of villages covered and the loan amount sanctioned are given in Annexure-I.

(b) Loan instalments aggregating Rs. 72.43 crores have been released by the Corporation during the last three years (1977-78 to 1979-80) in respect of the rural electrification schemes sanctioned in hill areas. Details are given in Annexure-II.

(c) According to the Perspective Plan proposals received from the various States, cent per cent electrification of villages, including the villages in the Hill States and hilly regions of other States, is expected to be achieved by 1994-95 subject to availability of the required resources. During the year 1981-82, 18,000 villages including those in hill areas are likely to be electrified in the country through REC schemes.

ANNEXURE I

Rural Electrification Schemes sanctioned by R.E.C. in Hill Areas

(Rs. in lakhs)

S. No.	State	No. of Schemes	Villages covered	Loan Amount sanctioned (31-1-1981)
1.	Assam	4	233	190·010
2.	Gujarat	10	824	505·850
3.	Himachal Pradesh	50	6947	2115·588
4.	Jammu & Kashmir	81	4505	2955·798
5.	Karnataka	15	609	473·280
6.	Kerala	17	57	485·161
7	Maharashtra	14	610	633·312
8.	Manipur	10	544	655·416
9.	Meghalaya	34	1023	1404·044
10.	Nagaland	9	178	440·616
11.	Orissa	162	12924	6814·042
12.	Rajasthan	51	2357	1955·650
13.	Tamil Nadu	..	..	..
14.	Uttar Pradesh	47	6710	3064·488
15.	West Bengal	2	104	141·349
	TOTAL	506	37625	21834·604

ANNEXURE-III

State-wise Position of loan amount Disbursed by Rec-During the last Three years (1977-78 to 1979-80) In Respect of the Rural Electrification Schemes Sanctioned in hill Areas

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	State	Amount disbursed during April, 1977 to 31st March, 1980
1.	Assam	42.560
2.	Gujarat	128.724
3.	Himachal Pradesh	604.805
4.	Jammu & Kashmir	1150.976
5.	Kerala	180.401
6.	Karnataka	146.409
7.	Maharashtra	28.203
8.	Manipur	187.463
9.	Meghalaya	687.432
10.	Nagaland	143.681
11.	Orissa	2293.131
12.	Rajasthan	646.425
13.	Tamil Nadu	—
14.	Uttar Pradesh	979.853
15.	West Bengal	22.954
	TOTAL	7243.017

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: From the answer to part (c) of the statement it appears that the date for total electrification is 1994-95. I want to know whether this is the date for the total electrification of the entire country or is it that preferential treatment has been given to the hilly areas? In case it is not, then will the Minister kindly tell us what is the special provision for the hilly areas?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: So far as 1994-95 is concerned, since it relates to the whole country, obviously it includes the hilly areas.

So far as special aid to hill areas is concerned, I think in annexures which are attached to the statement and which are laid on the Table of the House, I have given figures of all hill areas and the States which have other areas. In Annexure-I I have given the loan amount sanctioned upto 31st January, 1981. For Assam it is Rs. 190 lakhs. For Gujarat it is Rs. 505 lakhs. All those details are there. Not only this, we have categorised the different regions. There are categories like Ordinary Advanced Areas, Ordinary Backward Areas and then specially under-developed areas. Then there is the Minimum Needs Programme and Revised Minimum Needs Programme. These are the categories in which we have categorised the Backward, Tribal and Hill areas.

So far as hill areas are concerned, special efforts are being made to give maximum money.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Sir, the answer is not clear. In his reply he has said that 1994-95 is the date for hilly as well as the entire country to be covered. If the entire country is covered then automatically the hilly areas are also covered. My point was whether the date could be extended earlier in respect of hilly areas. Secondly, Sir, he has given figures for villages to be covered. Is it a fact that at present the REC considers a village to be electrified after the distribution line has reached the village. According to REC what is the definition of the total electrification of the villages?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: So far as REC is concerned unless most of the villagers get electricity we do not

consider the village to have been covered. If the hon. Member can give any specific instance we will enquire into it and find a remedy for the problem. So far as aid to the hill areas is concerned, I have specifically given the details in the Annexure. We are making a massive effort to develop the backward and hilly areas.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, in 1980-81 they have given loans to the State Electricity Boards to the tune of Rs. 218 crores. May I know the total amount of loan advanced to State Electricity Boards so far and also whether Govt. is aware that almost all the State Electricity Boards are running under loss? In this connection may I know whether the Government have asked the State Electricity Boards to streamline their functioning. What steps have been taken by the Government to monitor their activities?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): Sir, we have changed the whole thing. We are not only giving money but also monitoring the entire equipment so that they can do their job efficiently.... (*Interruptions*)

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, I had asked as to what is the total loan given to the State Electricity Boards so far and also whether the Government is aware of the fact that all the State Electricity Boards are on the red?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: Sir, we would like to have a separate notice for this. The hon. Member may put a specific question and we will answer it.

SHRI K. A. RAJAN: The Central Government is allotting so much of money for rural electrification to the various State Electricity Boards. I would like to put as specific question for answer by the hon. Minister, in the matter of rural electrification. Are we to understand that just drawing one distribution line to a corner of a village would be taken as electrification of the rural village? If not, what is the norm? What is the guideline in this respect? Are you not going by some standard like so many consumers or so many houses or something like that. Simply drawing a line to a village and putting up a post there would not constitute rural electrification.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Positive guidelines are there. The State Electricity Boards can get the money from the R.E.C. When they take the loan, the R.E.C. wants to know whether the State Electricity Board concerned is in a position to repay the loan or not. There are certain guidelines, for example, in respect of the agricultural sector, we want to know whether there is possibility of expansion in the Agriculture sector and so on. Like that, there are definite guidelines in regard to these matters.

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जो सूची दी है, उस में मध्य प्रदेश का उल्लेख नहीं है, जब कि मूल प्रश्न में मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछा गया था । मंत्री जी ने बतलाया है कि इस काम पर 218 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा 18 हजार गांवों को रूरल-इलैक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जोड़ा जायेगा, मैं जानना चाहता हूं—क्या आप इस बात की जानकारी अपने मंत्रालय से करेंगे कि जब मूल प्रश्न के अन्दर मध्य प्रदेश का नाम है तो वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के कितने गांवों के लिये विद्युतीकरण की योजना है तथा इस का मूल उत्तर में समावेश क्यों नहीं किया गया ?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I will collect the information and supply it.

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस को ठीक कर देंगे, उस में आ जायेगा ।

(*Interruptions*)

SHRI VIRBHADRA SINGH: Even in hilly areas there are some areas which are more hilly and backward and remote.

According to the present norms laid down by the R.E.C. these areas do not qualify for assistance from the R.E.C. I would like to know whether the Government has modified the norms in respect of these backward and hilly areas, so as to enable them to get assistance from the R.E.C. In the reply given by the hon. Minister, he has mentioned that as on 31-3-80, 50 schemes have already been approved in respect of Himachal Pradesh. I want to know how much money has actually been disbursed so far.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I request the hon. Member to see Annexure II where the information is given. As on 31-3-80, Himachal Pradesh has been given a loan of Rs. 604.805 lakhs. This is the figure regarding loan already disbursed. This is in Annexure II. In Annexure I, I have given information in respect of certain other categories. I have already given this figure.

Sharing of Power from Thein Dam

*218. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have considered the request of Rajasthan and Haryana Governments for sharing the power benefits accruing from the Thein Dam Project; and

(b) if so, the result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). In a meeting taken by the Prime Minister on 14-2-1979 with the Chief Ministers of the concerned States, the Prime Minister felt that since the issues are to be decided on the basis of legal rights, he would take the opinion of the Attorney General of India regarding the entitlement of Rajasthan and Haryana for a share in the power benefits from the Thein Dam Project. The Attorney General has given his opinion, which has analysed all aspects of the issues involved. A final view in the matter is yet to be taken.

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: May I know from the hon. Minister whether, after the change of the political set-up in the country after February 1979, any meeting of the two Chief Ministers of Rajasthan and Haryana was called by the Prime Minister....(*An hon. Member, Punjab also*) along with Punjab Chief Minister. Secondly I want to know when the Thein Dam project is likely to be completed. Thirdly I want to know this. The hon. Minister has stated that the Attorney General has given his opinion.

May I know when this information was received by the Government of India? What action has been taken by the Government on the opinion of the Attorney General? Why has this projected scheme been unnecessarily delayed?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: The project is likely to be completed in the Seventh Five Year Plan. So far as the opinion of the Attorney General is concerned, I have stated in my reply that a final view is to be taken. So far as the date is concerned, it was given on 2nd May 1979 and about the meeting of the Chief Minister, I will find out.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

पाकिस्तान द्वारा तेल की सप्लाई

*208. श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाख टन तेल सप्लाई के लिए भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच जनवरी, 1981 में कोई समझौता हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समझौते की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी):

(क) वर्ष 1981 के दौरान एक लाख मी० टन भट्टी का तेल आयात करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया गया है ।

(ख) मूल्यों आदि के सम्बन्ध में ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा ।

Energising Irrigation pump sets

*209. SHRI K. A. SWAMY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have considered a programme of energising irrigation pump-sets in the country; and

(b) if so, whether any funds have been allotted for encouraging the electrification of irrigation pump-sets?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHRY): (a) High priority is being extended to energisation of pumpsets with a view to increasing agricultural production. The total number of pumpsets/tubewells energised up to the end of March, 1980, was nearly 39.50 lakh. An additional 2.30 lakh pumpsets have been energised from 1-4-1980 to 31-12-1980.

(b) The Sixth Five Year Plan (1980—85) envisages to a total outlay of Rs. 1,576 crores for rural electrification programme, of which the Rural Electrification Corporation component is likely to be Rs. 880 crores. The main thurst of the Plan will be on energisation of pumpsets and 25 lakhs pumpsets in the country, are proposed to be energised during the Plan. Out of this, energisation of 16 lakh pumpsets (8 lakhs under REC Normal Programme and another 8 lakhs under SPA Programme of REC) will be financed through the Rural Electrification Corporation and the balance 9 lakh pumpsets with the funds which will be provided direct to the States for their Normal Development Programme. Thus, a major portion of the Plan outlay is proposed to be routed to the States through the Corporation.

Recoverable Reserves of Crude Oil

*210. SHRI SURYA NARAYAN SINGH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that total recoverable reserves of crude oil in the country have dwindled from 452 million tonnes in 1978 to 360 million tonnes as in January, 1980; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Broadcast over A.I.R. by State Chief Ministers

*212. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have decided that the State Chief Ministers would now be able to broadcast over the All India Radio;

(b) whether the procedure that will be followed in this regard has been worked out; if so, the details thereof;

(c) whether they would be required to give an advance copy of their speech prior to broadcast to the AIR for vetting; and

(d) whether all the Chief Ministers, particularly those ruled by Opposition Parties have agreed to the procedure evolved and if not, their points of view?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) There has never

been any restriction on broadcasts by Chief Ministers of States over All India Radio.

(b) DG: AIR have reiterated on 31st January 1981 their earlier instructions to All India Radio stations that Chief Ministers are always welcome to broadcast.

(c) Yes, Sir. It has been the practice of AIR Stations to obtain a copy of the script of the VIP's broadcasts in advance and also record the broadcast in advance.

(d) As this is a matter within the competence of the All India Radio, it is not necessary to consult State Governments.

Depreciation Formula for State Electricity Boards Funds

*215. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the names of States that have asked for changing the Central Electricity Authority's depreciation formula in respect of funds for the Electricity Boards which was fixed at 3 per cent of the fixed assets;

(b) the reasons that have been adduced for this demand; and

(c) the action taken thereon?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHARY): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Loss of Power on Account of Strikes

*219. SHRIMATI KRISHNA SAHI: Will the Minister of ENERGY be pleased to lay a statement showing:

(a) what was the total loss of power on account of strikes and go-slow during 1977—79;

(b) what was the total loss during 1980;

(c) are Government contemplating to raise reserve engineering units at national level to run thermal and hydel units in the event of strike or "go-slow" by engineers and others of a particular unit; and

(d) if so, when?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY: (a) to (b) It is not possible to assess the loss of power on account of strikes and go slow. Hence, no exercise has been undertaken to assess the same both for the period 1977—79 and 1980. The difficulty is mainly due to the complex nature of the equipments and characteristics of the occasional labour disputes which generally affect only part of the workers/staff/engineers of the industry. Various alternative strategies in the line mentioned by the Hon'ble Member are under examination by the Government and it is not possible to disclose the same at this stage in public interest..

Talks with Nepal on River Waters

*220. SHRI S. M. KRISHNA:
SHRI R. L. BHATIA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether during his recent visit to Nepal, he held any discussion with the Nepalese Government on the mutually beneficial use of river water, hydro-electricity generation, navigation and flood moderation; and

(b) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHARY): (a) and (b). Minister for Energy visited Kathmandu on 2nd and 3rd February, 1981 in connection with the foundation stone laying ceremony of Devighat Hydro-electric Project. During this visit, the Minister for Energy took the opportunity to call on the Prime Minister of Nepal and the Minister for Water Resources of His Majesty's Government, Nepal, and had discussions

with them. Opportunity was also taken during these discussions to briefly review the official level discussions held earlier on different multi-purpose projects such as Karnali, Pancheshwar etc. Both sides emphasised the need for further extension of mutually beneficial bilateral cooperation in the area of water resources development.

Allotment of Diesel to Madhya Pradesh

221. SHRI SHIV KUMAR SINGH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is total amount of diesel alloted to Madhya Pradesh between January and December, 1980; and

(b) how does it compare with allocations in the last two years?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) A quantity of about 4.45 lakh tonnes of High Speed Diesel (HSD) was allotted to Madhya Pradesh between January and December, 1980.

(b) The system of monthly allocations of diesel was started only with effect from October, 1979. The total allocation of diesel in 1980 for Madhya Pradesh was about 4,45000 tonnes against sales of about 403000 tonnes in 1979.

Joint Oil Exploration Work by India and U.S.S.R.

*222. SHRI RAMA CHANDRA RATH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether oil exploration work has been launched by India and Soviet Union jointly in our country;

(b) whether any agreement has been signed between both the countries for carrying such oil exploration work;

(c) the places in our country where such exploration works are going on;

(d) whether Government have any fresh proposal to have talks with Soviet Union for expanding such exploration programme; and

(e) the details in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Presently one Soviet-Indian team is drilling the Rokhia exploratory well in Tripura.

(d) and (e). In accordance with the agreement on Economic and Technical Cooperation signed on 10th December, 1980 the Soviet Side would render cooperation to the Indian Side in execution in one of the promising onshore areas in India of integrated work for oil and gas including geophysical exploration and drilling works, elaboration of basic technical concepts of development of the deposit and the installation of production facilities. The area will be chosen by mutual agreement between the Indian and Soviet Sides.

Visit by a French Consultancy Company to Bombay High

*223. SHRI JANARDHANA POOJARI:
SHRI LAKSHMAN MALLICK:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether a French Consultancy Company has visited Bombay High to study the possibility of increasing India's oil production;

(b) if so, details of the company's proposal to Government in this regard; and

(c) reaction of Government to it?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir. During the periodic consultations which the

CFP have with the ONGC under the existing consultancy agreement, possible extension of the agreement and enlargement of its scope, etc., were discussed in general.

(b) and (c) The details have yet to be discussed and negotiated.

Power Stations Facing Acute Coal Shortage

*224. SHRI HARINATH MISRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thermal power stations are facing acute shortage of coal;

(b) whether any review has been made by Government on infrastructure for movement of coal to thermal power stations in the country;

(c) if so, the details thereof; and

(d) improvement in power generation effected during the current financial year?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY): (a) Although some of the thermal power stations had been getting short supply of coal as compared to the linked quantities, during the first half of last year, the supply of coal to thermal power stations has been improving from October 1980 onwards and the coal supply position to most of the thermal power stations is at present by and large, satisfactory.

(b) and (c). The Government is regularly reviewing the infrastructure inputs like power, coal and wagons required for supply of coal to thermal power stations. A Cabinet Committee on Infrastructure has also been set up by the Government to monitor the infrastructure inputs. This is backed by special official support.

(d) The total thermal energy generation during the period April 1980 to January 1981 has been 7.1 per cent more over the generation in the corresponding period last year. However, during the months of November, December, 80 and January 81, total generation has increased by about 20 per cent, 16.3 per cent, and 9.5 per cent over the generation in the corresponding months last year and the thermal energy generation increased by 21.8 per cent, 22.3 per cent and 14.6 per cent over the thermal generation in the corresponding months of last year.

Priority to Scheduled Castes/Tribes for L.P.G. Distributorships

*225. SHRI K. KUNHAMBU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have issued any directives to the Indian Oil Corporation about priority to be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes applicants for distributorship of cooking gas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the total number of people who were given distributorship during the last year and the number of Scheduled Castes and Tribes among them?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) The policy of reserving 25 per cent of all types of agencies/dealerships for Scheduled Castes/Scheduled Tribes except for 'B' site retail outlets (dealer-owned and dealer-operated) has been in force in the Indian Oil Corporation since January 1, 1974. Since September 23, 1977 the policy is to reserve 25 per cent of all types of agencies/dealerships for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in all public sector oil companies including the Indian Oil Corporation.

(c) Out of a total of 58 LPG agencies awarded by the Oil companies during the year 1979-80, 25 agencies are reported to have been given to

persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

New Gas-based Fertilizer Projects

*226. SHRI RAMGOPAL REDDY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up nine gas-based fertilizer projects in the country;

(b) if so, whether the places where these will be set have been determined; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) In addition to the 5 gas-based fertilizer plants, 2 each at Thal-Vaishet in Maharashtra and Hazira in Gujarat and one plant at Namrup in Assam, already sanctioned by the Government, it is proposed to set up, in a phased manner, 6 more gas-based fertilizer plants.

(b) and (c). A Site Selection Committee has been appointed to recommend locations for the proposed gas based fertilizer plants. It is only after the report of this Committee is received that the locations can be firmed up.

Wakf Survey in States

2001. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state in how many States the Wakf surveys are being conducted by the State Government and what are their results?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): Wakfs surveys are being conducted in 5 States and one Union territory and their results are as follows:

Sl. No.	State/Union Territory	No. of wakf properties surveyed upto 31-12-80
1.	Delhi	2399
2.	Kerala	1073
3.	Madhya Pradesh	260
4.	Orissa	3352
5.	Tripura	94 (upto 30-9-80)
6.	Uttar Pradesh	3200

Employment by Officers after Retirement

2002. SHRI SANAT KUMAR MANDAL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2969 regarding employment with Industrial Houses by retiring officers dated 9th December, 1980 and state:

(a) whether he is aware that a Deputy Secretary in his Ministry who was dealing with Drug Industry, after retirement took up employment on fabulous salary and perks with the OPPI (Origanisation of Pharmaceutical Producers Industry, Bombay) as the Resident Representative at New Delhi;

(b) if so, whether he took Government permission to take up this employment;

(c) the post held by the Class II Officers (referred to in the above) reply and the subject dealt with by him at the time he sought voluntary retirement to join the large Industrial House; and

(d) the steps which he proposes to take up to stop such malpractices both by the retired Officers and the Industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b). A Deputy Secretary in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) dealing with matters relating

to Drug Industry was allowed to be absorbed permanently in Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited, a Public Sector Undertaking under the Administrative control of this Ministry with effect from the 13th April, 1978 subject to the condition, *inter-alia*, that in the event of the service of the officer being terminated at the instance of either the Public Sector Undertaking or the officer within a period of two years from the date of his retirement from Government of India service and permanent absorption in the Public Sector Undertaking, the approval of the Government of India would be obtained by the officer before he takes any private employment.

The Officer resigned from the Public Sector Undertaking after the expiry of the 2 year period and joined OPPI (Organisation of Pharmaceuticals Producer Industry), for which no permission of Government was required.

(c) The Class II Officer, whose name has been referred to in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 2969 answered on 9th December, 1980, was holding the post of an Assistant. He was dealing with matters pertaining to Synthetic Fibre Industry at the time of seeking voluntary retirement.

(d) Does not arise, as both the Officers referred to above were not required in the circumstances of each case to take permission from Government before accepting private employment after retirement.

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बोध घाट बिजली परियोजना

2003. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में बोध घाट बिजली परियोजना का सर्वेक्षण किया गया है और इस परियोजना का कार्य कब शुरू होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो बोध घाट बिजली परियोजना पर कितनी लागत आएगी और इस पर काम कब चालू होगा और यह कब तक पूरा होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :

(क) और (ख) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित बोधघाट जल विद्युत परियोजना (4×125 मेगावाट), 209.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1979 में स्वीकृत कर दी गई है । राज्य प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मार्च, 1981 तक इस परियोजना पर 1.42 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण-पूर्व कार्यों के लिए लगने वाले एक वर्ष के अतिरिक्त, यह परियोजना 6 वर्ष में पूरी किये जाने का कार्यक्रम है ।

Disposal of compensation Claims Cases

2004. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2968 on 9th December, 1980 regarding compensation claims-applications of Displaced Persons from Ulhasnagar (District Thana) Maharashtra and state:

(a) the efforts made and progress achieved during the last two months in respect of minimising pending cases of compensation claims of Displaced persons from Ulhasnagar (Distt. Thana, Maharashtra); and

(b) whether any compensation has been paid to them, and if so, how much and to how many applicants?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b). Out of 41 cases, 2

cases have been settled during the past two months and a sum of Rs. 29,792/- adjusted towards the associated cost of properties. Constant efforts are being made to obtain certain information from the State Government and displaced persons with a view to finalising the remaining cases expeditiously.

Members of Films Censor Board

2005.SHRI MATILAL HASDA:
SHRI SUBHASH YADAV:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) who are the Members of Censor Board (Films) including regional officers;

(b) whether Members of the Censor Board posses special knowledge about culture education, in history in politics;

(c) details of the educational qualification and experience of each Member; and

(d) the guidelines and criteria for issuing certificate for a film?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD-BEN M. JOSHI): (a) The Board of Film Censors at present consists of:—

1. Shri Hrishikesh Mukherjee —Chairman
2. Dr. (Smt.) Madhuri Shah Member
3. Kumari Anasuya M. Nadkarni Member
4. Shri M. Bhaktavatsala Member
5. L. V. Prasad Member
6. Shri Tapan Sinha Member
7. Shri V. V. John Member
8. Shri K. V. Jagannathan Member

(b) and (c). The criteria for being members of the Board are that they should be persons of individuals merit and suitability, and be qualified, in the opinion of the Central Government, to judge the effect of films on the public. Brief particulars about the existing members of the Board are given in Annexure I. Laid on the Table of the House. Placed in Library (*See* no. LT-2009/81).

(d) A copy of the guidelines issued by the Central Government to the Board of Film Censors under Section 5B(2) of the Cinematograph Act, 1952 in relation to certification of films is laid on the Table of the House. Placed in Library. (*See* No. LT-2009/81)

Set up of Radio Station at Baripada, Orissa

2006. SHRI MANMOHAN TUDU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government has a proposal to set up a Radio Station at Baripada of Orissa;

(b) if so, when this proposal is going to be implemented; and

(c) the details in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) There is at present no proposal to set up a separate radio station at Baripada. The 100 kw mw transmitter at Cuttack, which is presently operating on a single mast, provides primary grade day time service to the Baripada district in north-eastern Orissa. There is a proposal to have a second mast with directional antenna system. When it is installed, the coverage is likely to improve further.

(b) and (c). Do not arise.

Audience Research Unit at Doordarshan, Madras

2007. SHRI D. S. A. SIVA PARAKASHAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any audience research unit functioning at Doordarshan, Madras; and

(b) if so, the nature of audience research made and action taken following research?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Audience Research Unit undertakes from time to time surveys/studies for qualitative feed back as well as quantitative assessment of viewers' opinion in respect of various programmes such as rural programmes, health programmes, industrial programmes, etc. telecast by Doordarshan Kendra, Madras. The contents of the programmes are reviewed in the light of the findings of these surveys/studies and corrective measures taken to improve the quality of programmes.

Views of Scientists against introduction of Colour Television

2008. SHRI DAULAT SINHJI JADEJA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain scientists are against the introduction of colour television in the country;

(b) if so, the reasons given by them; and

(c) the action taken by Government on their suggestions?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). Some scientists are of the view that in the field of television digital system is being experimented and is likely to be introduced in about a decade. They, therefore, feel that the present analogue system would get replaced by the new technology all over the would and we should await that technology before going in for colour transmission on the existing analogue system. They also feel that we are at present self-sufficient in black and white technology and we should try to expand the black and white system instead of going in for colour transmission.

(c) Some other scientists are, however of the opinion that technology is all the time advancing and by the time digital system is introduced, some new technology might be evolved. The question of colour transmission has no direct bearing on whether the system is analogue or is digital. Most of the countries in the world today have gone in for colour transmission so as to make colour television compatible along with black and white. It is pertinent to note that introduction of colour transmission does not render black and white receiving sets obsolete because black and white receiving sets continue to receive transmission in black and white as before. With the introduction of video system, large number of sets are being introduced using colour film cassettes. There is also a question of capacity to exchange TV films with other countries of the world who have gone in for colour transmission. We are unable to exchange these films because we do not have TV films in colour. Another important element which is of urgent consideration is the question of television coverage of the forthcoming Asian Games. Unless the coverage is made in colour film, no country in the world be willing to accept our TV films on these games. As to the question of additional expenditure it is being worked out that additional expenditure on colour transmission will be only 20 per cent more but this would also enable us to get the latest

equipment in terms of cameras etc., as all the latest equipment in the world is for colour. These factors will also be borne in mind while taking decision in consultation with the scientists.

Poor Coverage by All India Radio, Orissa

2009. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the coverage by radio stations in the State of Orissa was the poorest in the country;

(b) if so, the steps taken by his Ministry to improve the situation in that State so far;

(c) whether his Ministry has proposed in Sixth Plan period to improve the coverage in that State by setting up:

(i) a new radio station with 20 K.V. transmitters at Bhawanipatna.

(ii) local broadcasting stations with V.H.F. (F.M.) transmitters at Berhampur and Rourkela;

(iii) a local broadcasting transmitter at Keonjhar;

(d) if so, the names of the proposed radio stations sanctioned by his Ministry in the Annual Plan of Sixth Plan 1980-81 or 1981-82?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). Day time primary grade service is at present available to 81 per cent of the population in Orissa from Cuttack, Jeypore and Sambalpur Stations of A.I.R. The State is better placed as compared to other States like Maharashtra, Himachal Pradesh, Rajasthan and Karnataka where the coverage is even less than 80 per cent.

(c) and (d). Proposals for setting up a 20 KW transmitter at Bhawanipatna and local broadcasting stations at Berhampur, Rourkela and Keonjhar were included in the Draft Sixth Plan 1980—85 but due to severe financial constraints only the setting up of a local broadcasting station at Keonjhar could be retained in the finalised Sixth Plan. This scheme has also been included in the Annual Plan 1981-82.

Setting up of Petro-Chemical Complex in Ratnagiri District

2010. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) Following the setting up of fertiliser plant at Thal in the Kolaba district of Maharashtra, is there possibility of setting up the petrochemical complex in Ratnagiri district with a view to open up the possibility of the development of backward region of Konkan in Maharashtra; and

(b) if so, what is the progress in this direction?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Government of India have decided in principle to set up a gas cracker Petro-chemical Complex at Usar in Maharashtra. Consequently there is no possibility of setting up of any Petro-chemical Complex in Ratnagiri District. However the setting up of Petro-chemical Complex at Usar can open up the possibility of setting up petro-chemical conversion industries in the backward region of Konkan.

(b) Does not arise.

Films Produced by Film Division

2011. SHRI HARIHAR SOREN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of films which have been produced by the Films Division on developmental programme in 1979-80 and 1980-81;

(b) the number of regional languages films which have been produced on developmental programme during the above period;

(c) whether any Oriya film has been produced during the period by the Films Division; and

(d) if so, the names of those films?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) The Films Division has produced 37 films in 1979-80 and 8 films in 1980-81 (upto February, 1981) on developmental programmes.

(b) Generally, the Films Division produces films either in English or in Hindi as basic version. However, the films are dubbed in all major Indian languages before release in cinema theatres. Films which are not released in theatres are dubbed only in these languages which are required by the sponsoring Departments.

(c) Yes, Sir. One film was produced in 1980-81 in Oriya as basic version. One more film is under production during the year 1980-81 with Oriya as basic version.

(d) A statement showing the names of the films is enclosed.

Statement

1. *Films on developmental programmes produced in 1979-80.*

1. Drought Prone Areas Programme.
2. Of Forests Tribals and Progress.
3. Barabandi.
4. Science and Agriculture.
5. Strength to Unity.
6. Basant Bahar.
7. Mandusi.
8. The Lesson of Sukhamajari.
9. Air Pollution.
10. Water and the Farmer.
11. Protecting the Workers.
12. National Highways.
13. Search for Black Gold.
14. Sinews of Small Industry.
15. Pasture Development in Dryland Areas.
16. Better Yields For Rainfed Crops.
17. Development in Command Areas (North).
18. A Change.
19. Science and the Farmer.
20. Freedom from Want.
21. Story of Waranagar.
22. Modern Kalpataru.
23. From Waste to Wealth.
24. Threshes A means of Prosperity Through Safe Use.
25. Potable Water For Millions.
26. Tools And Implements For Small Farmers.
27. On the Trace of Progress.
28. Better Homes.
29. For Them to Bloom.
30. Waves And Shores.
31. For Mother And Child.
32. Reclaiming Revines.
33. Harnessing The Tapi.
34. Of Hills Fruits and Mellow Fruitfulness.
35. New Dimension.
36. Low Cost Gobar Gas Plant.
37. Nuclear Power—A National Achievement.

2. *Films on developmental programmes produced in 1980-81.*

1. National Water Plan.
2. Improved Bullock Cart (New Bullock Cart).
3. Equitable Distribution of Water Warabandi.
4. Hydraulic Rams.
5. Multi Storeyed Cropping.
6. New Images.
7. Power For Rural Prosperity.
8. Electro Chemistry in Action.

3(a). *Films on developmental programmes in Oriya produced in 1980-81.*

1. Ame Privar Niyojan Grahana Karichu.

(b) *Under Production*

1. Mother's Love.

Ad hoc Appointments in Dandakaranya Project

2012. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the abuse of the powers of appointing authorities in Dandakaranya Project to appoint/promote employess in *ad hoc* terms in such large number of cases (each in some cases, by observing all formalities of recruitment rules and recruitment) for such long duration and treat such recruits/personnel less than casual employees denying them, among other things, the minimum protection of statutory temporary service Rules viz. CCS (TS) Rules, 1965; and

(b) the reasons why this practice of recruiting on *ad hoc* terms in Dandakaranya Project and treating the *ad hoc* employees less than casual employees with 240 days service at credit became common with the administration there and why this could not be reduced to minimum and totally eliminated before long?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) *Ad hoc* appointments are made in the interest of work.

New L. P. G. Connections in Delhi/New Delhi

2013. SHRI A. C. DAS: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government had a proposal to provide new L.P.G. connections to the consumers from January, 1981;

(b) if so, the number of new L.P.G. connections had given to the consumers of Delhi and New Delhi in January, 1981;

(c) the number of L.P.G connections are expected to be released for the consumers of Delhi and New Delhi in 1981-82; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) As per the plans of the oil industry, the new gas connections are to be released from the 1st quarter of 1981.

(b No new gas connections were released to persons on the waiting list in the Union Territory of Delhi in January, 1981.

(c) and (d). With the likely availability of LPG from Bombay High and Mathura Refinery from this year, the oil companies would make efforts to enrol about 1 lakh new customers in Delhi within, 1982.

पटना आकाशवाणी केन्द्र द्वारा विभिन्न समस्याओं पर आयोजित वार्ताएं

2014. श्री प्रभावतार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना आकाशवाणी केन्द्र द्वारा विभिन्न समस्याओं पर वार्ताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें राजनीतिक नेता, संसद् विधायक, संसद् और विधान-मंडलों के सदस्य, साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1980 में आयोजित की गई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है, और इस प्रयोजन के लिए आमंत्रित किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के चयन का मानदंड क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

Britain's Proposal for India's Oil Exploration

2015. SHRI B. V. DESAI:
SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Britain has shown greater interest to active participation in India's oil exploration programme;

(b) if so, whether India has received any concrete proposal from the British Government in this regard;

(c) if so, the details of the same; and

(d) the reaction of the Indian Government?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). No, Sir. Nor has any proposal been received from the British Government.

(c) and (d). Do not arise.

Drilling of Wells by Oil and Natural Gas Commission and Oil India Limited

2016. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the total number of wells drilled by O.N.G.C. (Oil & Natural Gas Commission) and OIL (Oil India Ltd.) together during 1979-80 and 1980-81;

(b) the total quantity of oil drilled from those wells during the above period;

(c) whether Government have a proposal to drill some more number of wells during 1981-82; and

(b) if so, the details about the total quantity of oil likely to be drilled during this period?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) ONGC and OIL drilled a total of 110 wells in 1979-80 and 87 wells in 1980-81 (upto December, 1980).

(b) While it may not be practicable to indicate the total quantity of oil produced from these wells only, during 1979-80, 11.73 million tonnes and during 1980-81 (upto December, 1980) 7.10 million tonnes were produced by these two organisations.

(c) Yes, Sir,

(d) During 1981-82, the indigenous production of crude is estimated at 16.9 million tonnes.

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में इन्सपेक्टरों (विद्युत) की नियुक्ति के लिए पैनल

2017. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में इन्सपेक्टरों (विद्युत) को नियुक्ति के लिए एक पैनल गठित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें सामान्य वर्गों तथा आरक्षित वर्गों के कितने उम्मीदवारों को शामिल किया गया था और

उन में से कितने उम्मीदवार नियुक्त किए गए थे और किस अनुपात में ;

(ग) क्या इस बारे में सांविधानिक उपबंधों के अनुसार सामान्य तथा आरक्षित अ वर्गों के लिए निर्धारित अनुपात के अनुरूप उम्मीदवार नियुक्त नहीं किए गए थे ; और

(घ) पेनल में शेष उम्मीदवारों को कब तक नियुक्त किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख) . जी हां। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में निरीक्षकों (तकनीकी) के पद पर नियुक्तियां करने के लिए कए नाम सूची मई 1980 में तैयार की गई थी जिसमें सामान्य श्रेणी के 92 उम्मीदवारों के नाम तथा अनुसूचित जाति के 15 उम्मीदवारों के नाम थे । इस नाम सूची में से 26.2.1981 तक सामान्य श्रेणी के 31 उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति के 15 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है ।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में पिछले बकाया को ध्यान में रखने के पश्चात्, उक्त नाम सूची से नियुक्तियां निर्धारित नियमों के अनुसार की गई थी ।

(घ) नामसूची, जोकि 25.5.1981 तक मान्य है, के अन्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां जब भी रिक्त स्थान उपलब्ध होंगे, तब की जाएंगी ।

Retrenchment of Supervisors of Lok Tak Hydro-Electric Project

2018. SHRI O. CHINNASAMY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the supervisors employed by the Central Electricity Authority and deputed to Lok Tak Hydro-Electric Project are facing retrenchment since the Central Electricity Authority is not in a position to absorb them while National Hydel Power Corporation authorities are not inclined to take them in suitable grades and to protect their seniority, pay and service conditions;

(b) whether these employees have services upto 10 years who have to become juniors to many other direct recruits even in case if those employees are absorbed in the Corporation;

(c) whether National Hydel Power Corporation has not accepted the guidelines recommended by the Energy Ministry in this regard;

(d) if so, the reasons for not accepting the recommendation of the Energy Ministry by the National Hydel Power Corporation authorities; and

(e) if not, the term applicable to Central Electricity Authority supervisors for absorption?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The supervisors of the Central Electricity Authority deputed at Lok Tak Hydroelectric Project are not facing any retrenchment. The National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) has offered to absorb all of them. However, their advancement in the Corporation will depend upon their satisfying the eligibility criteria adopted for respective grades and on their being found suitable.

(b) Does not arise, as they would be given benefit of their past service.

(c) The objective of protecting the interest of these Supervisors has been kept in mind by the NHPC.

(d) Does not arise.

(e) Details are furnished in the Statement.

Statement

Terms and Conditions which will Govern the Absorption of Supervisors on Deputation from C.E.A.

1. **Eligibility**

All CEA Supervisors on deputation to NHPC.

2. **Post and Scale of Pay**

The deputationists will be absorbed in the same post and scale of pay in which they are working at the time of absorption (officiating arrangements against short term vacancies, will not be considered). However, Supervisors in the scale of Rs. 425-700/425-800 who complete 5 years of their service as on 31-12-1980 will be considered for absorption in the scale of Rs. 550-900.

3. **Pay Fixation**

a. Supervisors on deputation from Central Electricity Authority may opt, at the time of absorption, for the following methods of fixation of pay, whichever is more beneficial to them:—

i. If an employee is not in receipt of deputation (duty) allowance and his pay has already been fixed in the scale of the post in the Corporation in which he is absorbed he will continue to draw the same pay in the scale on absorption. In such cases there would be no re-fixation of pay involved.

ii. The pay will be fixed in the scale of pay of the post in the Corporation in which a deputationist is absorbed, at the stage equivalent to basic pay in the parent deptt. on the date of absorption plus 20 per cent deputation (duty) allowance, subject to a maximum of Rs. 250, or the next higher stage if there is no such stage in that scale.

b. All allowance in respect of deputationists from Central Electricity Authority on absorption, will be regularised at the rates sanctioned for employees of NHPC from time to time.

c. In no case, the pay fixed above will be allowed to exceed the maximum of the scale in which the deputationist is absorbed. No advance increment will be considered at the time of absorption for purpose of fixation of pay on absorption which will be regulated only in the manner set out above.

3.1. On absorption, pay in the Corporation will be admissible in addition to the pension earned for pre-absorption service by the concerned deputationist, provided he has three years left for his normal date of superannuation when he joined the Corporation on deputation provided further that:—

i. his parent organisation does not object to the Corporation providing this facility; and

ii. the deputationist gives an undertaking that in the event of his service in the Corporation terminating at his instance or at the instance of the Corporation within a period of two years from the date of his release from the present organisation and permanent absorption in the Corporation, approval of the Corporation would be obtained by him, before he takes up any private employment.

4. **Seniority**

4.1. In case a deputationist is absorbed in the same grade in which he was originally appointed on deputation, his seniority in the grade shall count from the date of original appointment in that grade/equivalent grade, irrespective of whether it is in the Corporation or in the parent organisation.

4.2. In the case of absorption of deputationist already working in Lok Tak, Baira Siul, Salal Projects and erstwhile Control Board, the date of initial appointment in the grade/equivalent grade shall be effective irrespective of the date of transfer of these projects to the Corporation.

4.3. Those absorbed in an earlier batch will be treated senior to those absorbed in subsequent batches, for example:

The deputationists absorbed in the year 1980 will rank senior to the next batch of deputationists who may be absorbed in 1981 and later, irrespective of the length of service of a deputationist in a particular grade prior to absorption. In other words, if a Supervisor with two years service as Supervisor is absorbed in 1980, he will be senior to the Supervisor who may be having more than two years service as Supervisor, but is/are absorbed in 1981 and later.

5. **Provident Fund**

The persons permanently absorbed in the Corporation shall be eligible for membership of the Contributory Provident Fund of the Corporation from the date their resignation from parent post takes effect and they are permanently absorbed in the Corporation.

The amount of subscription together with interest thereon, standing to their credit in the Provident Fund Account shall be transferred to their new (Contributory) Provident Fund Account in the Corporation, provided the same is agreed to between the concerned deputationist and the Corporation .

6. **Leave**

i. On permanent absorption of the deputationists, the Corporation will take over the liability in regard to leave on average pay (earned leave) standing to the credit of the optee at the time of leaving the parent organisation, which will transfer in lumpsum an amount equivalent of leave salary to the Corporation. In the event of a parent organisation not agreeing to bear the liability for such leave salary for any valid reasons, the Corporation will bear the liability.

ii. In case the liability is borne by the parent organisation the leave so transferred can be encashed to the extent of 100 per cent at the option of of the employee, in accordance with the NHPC Rules. In the event of leave liability not being borne by the parent organisation, the leave credited by the Corporation, will not be admissible for encashment but will have to be actually availed of.

BIO DATA/OPTION FOR ABSORPTION OF CEA SUPERVISORS ON DEPUTATION TO NHPC.

1. Name

2. Present Designation

3. (a) Present Pay and scale of Pay

   (b) Present rate of Deputation (duty) allowance

4. Date of Birth

5. Qualifications, specialised training, if any

6. Parent Department

7. Date of joining the Project

8. Date of appointment to the present post

9. Experience in chronological order starting from the present assignment backwards. clearly indicating the period in each assignment :

Sl No.	Position Held	From	To	Organisation

Option for absorption

10. I hereby opt for absorption in the permanent cadre of the National Hydroelectric Power Corporation Ltd. on the terms and conditions circulated by the Corporate Office for absorption of CEA Supervisors.

Signature _____

Designation _____

Date _____

7. *RETIREMENT BENEFITS*

The benefits/facilities in respect of pre-absorption service of the employee shall be as laid down in the relevant orders of the parent department.

Benefits accruing out of pre-absorption service will be settled directly between the concerned employee and his parent organisation and NHPC will bear no liability in this regard.

8. *RESIGNATION/RETIREMENT FROM PARENT POST*

For absorption, the deputationist concerned will have to resign or take retirement from the parent organisation and his absorption will be effective only form the date on which resignation/ retirement becomes effective in the parent organisation.

9. On absorption, the employee concerned shall be governed by the Corporation's' rules, regulations, directives in force from time to time (including transfer from one project/ offiee to the other under the Corporation).

Inclusion of Kurukh Mundah, Kharia alongwith Nepali and Bhotia in Siliguri AIR

2019. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the steps taken or proposed to be taken to include local languages, such as Kurukh Mundah, Kharia along with Nepali and Bhotia in Siliguri Centre of All India Radio taking in view of the vast population of the tribals of these groups in North Bengal and eastern regions;

(b) details of the proposals if any, and if not, the reasons thereof;

(c) whether Government propose starting School Broadcasts in the backward eastern regions, North Bengal, South Bihar, Orissa and Assam on the lines of Maharashtra;

(d) if so, details of the proposal and by what time they will be put on operation; and

(e) if not, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN. M. JOSHI): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Self-Sufficieucy in Production of Life Saving Drugs

2020 SHRI SUBHASH YADAV:
SHRIMATI SANYOGITA RANE:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the country is not self-sufficient in the production of life saving drugs;

(b) whether any import of life saving drugs is made;

(c) the value of life saving drugs imported into the country during the last three years and in 1980-81 upto 28th February, 1981;

(d) the names of countries from where these life saving drugs have ben imported; and

(e) the steps taken to make the country self-sufficient in the production of life saving drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d). There are some life-saving drugs like Chloramphenicol, Streptomycin, Tetracycline etc. where the indigenous production is inadequate to meet the demand. There are also some life-saving drugs like Methyl Dopa, Amoxycillin, etc. for which there is no indigenous production. In such of these cases, imports are made to meet the demand. The c.i.f. value of imports of the drugs, drug intermediates and formulations during the last three years are as follows:

Year	c.i.f. value of imports (Rs. Crores)
1	2
1977-78	82·41
1978-79	95·32
1979-80 . .	93·81

The c.i.f. value of such imports during 1980-81 (upto 28th February, 1981) is being collected and will be laid on the Table of the House. The countries from which imports have been made include USSR, Rumania, Bulgaria, Switzerland, Italy, U.K., China and USA etc.

(e) Government expeditiously clears the proposals received from the Drug Industry for issue of Industrial Licenses, Letters of Intent, Carry on Business Licenses etc. This year 55 Industrial Licenses, 69 Letters of Intent, and 3 C.O.B. Licenses have been issued. However,

imports are not totally avoidable as there are some drugs which are not produced in the country for want of technology or due to insufficient demand for economic production of which is less than the estimated demand. Due also to local factors affecting production like power-cuts, industrial unrest etc. imports are required to supplement indigenous production.

Power Crisis in Bihar

2021. SHRI KRISHNA PRATAP SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether he is aware of the critical power supply position in Bihar; and

(b) what efforts have been made to ensure adequate power supply in Bihar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir. there is shortage of power in Bihar.

(b) One of the contributing factors for power shortage in Bihar is the unsatisfactory performance of thermal power stations and the State Electricity Board have been advised to prepare unit-wise plant betterment and maintenance programmes to improve the performance of the thermal power stations. Experts from Central Electricity Authority, NTPO and BHEL have also visited the power stations, to identify the deficiencies and modifications required to help the State Electricity Board in preparing the betterment programmes. In addition, assistance from Russian experts is also being taken for maintenance of the units as well as in procuring spares from USSR for Patratu Thermal Power Station.

As a long term measure, a number of generating schemes have been taken up for execution in the State. The details of the scheme and the likely date of commissioning are given below:—

Barauni	2x100 MW	Unit No. 6	3/82
		Unit No. 7	3/83
Patratu	2x110 MW	Unit No. 9	12/82
		Unit No. 10	6/83
Muzaffarpur	2x110 MW	Unit No. 1	1/84
		Unit No. 2	7/84
Tenughat	2x210 MW	Unit No. 1	6/85
		Unit No. 2	6/86

Besides the above, Bihar will also get benefits from the Central Sector projects to be commissioned in the Eastern Region during the Sixth Plan and the Seventh Plan periods.

Programmes Relating to Manifesto of the Ruling Party

2022. SHRI RAM VILAS PASWAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in compliance with the directive issued by the Government, the Director, Upgrah Doordarshan Kendra, New Delhi had issued instructions to all the Programme Producers to revise their schedule and to fix up targets of doing at least one programme a month on each topic included in the manifesto of the ruling party during elections to the 7th Lok Sabha; and

(b) if so, whether issuance of such directive is in conformity with the Government's policy if any in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN. M. JOSHI): (a) Upgrah Doordarshan Kendra had advised Producers at that Kendra to plan and produce at least one programme in a

month on the following themes of national importance:—

1. Secular society.
2. Safeguarding the rights of minorities.
3. Equitable employment opportunities to minorities.
4. Strengthening of democracy.
5. Emancipation of women.

(b) Yes, Sir, since the themes were of national concern and Doordarshan has been putting out various programmes relating to them as part of its social education programmes.

Coverage by Calcutta TV and AIR centres

2023. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state why the Calcutta T.V. and AIR centres use to give more coverage of a particular party instead of ruling party and Left Front Committee in the State of West Bengal?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN. M. JOSHI): It is not correct that AIR Calcutta has been giving more coverage to particular party instead of the ruling party and the Left Front Committee in the State. As a ruling party, the State CPI (M) gets good coverage. The statements of the Chief Minister and CPI (M) leaders are covered adequately in news bulletins. At the same time, the statements of the leaders of Congress (I), Congress (U), Janata and other parties are also covered according to their news value.

As regards coverage by Doordarshan Kendra, Calcutta, it may be mentioned that in the month of January, 1981, policy statements by the ruling party and Left Front Committee got 680 seconds of coverage from that Kendra. In contrast, Congress (I) got 240 seconds of T.V. coverage and other opposition parties got 190 seconds. These figures exclude the coverage given to functions attended by State Government leaders.

Denial of free legal aid to poor

2024. SHRI CHHANGUR RAM:
PROF. AJIT KUMAR MEHTA:
SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have at any time made any exercise to assess the instances where the State Governments refused to provide free legal aid to the poor even though such aid was justified;

(b) if so, the number of cases in which free legal aid was denied by the State Government (with the names of the States);

(c) reaction of Government with regard thereto; and

(d) if answer to (a) be in the negative, why it was not considered necessary to make such an assessment?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

(d) The legal aid schemes prepared and operated by the State Governments do not provide for any report being made to, or any assessment of the nature in question being made, by the Central Government. Since the schemes are prepared and operated by the State Governments, there is no question of the Central Government making an assessment of its operation in individual cases.

Consideration of Export of Malviya Committee

2025. SHRI RAM SWARUP RAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have considered the report of the 'Committee for review of the Oil and Natural Gas Commission' named Malviya Committee report, if so, Government's reaction thereto;

(b) whether the Malviya Committee have recommended for the creation of separate Ministry of ONGC under Prime Minister so that exploration work may be speeded up; if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government have taken action on this report in order to boost up Oil and Natural Gas production, if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) The Malviya Committee Report for review of the Oil & Natural Gas Commission (ONGC) was submitted to the Government several years ago in 1972 and it was considered in great detail at that time by the Government.

(b) The Malviya Committee had *inter-alia* suggested that the present ONGC should be dissolved and instead a three tier structure should be created for oil exploration work in the country. Firstly it had suggested that the responsibility for national policy for oil exploration at the highest level should vest in a body known as the Oil & Natural Gas Commission. The Chairman of this Commission should be a person of Cabinet Minister's rank and for some years the Prime Minister should take over the Oil Exploration portfolio. A Department (i.e. Ministry) of Oil Exploration should be created as the implementing agency for the Commission's policy. Thirdly the present functions performed by the ONGC should be entrusted to a Corporation which may be called the Oil & Gas Corporation of India.

These recommendations were considered by the Government but were not found acceptable.

(c) Yes, Sir. Government had taken action on various operational recommendations of the Malviya Committee Report. However, the Malviya Committee Report was submitted quite sometime back in 1972 and since then there have been many changes and the activities of the ONGC have increased manifold. Earlier the activities of ONGC were mostly confined to onshore areas. Now it is working in the offshore also and has discovered a number of oil and gas fields in the Bombay High. As a result of the expansion in the activities of the ONGC the production of indigenous crude oil by ONGC has increased from about 4.1 million tonnes in 1972 to 9.51 million tonnes in 1979-1980.

Development of Jharia coalfield with Polish assistance

2026. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Rs. 2,000 crore scheme for the development of Jharia Coalfields with Polish assistance, which had been lying in cold storage since 1975, has been revived; and

(b) if so, the details regarding its progress?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b) It is not a fact that the Scheme for reconstruction of Jharia coalfields, feasibility report of which was prepared by the Coal India Ltd. with Polish assistance, had been lying in cold storage since 1975. Appropriate Coordination Committees have been set up at Government level to solve the problems of land acquisition, re-

organisation of road and rail network, electricity distribution system etc. Eight projects, which, *inter alia*, constitute an integral part of the Scheme have been sanctioned so far for a capital outlay about Rs. 149.0 crores.

कोरबा, मध्य प्रदेश की खानों में पानी भर जाना

2027. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा क्षेत्र की कुछ खानों में, जहां से कोयला निकाला गया है, पानी भर गया है लेकिन उन्हें रेत और मिट्टी से नहीं भरा गया था ;

(ख) क्या इन पानी से भरी खानों से निकट की कोयला खानों और ऐसी खानों को भारी खतरा बना हुआ है, जहां से कोयला निकाला जा चुका था ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य खानों और लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख). कोरबा कोलियरी की दो इन्क्लाइन खानें जून, 1980 में भंडार समाप्त हो जाने पर बंद कर दी गई थी । यहां कोयला केविंग प्रणाली द्वारा निकाला गया था जिसमें कोयला निकालने से हुए खाली जगह ऊपर की पर्तों के धंसाव से प्राकृतिक रूप से ही भर जाती है । अतः इस खान में रेत भराई की जरूरत नहीं थी । यहां पास में ही कोई ऐसी खनन सम्पत्ति या खनन स्थल नहीं है जिनको इन चुकी हुई खानों में पानी भरने से कोई खतरा होने की संभावना हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Allocation of Funds for Setting up New Thermal Power in West Bengal

2028. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have approved allocated funds for setting up new thermal power projects in West Bengal during the Sixth Plan period; and

(b) if so, the amount allocated to each thermal power projects and the reaction of the West Bengal Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The Government of West Bengal had submitted proposals for some new schemes as part of their proposals for the Sixth Five Year Plan 1980-85 for the Power Sector. After detailed discussions in the Working Group for Power constituted by the Planning Commission, project-wise proposals were recommended for the on-going and sanctioned projects, and lump sum provisions, for the new schemes. Subsequently, after discussions with the State Chief Minister, the outlay for the power sector has been determined. The State Government have adopted Rs. 887.50 crores as the overall allocation for the power sector during the Sixth Plan. The State Government has been requested to suggest a scheme-wise break-up which is awaited. However, it is expected that over Rs. 300 crores should be during the Sixth Five Year Plan for all new schemes in West Bengal.

Production of coal

2029. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) total month-wise production of coal in various collieries during the calendar year 1980; and

(b) whether this shows progressive improvement in the production of coal in the last three monhs i.e. October, November, December, 1980?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The month-wise production of coal during the calendar year 1980 is given below:—

Month	All India Production (Figures in lakh tonnes)
January'80	99·4
February'80	100·94
March'80	108·36
April'80	88·80
May'80	88·22
June'80	81·75
July'80	82·44
August'80	78·47
September'80	80·80
October'80	86·32
November'80	90·92
December'80	105·39

(b) Yes, Sir. The increase in production during the periods, October, November and December, 1980 in comparison to corresponding periods of 1979 is indicated below:—

Month	1979	1980	Increase
	(Figures in lakh tonnes)		
October	78·72	86·32	7·60
November	86·87	90·92	4·05
December	94·75	105·39	10·64

राजस्थान में मरहटा रोड के निकट मिले लिग्नाइट के निक्षेप

2030. **श्री दौलत राम सारन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में मरहटा रोड के निकट लिग्नाइट के भारी निक्षेप मिले हैं जो देश में अब तक लिग्नाइट के मिले निक्षेपों से सबसे उत्तम किस्म के हैं ;

(ख) यह कितनी गहराई पर मिले हैं इस की परत कितनी मोटी है तथा यह किस क्षेत्र में मिले हैं; और

(ग) क्या इस कोयले के खनन तथा प्रयोग हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Assets of Big Business Houses

2031. SHRI RAJESH KUMAR SINGH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names and number of big business houses in country at present whose assets are more than Rs. one crore or more;

(b) the assets of each those big business houses at the beginning of 1976; and

(c) whether Government are satisfied as to how their assets have increased heavily during the last five years, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). According to the Industrial Licensing Policy announced by the Government in February, 1978, only such of the undertakings which by themselves or

alongwith their interconnected undertakings have assets aggregating to not less than Rs. 20 crores and are registered under section 26 of the M.R.T.P. Act are considered as constituting Large Industrial Houses referred to as big business houses in the Question. Statement annexed gives figures of assets during 1976 for each of such large industrial houses based on registrations under section 26 of the M.R.T.P. Act as on 30-6-1978.

(c) The assets of these large industrial houses increased from Rs. 7494.46 crores in 1975 to Rs. 9496.71 crores in 1976 or by 26.7 percent during three years, corresponding to an increase of 8.9 percent per annum. In this regard it may be stated that based on a recent sample study by the Reserve Bank of India of 1720 medium and large, non-financial, non-government public limited companies each having a paid-up capital of Rs. 5 lakhs and above, the assets of the private corporate sector grew from Rs. 11271.80 crores in 1975-76 to 13042.79 crores in 1977-78 or by 15.7 percent during two years, or 7.8 percent annually. In view of this, the growth in assets of the large industrial houses may not be considered as unduly heavy. The growth rates were, however, higher in case of some industrial houses, as compared to those for the private corporate sector as a whole.

Statement

Assets during 1976, for the big business houses based on registration under section 26 of the MRTP Act as on 30-6-1978.

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Name of the Business House	Assets
1	2	3
1	Tata	980·77
2	Birla	974·63
3	Mafatlal	256·54
4	J.K. Singhania	241·23
5	Oil India	202·59
6	Thapar	202·24
7	I.C.I	198·99
8	Bangur	195·33
9	Scindia	177·08
10	Shriram	171·70
11	Bhiwandiwala	166·43
12	A.C.C.	160·21
13	Kriloskar	152·47
14	Larsen & Toubro	147·74
15	Walchand	129·42
16	Mahindra & Mahindra	126·06
17	Hindustan Lever	122·51
18	Modi	117·79
19	Sarabhai	116·73
20	Macneil & Magor	113·35
21	Kasturbhai Lalbhai	109·63
22	T.V.S. Iyengar	105·78
23	I.T.C.	105.08
24	Bajaj	101·51
25	Khatau (Bombay)	100·22
26	Dunlop	99·10
27	Parry	91·11
28	Chowgule	80·15
29	G.K.W.	74·62
30	Union Carbide	71·31
31	Salgaocar	71·19
32	Simpson	70·96
33	Naidu G.V.	69·73
34	Bird Heilgers	69·33
35	Kapadia (Killick)	68·31
36	V.S. Dempo	67·88
37	Brooke Bond	65·67

1	2	3
38	Godrej	65·17
39	Escorts	64·54
40	Rallis	62·80
41	Ashok Leyland	61·51
42	Nowrosjee Wadia	59·64
43	Philips	57·02
44	Madura Coats	55·85
45	Soorajmull Nagarmull	53·77
46	United Breweries	52·92
47	Kamani	50·38
48	Jaipuria	49·70
49	Bombay Suburban	48·07
50	Oberoi M.S.	47·29
51	Shri Ambica	45·26
52	G.E.C.	45·08
53	Raunaq Singh	44·43
54	Murugappa Chettiar	43·47
55	Kilachand (Tulsidas)	40·21
56	Ghia	39·61
57	Shaw Wallace	38·82
58	V. Ramakrishana	38·77
59	S.P. Jain	38·24
60	Goenka (K.P.)	34·92
61	Somaiya	34·81
62	Metal Box	34·62
63	Central Pulp	31·95
64	Sahu Jain	31·53
65	Swedish Match	30·80
66	M.A. Chidambaram	30·69
67	Raliance Textiles	30·27
68	Prataplal Bhogilal	29·80
69	Jardine Henderson	29·17
70	Kothari (Madras)	28·90
71	Naidu V.R.	28·35
72	Thackersey	27·05
73	Madras Cement	26·93
74	Golden Tobacco	23·40
75	Thiagaraja	22·98
76	Asbestos Cement	20·24
77	Apeejay	19·70
78	Mohan Meakin	18·54
79	Seshasayee	14·57
80	R.N. Goenka	13·49
81	Ruia	0·54
82	Single Large Undertakings	1006·69

हिल्सा सब—डिवीजन, नालंदा, बिहार में पेट्रोल और डीजल पंपों को मंजूरी देना

2032. **श्री विजय कुमार यादव**: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के नालंदा जिले के अन्तर्गत हिल्सा सब-डिवीजन में केवल एक ही पेट्रोल तथा डीजल पम्प है जिससे वाहन मालिकों तथा किसानों को भारी असुविधा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए उपरोक्त सब-डिवीजन में पर्याप्त पेट्रोल तथा डीजल पम्पों को मंजूरी देने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Number of Adivasis in Employment in West Muddidih and Jagta Colliery of B.C.C.L.

2033. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) decrease in the number of Adivasis in employment in West Muddidih and Jagta colliery of Area No. V of B.C.C.L. in Dhanbad district in the last 5 years with year-wise break up in details;

(b) whether it is a fact that most of the Adivasis were driven out by the muscle men there who do no productive work and do money ending remaining on the roll of the BCCL;

(c) whether it is a fact that Shri K. B. Saxena, IAS now labour Secretary, Bihar gave a detailed report on this in 1975 while as Deputy Commissioner there; if so steps taken thereon;

(d) whether the local officers of the BCCL of the Area No. V are captive in the hands of the musclemen or in collusion with them; and

(e) whether the Government propose making a through probe into the affairs of the Area No. V of the BCCL?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे दूरदर्शन केन्द्र

2034. **श्री अशोक गहलोत :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस प्रकार के दूरदर्शन केन्द्र अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे ;

(ग) इस प्रकार के शहरी और ग्रामीण केन्द्रों पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां,तो सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को कब कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) गांवों में छोटे दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है । इस कवरेज को नए दूरदर्शन केन्द्रों और "इनसेट–1" के माध्यम से और बढ़ाया जायेगा ।

(ख) "इनसेट–1" के माध्यम से दूरदर्शन प्रसारण के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा .

(ग) और (घ). दूरदर्शन सेवाओं के लिए "इनसेट–1" का उपयोग करने की स्कीम तैयार की जा रही है । इसका कार्यान्वियन स्कीम को स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

Alleged violation of Company Laws by Companies of Birla Group

2035. SHRI SWAMY INDERVESH:
SHRI RAM VILAS PASWAN:
SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a number of companies owned by Birla Group are defaulting company law regulations in respect of submission of company balance sheets within a statutorily defined period after end of financial year;

(b) if so, what are the names of such companies; and

(c) what action Government have since been taken against such defaulting companies?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Setting up of a Central Board for Distribution of Power

2036. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to set up a Central Board for distribution of power;

(b) whether any such proposal was mooted at the recent Electricity Ministers' Conference held at Delhi;

(c) the details of the proposal; and

(d) when the Board expected to be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) There is no such proposal under consideration of the Government.

(b) to (d). Does not arise.

लंदन में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के एक कार्यालय का प्रस्ताव

2037. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लंदन में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसे खोलने में किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है; और

(ग) यह फिल्म-जगत के लिए किस प्रकार सहायक होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग). भारतीय फिल्म विकास निगम ने (1) महत्वपूर्ण मार्केट ग्रासूचना मानिटर करने; (2) भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने; (3) भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेटों सहित भारतीय फिल्मों की चोरी की रोकथाम करने ग्रौर (4) भारतीय फिल्म उद्योग के लाभ के लिए विदेशों की व्यापार नीतियां ग्रौर प्रक्रियात्मक ग्रौपचारिकताग्रों सम्बन्धी सूचना एकत्र करने ग्रौर उसकी तुलनात्मक जांच करने के लिए विदेशों में ग्रपने कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन में से एक कार्यालय लंदन में होगा।

Plans for Exploration of Oil

2038. SHRI D. M. PUTTE GOWDA: SHRI H. N. NANJE GOWDA:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what are the plans taken or proposed to be taken to explore oil finds in India;

(b) whether private sector is proposed to be collaborated; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Both ONGC and OIL have drawn up plans for stepping up to the maximum extent their efforts for oil exploration and production in the country. In on-shore, exploration work is to be intensified in Assam-Arakan, Krishna-Godavari and Cauvery basins. The pace of exploration in Cambay Basin will be maintained. Exploration in West Bengal, Ganga Valley, Himalayan foot-hills, Rajasthan,

Orissa Coast and other areas is proposed to be suitably stepped up. Some of the promising areas, like shoals and estuaries, which could not be taken up hitherto, due to logistic problems, will also be explored by engaging, wherever necessary, specialised contracting agencies. The total exploratory drilling envisaged by the ONGC and OIL in the on-land basins is of the order of 300 wells comprising 882,700 metres.

In respect of off-shore, Oil India is expected to continue their exploratory programme in the Mahanadi Delta area. ONGC will continue exploration in Bombay Off-shore Basin extending the limits to deeper waters. They also propose to explore the structures offshore of Saurashtra in Gulf of Kutch, Andaman and Nicobar Shelf as well as the East Coast Basins, like Palk Bay and Krishna-Godavari Basins. ONGC plan to increase the number of off-shore rigs deployed so as to drill about 95 exploratory wells in different off-shore areas during the Plan period.

Besides the full development of Bombay High Field, development of other structures, namely, R-12, South Bassein and North Bassein fields, B-37, B-38 structures would also be carried out during the Plan period.

(b) and (c). In order to supplement the efforts of ONGC and OIL Government have recently decided to invite offers from competent foreign parties for exploration in 32 selected blocks. In addition, ONGC and OIL would be obtaining technical assistance/consultancy wherever necessary from competent organisations to step up exploration/production activities.

Stoppage on Import of Indian Films By Bangladesh

2039. SHRI AMAR ROYPRADHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bangladesh has stopped import of Indian films;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the number of films which have been imported during the year 1980 in comparison to 1979?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). As a policy, Bangladesh does not import Indian films.

(c) Does not arise.

Tie up of all Hydro-Electric Potentials

2040. SHRI JAGDISH TYTLER: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are considering a tie-up of all hydro-energy potential in the country; and

(b) if so, the details of the proposal under contemplation in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). A tentative assessment of hydro-electric potential in the country places it at 75 MKW at 60 per cent load factor. Recognizing the immense hydel potential available, Government has decided to lay great stress on its exploitation. With this objective in view it is proposed to install additionally 4768 MW of hydel capacity in the VI Plan period, and 15000 MW of hydel capacity in the VII Plan period, which will bring the proportion of hydel to thermal capacity on par with each other.

It has also been decided that large hydro projects be taken up for execution in the Central Sector, with a view to expediting their commissioning. For the first time investgation of hydro projects has been entrusted to the National Hydroelectric Power Corporation, with a view to keeping ready a shelf of projects that would be available for execution.

Allotment of Distributorships by I.O.C., Hindustan Petroleum Ltd., and Bharat Petroleum Ltd.

2041. SHRI BHEEKABHAI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the total number of LPG, HSD and MS distributiorships issued by the IOC/Hindustan Petroleum Ltd., and Bharat Petroleum Ltd., in the country during the last five years, year-wise;

(b) the total number of such distributorships granted to members of SC/ST separately, year-wise;

(c) whether it is a fact such distributorships earlier reserved for reserved communities have been allotted to non-reserved communities; and

(d) why such distributorships were de-reserved and allotted to those communities?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). The policy to reserve 25 per cent of all types of agencies/dealerships for Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities was laid down for all public sector oil companies for the first time with effect from 23.9.1977. Prior to this, the reservation was applicable to only Indian Oil Corporation Limited for all their agencies/ dealerships except for 'B' site retail outlets i.e. dealer-owned and dealer-operated outlets.

The number of LPG agencies and retail outlet dealerships (petrol/diesel pumps) awarded by Indian Oil Corporation Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and Bharat Petroleum Corporation Ltd. since the introduction of reservation policy and the number out of them given to SC/ ST as on 1.4.1980 is reported to be as under:

	Petrol/Diesel Pumps	LPG agencies
Total number awarded (excluding prior commitments, upgradation/bifurcation etc.)	403	195
Scheduled Castes	92	39
Scheduled Tribes	11	8

Year-wise details are not readily available.

(c) and (d). Only in case of LPG distributorships locations were in the past predetermined by oil companies for award of distributorships to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. If a suitable SC/ST category candidate was not found, such location was decategorised to 'others' category and an alternate location put under SC/ ST category.

Term of experts to Examine the working of Indraprastha power station, Delhi

2042. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have deputed a team of experts to examine the working of Indraprastha Power Station, New Delhi and suggest measures to improve generation;

(b) whether the team has submitted any report to Government; and

(c) if so, what are the main feature thereof and steps taken by Government to implement the recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The Ministry of Energy has arranged for a Roving Team of Experts to visit a number of Thermal

Power Stations in the country. The Team has not yet visited the Indraprastha Power Station as it is working quite satisfactorily. There is much less load shedding at present.

(b) and (c). Do not arise.

Decentralisation of various subsidiaries of Coal India Limited

2043. SHRI KAMAL NATH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are considering decentralisation of various subsidiaries of Coal India;

(b) if so, by which date; and

(c) the details of such scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). The question of reorganisation of the Coal India Ltd. and its subsidiaries is under consideration of the Government and is likely to be finalised shortly.

Differential pricing policy for oil supply

2044. SHRIMATI MADHURI SINGH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether OPEC countries have agreed to adopt differential pricing policy for oil supplies to poor, populous countries like india; and

(b) if not, whether initiative is being taken by Government of India in this regard?

THE MINISTER OF PERTOLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir. However the long term strategy committee of OPEC has been considering the approach of OPEC to its relations with developing countries and in particular the issue of relief measures to alleviate the problems of oil importing developing countries. No final decision in this regard has been taken so far.

(b) Yes, Sir.

Studio of Leh Station of All India Radio

2045. P. NAMGYAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the studio of Leh station of All India Radio was built initially on emergency basis for 3 hours programmes but now 9 hours programmes are being broadcast without additional studio facilities;

(b) whether it is also a fact that due to lack of equipment, transport, additional studies and accommodation for the staff, employees and artistes are facing great difficulties which causes low quality production of programmes; and

(c) if reply to (a) and (b) above be in the affirmative, what steps Government propose to take to solve the above mentioned problems and when these are to be implemented?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN. M. JOSHI): (a) to (c). AIR Leh was commissioned in June, 1971 on top priority basis with limited studio facilities, and started broadcasting programmes for 4 hrs. and 45 minutes daily. This has now increased to 9 hours to meet the pressing demands and needs of the region. Since the station was started with limited facilities, difficulties are no doubt being faced. However, every effort is made to produce good quality programmes. Work is also in progress to provide additional technical facilities including more studios and office and residential accommodation.

Removal of brand names in pharmaceuticals

2046. SHRI H. N. NANJE GOWDA: Will the Minister of PETROLEUM,

CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government propose to remove the branded names in regard to pharmaceuticals;

(b) whether any representation has been received against this move; and

(c) if so, what are the details and what is the reaction of Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) Government have issued necessary Gazette Notification in January 1981 amending Drugs and Cosmetics Rules 1945 to give the needed statutory effect to the decision concerning abolition of brand names in respect of single ingredient formulations of the following five drugs and also preparations containing any new drug as the single active ingredient:—

1. Analgin
2. Aspirin and its salts
3. Chlorpromazine and its salts
4. Ferrous Sulphate
5. Piperazine and its salts.

The abolition of brand names of the above five drugs will be effective from 1st August, 1981.

(b) and (c). Representations were received against the decisions of the Government on the question of abolition of brand names. The points touched in the representations concern quality, identify of products, introduction of new drugs etc. As indicated in reply to part (a) Government have given statutory effect to the decision concerning abolition of brand names after considering the objections and suggestions in the representations.

Appointment of AIR or Doordarshan Correspondent for South of 24 Parganas

2047. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal for appointment of AIR or Doordarshan Correspondent for the South of 24 Parganas covering Sundarban areas; and

(b) if so, facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Agreement between the Eastern Coalfields Limited and Labour Unions in June, 1980

2048. SHRI NIREN GHOSH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the salient points of the decisions taken at a meeting held on the 20th June, 1980 between the representatives of Eastern Coalfields Limited Management and the representative of the Labour Unions;

(b) the names of the labour unions which participated; and

(c) what steps have been taken to implement the decisions taken at the June 20th meeting?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The salient points of the decisions taken in the meeting held between the Eastern Coalfields Limited management and the representatives of the labour unions on 20th June, 1980 pertained to the policy of fresh recruitment and transfer of surplus workmen from other mines of ECL for new and reorganised mines. It also indicated the pattern of recruitment to be made from among local persons, dependents of workmen, retrenched workmen, etc. The decision also covered

the constitution of a Screening Committee to consider applications for employment.

(b) The names of the Central Trade Unions which participated are given below:—

INTUC, AITUC, CITU, BMS. Apart from this, another labour union, SBKMS (UTUC) also participated.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Television Centre at Bhensal Taluka Khuldabar, Maharashtra

2049. SHRI QAZI SALEEM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the plans, proposals and estimates of Maharashtra and Central Government for a transmission and/or Television Centre at "Bhensal" Taluka Khuldabar in Maharashtra;

(b) whether any surveys have been made in the matter;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether the Maharashtra Government has written to the Centre any time for the same or any expert or engineering or any other committee had been appointed for the purpose;

(e) if so, the details of the Reports and the outcome thereof;

(f) whether the demand from various quarters have been made for the establishment or development of same during 1977, 1978, 1979 and during 1st February, 1980 to 31st January, 1981;

(g) if so, the details thereof and the action taken thereon; and

(h) when the said transmission/television centre is likely to be established and functioning?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) There is no proposal at present to set a TV Centre at Bhensal Taluka Khuldabar in Maharashtra.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

(f) No, Sir.

(g) and (h). Do not arise.

Periyar Hydro-Electric Scheme

2050. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the project report of the lower Periyar Hydro-Electric Scheme had been submitted to the Government of India for clearance by the Government of Kerala;

(b) the main details of the project proposed;

(c) what is the reason for the delay in giving clearance to the project; and

(d) whether Government of India are expected to give clearance to the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). Yes, Sir. The scheme as proposed involves construction of a 31 m. high concrete dam, a 12.09 Km. long unlined power tunnel and an overground power station with an installation of 3 units of 60 MW each. The scheme is estimated to cost Rs. 59.76 crores.

(c) and (d). The project report has been examined in the Central Electricity Authority and Central Water Commission. The technical examination of the scheme is complete, except for some clarifications that are required by the Central

Water Commission on aspects of dam design, hydrology etc. The Project authorities have been requested to depute their officers with a view to expediting the clarifications. As soon as the Central Water Commission clears the project, action to accord techno-economic clearance will be taken.

Rise in prices of life saving drugs and vitamins

2051. SHRI INDRAJIT GUPTA:
SHRI PHOOL CHAND VERMA:
SHRI MADHAVRAO SCINDIA:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have recently approved further rise in the prices of a large number of life saving drugs and even vitamins;

(b) if so, the list of items so covered and the extent of price-rise allowed;

(c) whether most of these items are manufactured by large firms which are making substantial profits; and

(d) if so, the grounds for Government's decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) The prices of 111 bulk drugs including a number of Vitamins have been revised so far involving increases in some cases and decreases in other cases. The prices of a number of formulations have also been revised.

(b) A Statement giving the names of the bulk drugs and the extent of price increase or decrease allowed is laid on the Table of House. [*Placed in Library. See* No. LT-2010/81].

(c) The bulk drugs for which prices have been revised are not manufactured by large firms alone. The drugs in question are manufactured by public sector, Indian companies in the organised Sector and small scale sector and also some foreign companies.

(d) The prices of most drugs which were under price control earlier had remained unchanged for a number of years and in March, 1978, a specific freeze was also imposed for a year under the New Drug Policy. Revisions of the prices was due thereafter in accordance with the provisions of Drugs (Prices Control) Order, 1979. Meanwhile there have been substantial increase in the cost of inputs particularly as a result of the hikes in prices of petroleum products. Hence the present revision in prices which takes into account all these factors.

Suspension of exploitation Work in Krishna-Godavari Basin

2052. DR. KRUPASINDHU BHOI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that oil exploitation work has been suspended in the Krishna-Godavari basin since December, 1980;

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount so far spent for exploitation in that basin; and

(d) the steps being taken by Government to resume exploitation work at that place?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) So far only exploration work is going on in Krishna-Godavari basin and no exploitation work has been done.

(b) Does not arise.

(c) Upto 31-3-1980, an amount of Rs. 16.43 crores, including depreciation of Rs. 4.52 crores was incurred

by ONGC on exploration work in the Krishna-Godavari basin, both onshore and offshore.

(d) Commencement of exploitation work will depend on the discovery of hydrocarbons in commercial quantities.

Proposal to formulate Uniform Civil Code

2053. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to formulate a Uniform Civil Code on the lines of the Uniform Civil Code formulated by the erstwhile Portuguese regime in Goa; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Closure of Fertilizer Kalol Plant

2054. SHRI CHHITTUBHAI GAMIT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that another Fertilizer Kalol Plant (Gujarat) of the I.F.C.O. stopped functioning following the rupture of its turbines; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b). Yes, Sir. On the 10th January, 1981, the ammonia plant of Kalol (IFFCO) was stopped as excessive vibrations were noticed from the bearings of the process air compressor turbine. On examination it was found that one of the shroude of the seventh wheel had opened up causing imbalance to the rotor and it was also found rubbing against the turbine casing. The damaged rotor was replaced with a spare rotor that was available and the plant was re-started on the 19th January, 1981.

सोडा एश का उत्पादन

2055. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन**
श्री ए० सी० दास

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा-ऐश का उत्पादन कर रही कम्पनियों की संख्या, उनकी उत्पादन क्षमता और वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलों द्वारा कोयले की अपर्याप्त सप्लाई किए गये कोयले की घटिया दर्जे और ट्रकों द्वारा परिवहन के कारण हुई इसके लागत मूल्यों में भारी वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप सोडा-एश के मूल्यों में वृद्धि हुई है, के कारण यह उद्योग भारी संकट से गुजर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संकट पर काबू पाने के लिए विभाग द्वारा दी जा रही अथवा दिए जाने के लिए प्रस्तावित विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क)

देश में सोडा ऐश के चार निर्माता है । उनके नाम, कलेण्डर वर्ष 1980 के दौरान उत्पादन क्षमता और उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	उत्पादन क्षमता (टन प्रतिवर्ष में)	वर्ष 1980 के दौरान उत्पादन (टनों में)
1. मै0 टाटा कैमिकल्स लि0, मिथापुर, गुजरात . .	3,60,000	3,16,513
2. मै0 सौराष्ट्र कैमिकल्स लि0, पोरबन्दर, गुजरात . .	2,30,000	1,52,889
3. मै0 धांगधरा कैमिकल्स वर्क्स लि0, धांगधरा, गुजरात .	65,000	67,907
4. मै0 उड़ीसा सीमेन्टस लि0, (हरी फॉस्फेटाइजर्स) वाराणसी, उ0प्र0 (भूतपूर्व न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स) . .	39,600	11,398
योग	6,94,600	5,48,707

(ख) तथा (ग). सोडा ऐश के निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कोयला कोक के परिवहन के लिये वैगनों की पर्याप्त संख्या आंवंटित नहीं की जाती और कोयला मानक किस्म का नहीं है । कोयला के विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के लिये निर्धारित की गई प्राथमिकता के अन्तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं और सोडा ऐश उद्योग को वैगनों की अधिकतम संख्या उपलब्ध कराने के लिये वे प्रयास जारी रहेंगे । जब वगनों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होगी तब निर्माता कोल का परिवहन सड़क मार्ग द्वारा करते हैं । निर्माताओं ने बताया है कि सड़क मार्ग द्वारा परिवहन की अतिरिक्त लागत, सामान बनाने के लिये ईंधन तेल के प्रयोग पर अतिरिक्त खर्च, कोल की कमी और निवेश लागतों में सामान्य वृद्धि आदि सब से कारखाने से बाहर सोडा ऐश के मूल्य में वृद्धि हुई है ।

Monthly quota of coal to smaller and tiny consumers

2056. SHRI P. M. SAYEED. Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to cut the monthly quota of coal to the smaller and tiny consumers;

(b) if so, whether the main reason for this decision was the refusal of the Railways not to undertake the responsibility of hauling from pit heads more than 20 per cent of the total number of wagons to the individual factory owners by the State Governments concerned;

(c) what are the main reasons for change of the Railways decisions;

(d) whether Ministry has taken up the issue with the concerned departments to see that coal quota is not reduced; and

(e) if so, to what extent they have succeeded?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) No Sir.

(b) to (e). Does not arise.

Recommendations of Kulkarni Committee on Power

2057. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the principal recommendations of Kulkarni Committee on the maintenance planning and spare parts management in the Power Stations of the country; and

(b) the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The main recommendations of the Kulkarni committee on the modernisation of maintenance procedure in large thermal power stations are given below:—

1. A central maintenance Organisation in each Board wnich can be deployed from station to station be formed.

2. A coordinated schedule of overhaul of units in the system should be drawn up at the beginning of the year in consultation with State/ Regional Load Despatch Station etc.

3. The period of annual inspection and overhaul of the boilers should be of the order of 30 days and complete major overhaul of turbines undertaken at 3 to 5 years intervals should be about 45 days.

4. In order to expedite repair and maintenance work, modern tools and tackle like sky-climbers should be deployed.

5. Besides preventive maintenance, predicative maintenance using observational techniques like signature analysis and modern instruments like vibration analysers, thickness detectors etc. is also essential;

6. Adoption of new techniques of management and introducing managerial functional improvement (such as setting objectives, employing adequate number of technically qualified, competent and experienced personnel) including behavorial sciences & materials management etc.

7. The workshop at the power station should also have the following facilities:

(i) Balancing of rotors
(ii) vibrations tests
(iii) Reblading and
(iv) Ultrasonic Testing of welds etc.

8. Imported spares are stocked for a minimum of two years requirements and sufficient number of indigenous spares are stocked based on load time required for procurement.

9. BHEL should maintain required stocks of various major/important spares and materials for prompt supply to power stations.

(b) The recommendations have been circulated to all the State Electricity Boards for implementation.

Proposal of West Bengal to set up New Thermal Power Projects during Sixth Plan

2058. SHRI SUNIL MAITRA:
SHRI AMAR ROYPRADHAN:
SHRI CHITTA MAHATA:
SHRI NARAYAN CHOUBEY:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) is it a fact that Government have rejected all the proposals of the State Government of West Bengal for setting up new thermal power projects in the State during the Sixth Plan; and

(b) if so, what are the reasons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). Nc, Sir. The Government of West Bengal had submitted proposals for some new scheme as part of their proposals for the Sixth Five Year Plan 1980—85 for the Power Sector. After detailed discussions in the Working Group for Power constituted by the Planning Commission, project-wise proposals were recommended for the on going and sanctioned projects, and lump sum provisions for new schemes. Subsequently, after discussions with the State Chief Minister, the outlay for the power sector has been determined. The State Government have been requested to suggest the break-up of allocations for the different schemes which is awaited. However, it is expected that over Rs. 300 crores should be available during the Sixth Plan for all new schemes.

Cost Price of Cooking Gas Cylinders

2060. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the cooking gas which is recently explored in India can meet the urban demand;

(b) the number of cylinders filled per day and expected total yearly production in 1981;

(c) the reasons for raising price per (22 Kg) Indane gas cylinder when it is produced in India—the details of cost of production of 22 kg cooking gas and its selling price in the market; and

(d) the total number of cooking gas connections in India on 31-12-80 and the number of connections to be added in 1981 and the persons in the waiting list at present?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) If the intention is to ask about L.P. Gas the demand in the urban sector is being partly met.

(b) A total number of about 85,000 cylinders per day are filled at the bottling plants of the oil companies. The LPG production in the year 1981 is likely to be over 5 lakh tonnes.

(c) The oil companies do not market cooking gas in cylinders of 22 Kg capacity. Prices of cooking gas as well as of other petroleum products were raised in January, 1981 on account of increased price of imported crude and petroleum products, additional product imports due to continued closure of refineries based on Assam crude, escalation in operational costs and additional expenditure on transportation of Bombay High crude through new pipleline.

(d) The total number of cooking gas connections in the country as on 31-3-80 is about 31.5 lakh. About 12 lakh new connections are expected to be released during 1981-82. There are about 37 lakh applicants on the waiting list.

Assurance by State Governments to Supply Electricity to Rural Areas for six Hours Daily

2061. SHRI K. P. SINGH DEO:
SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of Centre's efforts, a majority of the State Governments have now assured the Centre that it would be possible for them to give power to rural areas for at least six hours,

(b) if so, the States which have given such assurance and the names of those which have not been able to do so,

(c) the difficulties being experienced by the States which are not able to

supply electricity and the steps the Centre propose to take to help them, and

(d) whether such supplies will be regular and the total quantum for each State that would now be available?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). All the States are at present giving supply to the rural areas for at least six hours a day. Normally, no difficulty is envisaged to continue this supply.

Regularisation of Colonies set up by Displaced persons in West Bengal

2062. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether all the squatters colonies set up by the displaced persons from East Pakistan (now Bangladesh) in different places in West Bengal have since been regularised;

(b) whether ownership title has been given to them for the land under their possession in such regularised colonies;

(c) if not, whether Government proposes to confer that ownership title in near future;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) whether free-hold right has already been conferred upon the displaced persons who have resettled themselves in Delhi and East Punjab?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI P. K. THUNGON): (a) 149 pre-1951 colonies and 175 post-1950 colonies as per recommendations of the Working Group have been regularised.

(b) Ownership title is being given by the State Government after acquisition of lands.

(c) and (d). Do not arise.

(e) Yes, Sir, except for certain urban and cantonment areas where lands have been given on lease-hold basis.

Agreement with United States of America to develop Coal Mines in Ghusick and Asnapani in Raniganj and Bokaro Coalfields

2063. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that United States of America has reached a broad agreement with India to undertake integrated development of two underground coalmines in Ghusick and Asnapani in Raniganj and East Bokaro coalfields respectively; and

(b) if so, the details regarding the agreement in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Provision of Cooking Gas Service in States/Towns

2064. SHRI ZAINUL BASHER: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in some States, towns under the population of fifty thousand have been provided cooking gas service and in some States, towns over one lakh population are yet to be provided gas service;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons for disparity?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) The names of towns, which have more than one lakh population but are not being supplied LPG are not readily available.

(c) Till recently the main consideration in marketing of cooking gas at

various locations were the proximity of the locations to the refineries, other factors of operational convenience like the filling plant capacity available in the region, logistics of supply etc. and not the population of the locations. With the anticipated additional availability of cooking gas, oil industry has plans to cover all district H.Q. locations by March, 1981 followed by the coverage of all towns having a population of over 50,000.

Setting up of a Large Power Plants on the Borders of U.P. and M.P. with Russian Help

2065. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that huge power plant on the border of U.P. and Madhya Pradesh is being set up with the help of Russia; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b): Yes, Sir. An integrated thermal power plant with a capacity of 1000 MW and capable of expansion up to 3000 MW is to be established with Soviet assistance at Waidhan in Madhya Pradesh near the Uttar Pradesh State Border. Soviet assistance will also be extended to the construction of the associated transmission lines for the 1000 MW capacity and the development of coal in stages to match the power requirements at the Nigahi coal mines in the Singrauli region.

Lowering of Voting Age

2066. SHRI P. K. KODIYAN:
SHRI SUBHASH YADAV:
SHRI KRISHNA PRATAP SINGH:

Wil the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the question of lowering voting age to 18 has been examined by Government; and

(b) if so, what decision has been taken thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). The question of lowering voting age from 21 years to 18 years for elections to Lok Sabha and to the Legislative Assemblies of States, which forms part of the comprehensive proposals for Electoral Reforms, is under consideration.

Average Cost of Power Generation from Hydel Thermal Diesel and Atomic Power Stations

2067. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what is the average cost of power generation in each State from Hydel, Thermal Diesel and Atomic Power Station; and

(b) how do they compare with that from biogas, sun, wind and tide?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The average cost of power generation in respect of various State Electricity Boards is given in the statement attached.

(b) No tidal projects have yet been set up in India. As regards energy from solar and wind, the projects are still in a development and demonstration stage and, therefore, the costs of bulk power generation from these sources have not been worked out. Biogas too is not being used commercially for generation of electricity. It is, however, estimated that the cost of power from decentralised biogas for applications in remote rural areas may be comparable to the conventional rural electrification for such remote areas.

Statement

Average cost of Power Generation per KWH (in Paise) as received from various State Electricity Boards

S. No.	Name of State	1979-80			
		Hydro	Thermal	Atomic	Diesel
1	Andhra Pradesh	*6·9	24·95	..	..
2	Assam	..	16·72	..	607
3	Bihar	16·5	22·5	..	..
4	Gujarat	*3·43	*20·26	*16·06	..
5	Haryana	5·3	31·43	..	..
6	Himachal Pradesh	11·1	..	..	380
7	Karnataka	*6·27	..	..	..
8	Kerala	*5·29	..	..	..
9	Madhya Pradesh	*5·31	*12·98	..	1495
10	Maharashtra	*4·89	*16·87	..	..
11	Orissa	*5·45	*18·61	..	..
12	Punjab	*2·8	*27·8	..	297
13	Rajasthan	*5·31	*12·6	..	..
14	Tamil Nadu	*5·47	*32·07	..	..
15	Uttar Pradesh	10·61	22·69	..	..
16	West Bengal	*26·16	11·89	..	*81·37
17	Jammu & Kashmir	15·92	103	..	..
18	Meghalaya	11·45 *	..	..	..

*Where information for the year 1979-80 is not available figures for 1978-79 have been given.

**Average cost of power generation from hydel/diesel for the year 1977-78.

Production of Haldia Fertilizer

2068. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) is it a fact that Haldia Fertilizer Company in public sector is yet to begin production properly;

(b) if so, what are the impediments and what is being done to remove those;

(c) whether the gas turbine needed for the plant has been supplied;

(d) if not, whose responsibility was it to supply that and what caused the delay; and

(e) when is it expected to be supplied?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (e). Non supply of the requir ed power by the West Bengal State Electricity Board is the main impediment for starting production in this

plant. Government has sanctioned the installation of a 20 MW gas turbine by the Company to meet the requirements of power of the plant in part. The order for the turbine was placed by Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., (H.F.C.) in December, 1980 and it is expected to be in operation from September, 1981.

Report of Committee on Environmental Aspect of Silent Valley Project

2069. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Committee appointed to go into the environmental aspect of the Silent Vally Project in Kerala has submitted its report; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The report has not yet been received.

(b) Does not arise.

Employment to the Departments of D.E.S.U. Employees Died/Retired on Medical Grounds

2070. SHRI HIRA LAL R. PARMAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether sons/daughters/near relatives of the employees working in DESU are provided employment on the death/premature retirement of the employees on medical grounds;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether the Cabinet Secretariat Department of Personnel O.M. No. 14/10/71-Estt-(D) dated 15th January, 1972 has been implemented in DESU, if so, from which date, if not, the reasons not implementing the Government orders; and

(d) whether some class IV employees of Delhi Electricity Supply Undertaking were prematurely retired on medical grounds in April, 1980 and if so, the datewise number and names of these employees and whether their dependents have been given employment, if not, by which time their dependents would be given employment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). Delhi Electric Supply Undertaking provides employment to one of the dependents of the employees who die in harness. However, no employment is given at present to the son/daughter/near relation of an employees who is prematurely retired on medical grounds.

(c) The Office Memorandum in question which has been made applicable to Delhi Electri Supply Undertak from 8th February, 1980, as notified by Delhi Administration, has not yet been implemented pending amendment of the Recruitment and Promotion Regulations. The DESU is being advised to expedite the adoption of the amendment to the Regulations with a view to extending, to its employees the benefit of the Office Memorandum cited earlier.

(d) Only Shri Parkash Chander Sharma, ex-Daftry was retired prematurely on medical grounds with effect from 30th April, 1980. No employment to the dependent member of the family could be given as no provision exists at present for the same.

Increase in Price of Drugs Formulations

2071. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the public sector company have been seeking consfant price rise in various basic raw materials essential for drug formulation;

(b) if so, how many times, was such price rise granted to Hindustan Organic Chemical and other companies by increasing 'Leader Prices';

(c) whether the Pharmaceutical manufacturers are facing crisis as consequential rise in drug formulations due to increase in 'Leader Price' has not been granted;

(d) the names of the companies who are facing closure, loss of production due to non-increase in the prices of final drug formulations; and

(e) if so, when the decision will be taken, without waiting for further price rise which is demanded for HOC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI BAL BIR SINGH): (a) There has been demand from the drugs and pharmaceuticals industry including Public Sector Companies manufacturing price-controlled bulk drugs for revision of the prices, particularly after the hikes in the prices of petroleum products in 1979 and 1980.

(b) There is no price control on chemicals and chemical/drug intermediates. Of the chemical/drug intermediates manufactured by M/s. Hindustan Organic Chemicals, in the case of Meta-Amino-Phenol, an intermediate required for the production of anti-T.B. drug PAS and its salts M/s. Hindustan Organic Chemicals increased the price from Rs. 42.40 per kg. to Rs. 47.30 per Kg., with Government's knowledge, in October, 1979. Although price of petroleum products have increased during 1979 and 1980, the Company has so far not increased the selling price of Meta-Amino-Phenol. Government have revised the price of PAS and its salts on 19th December, 1979, and subsequently on 16th January, 1981, on the basis of the Meta-Amino-Phenol price at Rs. 47.30 per kg.

(c) to (e). The leader prices of formulation based on the price of PAS and its salts announced on 19th December, 1979, have already been revised. Further revisions are being expedited.

समुद्र में तेल का पता लगाने के लिए गैर-सरकारी उद्योगों से सहयोग प्राप्त करना

2072. **श्री जगपाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र में तेल का पता लगाने में गैर सरकारी उद्योगों से सहयोग मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनका सहयोग मांगा गया है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of a regional Headquarter of ONGC in Andhra Pradesh

2073. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the Minister of PEROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government of Andhra Pradesh represented to the Centre to set up a regional headquarter of ONGC in Andhra Pradesh and requested to combine on-shore and off-shore drilling operations;

(b) whether the Government of Andhra Pradesh assured to provide necessary infrastructure required for the location of the regional headquarters; and

(c) if so the details of the action taken by Government?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) With regard to the setting up of a Regional Office of ONGC in Andhra Pradesh, the State Government were informed that the existing set up of a Project Manager and the supporting establishment for the onshore area was considered adequate for the present, while the offshore activities could best be carried out from Madras harbour for the time being in view of the logistics involved. The State Government were also informed that the onshore and offshore operations being different in nature cannot be integrated.

राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की मांग

2075. **प्रो० निर्मला कुमार शक्तावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली की कुल कितनी मांग है ;

(ख) क्या 1980–81 के दौरान बिजली की लगातार कमी रही है ;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में किसी नई परियोजना को स्वीकृत किया जायेगा ताकि बिजली सप्लाई में कोई कमी न हो ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान की (ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की सम्मिलित) वर्तमान आवश्यकता लगभग 16 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है ।

(ख) और (ग) अप्रेल से नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक थी । तथापि, दिसम्बर, 1980 से आगे, नदी अन्तर्वाहों में कमी के कारण भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड काम्पलेक्स तथा चम्बल काम्पलेक्स से 18 दिसम्बर, 1980 से 28 जनवरी, 1981 तक राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की यूनिट संख्या-एक के बन्द करने के कारण कम विद्युत उपलब्धता के कारण राजस्थान में विद्युत की कमी रही ।

(घ) 1980–85 की अवधि के दौरान राजस्थान प्रणाली में लगभग 496 मेगावाट की एक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि होने की आशा है । इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 1980–85 के दौरान चालू की जाने वाली केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को भी कुछ विद्युत आवंटित की जाएगी ।

Complaints against Newspapers

2076. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have lodged any complaints with the Press Council of India against any newspapers in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken by the Press Council thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes Sir.

(b) and c). Two statements (Statement I and Statement II) containing the information are attached.

Statement—I

COMPLAINTS PREFERRED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

Sl. No.	Complainant	Respondent	Subject	Date of receipt	Findings of the Council/Action taken
1	2	3	4	5	6
1	Ministry of External Affairs, External Publicity Division, New Delhi.	"Capitalist"	Publication of a defamatory news item in its issue dated June 1, 1979 regarding First Secretary of Quatar Embassy's desire for women and his adventures in the Delhi University.	12-10-1979	In view of the fact that "Capitalist" had ceased publication the complainant informed that the matter may be dropped and the case was accordingly treated as closed on 27-8-1980.
2	Do.	Do.	Publication of a defamatory news item in its issue dated June 1, 1979 regarding Moroccan Ambassador.	Do.	Do.
3	Do.	"New Delhi"	Publication of a defamatory article in its issue of September 4, 1979 wherein reference to humiliation faced by Indians while applying for Visa at Foreign Missions in Delhi has been made.	Do.	The Council at its meeting held on March 5, 1980 felt that there was no sufficient ground for holding an inquiry in the matter and decided not to take cognizance of the complaint.
4	Do.	Do.	Publication of a defamatory article in its issue dated September, 4, 1979 wherein innocuous reference to Chinese Embassy parties had been made.	Do.	Do.
5	Do.	"Deccan Herald"	Publication of a defamatory article in its issue dated June 2, 1979 regarding alleged misbehaviour of Iraqi Diplomats at the Ashoka Hotel in Bangalore.	Do.	In the light of the preliminary comments offered by the newspaper the complainant expressed its desire to withdraw the complaint on May 17, 1980.
6	Do.	"Indian Express"	Publication of a defamatory article in its issue dated May, 12, 1979 regarding alleged misbehaviour of Moroccan Diplomat at a New Delhi nursing home.	Do.	The complainant on reconsideration decided to withdraw the complaint on 17-5-1980.

1	2	3	4	5	6
7	Ministry of External Affairs, External Publicity Division, New Delhi.	"The Hindu"	Publication of a defamatory article published in its issue dated June 23, 1979 about the Moroccan Ambassador's episode.	12-10-1979	The complainant on reconsideration decided to withdraw the complaint on 17-5-1980
8	Do.	"India Today"	Publication of a defamatory article published in its issue dated September 1—15, 1979 on the so-called diplomatic excesses.	Do.	Do.
9	Ministry of Home Affairs, New Delhi.	"Nav Bharat Times"	Publication of fabricated news item regarding rape committed on 65 women during the agitation against the reservation of jobs for backward classes in Bihar, in its issue dated April 14, 1978.	24-9-1979	The Council at its very first meeting held on May 26, 1979 decided not to entertain complaints relating to period anterior to the establishment of the Council. The case was closed accordingly on 17-10-1979.
			1980		
10	Chief Medical Officer, C.G. H.S., Kanpur.	"Da'nik Gagha" Kanpur	Publication of false and malicious news items in its issue dated 31-8-1978. 1-9-1978, 9-10-1978 and 28-12-1978 against Central Govt. Health Scheme.	2-7-1980	The Council at its very first meeting held on May 26, 1979 decided not to entertain complaints relating to period anterior to the establishment of the Council. The case was closed accordingly on 4-7-80.
11	Chief Producer, Films Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.	"Mirror"	Publication of unwarranted derogatory remarks against Films Division regarding its failure to cover solar eclipse in the July 1980 issue of "Mirror".	22-7-1980	The complainant fulfilled the preliminary requirements namely drawing the attention of the Editor to the impugned matter, declaration as to the pendency of legal proceedings, and forwarding of the original clipping of the impugned matter on 4-10-80. A copy of the comments received from the Editor, Mirror was forwarded to the complainant on 9-2-81. The complainants in the meantime having expressed their desire to close the matter in the light of clarification given by Shri Abbas of Mirror the case was treated as closed on 12-2-1981.

12	Information Officer, Press Information Bureau, Govt. of India, New Delhi.	"Indian Express"	Publication of an Editorial in its issue dated Dec. 27, 1980 under the caption "Mr. Sathe's Threat" on an alleged statement of Minister of Information and Broadcasting at Calcutta that the Minister had threatened to send journalists to jail.	30-12-80	A show-cause notice was issued on 5-1-1981 to the Editor, the Indian Express, inviting his written statement in the matter. This was received on Jan. 28, 1981. The case came up for consideration by the Inquiry Committee of the Council at its meeting held on February 31. 1981 and was adjourned to one of its future meetings.
13	Do.	"Tribune"	Publication of an editorial in its issue dated Dec. 27, 1980, under the caption "Jail for Journalists" on an alleged statement of Minister of Information and Broadcasting at Calcutta that the Minister had threatened to send journalists to jail.	Do.	A show-cause notice was issued on 6-1-1981 to the Editor, Tribune, inviting his written statement in the matter. This was received on 11-1-81 and the case came up for consideration by the Inquiry Committee of the Council at its meeting held on February 21, 1981 and was adjourned to one of its future meetings.
14	Information Officer Press Information Bureau, Govt. of India, New Delhi.	"Hindustan Times"	Misreporting of the speech of Minister of Information and Broadcasting at Calcutta on December 25, 1980 attributing to him the statement that he had threatened to send journalists to jail.	Do.	A show-cause notice was issued to the Editor, Hindustan Times, on 6-1-81 inviting his written statement in the matter. In the meantime the newspaper published an apology in this behalf. In view of this, the complainant wrote to the Press Council to say that the complaint against the Editor may be dropped and that it may be treated as a complaint against the correspondent. The editor as the head of a newspaper organisation is normaly held responsible for whatever appears in his paper. As such, the parties were informed, that the complaint has to be treated as against the Editor, on 16-1-81. The Editor submitted his written statement on 14-1-81. The case came up for consideration by the Inquiry Committee of the Council at its meeting held on February 21, 1981 and was adjourned to one of its future meetings.

Statement—II

COMPLAINTS PREFERRED BY THE STATE GOVERNMENTS

S. No.	Complainant	Respondent	Subject 1979	Date of receipt	Findings of the Council/ Action taken.
1	Director of Information & Public Relations, Govt. of Tamil Nadu.	"Dinakaran" Madras.	Publication of a false news item in its issue dated April 4, 1979.	10-4-1979	The Complainant was requested to fulfil the preliminary requirements of the Council Inquiry Regulations on April 11, 1979. Despite three reminders, since the complainant failed to comply with the preliminary requirements, the case was treated as closed on 25-9-1979.
2	Director of Public Relations and Tourism, Government of Tripura.	Local newspapers in general.	The Press Advisory Committee's concern over reporting of sensitive issues by certain local newspapers.	18-7-1979	The complainant was requested to lodge formal complaints against various newspapers fulfilling the preliminary requirements of the Council's Inquiry Regulations on July 13, 1979. Despite two reminders the complainant failed to comply with the preliminary requirements and the case was treated as closed on 14-11-1979.
3	Secretary, Home Department, Govt. of Assam.	"Saptahik Nilachal"	Publication of an editorial in its issue dated July 25, 1979 aiming to create political instability by inciting feelings of local residents against the non-residents of Assam.	18-9-1979	Preliminary comments of the editor were invited and the State Govt. was asked in the meantime to comply with certain requirements. They took some time to comply with them. After these requirements have been fulfilled a show-cause notice was issued to the Editor inviting his written statement on 21-1-81. It is awaited.
4	District Magistrate, Pune.	"Sobat"	Publication of articles in its issues dated 29-6-80 and 6-7-80 with a view to incite communal disharmony.	16-8-1980	The Inquiry Committee of the Council at its meetings held on November 29, 1980 and December 20, 1980 heard both the parties and concluded its hearings. The Council is likely to give its verdict soon.

5	Commissioner & Secretary, Home Department, Govt. of Assam.	"Dainik Asom".	Publication of false, fabricated and distorted reporting.	16-10-1980	The State Government were requested to comply with certain preliminary requirements on Oct. 31, 1980. Simultaneously, the comments of the Editor were invited on Dec. 18, 1980. The State Government fulfilled the preliminary requirements vide their letter dated 27-12-80. A show-cause notice was, issued to the Editor on 21-1-81 inviting his written satement in the matter. It is awaited. However, the preliminary comments received from the Editor on 23-1-1981 have been forwarded to the State Government and both the parties have been further requested to clarify certain points/send documents, on 3-2-81.
6	Assistant Commissioner of Police and Public Relations Officer, Crime Branch, C.T. D. Bombay.	"Free Press Bulletin" Bombay	Non-Publication of contradiction to a news-item in its issue dated November 13, 1980.	12-1-81	The complaint was an unsigned one and the complainant was requested on 24-1-81 to send a signed copy fulfilling certain preliminary requirements. The complainant by means of his letter dated February 23, 1981 has filed a formal complaint and the same is under examination.

राजस्थान को डीजल तथा मिट्टी के तेल का आवंटन

2077. **श्री चतुर्भुज** : क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को दिसम्बर, 1980 के दौरान तथा उसके बाद 15 फरवरी, 1981 तक डीजल तथा मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया और उसमें से कितनी मात्रा वास्तव में सप्लाई की गई तथा कोटे के शेष मात्रा की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राजस्थान के दूरस्थ गांवों में डीजल की कमी है चूंकि डीजल के वितरक निर्धारित दरों पर इन स्थानों पर अपने टैंडर नहीं भेजते और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या जनवरी मास के लिये डीजल का कोटा छीपा बारोड, छाबड़ा तथा उडतार (कोटा, राजस्थान) नहीं पहुंचा है और इस कोटे को किसने और कहां पर बेच दिया है तथा अन्तय तक डीजल कब पहुंचेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कारवाई करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिसम्बर, 1980—फरवरी, 1981 के दौरान राजस्थान में हाई स्पीड डीजल तेल (एच०एस०डी०) और मिट्टी के तेल के आवंटन और विक्रय के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

आंकड़े मीट्रिक टनों में

	एच० एस० डी०		मिट्टी का तेल	
माह	आवंटन	विक्रय	आवंटन	विक्रय
दिसम्बर, 80	44300	39300	12000	12340
जनवरी, 81	46300	40966	11300	11697
फरवरी, 81	45500	18297 (15 तक)	10700	4631 (15 तक)

चलन बाधाओं और स्थानीय परिवहन समस्याओं के परिणाम-स्वरूप एच०एस०डी० के विक्रय उसके आवंटन की अपेक्षा कम थे ।

(ख) इस प्रकार की कोई विशेष शिकायत मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है ।

(ग) छीपा, बारोड़ छाबड़ा तथा उडतार में किसी भी तेल कम्पनी का खुदरा बिक्री केन्द्र (पम्प) नहीं है । इन स्थानों को एच०एस०डी० की सप्लाई वारान से की जाती है । वारान बिक्री केन्द्र से विक्रय उसको किए आवंटनों के लगभग बराबर रहे ।

Recommendations of Committee on Power regarding Inter-State Water Disputes

2078. SHRI D. P. YADAV: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Report of the Committee on Power, has inter-alia, recommended that "twenty nine Inter State Water

Disputes if not resolved amongst the concerned States in 3 months, should, by law, be referred to an arbitrator to be appointed by the Central Government who should be required to submit his award in 3 months, such an award should be made "non-justiciable" and that thirty "As an alternative the possibility of river and lake waters being declared a Central subject under a constitutional amendment may be given serious consideration"; and

(b) if so, the reaction of Government to this recommendation and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Department of Irrigation who are primarily concerned with the subject have been requested to consider the recommendation of the Committee on Power.

Planning Commission's approval for Fertilizer Industry

2079. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission have approved a massive outlay during the Sixth Plan period (1980-81) for the fertilizer Industry;

(b) if so, to what extent it would augment the production capacity of fertilizer industry; and

(c) reduce external dependence or import of this commodity?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Adequae provision has been made for the fertilizer programme envisaged during the 6th Five Year Plan.

(b) The installed capacity of fertilizer production which was 3.91 lakh tonnes of nitrogen and 12.3 lakh tonnes of $P^2 O^5$ at the beginning of the 6th Plan is expected to go up to about 65 lakh tonnes of nitrogen and 19 lakh tonnes of $P^2 O_5$ by the end of the Sixth Plan. This capacity would go up further to about 100 lakh tonnes of nitrogen and about 35 lakh tonnes of $P^2 O^5$ by 1989-90, by which time the new projects for which provision is being made in the Six Plan are expected to be completed.

(c) The percentage of import of nitrogenous and phosphatic fertilizers to their total consumption which was about 39 per cent at the beginning of the Sixth Plan is expected to go down to about 29 per cent by the end of the Sixth Plan and to about 15 per cent by 1989-90.

Decision on applications under section 30 of MRTP Act

2080. SHRI R. PRABHU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Section 30 of the MRTP Act lays down that an application on the part of Government to decide any case under Sections 21, 22 and 23 of the Act within a period of 3 months in case the matter is not to be referred to the MRTP Commission;

(b) if so, how many applications under each of the Sections 21, 22 and 23 of the Act were decided during the year 1978, 1979 and 1980;

(c) the time taken in disposing of each such case;

(d) whether any single case was decided within a period of 3 months; and

(e) if not, the steps proposed to be taken to streamline the work of the administration of the MRTP Act to comply with the statutory provisions?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) According to Sub-Section 4 of Section 30, every notice, application or proposal which has not been referred to the Commission shall be disposed of by the Central Government within 90 days from the date on which such notice, application or proposal is received by it. But the Central Government may dispose of a notice, application or proposal in a time beyond the period of 90 days if special reasons exist. The provision is directory and not mandatory.

(b) and (c). Statements I, II and III are laid on the Table of the House. [*Placed in library. See* No. LT-2011/81].

(d) Yes Sir, thirty-five cases were disposed of within a period of ninety days.

(e) MRTP Act being an economic legislation with far reaching implications, the proposals have to be examined in depth from the various connected angles in consultation with other concerned Government Departments and no effort is being spared to dispose of the cases within the quickest possible time.

Additional Realisations from Price of Petroleum Products

2081. SHRI JYOTIRMOY BOSU:
SHRI SUBHASH YADAV:
SHRI KRISHNA PRATAP SINGH:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) total additional amount expected to be realised through the latest price hike of each petroleum products;

(b) what was the total amount realised through price like in June, 1980;

(c) the reasons why it became necessary to resort to the sweeping hike in the oil prices on the eve of the Budget Session; and

(d) whether he is aware that the latest price hike has already generated a chain reaction?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) About Rs. 1195 crores per annum.

(b) Total amount estimated to be realised through price hike in June 1980 is Rs. 2080 crores.

(c) The reasons for raising the prices of various petroleum products w.e.f. 13-1-81 are:—

(i) Increase in the price of imported crude by about Rs. 243 per tonne from the last price increase in June 1980 till January 1981 due to successive prices increase by OPEC countries, including a 10 per cent increase w.e.f. January 1981.

(ii) Increase in the price of imported deficit petroleum products by about 35 per cent.

(iii) Increased imports to make good shortages on account of Assam oil blockade.

(iv) Costlier purchases in the spot market in the last quarter of 1980 due to disruption in supplies from Iran and Iraq.

(v) Increased rupee burdens due to escalation in operational costs including expenditure on new pipelines for transportation of Bombay High crude.

(d) Due to the price rise of petroleum products w.e.f. 13-1-1981, it is estimated that the whole sale consumer price index is likely to rise by about one per cent only.

दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से मैथन ले जाना

2082. **श्री रोत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत बिहार में 24 परियोजनायें और पश्चिम बंगाल में बिहार सीमा के निकट 2-3 परियोजनायें हैं ;

(ख) क्या प्रशासनिक सुधारों और कार्य के सूचित अनुरक्षण के अभाव में विद्युत उत्पादन तथा अन्य कार्यों की कार्यकुशलता में गिरावट आई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कलकत्ता में बनाए रखना और उस पर बहुत अधिक अनावश्यक व्यय करना न्यायोचित नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुख्यालय को उसकी परियोजनाओं के केन्द्र, मैथन (कलकत्ता से 225 किलोमीटर दूर बिहार-बंगाल सीमा पर स्थित जल विद्युत कम्प्लेक्स) में ले जाने और प्रशासन में सुधार लाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विकल महाजन) : (क) दामोदर घाटी निगम को बिहार में 7 और पश्चिम बंगाल में 4 परियोजनाएं हैं । अन्य चार परियोजनाएं, बिहार और पश्चिम बंगाल, दोनों ही राज्यों के क्षेत्रों में फैली हुई हैं ।

(ख) से (घ). विद्युत उत्पादन कम होने का कारण था औद्योगिक संबंध खराब होना तथा संयंत्र और मशीनरी की तकनीकी ढंग पर अवहेलना । विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले ही उपाय किए गए हैं जिनसे पिछले चार महीनों में सुधार हुआ है । दामोदर घाटी निगम का प्रचालन मुख्यालय पहले से ही मैथन में है, अतः प्रशासनिक मुख्यालय का स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं समझा गया है । प्रशासनिक मुख्यालय कलकत्ता में होने से कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, यथा भागीदार राज्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सुलभ सम्पर्क ।

तेल का अन्वेषण

2083. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम निर्यातक देशों द्वारा वर्ष 1979 में रखे गये प्रति बैरल दो डालर से भी कम मूल्य में समक्ष, इस समय तेल का प्रति बैरल मूल्य क्या है और वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितने तेल का आयात किया गया तथा कितना मूल्य अदा किया गया और इस समय कितने तेल का आयात किया गया है और कितनी राशि अदा की गई है ;

(ख) भारत में तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ और भविष्य में इस की क्या संभावनायें हैं;

(ग) क्या सरकार ऊर्जा के नये स्रोत ढूंढने और तेल की खपत में किफायत करने के लिए कोई कदम उठा रही है ताकि ऐसे वित्तीय बोझ से मुक्ति मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जनवरी,

1979 से जनवरी, 1981 के दौरान भारत द्वारा निरन्तर आयात किये गये विभिन्न प्रकार के कच्चे तेलों का सरकारी विक्रय मूल्य और उन के मूल्य में हुए मुख्य परिवर्तन निम्न प्रकार हैं :—

(डालर–बैरल)

कच्चे तेल की किस्म	जन. 79	दिस. 79	जन. 80	अक्तू. 80	जन, 1981
अरबियन लाइट .	13.34	24.00	26.00	30.00	32.00
ईरानियन लाइट .	13.45	28.50	31.00**	35.00	37.00
ईराक बसरा .	13.29	25.96	27.96	31.96	35.96
डम शैंक .	13.78	27.36	29.36	31.36	35.36

*नवम्बर, 1980 से पूर्व प्रभावी ।

**1 फरवरी, 1980 से प्रभावी ।

(ख) 1980–81 के दौरान, कच्चे तेल की स्वदेशी उपलब्धता का अनुमान 14 लाख मि.मी. टन है । देश में तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिस से अनुमानित स्वदेशी उत्पादन 1984–85 तक 21.3 मि. मी. तक 21.3 मि. मी. टन हो सके ।

(ग) और (घ) बड़े पैमाने के संभावनाओं संबंधी प्रयोगों जहां इस समय तेल का प्रयोग किया जा रहा है, के लिए सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिये उपयुक्त तकनीक के विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । तथापि प्रारम्भ में, इस समय उदत्त तकनीक को अपनाने में परम्परागत विकल्पों की तुलना में अधिक लागत विहित है । इस समय विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग होने वाली विभिन्न पद्धतियों में कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । परिवहन क्षेत्र में, जो पेट्रोल और डीजल का मुख्य उपयोगकर्त्ता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रेल सड़क प्रणाली का विद्युतीकरण, लम्बी ढुलाई के सड़क परिवहन को रेल परिवहन में बदलना, बैटरी से चलने वाले वाहन जो बाद में थोड़ी ढुलाई आदि के लिए सौर ऊर्जा से चल सकेंगे, पहल की गई है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने एक नेशनल स्टियरिंग कमेटी (राष्ट्रीय संचालन समिति) गठित की है जो बायो-मास के उत्पादन और बायो मास को तरल ईंधन जैसे मिथनाल और इथनाल में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बतायेगी, का पता लगाये तथा उन की जांच करेगी । कुकिंग और लाइटिंग के अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी पम्प सेटों को चलाने में बायो-गैस को प्रयोग में लाने के लिए सामुदायिक बायो-गैस प्लांटों की स्थापना की जा रही है ।

सौर ऊर्जा का दीर्घावधिक प्रयोग की दूसरी संभावना हाइड्रोजन जैसे तेल के स्थान पर स्वच्छ, परिवहनीय ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, का उत्पादन करता है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त हवा-गति उपलब्ध है, वहां कई प्रकार की पवन चक्कियों की जांच की जा रही है ।

Proposal for introduction of Colour TV

2084. PROF. P. J. KURIEN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have dropped the proposal to introduce colour T.V. in the country; and

(b) if so, the reasons for the same?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). No decision has been taken so far by the Government on the question of introduction of colour television in the country.

Representation by Employees

2085. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether he had received any representation dated 17th June, 1980 from the employees of Udyogamandal unit, Kerala;

(b) if so, the salient points raised in the representation;

(c) whether he is aware that as per I.D. Act any agreement reached before can be rejected by the employees if they unanimously take decisions in their General body meeting; and

(d) if so, what steps Government propose to take on the demands of the employees of Udyogamandal Unit, Kerala?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) A representation dated 17th June, 1980 was received by my predecessor from the Hindustan Insecticides Employees Union, Udyogamandal, Kerala.

(b) The following are the salient points made in the representation:

(i) that a long-term agreement was signed by the leaders of the unions from Udyogamandal unit and the management of Hindustan Insecticides Limited (HIL) in February, 1980, without the knowledge or the concurrence of the workers of that unit and that the employees of Udyogamandal unit have rejected the agreement unanimously in their General body meeting;

(ii) that in the settlement there are many clauses which are detrimental to the very basic concept of an agreement, such as those relating to work study, production incentive scheme, revision of period of settlement, change over from Central Government D.A., to Industrial D.A., mode of fixation of pay, payment of lump sum one time ad hoc addition, night shift allowance, overtime payment, and admission of employees' children in FACT's schools;

(iii) that the management were not prepared to consider many of their reasonable and lawful demands.

(c) and (d). Government have constituted a National Industrial, Tribunal with Justice Cintaman Tukaram Dighe, as its Presiding Officer and have referred to it the Charters of Demands of the employees of all the units of Hindustan Insecticides Limited, including Udyogamandal unit, for adjudication.

Production by Bongaigaon Unit and Distribution

2086. SHRI N. K. SHEJWALKAR: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bongaigaon unit has once again started

production; if so, the quantum of production achieved so far;

(b) whether it is also a fact that the agitators have suggested that the production now being made there should be earmarked for supply to the North Eastern States of the country which are facing acute shortage of petrol and also kerosene;

(c) whether they have also stressed that the oil production in the refinery should not be sent through the pipeline but transported through road transport or rail so that the need of the needy Eastern States is met; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) The Crude Distillation Unit of Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited started operating from 10th February, 1981 and is expected to run at a throughout of 25,000 MTs per month

(b) and (c). The agitators desired that (i) the kerosene produced in the refinery shall not be sent outside the North Eastern Region and be despatched only for the use of this region and (ii) the newly connected product pipeline will not be operated to send the products outside the refinery.

(d) No such assurances have been given to the agitators.

Allotment of residential accommodation for junior executives of Rashtriya .. Chemicals and Fertilisers ..

2087. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several junior executives in the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Bombay have not so far been allotted residential accommodation in the factory irrespective of the fact that they have rendered 4-5 years service and have to attend shift duties at odd hours during day and night; and

(b) if so, how Government propose to provide them residential accommodation in the factory area in the near future so that those junior executives may take a sigh of relief?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Due to shortage of accommodation in the township, the Rashtriya Chemicals and Fertilizers have not been able to provide residential quarters to some of their junior engineers. However, they have taken special care to see that the employees who are required to attend emergency duties are provided accommodation in the township.

(b) The Corporation is advancing loans to its employees for construction of their own houses and when these are completed, the employees concerned will vacate houses in the township. According to the assessment made by the company, the housing problem is likely to be solved within two years.

Power Projects undertaken to improve the Power situation in Bihar

2088. SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) how many power projects have been undertaken for improving the power situation of Bihar;

(b) what are reasons of unsatisfactory working of several power houses situated in Bihar, specially the Chandrapura and Patratu Thermal Power Stations;

(c) what remedial measures are being taken for setting right the working of these power stations; and

(d) give details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The following generating schemes are under execu-

tion in Bihar to improve the power availability in the State. The anticipated date of commissioning has also been indicated.

Barauni . . .	2x110 MW	Unit No. VI Unit No. VII	March, 82 March 83
Patratu	2x110 MW	Unit No. IX Unit No. X	December, 1982. June, 1983
Muzaffarpur . . .	2x110 MW	Unit No. I Unit No. II	January, 1981 July, 1982.
Tenughat . . .	2x210 MW	Unit No. I Unit No. II	June, 85 June, 86

(b) There are two thermal power Stations in Bihar under the Bihar State Electricity Board namely Barauni thermal power station and the Patratu thermal power station. The performance of these power stations has been comparatively unsatisfactory due to frequent forced and long duration outages, lack of spare parts and lack of expert personnel in operation and maintenance of the power stations.

(c) and (d). A high level team consisting of the officers of the Central Electricity Authority, National Thermal Power Corporation and BHEL recently visited Bihar Thermal Power stations and the State Electricity Board has been given assistance in the preparation of plant betterment and maintenance programmes. On the advice of the team, the following action has been taken to improve the performance of thermal power stations at Barauni and Patratu:

(i) Monitoring cells one each at Patratu and Barauni thermal power stations and Board's Head Quarters have been formed to monitor effectively maintenance and construction works.

(ii) A spare parts cell has been created at Board's Headquarters to survey requirement and identification of spares. Action is being taken for procurement of adequate number of fast moving and slow moving spares.

(iii) For maintenance works of long duration pert net works and microplanning methodology is being adopted to monitor to achievement of mile stones and target dates.

(iv) Task force teams have been formed at both the above thermal power stations to study and identify the problems related to generation. Constraints in the generating sets have been identified.

(v) All the tripplings, outages and blasts are recorded. Every outage and tripplings is analysed now and where remedial measures are called for they are promptly attended to. Where outage are trippling are taking place on account of mal-operation responsibility is fixed on the personnel and disciplinary action taken against guilty staff.

(vi) Action have been taken and further actions are being taken to stock sufficient control and instrumentation equipments so that these may be used immediately wherever required.

(vii) Assistance from Russian experts is also being taken for maintenance of the units supplied by USSR and to obtain spares from them.

कोल इंडिया लिमिटेड में पदों का भरा जाना

2089. श्री तारिक अनवर : क्या ऊर्जा मंत्री कोल इंडिया लिमिटेड में पदों के भरे जाने के बारे में 5 अगस्त, 1980 के

तारांकित प्रश्न संख्या 6840 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पूरी जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे एकत्रित करने में कितना समय और लगने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Promotion of production assistants and transmission executives in A.I.R.

2090. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) is it a fact that Production Assistants and Transmission Executives in All India Radio are working in a same grade that is Rs. 425/- Rs. 750/-;

(b) if so, is it also a fact that Transmission Executives are promoted as Programme Executives through DPC after completing 6 years service in their own cadre;

(c) is it also a fact that there is no promotional channel for Production Assistants in All India Radio and persons after completing 20-25 years of service as production assistance are still working as production assistants and were never promoted as producer through DPC; and

(d) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) Production Assistants are Staff Artists who are working against contract posts having a running fee scale of Rs. 425-750. On the other hand, Transmission Executives are regular civil employees who work against posts which carry the pay-scale of Rs. 425-750. In addition, there is Selection Grade for Transmission Executives in the Scale of Rs. 550-900.

(b) Transmission Executives with five years' approved service in the Grade are eligible for being considered for promotion to the Grade of Programme Executive subject to the availability of vacancies in promotion quota.

(c) Production Assistants are eligible, by limited selection, to be considered for the posts of Producers alongwith other categories of staff artists, as per provisions of Recruitment Rules. There is no direct channel of promotion exclusively for them.

(d) Government appointed a Cadre Review Committee which has made certain recommendations regarding promotion prospects of Production Assistants. The Recommendations are under consideration.

बीड़ी निर्माता कम्पनियां

2091. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी बीड़ी निर्माता कम्पनियां हैं, उन के नाम क्या हैं तथा उन के मुख्यालय कहां कहां हैं; और

(ख) इन बीड़ी निर्माता कम्पनियों के शेयरधारियों के नाम और पते क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) 31-3-1980 तक, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत 48 बीड़ी निर्माता कम्पनियां थीं । इन कम्पनियों के नामों और पंजीकृत कार्यालय के पते संलग्न विवरण-पत्र में दिये जाते हैं ।

(ख) इन सभी 48 कम्पनियों के शेयर-धारियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने में बहुत ही ज्यादा समय और श्रम लगेगा तथा इस के परिणाम इस प्रयत्न में पूरी तरह अनुकूल नहीं हो सकेंगे । इस अभिप्राय से, संलग्न विवरण-पत्र में कम्पनियों के केवल नामों और पतों को ही प्रस्तुत किया जाता है ।

विवरण पत्र

31-3-1980 तक देश में कार्यरत बीड़ी निर्माता कम्पनियों की सूची

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता
(1)	(2)	(3)
1.	असम बीड़ी फैक्ट्री प्राइवेट लि०	10, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता–1
2.	बांधव बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लि०	2, रूप चन्द राम स्ट्रीट, कलकत्ता––7
3.	बेलाल बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लि०	26, फेयर्स लेन, कलकत्ता––73
4.	भगवान दास शोभा लाल जैन टोबाको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	डाल चन्द जैन के भवन में, न्यू बांदी चौक, सागर (मध्य प्रदेश)
5.	भारत बीड़ी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	मकान नं. 123, कदरी रोड, मंगलौर–3 (कर्नाटक)
6.	भीकूसा मामासा क्षेत्रीय प्राइवेट लि०	सोन्नार जि० नासिक, महाराष्ट्र
7.	बस्ती राम नारायन दास शारदा प्राइवेट लि०	सूना महल, मैरीन ड्राइव, बम्बई–20 महाराष्ट्र
8.	बोड़ी एन्ड अलाइड टोबाको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	जहाल पुर रोड, कुराई, जिला सिओनी, मध्य प्रदेश
9.	बुन्देलखण्ड बीड़ीज प्राइवेट लि०	229, बड़ा गौरी गेट, झांसी
10.	कोक ब्रांड सिन्नार बीड़ीज प्रा० लि०	फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट न० 5 जसविले, 9 न्यू मैरीन लेन्स, बम्बई–1
11.	दास बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रा० लि०	2 ए, रामजीदास जेठिये लेन, कलकत्ता–7
12.	दास टोबाको एन्ड अलाईड एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	पी–34, रवीन्द्र सरनी कलकत्ता–1

1	2	3
13.	देसाई बीड़ीज प्राइवेट लि०	चाल्कातासी मगोल, नदियाद, गुजरात
15.	एम्ब्राटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	67, बाजार गेट, फोर्ट बम्बई–1
14.	देसाई ब्रादर्स लिमिटेड	1436, कासबा पेठ, पूना–II, महाराष्ट्र
16.	जी० बी० ब्रादर्स एन्ड कोन्डर राजगोपाल चैट्टी, बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड	1-1-62, खलाहोस्नीर्ट रोड, मेल्लोर, जिला (आंध्र प्रदेश)
17.	जयप्रकाश सुधूंर प्राइवेट लि०	सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र
18.	के० सी० साहा एन्ड सन्स (बीड़ी मर्चेन्टस) प्राइवेट लिमिटेड	28/8, गरीहाट रोड, कलकत्ता—19
19.	कुमार ब्रदर्स (बीड़ी) प्राइवेट लि०	167, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—7
20.	लल्लू भाई बी० पटेल एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	राधे श्याम भवन सागर (म० प्र०)
21.	मलय बीड़ी कम्पनी प्राइवेट लि०	25/बी, मदन मोहन टोला, स्ट्रीट, कलकत्ता–5
22.	मन्टू बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लि०	56/1, शामपुकुर स्ट्रीट, कलकत्ता–4
23.	मैना बीड़ी वर्क्स प्राइवेट लि०	द्वारा सेन एन्ड राय (सी० आर०) मर्केन्टाइल बिल्डिग, सैकिंड फ्लोर, लाल बाजार स्ट्रीट कलकत्ता—1
24.	मेरठ बीड़ी एन्ड कम्पनी प्रा० लि०	धर्मशाला मुकन्दी देवी घंटाघर, मेरठ सिटी, यू०पी०
25.	मृणालिनी बीड़ी मैन्यु० कम्पनी प्रा० लि०	21–ए, रामजी दास जेट्टिया लेन, कलकत्ता–7
26.	मोहन लाल हरगोबिन्द दास टोबाको प्रा०लि०	जवाहर गंज, जबलपुर, म० प्र०
27	मोडर्न टोबाको कम्पनी प्रा० लि०	22/114, फील खाना, कानपुर, उ० प्र०
28	नानजीनाद बिजनैस प्रा० लि०	37/4, टाट्टा विलाई, भूता पंडी थीवली, टी० जी० लि० कन्या कुमारी

1	2	3
29.	निजामाबाद बीड़ी मैन्यु० कम्पनी लि०	महबूब गंज, हैदराबाद, आ० प्र०
30.	प्रभु दास किशोरी दास टोबाको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	गोमलचितूर रोड, अहमदाबाद, गुजरात
31.	पी० बी० एस० बीड़ीज प्रा० लि०	कोडियाल बेल, मंगलौर–3 कर्नाटक
32.	पिस्तौल बीड़ी वर्क्स प्राइवेट लि०	नं० 109, सकरवादी निपानी, बेल गांव जिला कर्नाटक
33.	प्रकाश बीड़ीज प्राइवेट लि०	13–340, कूलिमावेद, मंगलौर, जिला साऊथ कनारा, कर्नाटक
34.	पायनीमर टोबाको एजेन्सी प्रा० लि०	5/1, क्लाइव रोड, कलकत्ता—1
35.	पटेल ओवरसीज ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लि०	हाउस नं. 119, चन्दन सर, वाया विर्मटर तालुक वासी जिला थाना, महाराष्ट्र
36.	आर० आर० अग्रवाल प्रा० लि०	शंकर बीड़ी फैक्टरी गांजा खेत, इतवारी, नागपुर, महाराष्ट्र
37.	आर० आर० लोइमा सन्स (बीड़ी) प्रा० लि०	विजयलाल, मीनीरीलाल सर्राफ जनरल मर्चेन्ट्स जौहरी बाजार, जयपुर—3
38.	राजा ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लि०	23, अलिमार स्ट्रीट, गुडिमाट्य,
39.	श्री अशोक पटेल बीड़ी मैन्यु० कम्पनी प्राइवेट लि०	एम० जी० रोड, सागर, म० प्र०
40.	एस० गुप्ता बीड़ी मैन्यु० प्रा० लि०	1, नारायण बाबू लेन, कलकत्ता—7
41.	एस० के० नासिरूद्दीन बीड़ी मर्चेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	145, केशव चन्द्रासेन स्ट्रीट, कलकत्ता–9
42.	सुन्दर लाल सुरेन्द्र कुमार जैन एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेट	3698, बारा टूटी, सदर बाजार, देहली-6
43.	शिल्पी-ओ वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड	12–डी, रामचन्द्र मिर्जा लेन, कलकत्ता

1	2	3
44.	सुवासिनी बीड़ीज प्राइवेट लिमिटेड	3-31,2645 करनगल पैड्डी, मंगलौर-3, कर्नाटक
45.	श्री टोबाको सप्लायर्स प्राइवेट लि०	शिवाजी चौक निपाणी बेलगांव, कर्नाटक
46.	सिन्नार बिड़ी उद्योग लि०	"कांगेस भवन" महात्मा गांधी रोड, नासिक 400001
47.	टी० पी० सोकवालाल रामसेत फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड	14, बी० आई० स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास-17
48.	ठाकुर सावदेकर एन्ड कम्पनी लि०	377, गुरुवार पेठ, पुना, महाराष्ट्र

Nangal Fertilizer Factory

2092. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

What are the annual losses/profits for the past five years for Nangal Fertilizer Factory?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTLIZERS (SHRI DALBIR SINGH): The profits of the Nangal Fertilizer Factory for the last five years as follows:—

Year	*Net Profit* (Rs. in lakh)
1975-76	990
1976-77	696
1977-78	313
1978-79 (after prior period adjustments)	94
1979-80	115

Demand for increased rate of Royalty on Crude Oil

2093. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a demand to increase the rate of royalty on crude oil from various States;

(b) the names of the States and the present rate of royalty being paid on crude oil production; and

(c) the amount of royalty given to different States during the last five years?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) Gujarat, Assam, Arunachal Pradesh in addition to the Union of India.

The present rate of royalty is Rs. 42/- per tonne.

(c) Amount of royalty paid/payable by ONGC during the last five years:—

(Rs. in crores)

State	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
Assam	1.68	3.50	5.71	5.70	5.54
Gujarat	6.16	11.25	18.96	17.68	15.62
Govt. of India (for Offshore Crude)	..	1.54	8.59	13.49	17.61
Total . .	7.84	16.29	33.26	36.87	38.77

Amount of royalty paid/payable by Oil India Limited during the last five years:

Year	Amount of Royalty
	Arunachal Pradesh
	Assam
	(Rupees in crores)
1976	.0001 (upees one th.)
1977	Nil
1978	Nil
1979	Nil
1980	.0087
	(Rupees Eighty seven thousand)

Waste of Natural Gas due to Flare-up

2094. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the large quantity of natural gas in Assam is wasted by burning; the total amount of gas wasted by burning during the last five years;

(b) the value of the gas wasted by burning; and

(c) whether Government have drawn out any plan for utilization of the gas being so wasted and what are the details in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir; about 3000 million cubic metres of gas was flared in Assam during the last five years mainly for want of consumers at the places where gas is available.

(b) The weighted average price in Eastern Region for gas that is sold is about Rs. 224 per 1000 cubic metres, at present.

(c) Yes, Sir; utilisation plan of ONGC gas in Assam is indicated below:—

(i) Gas being supplied to Tea Gardens 20,000 SCMD

(ii) Gas committed to ASEB Power Plant near Lakwa 2,30,000 SCMD

(iii) Gas earmarked for 3rd Phase expansion unit of Namrup Fertilizers Plant 4,50,000 SCMD

(iv) Commitment made to ASEB for 3x3 MW Mobile Generating Sets 90,000 SCMD

(v) Gas being utilised for producion purposes in its fields by ONGC. 35,000 SCMD

Till such time as these consumers start taking supply of gas, the same has to be unavoidably flared. Oil India Limited has further committed to make available additional supplies of gas to the Assam State Electricity Board (ASEB), Assam Petrochemicals Limited and Namrup Phase III (Phase III of HHFCL, Namrup). Mobile gas turbines are being ordered by the Assam State Electricity Board to utilize some of the low pressure gas for generation of electricity.

बस्तर और जगदलपुर के आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या

2095. श्री लक्ष्मण वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर और जगदलपुर के आकाशवाणी केन्द्रों में, वर्गवार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकार ने आकाशवाणी केन्द्रों में इन वर्गों के लिये कुछ कोटा आरक्षित

किया है और यदि हां, तो इन वर्गों से अब तक कितनी भर्ती हुई है;

(ग) शेष आरक्षित कोटा कब पूरा किया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार प्रसारण सेवा में स्थानीय गंडी भाषा को शामिल करेगी ताकि बस्तर के आदिवासी प्रसारण को ठीक तरह से समझ सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग). आकाशवाणी जगदलपुर (बस्तर) के 11 कर्मचारी अनुसूचित जातियों और 15 कर्मचारी (एक स्टाफ आर्टिस्ट सहित) अनुसूचित जनजातियों के हैं। समूह "क" से समूह "घ" तक के विभिन्न पदों के आरक्षण सम्बन्धी सरकार के आदेश आकाशवाणी, जगदलपुर पर लागू हैं। 12 सिविल पद और स्टाफ आर्टिस्टों के 9 पद खाली हैं और इन को भरने की कार्यवाही चल रही है।

(घ) भर्ती, भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। अर्हताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाता है। स्थानीय भाषा बोलने वाले लोग निःसन्देह प्रसारण सेवा में अधिक उपयोगी होंगे।

Purchase of Ready-made Films by Films Division

2096. SHRI D.S.A. SIVAPRAKASAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the purchase committee of Films Division purchased any ready-made films from independent producers during the last 3 years; and

(b) if so, the names of the films, producers and the amount paid for each?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) and (b). A statement showing the names of ready-made films purchased by the Films Division from independent producers during the years 1977-78 to 1979-80 and 1980-81 (upto 31st January, 1981), the names of their producers and the amount paid to each, is enclosed.

Statement

Year	S. No.	Name of the Film	Name of the Producer	Amount Paid
1	2	3	4	5
1977-78	1.	Mata Ganga (E. Col)	M/s Bhardwaj Films, Bombay	Rs. 1,20,000/-
	2.	Zimmedar Kaun (B&W)	M/s Rajeev Films, Bombay	Rs. 9,000/-
	3.	Bhubaner Galpo (B&W)	M/s Ujjain Films, Calcutta	Rs. 30,000/-
	4.	Zindagi Sambhalo (B&W)	M/s Kishore Pictures, Calcutta	Rs. 22,000/-
1978-79	1.	Think, Think, Think (B&W)	M/s Television Films of India, Bombay	Rs. 40,000/-
	2.	Patan (B&W)	Shri Amerjeet Ranu, M/s Universal Films, Bombay	Rs. 30,000/-
	3.	A Living Tradition (Orwo Col)	M/s Samrat Films, Bombay	Rs. 50,000/-

1	2	3	4	5
	4.	Maa-O-Sishu (B&W)	Shri G.S. Mohapatra M/s Konark Films (P) Ltd., Bhubaneshwar	Rs.3,120/- (Purchased 5 prints only)
	5.	Beauty in Stone (Orwo Col.)	Shri Dilip Dutta, M/s Twin Films, Cuttack	Rs. 54,000/-
	6.	Lock Out (B&W)	Shri N.M. Baruah, M/s Do Ro Me Films Jorhat, Assam	Rs. 17,052/-
	7.	Wood Carvings of Orissa (Orwo Col.)	Shri Dilip Dutta, M/s Twin Films, Cuttack	Rs. 54,000/-
1979-80	1.	Dashratha Rajendra Prasad (Colour)	Shri Arvind Kumar Sinha, M/s Kala Srishti, Bombay	Rs. 1,74,557·57
	2.	Ode to the Child (B&W)	Shri Prakash Jha, M/s Chalchitra, Bombay	Rs. 25,000/-
	3.	Patachitra(Orwo Col.)	M/s Shankar Ghosh, Calcutta.	Rs. 75,000/-
	4.	Kendu Leaf (Fuji Col.)	M/s Satyabhama Films, Cuttack	Rs. 80,000/-
	5.	Mehnat Aur Manzil (Orwo Col.)	Shri. Braj Bhushan, M/s Chitrashram, Bombay	Rs. 60,000/-
	6.	Pankaj Mullick (Orwo Col.)	M/s Kalatak, Bombay	Rs. 90,000/-
1980-81 (Upto 31st January, 1981)	1.	Bijli Kare Andhera (Fuji Col.)	Shri Amrit Nahata, New Delhi	Rs. 65,000/-
	2.	Unchain the Woman (B&W)	Shri. Narpendra Mohla, M/s V.B. Picture, Bombay	Rs. 25,000/-
	3.	Homoeopathy the Humane Medicine (Col.)	M/s S.H. Productions, Bombay.	Rs. 70,000/-
	4.	The Way to the Village (B&W)	Shri R.C. Sanghavi, M/s Cinegraph Association, Ahmedabad.	Rs. 65,250/-
	5.	The Bedias (Fuji Col.)	M/s Chan Enterprises	Rs. 90,000/-
	6.	Just Plain Facts (B&W)	Shri Ezra Mir, M/s India Film Enterprises, Bombay	Rs. 50,000/-
	7.	Abhishap (Orwo Col.)	M/s Meenakshi Film Productions, New Delhi.	Rs. 76,000/-
	8.	Apna Hath Jangan Nath (Colour)	Shri Satish Kadrakar, M/s Filmikar, Bombay	Rs. 28,000/-

Report of Working Group on Tribal Development

2097. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Ministry received the recommendation relating to his Ministry from the Ministry of Home Affairs regarding the administration of Justice in tribal areas of the country according to the Report of the Working Group on Tribal Development during medium term plan, 1978-83;

(b) if so, the recommendations thereof and the measures taken by

his Ministry on the basis of the said recommendations so far;

(c) whether his Ministry has asked the States to formulate the procedure according to the need of the tribal areas and the people to give simple and quicker administrative justice; and

(d) if so, the details thereof and the steps taken by the States so far?

THE MINISTER OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) No, Sir.

(b) to (d). Does not arise.

हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि० का उत्पादन

2098. **श्री निहाल सिंह**: क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली, स्थित हिन्दुस्तान नाशकमार कारखाने का गत तीन वर्षों का, वर्ष वार उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कारखाने का उत्पादन बढ़ाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कारखाने द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया और इस कारखाने ने बोनस के रूप में अपने कर्मचारियों को वर्षवार कितनी धनराशि का भुगतान किया ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि० की दिल्ली फैक्टरी में उत्पादन

(टन में)

मद उत्पादन	1977–78	1978–79	1979–80
तकनीकी डी० डी० टी०	3024	3119	3372
फार्मुलेटिड डी० डी० टी०	5491	5758	5761

(ख) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल मिला कर कम्पनी द्वारा कमाया गया शुद्ध लाभ और कर्मचारियों को अदा किया गया बोनस वर्षवार निम्न प्रकार था : —

(लाख रुपयों में)

	1977–78	1978–79	1979–80
शुद्ध लाभ	36.56	92.45	80.49
बोनस	17.43	17.46	11.62

परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण

2099. **श्री निहाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे क्या कारण हैं जिन से सरकार ने परेल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध का अधिग्रहण किया था और उस समय ये कम्पनियां लाभ में चल रहीं थीं अथवा घाटे में; और

(ख) इन कम्पनियों के प्रबन्ध का अधिग्रहण किये जाने के समय उन्हें कितना मुआवजा दिया गया और वर्तमान में इन कंपनियों की क्या स्थिति है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इन दो कम्पनियों के प्रबन्ध का अधिग्रहण जनहित में किया गया था । सरकार की इस नीति के अनुसार की तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के बाटलिंग, परिवहन, विपणन तथा वितरण के संसाधनों के स्वामित्व तथा संचालन को भी उत्तरोत्तर राज्य में निहित किया जाए तथा इस के द्वारा उन्हें इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह आम लाभ के लिए उपभोगी हो । कम्पनी द्वारा दिये गये लेखों की संवीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने की थी । जिस तिथि को इन के प्रबन्ध का अधिग्रहण किया गया था इन कम्पनियों की शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) नकारात्मक थी ।

(ख) प्रत्येक उस माह के लिए जिस में कि इन का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित रहा परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को 750 रुपये तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड को 250 रुपये की धनराशि दी जानी थी। चूंकि इन कम्पनियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकद्दमा किये जाने के कारण मामला न्यायाधीन है इस कारण उन्हें अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

कौसन गैस कम्पनी का अधिग्रहण

2100. **श्री निहाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा कौसन गैस कम्पनी का 26 मई, 1979 को अधिग्रहण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस समय कम्पनी में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और क्या कम्पनी उस समय लाभ अर्जित कर रही थी या हानि उठा रही थी और हजनि (मुआवजे) के रूप में सरकार को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिग्रहण किये जाने के समय, कौसन गैस कम्पनी में 242 कर्मचारी काम कर रहे थे । भूत-पूर्व कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण-पत्रों के अनुसार, कम्पनी के अधिग्रहण किये जाने से पूर्व, कम्पनी घाटे में चल रही थी । इस कम्पनी के अधिग्रहण करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इस कम्पनी को 10,000 रुपये की राशि दी जानी थी ।

मथुरा में एक औद्योगिक एकक की स्थापना करनी

2101. **श्री निहाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री मथुरा औद्योगिक

कम्प्लैक्स स्थापित किये जाने के बारे में 2 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2084 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा में एक औद्योगिक एकक की स्थापना के बारे में गठित समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राकेश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

Monthly requirement of Petroleum Products in Haryana

2102. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the total kilo litres of kerosene oil, petrol and diesel Haryana needs monthly; and

(b) the total kilo-litres of kerosene, petrol and diesel being supplied in a month in Haryana?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) During the last five months, the Government of Haryana had indicated the demand of High Speed Diesel (HSD) and Kerosene for the State as under:—

	Figures in kilo litres	
Month	*HSD*	*Kerosene*
October' 80	3600	—
November' 80	—	—
December' 80	30000	9000
January' 81	34000	9000
February' 81	30000	7000

In so far as petrol is concerned, there is no system of making month-wise allocations from Central Government. The product is moved to different supply zones by the oil companies based on historical sales and other relevant factors, such as product availability, movement capacity, etc.

(b) The following are the details of sales of HSD and kerosene in Haryana during November, 1980 to January, 1981:—

Figures in Kilo Liters

	SALES	
Month	HSD	Kerosene
Novembe'r80	33287	8340
December '80	32791	8507
January '81	29288	8084

Shortage of Cooking Gas in Haryana

2103. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Haryana is facing acute shortage of cooking gas; and

(b) steps taken or propose to be taken to make the requirement and new agencies to be set up during 1981?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) There is some shortage in the supply of cooking gas in Haryana.

(b) Necessary steps have been taken to move the product from alternate sources to meet the demand in the State to the extent possible. The plans for setting up of new gas agencies have been drawn up by oil companies on a financial year basis. It is planned to set up 12 new gas agencies in the State during 1981-82

Quota of Diesel and Kerosene to Haryana

2104. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the diesel and kerosene quotes demanded by Haryana Government for the 3rd and 4th quarter of 1980;

(b) the actual quantity of these commodiates made available to the State; and

(c) the difference between the allocation and the supply made?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) The Government of Haryana had not made any specific demand of diesel and kerosene for the third and fourth quarters of 1980. But they had indicated, for the months of Oct. '80 and December '80, the demand of high speed diesel oil as 30,000 tonnes and 25,000 tonnes respectively. With regard to kerosene, the State Government had demanded an allocation of around 7,000 tonnes for December, 1980, only.

(b) and (c). The allocations/sales of diesel and kerosene, as also the difference between the two, for the two quarters is as under:—

Figures in metric tonnes

Period	High Speed Diesel oil			Kerosene		
	Allocation	Sales	Difference*	Allocation	Sales	Difference*
Third quarter of 1980 (July-Sept.'80)	70,600	69,592	(—)1,008	18,030	18,010	(—)20
Fourth quarter of 1980 (Oct.—Dec.'80)	72,780	80,840	(+)8,060	18,040	19,540	(+)1,500

*between allocation and sales

Setting up of more Thermal Power Stations

2105. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up six more thermal power stations in the country;

(b) whether the places where those stations will be set up have been identified;

(c) if so, whether necessary survey has been conducted and estimates formulated;

(d) if so, what will be the total expenditure involved in each stations;

(e) whether Government propose to seek foreign assistance for setting up those stations; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (d) Besides the various thermal power stations planned to be set up by the State Electricity Boards and other utilities, feasibility reports in respect of the following four regional Super Thermal Power Stations proposed to be taken up in the Central sector have been prepared and are under techno-economic appraisal by the Central Electricity Authority:—

Name of the Project	State	Total expenditure for the Proposed ultimate capacity)
		(Rs. in crores)
Kahalgaon (2800 MW)	Bihar	1647.17
Pench (840 (MW)	Madhya-Pradesh	477.55
Talcher (2800 MW)	Orissa	1472.31
Waidhan (300 MW)	Madhya-Pradesh	1364.63

The National Thermal Power Corporation have also initiated feasibility studies for the setting up of a super thermal power station at Manguru in Andhra Pradesh and for another Super Thermal Power Station in the Singrauli region.

(e) and (f) Soviet Assistance is being made available for partly financing the first stage development of 1000 MW generating capacity of the Waidhan project along with its associated transmission and coal facilities. Details of the Soviet Assistance have not yet been finalised. No proposal regarding foreign assistance for the other project has been considered so far.

Absorption of Casual Artists

2106. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether any plan for permanent absorption of the Casual Artists into the regular services has been drawn up by the AIR/Doordarshan; and

(b) if so, the details thereof and the number of Casual Artists who have been absorbed into regular service so far during the last 3 years at each station of the AIR and Doordarshan?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) Broadly speaking, the present citeria followed for regularisation of casual artists both in AIR and Doordarshan are is follows:—

Casual Artists of All India Radio and Doordarshan who had been booked for (i) 200 days in any one financial year during the years 1974-75 to 1979-80, or

(ii) 365 days during any of the two blocks of the three financial years, viz., 1974-77 or 1975-78 are to be considered for regularisation against vacant posts of staff artists, subject to their being educationally and otherwise qualified for holding the posts against which they are to be regularised.

The information regarding the number of casual artists who have been absorbed into regular service during the last three years at each station of All India Radio/Doordarshan is given in the Statement I & II.

Statement—I

ALL INDIA RADIO

Statement showing number of Casual Artists regularised in All India Radio

S. No.	Station/Office	Category of staff artist	No. of persons regularised
1	2	3	4
1.	Vividh Bharti Service, AIR, Bombay	General Assistant	21
2.	AIR, Delhi	Copyist	1
3.	DDK, Delhi	General Assistant	1
4.	External Services Division, AIR, Delhi.	Copyist	1
5.	Commercial Broadcasting Service, AIR, Delhi	General Assistant	1
6	AIR, Allahabad	Copyist	1
7.	Monitoring Service, Simla	Monitors (Indian Language)	16
8.	DDK, Delhi	Production Assistant	4
9.	News Services Division, Delhi	Newsreader-cum-Translator	5
10.	AIR, Gorakhpur	Do.	1
11.	AIR, Kohima	Assistant Editor (Tribal Dislect)	7
12.	AIR, Dibrugarh	Do.	2
13.	AIR, Tewang	Do.	1
14.	AIR, Tezu	Do.	1

1	2	3	4
15.	AIR, Agartala	Announcer	1
16.	AIR, Delhi	Do.	1
17.	CBS, AIR, Delhi	Do.	1
18.	External Services Divn., AIR, Delhi.	Do.	4
		TOTAL :	70

Statement—II

DOORDARSHAN

Statement showing the Total No. of Long Term Casual Artists Regularised during the last three Years

S. No.	Kendra	No. of casual artists regularised
1	2	3
1.	Bombay	18
2.	Calcutta	11
3.	Lucknow	33
4.	Srinagar	21
5.	Jullundur	20
6.	Delhi	17
7.	Madras	11
8.	UDK, Delhi	9
9.	Gulbarga	2
10.	Hyderabad	6
11.	Cuttack	9
12.	Raipur	2
13.	Muzaffarpur	2
14.	Ahmedabad	4
15.	Jaipur	3
16.	Sambalpur	1
	TOTAL :	197*

*This includes 28 persons for whom offers of regularisation were issued but who had in the meantime got absorbed in jobs in other organisations

Setting up of a field Publicity unit at Hamirpur

2107. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether a Field Publicity Unit has been sanctioned at Hamirpur in Himachal Pradesh; and

(b) if so, the likely date by which it would be set up?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) One Field Publicity Assistant has already been posted. As soon as accommodation is available, full complement of staff would be posted.

Names of New Relay Stations/Transmitters of Doordarshan in North Region

2108. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the names of the places where new relay stations/transmitters of Doordarshan have been sanctioned in the Northern regions; and

(b) the likely dates by which they would be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) During the Sixth Plan Period (1980-85), it is proposed to set up two TV relay transmitters in the Northern region, one at Kasauli and the other at Varanasi.

(b) These relay centres are expected to be ready by 1984-85.

Coal-based Fertilizers Plants

2109. SHRI RAMA CHANDRA RATH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the name and number of the coal-based fertilizer plants of our country;

(b) whether some of them are facing certain teething problems;

(c) if so, the remedial measures his Ministry has taken or proposed to be taken to overcome the equipments

problems of Talcher and Ramagundam fertilizer plants;

(d) when such fertilizer plants are going to attain stability and sustained production; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) There are two coal based fertilizer plants—one at Talcher in Orissa and the other at Ramagundam in Andhra Pradesh—owned by the Fertilizer Corporation of India Limited (FCI).

(b) Both are facing teething problems.

(c) to (e). During the first three months after they went into commercial production with effect from 1-11-1980, the plants faced problems in the waste heat boilers of the gasifiers, the air separation unit, the raw gas compressors and the Rectisol sections. These problems have been identified and remedial action taken. It is expected that the plants would attain stability in production after they are operated for some months.

Setting up of mini-hydel plants

2110. SHRI RAMA CHANDRA RATH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government has a proposal to set up some mini-hydel plants in the country during 1981-82;

(b) if so, the number of such plants that are going to be set up in Orissa; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Government attaches great importance to the installation of mini/small hydel units utilising low heads, generally available at the irrigation canal falls etc. This is an activity that would have to be undertaken by the respective States in which the potential exists. The Ministry of Energy has advised the States to explore the possibilities in this regard, and has also offered to make available to them the services of experts, and any other technical assistance that may be required. Presently, the following low head mini/small schemes are under execution in the country:—

Name of the Scheme	Installed Capacity (MW)	State	Expected date of commissioning
1. Western Yamuna Canal	48 MW	Haryana	1984-85
2. Anoopgarh . .	9 MW	Rajasthan	VII Plan
3. Lower Mettur . .	120 MW	Tamil Nadu	VII Plan
4. UBDC St. III . .	45 MW	Punjab	VII Plan
5. Dhansiri . . .	19·95 MW	Assam	VII Plan

At present, the total generating capacity of such schemes in operation in the country is about 300 MW.

(b) No proposal has been received from the Govt. of Orissa/Orissa State Electricity Board for setting up of mini/small hydel plants in the State.

(c) Does not arise.

Loss in Fertilizer production

2111. SHRI B. V. DESAI:

SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether fertilizer production which has suffered a colossal loss this year owing to numerous factors, including the Assam agitation, is expecting to pick up subsequently;

(b) if so, whether it is also a fact that an all time high production of 2.26 lakh tonnes of nitrogenous fertilizer valued at Rs. 100 crores was recorded during December last year;

(c) if so, whether this encouraging trend in fertilizer production is expected together further momentum with the recommissioning of Goa fertilizer plant which had to be shut down five months back;

(d) if so, whether all the fertilizer projects have started increasing their production;

(e) if so, to what extent; and

(f) to what extent fertilizer production will rise during 1981-82?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c). Yes, Sir.

(d) and (e). Production in the fertilizer plants which were affected earlier by limitations of feedstock inputs and power has shown considerable improvement during the past few months except in the case of Gorakhpur and Namrup plants. These plants are still affected by inadequate availability of feedstock.

(f) The production of fertilizers in 1981-82 is expected to show a marked improvement over that in 1980-81.

Aid Programme on Hindustan Petroleum Corporation

2112. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindustan Petroleum Corporation has enlarged its aid programme for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students;

(b) if so, the total number of scholarships proposed to be given at the University level;

(c) whether such scholarship will be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students studying in the Universities of Orissa; and

(d) if so, the total number of scholarship proposed to be given to them?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) All the scholarships are for college-going SC/ST students. This scheme was started in 1976 with 6 scholarships. This number has been increased to 25 for the academic year 1980-81.

(c) and (d). At present, this scheme covers only Refinery areas viz. Bombay and Vizag. When the scheme is further extended it may be possible to cover other areas including Universities in Orissa.

M/s. Mackinnon Mackenzie

2113. SHRI K. LAKKAPPA:

SHRI H. N. GOWDA:

SHRI D. M. PUTTE GOWDA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s. Mackinnon Mackenzie, a leading shipping company is heading towards

bankruptcy and if so, full details thereof;

(b) what are the present assets and liabilities of the company;

(c) the particulars of major shareholders and details of shares held by them;

(d) who is responsible for mismanagement and bringing huge losses to the company;

(e) whether Government have ordered any inquiry into the affairs of the company; and

(f) if so, what action Government propose to take to safeguard the interest of the employees?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). The information is furnished in Statement. It will be seen therefrom that while the Net Worth of the Company as per Balance Sheet as at the end of December, 1979 was in the negative it would not be correct to surmise at this stage that the Company is heading towards bankruptcy.

(d) It is observed from the reports of the Board of Directors attached to the audited balance sheets for the last three years that huge losses incurred by the company were mainly due to adverse operating conditions.

(e) No enquiry has been ordered into the affairs of this company by the Department of Company Affairs.

(f) Does not arise.

Statement

Part (a) Financial position of M/s. Mackinnon Mackenzie & Co. Ltd. as per its balance sheet as at 31-12-1979.*

	Rupees in lakhs
Share capital	248·45
Reserve and Surplus	119·71
Less miscellaneous exependiture and accumulated loss.	368·16
	476·67
	(—)108·61

PART (b) Assets and libilities of the company as per its balance sheet as at 31-12-1979.*

Liabilities	Rupees in lakhs
Share capital	248·45
Reserve and Surplus	119·71
Secured Loans	1298·75
Unsecured Loans	104·47
Current liabilities	498·46
Provisions	11·29
	2281·13

Assets	Rupees in lakhs
Fixed assets	1254·47
Investments	12·76
Current assets	387·40
Loan & advances	149·83
Miscellaneous expenditure	200·48
Profit and loss account	276·19
	2281·13

*Balance sheet for 1980 is not yet due.

PART (C) LIST OF (MAJOR) SHAREHOLDERS HOLDINGS 2000 SHARES AND ABOVE

M/S. MACKINNON MACKENZIE

Sl. No.	Name of shareholders	No. of Shares
1.	Life Insurance Corporation of India	1,00,000
2.	Unit Trust of India	72,650
3.	Industrial Credit & Investment Corpn. of India	54,540
4.	Industrial Investment Trust	2,750
5.	United India Fire & General Insurance Co. Limited	54,450
6.	National Insurance Co. Limited	45,340
7.	Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd.	36,300
8.	New India Assurance Co. Limited	22,700
9.	General Insurance Corporation Limited	22,700
10.	Bank of India	81,700
11.	United Bank of India	68,100
12.	Central Bank of India	39,350
13.	British India Steam Navigation, U. K.	9,99,990
14.	Mr. Anant Prakash Saxena	2,000
15.	Mr. Chandrason Valabdas Jangla	2,000
16.	Mr. Chhedilal Agarwal	15,350
17.	Mr. Chandulal Vithaldas Shah	13,300
18.	Mr. H. H. Yeshwantrao Mukhe	5,000
19.	Mr. Harakchand Valljee Gala	17,150
20.	Mr. Indukumar Sanghavi	3,000
21.	Mrs. Indira Chandulal Shah	14,100
22.	Mr. M. Anant Rao	2,000
23.	Mr. Nanigopal Choudhury	2,000
24.	Mrs. Nirmala Harakchand Gala	16,150
25.	Mr. Prakash Mathur	3,200
26.	Mr. Salil Ghose	2,500
27.	Mr. T. N. Javeri	4,000
28.	Mr. Viond Ratilal Dangarwala	10,000
29.	Mr. Vijay Kumar Chanderlal	3,000
30.	Balilal Mookerjee & Co. Pvt. Limited	5,000
31.	Alux Miller Shapenendler Pvt. Limited	5,000
32.	Industrial Investment Trust Limited	2,750
33.	Gangas Rolling Industries Pvt. Ltd.	2,500
34.	Mrs. Alia N. Latif, and Mr. Nazir Latif	4,000

कोरबा, मध्य प्रदेश में पाए गए कोयले में राख के अंश

2114. श्री दया राम शाक्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: कोरबा क्षेत्र की खुली कोयला खानों में पाए गए कोयले में राख का कितना अंश है और क्या यह कोयला ताप-बिजली घरों के लिए उपयुक्त है और यदि नहीं, तो क्या विद्यमान बिजली स्टेशनों की मशीनरी को कोयले की उक्त किस्म के योग्य बना लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : कोरबा कोयला क्षेत्र में मानिकपुर और कुसमुंडा यह दो ओपेनकास्ट खानें हैं । इन खानों का आयोजन और डिजाइन बनाने का काम मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से परामर्श कर के किया गया था—इस बिजली बोर्ड के खान मुहाना ताप बिजलीघर हैं जिन की डिजाइन इस घटिया कोयले को जलाने के लिये विशेष रूप से बनाई गयी है ।

इन दोनों कोयला खानों के कोयले में राख नीचे दिया गया है :—

कोलियारी/सीम का नाम	राख का प्रतिशत
(1) मानिकपुर ओपेन कास्ट (जटराज सीम)	31.4 से 38.8
(2) कुसमुंडा विस्तार	
(क) अपर कुसमुंडा सीम	42.6 से 49.3
(ख) लोअर कुसमुंडा सीम	38.0 से 44.3

Polyster plants planned in joint sector

2115. SHRI R. L. BHATIA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow new polyester fibre production capacity in the joint sector;

(b) if so, the broad details of the polyester units planned in the joint sector — their location and annual production;

(c) how long will it take for these units to come up; and

(d) the details of the capacity already licensed to the private sector during the current year by way of expansion of the existing capacity or installation of new units?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Final decision on proposals for setting up of additional capacity for the manufacture of polyester staple fibre has not been taken yet.

(b) and (c). Do not arise.

(d) No capacity has yet been licensed during the current year.

Demand by Bihar Government to enhance kerosent quota

2116. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Bihar Government has approached the Central Government to enhance the quota of Kerosene oil to that State;

(b) if so, whether Central Government has got its agency to supervise the distribution system of the Kerosene oil;

(c) whether Government are aware that in the remote areas where the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are residing, there is a acute shortage of Kerosene oil; and

(d) if so, what practical steps have been taken by Government for the proper arrangements in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). This Ministry makes monthly allocation of kerosene to all States, including Bihar. Distribution of the product within the State between different areas, including the remote areas where the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are residing, is the responsibility of the concerned State Government.

The State Governments have been advised to ensure equitable distribution of the product between the different areas and to take action against those indulging in malpractices like hoarding and black-marketing.

State and District Level Coordinators of the oil industry who are functioning at State Capitals and headquarters of revenue districts respectively, maintain constant liai-

son with the State and district authorities and generally assist them in the proper and equitable distribution of kerosene according to the priorities evolved by State Government.

Soviet Union's offer for collaboration in India's power production

2117. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Soviet Union has offered wide-ranging collaboration in India's power production;

(b) if so, whether it is also a fact that Soviet Union is not the only country to have shown interest in India's vast power production market but offers have also been received from other countries; and

(c) if so, the names of those countries and the decision taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). Under the Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Republic of India and the Union of USSR, signed between the Prime Minister of India and President Brezhnev in December, 1980, U.S.S.R. financial assistance has been committed for a variety of projects including the construction of an integrated thermal power plant with matching coal-mining facilities and associated transmission system for an installed capacity of 1000 MW with the possibility of expansion for future upto 3000 MW.

Other countries have also made indicate offers or have shown interest in supply of power generating equipment linked with export credits, or suppliers' credits and/or partial governmental assistance. Such countries are United Kingdom, Romania and Poland. Individual foreign companies have also made exploratory offers for supply of equipment such as M/s. Mitsui and Co. of Japan, Deutschi Babcock of West Germany, Alsthom-Atlantique of France and Ansaldo of Italy.

No country has so far offered substantial financial assistance to cover the cost of import of equipment and rupee resources for construction of the project. No decision has been taken by the Government as yet on any of the above indicative proposals.

Amount spent for rural electrification

2118. SHRI K. A. SWAMI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the funds spent by Rural Electrification Corporation in the last five years, giving details year-wise;

(b) the funds allotted to be spent for the next five years; and

(c) the annual expenditure by the Rural Electrification Corporation on staff, salaries travel and administrative expenses for the past five years, giving annual break-up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The funds disbursed by Rural Electrification Corporation during the last 5 years (1975-76 to 1979-80) are given below:—

(Rs. in lakhs)

Year	Loan amount disbursed
1975-76	7342
1976-77	8822
1977-78	11299
1978-79	15610
1979-80	16705
Total	59778

(b) The Planning Commission has allocated an outlay of Rs. 880 crores to Rural Electrification Corporation, for the Sixth Five Year Plan (1980-85) as per details given below:—

	(Rs. in crores)
(i) Normal programme of Rural Electrification Corporation	595·00
(ii) Special Project Agriculture (SPA)	210·00
(iii) Rural Cooperatives . .	33·00
(iv) System Improvements .	42·00
Total:	880·00

(c) The annual expenditure incurred by the Corporation on staff, salaries, travel and administrative expenses, for the past five years 1975—80) is as follows:—

Year	(Rs. in lakhs)
1975-76	119
1976-77	147
1977-78	182
1978-79	192
1979-80	220
Total:	860

Assistance to industries to set up their own Power Generation Units

2119. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Central Government have under consideration any scheme of financial assistance to the State Governments which are currently suffering from power shortage to permit the industries to set up their own power generating units and the Centre would subsidise the cost;

(b) whether the States of Rajasthan, West Bengal and Bihar are worst hit so far as the availability of power is concerned for industries;

(c) if so, the nature of decision taken and the amount of help that would be made available to the State Governments; and

(d) if not, in what way Government propose to deal with the difficulties of the industries in the States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The existing policy of the Government in respect of captive power plants is that where in industries process steam is required or where waste heat is available, captive generation capacity should be encouraged in accordance with the "total energy concept". Keeping in view the shortage of capacity to meet the power demand in the country and the need to insulate productive sectors like core industries of steel, fertilisers and aluminium, Government have recently been more sympathetic in considering proposals for setting up captive power plants based on coal in such units. Necessary financial resources for this purpose will have to be raised by the industries either internally or through various financial institutions.

(b) to (d). Industries located in Bihar and West Bengal are affected due to power shortage while the impact of the temporary power shortage on industries in Rajasthan has not been assessed. A number of short term and long term measures have been taken to improve the power availability in the country. These measures include:

(i) better management of load demand by staggering of holidays, shifting of loads from day time to night etc.

(ii) accelerated addition of new generating capacity in the system;

(iii) detailed monitoring of the construction schedules of all the on-going projects to ensure expeditious completion of the projects; and

(iv) close monitoring of operation of existing stations is being undertaken and assistance has been extended to the State Electricity Boards to enable them to improve the operation and maintenance of existing thermal power Plants with a view to maximising generation from the existing installed capacity.

Alleged racket in Coal in Dhanbad Area

2120. SHRI SATISH AGARWAL:
SHRI S. M. KRISHNA:
SHRI M. RAMGOPAL REDDY:
SHRI CHITTA MAHATA:
SHRI KRISHAN CHANDRA HALDAR:
SHRI R. L. BHATIA:
SHRI DHARAM VIR SINHA:
SHRI N. K. SHEJWALKAR:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a big racket in coal in the Dhanbad area involving crores of rupees has been unearthed;

(b) whether it is a fact that huge sale and delivery orders were secured in the names of fake firms of coal users and they were sold in black market;

(c) how many persons have since been arrested and the details of the modus operendi followed in this case; and

(d) what steps have been taken by Government to check similar incidents in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). Raids were conducted by CBI from December 1979 to February 1980 and three cases were registered by them for investigation into alleged release of a huge quantity of hard coke in favour of non existing and fictitious parties on the basis of forged delivery orders. In this connections, CBI have so far arrested 17 persons, and out of them, two are officers of BCCL. The cases are still under investigation by CBI.

(d) Vigilance in the Sales and Marketing Divisions of Coal India Ltd. and BCCL has been tightened in order to check the recurrence of such cases in future. Government has also formulated a policy for the rotational transfer of officers and staff posted in the sensitive positions at fixed intervals.

Decision regarding Introduce of Commercial Channel in T.V

2121. SHRI SATISH AGARWAL:
SHRI K. MALLANNA:
SHRI N. K. SHEJWALKAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to introduce commercial channel in T.V. soon;

(b) if so, which T.V. stations of the country will have this facility;

(c) whether Government have worked out the tariff for such advertisements and the time that will be allotted for this purpose; and

(d) whether Government have considered the impact that the new service will have on AIR commercial service?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD

BEN M. JOSHI): (a) to (d). The matter is under study. The details have yet to be worked out.

Britain's help to Coal India Limited to develop Coal Mines

2122. SHRI SATISH AGARWAL:
SHRI K. P. SINGH DEO:
SHRI K. PRADHANI:
SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI:
SHRI JANARDHANA POOJARI:
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:
SHRI N. K. SHEJWALKAR:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Government of Britain has agreed to help the Coal India in a big way for the integrated development of coal mines in our country;

(b) whether they have also agreed to give the benefit of their advanced technology in the field of coal development; and

(c) if so, the precise plans that they have offered in this respect and what is Governments decision in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Government of U.K. have during the last five years given assistance amounting to $ 21 million to finance import of sophisticated mining equipment from U.K., prepartion of feasibility reports for two mines and training of technical personnel in U.K. as well as in India.

Allocation of Bitumen

2123. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the reasons for reducing the allocation of bitumen from 84500 metric tonnes in 1979-80 to 75000 metric tonnes in 1980 for Tamil Nadu, while in the case of all other States and Union Territories the bitumen allocation has been increased in 1980 as compared to 1979;

(b) the quantum of advance payment made by the State Government to I.O.C. towards the cost of bitumen and since when this amount remains unadjusted; and

(c) the steps proposed to be taken for increasing the allotment of bitumen to Tamil Nadu?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) The allocations of bitumen for 1980-81 to all the Staes were based on the average sale of the product in the three preceding years. The allocation for Tamil Nadu for 1980-81 was accordingly kept at 75,000 tonnes on the basis of figures of three years rather than the figure for 1979-80 alone.

(b) An amount of Rs. 14.13 crores, which includes the increased price of bitumen, was received from the State Government as advance towards the cost of bitumen by the Indian Oil Corporation. The balance pending for adjustments at present is Rs. 4.09 crores.

(c) It is not possible to increase the allocation of bitumen for Tamil Nadu in 1980-81 in view of constraints of its availability at present.

Waiting Lists for Gas connection in Metropolitan Cities

2124. PROF. NARAYAN CHAND PARASHER: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state the number of persons registered for gas connections who were still on the waiting list as on 31st January, 1981 in the Metropolitan cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): The number of

persons registered for gas connections in the waiting lists of the dealers of different oil companies as on 31st January, 1981 in the metropolitian cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras approximately is as follows:-

Delhi	414,000
Bombay	342,500
Calcutta	49,000
Madras	113.000

फिल्म समारोह में दिखाई जाने वाली फिल्मों में पूर्वप्रदर्शित फिल्म का शामिल किया जाना

2125. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में आयोजित आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रतियोगी वर्ग में एक ऐसी विदेशी फिल्म, जो विदेशी समारोह में पूर्व प्रदर्शित की जा चुकी थी, शामिल की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से प्रतियोगी समारोह के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है; और

(ग) क्या सरकार ने इस को प्रतियोगिता में शामिल करने की परिस्थितियों की जांच की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नियम का भारत के आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के विनियमों में, जो फिल्मों को समारोह में प्रविष्ट करने की इच्छा रखने वालों को भेज दिए गए थे, विशिष्टि रूप से उल्लेख कर दिया गया था । इस के अतिरिक्त, फिल्मों के लिये बातचीत के दौरान इस की ओर स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था । तथापि, मिस्टर स्लाटर्ज सिल्वर जुबली नामक फिल्म को प्रविष्ट करने वाले निर्माता ने समारोह प्राधिकारियों को इस बात से सूचित नहीं किया कि इस फिल्म ने और कहीं भी प्रतियोगिता की थी । जैसे ही इस बात का पता चला कि इस फिल्म ने कहीं और भी प्रतियोगिता की थी, इस को प्रतियोगिता के अयोग्य कर दिया गया और जूरी को सूचित कर दिया गया कि वह पुरस्कारों के लिए इस फिल्म पर विचार न करें ।

Setting up of Drug Factory at Bhubaneswar

2126. SHRI RAMA CHANDRA RATH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether a drug factory is going to be set up at Bhubaneswar;

(b) if so, when this factory is likely to come up; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) The Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, a public sector drug company has proposed to set up a drug formulation unit at Bhubaneswar, in Orissa State, in association with Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Limited (IPICOL). No final decision has yet been taken.

(b) and (c) Do not arise.

French Expertise to set up a Tidal Plant

2127. SHRI JANARDHANA POOJARI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are considering to seek French expertise to set up a tidal plant;

(b) whether the site for its location has been decided;

(c) whether Government have made study of the project; and

(d) if so; what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): ,a(to (d). The Government have approved a proposal for taking up investigations and studies in the Gulf of Kutch, Gujarat to establish the feasibility for generating energy from tidal waves, at an estimated cost of about Rs. 2.18 crore. The project envisages utilisation of foreign technical assistance in areas where sufficient expertise is not available within the country. Since there is an agreement between the Central Electricity Authority and the Electric De France (EDF), Paris for collaborative effort in the efild of power development, the possibility of securing assistance of French Experts to assist in the planning of the proposed investigations is being explored.

Steps taken/proposed to be taken to develop AIR Darbhanga

2128. SHRI HARINATH MISHRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the steps that have already been taken or are proposed to be taken during the current financial year to develop AIR, Darbhanga with regard to the following issues, namely:—

(i) filling up the post of Director and other sanctioned posts;

(ii) providing the employees with residential accommodation;

(iii) increasing the present transmission capacity so as to cover the entire Maithili-speaking belt of Bihar and Nepal Terai;

(iv) in view of the extremely irregular supply of electricity from the electricity Board, to have its own independent generator which may ensure regular supply of electricity all the 24 hours; and

(v) increase the duration of independent Maithili programmes?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (i) Most of the sanctioned posts including that of Station Director at AIR Darbhanga have been filled up. Action for filling up the remaining posts is also in progress.

(ii) Provision of Rs. 500 lakhs has been made in the Sixth Plan (1980—85) for the construction of additional staff quarters at existing centres of A.I.R. Darbhanga will also be considered along with other centres on the basis of relative priority.

(iii) Darbhanga station of AIR was set up to meet the aspirations of the Maithili speaking population of the State and not to provide Maithili service to transborder areas. As such there is no proposal for the present to increase the power of the Darbhanga transmitter.

(iv) A proposal for the provision of a standby diesel generator for Darbhanga Station is being considered.

(v) The existing duration of time allotted to the programmes of Maithili language is considered adequate and there is no proposal to increase the same.

Development of Darbhanga Radio Station

2129. SHRI HARINATH MISRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring about an all-round development in the working of the AIR, Darbhanga during the Sixth Plan period;

(b) if so, what steps have been taken or are proposed to be taken in this connection; and

(c) if not, the reason therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) to (c): Darbhanga station of All India Radio is a fullfledged station and there is no proposal in the Sixth Plan for development in the working of the station. A proposal for the provision of a diesel generator as a standby power supply source is, however, being considered.

Commissioning of Barauni Refinery

2130. SHRI HARINATH MISRA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the immediate gain from the commissioning of Barauni Refinery and the pumping of crude from the Narengi oilfields of Assam;

(b) how far it will reduce the oil import bill during the current financial year;

(c) whether prices of petroleum products will be kept within reasonable limits with a view to maintaining the economy on better footing; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) With the resumption of pumping of crude from Narengi pumping station, Barauni and Bongaigaon refineries have resumed production. The increased product availability as a result thereof will help not only in meeting the demand in the area but also in saving foreign exchange on import of products.

(b) It is estimated that with the resumption of operations at Bongaigaon and Barauni refineries, about 567000 tonnes crude is estimated to be processed during the current financial year. The products corresponding to this crude run are estimated to be valued at Rs. 125 crores.

(c) and (d): Yes, Sir. The prices of kerosene and inputs for the fertilizer industry like naphtha and furnace oil have been kept low with a view to keeping prices of essential commodities at the minimum level. The prices can be expected to stabilise when increases in the indigenous production are higher than increases in the demand for petroleum products. Improvements in the production/generation of coal and power would also help relieve the burden on the oil industry.

Staffing Pattern of Programme Staff of Doordarshan

2131. SHRI RAM AWADH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to lay a statement showing:

(a) the details of the Staff Inspection Unit report regarding staffing pattern of Programme Staff of Doordarshan;

(b) what are the details of the recommendations made by the Rationalization and Review Committee of Doordarshan on the basis of S.I.U.;

(c) the reasons for delay in implementing its recommendations; and

(d) when these are expected to be implemented?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a): The report contains norms for providing staff at the seven main Doordarshan Kendras. The norms for programme staff are based on programme commitments, studio and technical facilities available at a Kendra and other related operational factors. As per these norms, there was an overall shortage of programme staff including staff artists to the extant of about 8.5 per cent Additional staff has been sanctioned as per the norms.

(b) The Committee made recommendations regarding revision of fee

scales, conversion of staff artists into civil posts and also about staff structure of a Doordarshan Kendra with reference to SIU recommendations. It has suggested avenues of promotion to be made available to various categories, certain changes in their nomenclature and their reclassification into local, zonal and All India Cadres and has recommended sanctioning of selection grade to certain categories and creation of a supervisory post each in Film Editing and Second Recording areas.

(c) and (d). The recommendations required detailed examination. These recommendations by and large have now been accepted and are being implemented.

Number and details of programme staff of T.V. sent for training and workshops abroad

2132. SHRI RAM AWADH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3028 on the 9th December, 1980 regarding scholarships offered by Doordarshan for training abroad and state:

(a) how many programme staff of T.V. was sent for various trainings and workshops during the past three years;

(b) number with complete details training courses/scholarships or workshops available for programme staff from various countries for the coming one year; and

(c) how many training courses or workshops could not be utilised during the past three years with reasons for not utilising them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) 30 (including Staff Artists).

(b) Only one offer from Asia-Pacific Institute of Broadcasting Development, Kuala Lumpur for training course on Population Communication has been received so far.

(c) Offers of two training courses/workshops were not utilised: One was not considered worthwhile while the other could not be utilised due to administrative reasons.

कम्पनियों का पंजीकरण

2133. **श्री अशोक गहलोत :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1980 से दिसम्बर, 1980 के दौरान भारत सरकार द्वारा कितनी कम्पनियां पंजीकृत की गई ;

(ख) इन कम्पनियों पर सम्भवतः कितना पूंजी-निवेश किया जाएगा ;

(ग) इन कम्पनियों में संभवतः कितने व्यक्ति नियुक्त किए जायेंगे ;

(घ) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन्हें कहां-कहां स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) उन में किन-किन मदों का उत्पादन होगा और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1 मार्च, से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हिस्सों द्वारा सीमित 5213 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था ।

(ख) इन सभी कम्पनियों की कुल अधिकृत पूंजी 626.6 करोड़ रुपये राशि की थी, जो वर्तमान में, उस पूंजी की राशि की सीमा है, जो इन कम्पनियों में नियोजित की जा सकती है ।

(ग) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, इस प्रकार की कम्पनियों के लिए, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें उनके द्वारा नियुक्त किये जाने की संभावना है, की बाबत सूचना, इस विभाग को भेजा जाना अपेक्षित नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) . नवीन रूप से विनिगमित कम्पनियों के नाम व उनके पंजीकृत कार्यालयों के पते, तथा उनके उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण, उनके द्वारा उत्पादित किये जाने वाली वस्तु की प्रकृति अथवा उनके व्यापार की सामान्य रेखा सहित, इस विभाग की मासिक पत्रिका "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" में प्रकाशित किये गये हैं, जिनकी प्रतियां, संसद् भवन पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

इन कम्पनियों की वार्षिक उत्पादन (अधिष्ठापित) क्षमता की बाबत सूचना उनके वार्षिक लेखाओं में वर्णित की जानी है । तथापि, प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट नवीन रूप से पंजीकृत 5213 कम्पनियों के वार्षिक लेखे, कम्पनी अधिनियम के अनुसरण में, अभी प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं ।

Electrification of more villages during Sixth Plan period

2134. SHRI HARIHAR SOREN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to provide electricity to some additional villages in the Sixth Plan period;

(b) if so, the number of villages in Orissa proposed to be electrified during the above period;

(c) whether district level committee's are going to be constituted to review the progress of the rural electrifications programme;

(d) if so, the States where such committees have been formed; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) The draft Sixth Five-Year Plan (1980—85) envisages a target of electrifying 13.179 villages in the State of Orissa.

(c) to (e) All the State Governments have been requested to form District Level Coordination Committees for rural electrification. The States of Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal have formed District Level Coordination Committees. These committees are presided over normaly by the District Collector/Deputy Commissioner and various Developmental Agencies including the Minor Irrigation, the Zila Parishad, the Cooperative Department, Rural Industries Division, Financing Institutions etc. are represented in these Committees. States like Assam, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Nagaland and Orissa have formed Coordination Committee either at the State Level or otherwise to ensure necessary coordination at the District Level. Haryana and Punjab, having achieved cent per cent village electrification, do not feel the necessity for coordination of rural electrification programme and are concentrating their attention on pumpset energisation. The State of Karnataka does not feel it necessary to have a Coordination Committee.

Shifting of headquarters of H.F.C. to Calcutta

2135. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what steps have been taken to implement the decision to shift the Headquarters of the Hindustan Fertilizer Corporation to Calcutta; and

(b) whether he is aware that Government of West Bengal offered ten acres of land in Salt Lake City-two acres for building the office complex of HFC and eight acres for the staff quarters?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHR P. C. SETHI): (a) and (b). It was tentatively decided in March, 1979 that the headoffice of the Hindustan Fertilizer Corporation should be shifted to Calcutta. While the Corporation was on the look out for finding suitable accommodation in Calcutta to shift the headoffice, certain offers were made by the Govt. of West Bengal for providing accommodation for the office and the employees. Meanwhile, pending consideration of certain representations received by the Government against the shift, the Corporation has been advised not to make any financial commitments in this regard.

Problems of Alcohol-based industries in West Bengal

2136. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether he has received a letter of the Finance Minister, Government of West Bengal regarding the problems of the alcohol-based industries in West Bengal; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir. In a letter to Government dated 30-12-1980, the Finance Minister of West Bengal, has said that:

(i) the Government of Maharashtra and Bihar have not released any alcohol or molasses against the allocations made by the Government;

(ii) the Government of Uttar Pradesh have increased the Export Pass Fee on alcohol in two stages from Re. 0.25 to Re. 0.50 and from Re. 0.50 to Rs. 2.00 per bulk litre of alcohol, with consequential adverse effect on the economic viability of alcohol based industries in West Bengal.

(b) Government is actively pursuing with the Governments of Maharashtra & Bihar the question of release of molasses and alcohol. The Government of Uttar Pradesh have also been requested to consider the issues raised by the West Bengal Government regarding increase in pass fee.

Appointment of Foreigners as top executives of companies

2137. SHRI JAGDISH TYTLER: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the appointment of foreigners as Chief or Top Executives of a number of foreign companies in India is being readily approved by Government; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIVSHANKAR): (a) and (b). Approval of the Central Government is required under the provisions of the Companies Act, for appointment/reappointment of expatriates as managing or whole-time directors in public limited companies and private limited companies which are subsidiaries of public limited companies. Sub-sec. (3) of sec. 269 *ibid* sets out the criteria for such approvals.

Each case of appointment/reappointment is decided on merits keeping in view the qualification and background of the persons in question and the views if any of the administrative Ministry concerned, on the essentiality aspect of their services. As a broad policy, Government discourages ap-

pointment of foreigners where Indians with requisite skills and experience are available. However, where it is felt that the appointment of an expatriate is essential, the proposal is approved in consultation with the concerned administrative Ministry.

The exercise of this power is made with due regard to the facts and merits of each case and without undue haste.

Seven Day Schedule of work in all Coal Mines

2138. SHRI JAGDISH TYTLER: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration to have a "seven-day" Schedule of work in all coal mines;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) when it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). In order to increase coal production, Government is examining a suggestion to increase the number of shifts per week worked in some mines.

Details of survey undertaken by National Hydel Power Corporation

2139. SHRI KAMAL NATH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the details and nature of surveys undertaken by National Hydel Power Corporation for new Hydro Generating Plants in 1980; and

(b) details of surveys proposed to be undertaken in 1981?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The following projects are to be taken over for investigation and execution by the National Hydro-electric Power Corporation/North-Eastern Electric Power Corporation:—

Himachal Pradesh:

1. Kol Dam H.E. Project
2. Parvati H.E. Project
3. Chamera H.E. Project

Madhya Pradesh:

1. Konhan Hydel Scheme

Uttar Pradesh:

1. Eastern Ramganga H.E. Project
2. Dhauliganga H.E. Project
3. Goriganga H.E. Project
4. Tanakpur H.E. Project

Mizoram:

1. Kolodyne (Tuipui)
2. Dhaleshwari (Twalong)

The investigation of Chamera Project has been sanctioned, and work is under progress. In respect of the other schemes, action to obtain investment sanction is being processed.

Number of new Coal Mines opened during 1980

2140. SHRI KAMAL NATH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) number of new coal mines opened during the calendar year 1980 and proposed to be opened during the calendar year 1981;

(b) total employment generated in 1980 arising out of opening of new mines; and

(c) total employment expected to be generated in 1981?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Dul Hasti Hydel Project in J. and K.

2141. SHRI NAMGYAL: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) when the Dul Hasti Hydel Project in Jammu and Kashmir State was cleared by the Government of India, when work on this project will be taken in hand and when it is likely to be completed; and

(b) what is the total cost involved and what is the total power generation capacity on its completion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The Dul Hasti Hydro-electric Project was cleared by the Public Investment Board in its meeting held on 18th December, 1980. Formal approval of the Central Cabinet is expected shortly. In the meantime, all preparatory action has been taken. The Project is expected to be completed in about 8 years which includes two years spent on the building up of infrastructure.

(b) The Project is estimated to cost Rs. 18217 crores. The total power generation capacity of the Project on completion will be 390 MW.

Supply of Diesel and Kerosene to West Bengal

2142. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the diesel and kerosene quotas for west Bengal have been reduced considerably;

(b) if so, facts thereof; and

(c) what were the quotas and allotments of the diesel and kerosene during the last six months for West Bengal (separately)?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of the answer at (a) above.

(c) The following are the details of allocation and sales of high speed diesel (HSD) and kerosene in West Bengal during the period August—December 1980, as also allocation for the months of January to March, 1981:—

(Figures in metric tonnes)

Month	High Speed Diesel oil		Kerosene	
	Allocation	Sale	Allocation	Sale
August 1980	55,200	44,817	34,100	31,981
September 1980	55,200	48,476	34,100	32,702
October 1980	41,100	43,240	33,300	34,559
November, 1980	54,000	48,261	34,830	33,188
December 1980	57,000	51,505	34,450	31,873
January 1981	57,000	N.A.	34,400	N.A.
February 1981	57,000	N.A.	30,500	N.A.
March 1981	66,000	Month not over	33,100	Month not over

(N.A. stands for Not Available)

Demand of Royalty on crude by Gujarat and Assam

2143. SHRI NIREN GHOSH:
SHRI NARSINH MAKWANA:
SHRI SONTOSH MOHAN DEV:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government of Gujarat and Assam have demanded a rise in the royalty on crude;

(b) if so, what is the exact demand they have made;

(c) what is the method of calculation adopted by the Centre for payment of royalty on crude;

(d) whether two different methods are being followed in determining the price of refined petroleum and fixing the royalty payment as regards the fixing of crude.

(f) if so, reasons therefor; and

(f) whether the demand of Gujarat and Assam would be considered soon; if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) The State Governments of Assam and Gujarat submitted memoranda for the revision of rate of royalty on crude oil and easing head condensate. The main points in general thereof are:

(i) The proprietory rights of oil producing States in all respects should be fully protected and reasonabl compensation should be paid to them.

(ii) The royalty should be revised with effect from 1-1-1976.

(iii) While fixing royalty the international price of the crude oil F.O.R. Indian port should be taken into consideration and the royalty should be fixed at 20 per cent *ad valorem* of the weighted average posted price of Middle Eastern Crude plus 4 per cent as compensation from Sales Tax.

(iv) In order to check the loss of royalty due to frequent increaseses in international prices of crude oil, necessary provision should be made in this direction, viz., introduction of escalation clause, quarterly review of the payment of royalty amount etc.

(v) The State Government of Assam has stated that the royalty should be fixed at Rs. 315/- per tonne of crude with effect from 1st January, 1980 and it should be revised every quarterly if the international price of crude varies by 5 per cent or more.

(c) Royalty is payable and the rate of royalty on crude oil is fixed under the Oil fields (Regulation and Development) Act, 1948. Under the provisio to Section 6(A)(4) of this Act, the Central Government shall not (a) fix the rate of royalty in respect of any mineral oil so as to exceed 20 per cent of the sale price of the mineral oil at the oil fields or the oil well-head as the case may be or (b) enhance the rate of royalty in respect of any mineral oil more than once during any period of four years.

The existing rate of royalty of Rs. 42/— per tone is based on the selling price of crude oil which has been fixed at about Rs. 300/- per tonne of indigenous crude oil produced from on-shore fields.

(d) and (e) Yes, Sir. Petroleum product prices are linked to the pooled average price of crude (indigenous on-shore, off-shore and imported crude) to ensure full benefit of the lower price of indigenous crude to the consumer. As already stated in reply to part (c), royalty on crude is governed by an Act, while price of petroleum products are based on the recommendation of the Oil Pricing Committee as accepted by Government.

(f) Yes, Sir.

Puyankutty Hydro-Electric Project in Idukki District

2144. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the investigation going on as regard to the Puyankutty Hydro-electric Project in the Beriyarbasin located in the Idukki district of Kerala;

(b) if so, details of the investigation;

(c) whether the project report of the above project had been completed;

(d) if so, whether it had been submitted to Government of India for clearance; and

(e) if not, when it may be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (e). The Kerala State Electricity Board has intimated that the investigation on Puyankutty Hydro-electric Project (750 MW) has been completed. However, the detailed project report is awaited from State authorities.

Formulation of Scheme to Achieve Efficiency in Energy Distribution

2145. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government of India have formulated any scheme to achieve efficiency in Energy distribution;

(b) if so, the details of the scheme;

(c) whether every State has agreed with scheme; and

(d) if not, the names of the States which have not agreed with the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (d). The question of achieving efficiency in Energy distribution *inter-alia* reducing the system losses in the country, is receiving attention of the Government. The State Electricity Boards are taking up system improvement schemes within the prevailing constraint of the resources. However, following guidelines have been issued by the Central Electricity Authority to the State Electricity Boards:

(i) Formation of a special set-up in each Electricity Board to identify the weak areas.

(ii) Electricity Boards to initiate pilot system studies for distribution planning and make endeavour to cover not only the primary distribution and L.T. net works, but also the associated sub-transmission and transmission systems.

(iii) Setting up of special units in the Electricity Boards to prepare scheme for reduction of losses.

(iv) Amendment of conditions of 'Supply' to make it obligatory on the part of the inductive motive power consumers to instal shunt capacitors at their terminals.

(v) Erection of new transmission lines and sub-stations to relieve over-loaded lines. Changing of conductors by higher size. Of the existing lines, relocation of sub-stations and re-arrangement of existing L.T. systems.

(vi) Installation of high tension (HT) capacitors at various (a) Grid and (b) primary distribution sub-stations for improving voltage conditions, power factor and to reduce loading of the transmission and sub-transmission lines.

(vii) Setting up of vigilance squads comprising Electricity Boards'/Departments' engineers and a police inspector, to conduct surprise inspections to check pilferage of energy.

The Rural Electrification Corporation (REC) is advancing loans to the State Electricity Boards for system

improvement (SI). Under this category 110 schemes for a total loan assistance of Rs. 60.03 crores were sanctioned by the REC upto March, '79. The budget provision for the ongoing S.I. Schemes to be funded by the REC for the year 1980-81 is Rs. 17.5 crores.

Conference of Eastern Regional Power Ministers held in Calcutta

2146. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether a conference of Eastern Regional Power Ministers was held in Calcutta recently;

(b) whether the Union Minister also attended to Conference; and

(c) if so, what are the details of the discussion taken therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Conference of the Eastern Region Power Ministers was held in Calcutta on 8-2-1981.

(b) Yes, Sir.

(c) In the above Conference, the following were discussed:—

(i) Power supply position in each State and the Region.

(ii) Progress in the Commissioning of on-going projects in the region.

(iii) Power cuts and efforts taken to minimise its impact.

(iv) Rural Electrification.

(v) Salient features of the Rajadhyaksha Committee Report on Power.

(vi) Formation of All India Service of Engineers.

पालना तापीय बिजलीघर के निर्माण-कार्य के लिये वित्तीय मंजूरी

2147. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालना तापीय बिजलीघर के निर्माण-कार्य के लिए वित्तीय मंजूरी दी गई है और इस बिजलीघर की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) उपरोक्त बिजलीघर का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा; और

(ग) उपरोक्त बिजलीघर के निर्माण-कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और यह निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और बिजलीघर कार्य करना शुरू कर देगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :(क) से (ग) । बीकानेर जिले में पालना में, लिग्नाइट पर आधारित 60–60 मेगावाट की दो यूनिटों वाले ताप विद्युत् केन्द्र की प्रतिष्ठापना के लिए स्कीम का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन कर लिया गया है तथा इस पर निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है । परियोजना पर 6738 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है । इस परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने पालना विद्युत् परियोजना और पालना खनन परियोजना को एक साथ ही स्वीकृति की सिफारिश की है ताकि अपेक्षित समय-अवधि में लिग्नाइट की उपलब्धता सुनिश्चित हो। लिग्नाइट खनन परियोजना के लिए राज्य सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान किसी वित्तीय प्रावधान के लिए प्रस्ताव नहीं किया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कीम पर निवेश निर्णय इस समय स्थगित रखा गया है।

राजस्थान में पैट्रोल पम्पों की स्थापना

2148. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले का क्षेत्र 16,000 वर्गमील है फिर भी उपर्युक्त जिले में अब तक केवल जैसलमेर तथा पोखरन में ही पैट्रोल पम्प स्थापित किए गए हैं; और

(ख) क्या इस तरह के विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, चांदना, फलूसद, रामगढ़, साम, नाचना गांवों तथा उपर्युक्त जिले के उन अन्य दूसरे स्थानों पर पट्रोल पम्प स्थापित करने का मंत्रालय का विचार है, जिन्हें मंत्रालय अपेक्षित शर्तों, नियमों में ढिलाई करने के उपरान्त क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की मांग पूरी करने के लिए पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए उचित समझता हो और यदि हां, तो कब तक ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड खुदरा बिक्री केन्द्र (रिटेल आउटलेट) कम लागत के बिक्री केन्द्र (लो कास्ट आउटलेट) खोलने की संभावना के मूल्यांकन के लिए तथा जहां आवश्यक है और आगे कार्यवाही करने के लिए इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करा रहा है ।

Allotment of diesel to Rajasthan

2149. **SHRI VIRDHI CHANDER JAIN**: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the quantity of diesel allotted to Rajasthan during the month of January, 1980 to January, 1981;

(b) the quantity of diesel allotted to Rajasthan during these months in the last three years;

(c) the criteria adopted by the Centre for allotment of diesel to the States; and

(d) whether it is a fact that in the States affected by drought the quota of diesel is increased to augment the production of Rabi crops; if so, how and the extent to which it has been decided to increase the quota of diesel for Rajasthan where acute drought conditions prevail for three years consecutively?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) The following are the details of High Speed Diesel (HSD) and allotted to Rajasthan during the months of January '80 to January, 1981:—

Name of the month	Figures in metric tonnes Quantity allotted
January, 1980	32300
February, 1980	36770
March, 1980	40000
April, 1980	39000
May, 1980	39000
June, 1980	42000
July, 1980	42000
August, 1980	36800
September, 1980	44100
October, 1980	39853
November, 1980	42600
December, 1980	44300
January, 1981	46300

(b) The system of making monthly allocations of High Speed Diesel oil was started only from October, 1979, and the following quantity of HSD was allotted to Rajasthan from October '79 to December '79:—

Name of the month	Figures in metric tonnes Quantity allotted
October, 1979	41377
November, 1979	41648
December, 1979	41421

(c) In recent months, the allotment of HSD to all the States has generally been made on the basis of a 5 per cent increase over the original allocation made in the corresponding month of last year. Ad-hoc increases over these allocations have been made for Rajasthan keeping in view the special requirements of the State.

(d) Yes, Sir. Between October '80 and February '81, the HSD allocations for Rajasthan were increased mainly in view of problems of drought and power shortage experienced there. The details of additional allocations of HSD made during these months to the State are as under:—

Month	Figures in metric tonnes Additional allocation
October '80	1,653
November '80	2,000
December '80	4,500
January '81	4,000
February '81	9,500

Demand and distribution of kerosene and diesel oil by States

2150. SHRI VIRDHI CHANDER JAIN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the State-wise monthly demand and distribution of Kerosene and diesel since January, 1981;

(b) total monthly deficit of kerosene and diesel in our country; and

(c) the proposals of Government to meet this crisis?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) It is not possible to indicate the monthly demands of kerosene and High Speed Diesel (HSD) State-wise. However, the details in regard to sales of these two products, State-wise, for the month of January, 1981, and allocation for February, 1981, are given in the enclosed statement.

(b) and (c). The gap between the actual production of kerosene and HSD in the refineries of the country and consumption is being met through imports of these products. During 1980-81, the domestic production of about 2.40 million tonnes of kerosene is to be supplemented by about 2.2 million tonnes of import. The imports of HSD during 1980-81 would be of the order of 3.9 million tonnes.

Statement

The sales of High Speed Diesel oil (HSD) and Kerosene, State-wise, for the month of January 1981, and allocation for February, 1981.

(Figures in metric tonnes)

States/Union Territories	HSD		Kerosene	
	January, 1981 Sales (Provisional)	February 1981 Allocations	January 1981 Sales (Provisional)	February 1981 Allocations
1. Andhra Pradesh	62,152	67,300	27,467	27,900
2. Arunachal Pradesh	505	800	344	200
3. Andaman & Nicobar	N.A.	900	N.A.	100
4. Assam	15,189	12,300	8,473	7,100
5. Bihar	38,177	38,300	18,498	19,000
6. Chandigarh	1,539	1,500	818	700
7. Dadra and N. Haveli	N.A.	400	N.A.	50
8. Delhi	31,386	29,300	11,856	12,400
9. Gujarat	57,711	64,000	38,905	32,300
10. Goa, Daman and Diu	5,488	8,500	1,176	1,500
11. Haryana	24,203	20,400	6,757	5,300
12. Himachal Pradesh	3,546	3,300	1,475	1,700
13. Jammu and Kashmir	5,205	5,600	2,831	2,300
14. Karnataka	45,627	45,100	21,434	40,200
15. Kerala	31,314	28,000	11,483	11,600
16. Madhya Pradesh	39,520	37,200	17,259	16,900
17. Maharashtra	1,05,903	1,05,200	71,282	72,000
18. Manipur	780	1,700	751	700
19. Meghalaya	1,260	1,100	285	300
20. Mizoram	303	600	178	200
21. Nagaland	718	600	419	400
22. Orissa	13,851	14,000	6,467	6,800
23. Punjab	42,550	43,600	12,605	10,100
24. Pondicherry	830	1,800	551	700
25. Rajasthan	40,966	45,500	11,697	10,700
26. Sikkim	370	300	454	300
27. Tamil Nadu	83,262	76,000	32,045	30,200
28. Tripura	918	1,000	670	800
29. Uttar Pradesh	92,264	80,500	33,647	30,700
30. West Bengal	N.A.	57,000	N.A.	30,500
31. Lakshadeweep	N.A.	100	N.A.	50
TOTAL	7,45,537	7,91,900	3,41,827	3,53,700

N.A. stands for Not Available.

Residential accommodation taken on lease by oil companies

2151. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number of private residential accommodation that has been taken on lease by each of the public sector oil companies in Calcutta, Delhi, Bombay and Madras;

(b) whether it is a fact that the lease period is being extended unilaterally by the public sector oil companies;

(c) the number of petrol outlets that have been established in these 4 metropolitan cities by each of these public sector oil companies on lease-hold plots and even after the expiry of such leases these public sector oil companies have not taken steps to vacate such plots; and

(d) the number of cases that have been filed in courts against these public sector oil companies by the owners of residential accommodation and plots on which petrol outlets are there?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C SETHI): (a) Private residential accommodation taken on lease by the four public sector marketing oil companies, namely Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum Corporation (HPC), Bharat Petroleum Corporation (BPC) and Indo-Burma Petroleum Company (IBP) in the four metropolitan cities is as follows:—

IOC	...	...	283
HPC	...	...	139
BPC	...	...	107
IBP	...	...	29

(b) It is not a fact that lease periods are being extended unilaterally. Leases are renewed by negotiations and by increasing rentals where necessary. Besides, wherever necessary, occupancy is continued under the local tenancy laws and in exercise of the rights of the oil companies under the respective Acquisition Acts in respect of take-over of foreign oil companies. There are also cases where the oil companies have surrendered flats on expiry of lease periods.

(c) There are 773 Retail Outlets on lease-hold plots including the plots which have been taken on lease from Government authorities. In 153 cases the leases have expired.

(d) There are 30 cases in respect of Retail Outlets and 55 in respect of residential accommodation against the oil companies in various courts.

Setting up of a Tidal Wave Power Station in the Gulf of Kutch

2152. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have launched a Rs. 2.18 crore project to find out the feasibility of establishing a tidal wave power station in the Gulf of Kutch with the assistance of French Exports;

(b) if so, the reasons for not taking up the Ocean Thermal Power Conversion Scheme that has been formulated by the Tamil Nadu Government for which U.S. Experts had promised to give a feasibility report;

(c) whether a central monitoring agency has been set up to keep an eye on all thermal power stations in the country; and

(d) the steps taken to eliminate slippage of power stations in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The Government have approved a proposal for taking up investigations and studies in the Gulf of Kutch, Gujarat to establish the feasibility for generating energy from tidal waves, at an estimated cost of about Rs. 2.18 crores. The project envisages utilisation of foreign technical assistance. Since there is an agreement between the Central Electricity Authority and the

Electric De France (EDF), Paris for collaborative effort in the field of power development, the possibility of securing assistance of French Experts to assist in the planning of the proposed investigations is being explored.

(b) As the R&D in respect of the Ocean Thermal Power Conversion technique is still at a very preliminary stage and no actual installation of even 1 MW OTEC Plant is in operation or has so far been built any where in the world, the offer of the US Experts to make preliminary design of a 25 MW OTEC Plant was not considered worth while for taking up at this stage especially as it involved outflow of free foreign exchange.

(c) and (d). While the power planning is with the Central Government, the execution of power projects, their operation and maintenance etc. is mainly with the State Governments and State Electricity Boards. Considering the importance of thermal power stations on the energy scene an operation and monitoring unit has been set up in the Central Electricity Authority to watch and review the performance of thermal power stations and to advise on remedial action required for the proper operation and maintenance of the thermal power stations. In the interest of speedier execution of new thermal projects a monitoring cell has been set up in the Central Electricity Authority. The progress of construction and timely availability of plant and equipment is reviewed periodically in various meetings with the project authorities where various inputs and their availability are critically appraised and remedial action suggested. The Ministry of Energy also reviews the progress of construction and performance of the projects from time to time and renders necessary help to meet the requirements of material and equipment so that slippage is minimised. Several Power Minister's Conferences have also been organised to review the performance of power stations and to monitor the execution of new projects.

Oil Exploration by foreign multinational Companies

2153. SHRI B. D. SINGH:
SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that proposal to have some foreign multinational companies for the oil exploration in India;

(b) whether it is a fact that a separate Directorate to deal with the foreign multinational companies is proposed to be set up;

(c) if so, the decision, if any, taken by Government; and

(d) the reasons for dissociating the ONGC from the oil exploration in the country?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir. Government has decided to invite offers from selected foreign oil companies for oil exploration contracts in India in certain areas.

(b) and (c). The setting up of a suitable organisation to monitor and control various activities relating to the exploration and production of hydrocarbons in the country is being considered. But no decision has yet been taken.

(d) No, Sir. ONGC is not being dissociated from the oil exploration work in the country. Instead the ONGC is being given every possible assistance and encouragement to maximise its efforts.

Cost of Power Generation per Unit

2154. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the cost of generation per unit (MW) of hydro electric thermal, tidal, wind, geo-thermal and atomic energy:

(b) the total energy we need per year;

(c) the total production per year;

(d) the total consumption needed by industries and the supply by his Ministry; and

(e) the steps his Ministry are taking to fulfil the gap of demand and supply during next year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The overall cost of generation depends on the ratio of hydel and thermal power in the system and also the capital cost of individual projects and the cost of fuel in the case of thermal power stations, etc. The present average cost of power generation from different sources is indicated below:

(i) thermal	25 to 35 Paise/kwh
(ii) hydro	12 to 15 paise/kwh
(iii) diesel	round 100 paise /kwh
(iv) nuclear	16 to 17 paise/kwh for already commissioned units (Tarapur and RAPP-I) and 30 to 35 paise/Kwh for new projects.

(b) The energy requirement during the year 1980-81 is estimated to be about 127325 million units.

(c) The energy generation during the year 1980-81 is anticipated to be 113000 million units.

(d) About 60 per cent of the total energy was supplied to industries during 1979-80.

(e) A number of short-term and long-term measures have been taken and are being taken to improve the power availability in the system. These measures include:

(i) better management of load demand by staggering of holidays, shifting of loads from day time to night time etc.

(ii) accelerated addition of new generating capacity in the system. It is envisaged to add about 20,000 MW of additional generating capacity during the period 1980—85. Detailed monitoring of the construction schedules of all the on-going projects is being undertaken to ensure expeditious completion of the projects;

(iii) number of steps like undertaking of plant betterment programmes in a time-bound timeframe, arranging supply of spares, supply of requisite quantity and quality of coal for thermal power stations etc. have been taken to improve the operation and maintenance of existing thermal power plants with a view to maximising generation from the existing installed capacity;

(iv) Undertaking training programmes for engineers and technical personnel entrusted with the operation and maintenance of power stations.

Refining of Crude Oil

2155. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the crude oil we produce in the country is totally refined here indigenously or foreign assistance is also needed.

(b) names of the refineries and details of production with expenditures incurred on refining (per 200 litre) car petrol and diesel;

(c) whether the high speed fuel for aircrafts is also refined in India;

(d) if so, the cost per 200 litre; and

(e) the details of total supply to our needs of high speed fuel?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) All the Crude oil produced in the Country is refined in the country.

(b) and (d). The names of the refineries, their installed capacity as well as the crude throughout during the year 1979-80 are given below:—

Name of the Refinery	Installed Capacity	Crude throughout during 1979-80
HPCL (Bombay) .	3·50	3·13
BPCL (Bombay)	5.25	4.82
HPCL (Visakh) .	1.50	1.10
CRL . . .	3·30	2.87
MRL . . .	2.80	2.82
Koyali . . .	7·30	6.71
Haldia . . .	2.50	2.49
Barauni . . .	3.30	2.29
Gauhati . . .	0.85	0.64
Digboi . . .	0.50	0.41
Bongaigaon . .	1.00	0.19

A statement indicating the break-up of the retail selling price of MS, HSD and ATF (200 litres) at Delhi under different elements of cost including the amount relating to average expenses on refining costs and margins for all refineries is enclosed.

(c) The bulk requirements of Jet engine aircraft are met totally from ATF produced in our refineries. Small quantities of Av Gas required for piston engine aircraft are met by imports.

(e) During the year 1979-80 the total requirements of ATF and Aviation Gasoline were about 1.1 million tonnes and 19,000 tonnes respectively.

Statement

Retail selling price at Delhi w.e.f. 13-1-1981.

	MS		HSDO		ATF	
	Rs./KL	Rs./200 Litre	Rs./KL	Rs./200 Litre	Rs./KL	Rs./200 Litre
1. Crude oil including surcharge . .	2591.64	518.33	1929.58	385.92	3110.71	622.14
2. Refining cost and margin . . .	38.60	7.72	40.72	8.14	43.30	8.66
3. Marketing cost and Margin . . .	62.67	12.45	29.25	5.85	58.76	11.75
4. Taxes including S.T./ Octroi . . .	2571·90	514.38	507·95	101.59	608.05	121.61
5. Rail freight including RPO charges and surcharges . . .	182·46	36·49	141.06	28.21	146.33	29·27
6. Retailer Marginr .	50.00	10.00	20.00	4.00	..	..
TOTAL . . .	5496.87	1099·37	2668.56	533·71	3967.15	793·43

Set Back to Rural Electrification Programme due to Industrial Priorities

2156. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the rural electrification programme has suffered a set back due to industrial priorities; and

(b) if not, the programme of his Ministry to electrify Madhya Pradesh rural districts (including Betul division) in near future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) No, Sir.

(b) According to the latest Progress Report received from the Madhya Pra-

desh Electricity Board, 2,200 villages (including 30 villages in Betul district) have been electrified up to the end of January, 1981.

The Madhya Pradesh Electricity Board has drawn up a programme to electrify 3,000 villages (including 30 villages in Betul District), in the different districts of Madhya Pradesh during the year 1980-81.

Mismanagement in Madhya Pradesh Electricity Board

2157. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is true that Madhya Pradesh Electricity Board is suffereing from mismanagement or malpractices of yester years or other causes, if any; and

(b) if so, the details of routing out hurdles in progress of power distribution in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The performance of a State Electricity Board depends on various factors such as proper maintenance and operation of power plants, sound financial management and organisational structure of the Board etc. No reports have been received by the Central Government about the mismanagement of Madhya Pradesh Electricity Board. As a matter of fact, Madhya Pradesh Electricity Board is running into profits and cumulative profits of the Board after taking into account subventions from Government, as on 31st March, 1979, are the tune of Rs. 1458 lakhs. The State Electricity Boards are under the direct control of the State Governments and they would be taking appropriate action in cases of malpractices or mismanagement.

Set up of T. V. Centres in Orissa

2158. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the T.V. Centres that Government is proposing to set up in Orissa during the Sixth Plan Period;

(b) what is the area coverage of the present arrangement; and

(c) what steps are being taken to expand the same?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTI†G (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) It is proposed to set up a T.V. Transmitting Centre at Cuttack during the 6th Plan period

(b) The Transmitting Centre at Sambalpur which is functioning at present has a service range of 40 kilometres in radius covering an area of 5,000 sq. kilmotres.

(c) With the commissioning of the Transmitting Centre at Cuttack, the service area will increase by 18,000 sq. kilometres. A proposal to expand T.V. service in the country by utilising INSAT-I is under formulation. It is likely that some districts of Orissa will be covered under this scheme. The areas that would be covered through INSAT would however, depend on the approval of the scheme, availability of resources and relative priorities.

Adulteration of Kerosene with other Petroleum Products

2159. SHRI K. P. SINGH DEO:
SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that kerosene is being adulterated and is being used for mixing it up with other petroleum products;

(b) if so, whether Government have taken steps to stop this adulteration; and

(c) whether the price difference between Diesel and HSD is contributing towards adulteration?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Due to the difference in the retail selling prices of High Speed Diesel (HSD) and kerosene, the possibility of some adulteration of HSD with kerosene cannot be ruled out.

(b) The oil companies have intensified the check over the availing of their diesel pumps. The attention of the State Governments etc., has been drawn to the possibility of adulteration of diesel with kerosene and they have been requested to draw up a detailed scheme for closely checking the delivery and sale of kerosene oil in order to ensure that the entire product supplied by the oil companies reaches the consumers for whom the same is meant. The oil companies have also been asked to get in touch with State Governments and extend all possible assistance to them in preventing the substitution or adulteration of HSD by kerosene. In order to prevent adulteration of high speed diesel oil with kerosene, a proposal for colouring of kerosene is under consideration of the Indian Oil Corporation. The various technical and administrative aspects relating to the proposal are required to be examined in detail before it can be implemented.

(c) Already covered in the reply to part (a).

Demand of Ladakh for Disel Generators

2160. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Ladakh, the demand for a diesel generator created and continues to create tension as a great part of it is in darkness;

(b) if so, whether Government have considered it desirable to supply some generators to the area which will help to solve the tension there; and

(c) if not, how does the Government propose to solve the issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Soft coal dump scheme proved to be non-starter

2161. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the soft coal dump scheme has proved to be a non-starter as a result of non-availability of railway wagons to move coal to dump centres;

(b) whether it is also a fact that it was almost decided six months back that the Department of Coal had decided to open soft coke dumps to ease the coal availability in the Eastern Region; and

(c) if so, the details regarding the movements, if any taking place and to which States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). A decision to open soft coke dumps in certain States was taken in 1980. Some rakes for movement of coal to these dumps have been allotted recently and the dumps are expected to start functioning shortly. Five dumps for soft coke are functioning in the Calcutta-Howrah region.

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रेलवे से मांगे गए वैगनों की संख्या

2162. श्री जैनुल बशेर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक के बीच कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मांगे गये कोयला-वैगनी की संख्या कितनी है ;

(ख) रेलवे द्वारा सप्लाई किये गए वैगनों की संख्या कितनी है ;

(ग) रेलवे द्वारा मांग के अनुसार वैगनों की सप्लाई न करने के लिए क्या कारण दिये गये हैं; और

(घ) महीने-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख). दिनांक पहली जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक कोल इंडिया लिमिटेड ने 1,34,277 वैगनों की मांग की और लदान 93,098 वैगनों का हुआ :

(ग) और (घ). रेलवे के अनुसार कोयले के लदान के लिए वैगनों की सप्लाई में कमी उन विभिन्न कारणों से हुई जो रेल वैगनों के आने जाने के चक्करों को प्रभावित करते हैं। कोलियरियां भी सप्लाई किए गये वैगनों में से औसतन 104 वैगन प्रति दिन का लदान निर्धारित समय में नहीं कर सकी और इस कारण भी और वैगनों की सप्लाई प्रभावित हुई।

Television Centre at Andhra Pradesh

2163. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the proposed coverage of Television Centre that Government is proposing to set up in Andhra Pradesh during the Sixth Plan period;

(b) what is the area coverage of the present arrangement; and

(c) what steps are being taken to increase the same?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI):(a) It is proposed to set up a TV Relay Centre at Vijayawada during the Sixth Plan period. This Relay Centre, when commissioned, will serve an area of 36,000 sq. kilometers.

(b) The existing TV transmitter at Hyderabad covers an area of 17,000 sq. kilometres.

(c) With the commissioning of the relay centre at Vijayawada, the service area will increase by 36,000 sq. kilometres. A proposal to expand TV services in the country by utilising INSAT-I is under formulation. It is likely that some districts of Andhra Pradesh will be covered under this scheme. The areas that would be covered through INSAT would, however, depend on the approcal of the scheme, availability of resources and relative priorities.

Coverage of Television Transmission

2164. SHRI P. K. KODIAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the overall reach of the Television transmission covers only 15 per cent of the population and six per cent of the country's area;

(b) if so, what steps have been taken to extend the coverage of Television transmission in the next ten years; and

(c) what steps have been taken to improve the quality of the telecasts?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) Yes, Sir.

(b) The approved Sixth Plan proposals (1980—85) include setting up of full-fledged TV centres at Ahmedabad, Bangalore, Trivandrum and Gauhati and Relay transmitters at Panaji, Asansol, Madurai (Kodaikanal), Murshidabad, Varanasi, Vijayawada Cuttack and Kasauli. TV coverage will increase considerably with the commissioning of these projects.

A scheme for expansion of TV services by utilising INSAT-I is also under formulation. Its implementation will, however, depend on the approval of of the scheme, availability of resources and relative priorities.

(c) Details of the steps taken by Doordarshan to improve the quality of the telecasts are given in the statement enclosed.

Statement

A lot of expeditious measures have been taken to effect improvement in TV Programmes, the highlights of which are as under:—

(1) Fixed point schedule of TV centres have been revised so is to make them more interesting and to cater to tastes of various categories of viewers based on the feedback received from Audience Research.

(2) News and Current Affairs Programmes have bene given a revamping by making them more visual in formal and topical in approach.

(3) Under Plan Schemes outside producers are being invited to produce TV Documentaries. All major Kendras of Doordarshan have offered such contracts.

(4) Under the various schemes financed from the Non-lapsable fund of AIR/TV, eminent film producers have been invited to make short TV films.

(5) To promote National Integration a film serial on various States in India is shortly proposed to be mounted. This will not only exhibit visuals connected with regional cultures and traditions but also focus on the development work being undertaken in these States.

(6) On the pattern of Late J. N. Gaus award for TV Documentaries, some other awards are being instituted to induce TV producers to produce high quality of TV programmes.

(7) Efforts are being made and some measures of success have already been achieved in obtaining better and award winning feature films for TV showing.

(8) A weekly National Programme of Music and Dance has been instituted from Metropolitan TV centres w.e.f. April 1980. The duration of this programme was later extended to 45 mts. on viewers demand.

(9) Special Training Course and Workshops are being organised for Doordarshan Staff, so as to upgrade their skills.

(10) A scheme for intensification of exchange of TV programmes from TV networks of friendly countries is being chalked out. This may help in obtaining choicest programmes from other TV networks.

More thermal power plants in the Central Sector

2165. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is any plan to set up more thermal power plants in the Central Sector;

(b) if so, the number of plants to be set up;

(c) the estimated cost and production capacity of each plant; and

(d) the location of the proposed plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (d) Yes, Sir. The Government propose to set up some more thermal power stations in the Central sector. For the purpose, the feasibility reports of the following projects have been prepared and are under techno-economic examination by the Central Electricity Authority.

Name of the Project	State	Total expenditure for the proposed ultimate capacity
		(Rs. in crores)
Kahalgaon (2800 MW)	Bihar	1497.17
Pench (840 MW)	Madhya-Pradesh	477.55
Talcher (2800 MW)	Orissa	1472.31
Waidhan (3000 MW)	Madhya Pradesh	1364.63

Set up of Gas-based fertilizer plants

2166. SHRI A. C. DAS: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government has any proposal to set up some gas-based fertilizer plants in the country;

(b) if so, the places where they will be located;

(c) whether any such plant is going to be set up with the collaboration of U.K. Government;

(d) the expected time of the implementation of the above proposals; and

(e) the details in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir. In addition to the five gas-based fertilizer plants—two each at Thal-Vaishet in Maharashtra and Hazira in Gujarat and one at Namrup in Assam—it is proposed to set up six more plants based on the Bombay High/Base in gas.

(b) A Site Selection Committee has been appointed to recommend locations for the proposed plants. The exact location would be decided after the report of the Committee is received.

(c) There is at present no proposal to set up any of thhese plants with the collaboration of the U.K. Government.

(d) and (e). Work on these plants is proposed to be started in a phased manner during the 6th Plan period.

Generating capacity and the demand of power in Gujarat

2167. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the total generating capacity against the total demand in Gujarat;

(b) whether the demand falls short of the generating capacity in Gujarat; and

(c) if yes, steps taken to meet the gap and the demand likely to arise in the next 5 years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). The total installed generation capacity of Gujarat is 2404 MW including 50 per cent share from Tarapur Atomic Power Plant and the present estimated demand is 2050 MW.

(c) The following steps have been and are being taken to meet the demand likely to arise in the next 5 years;

(i) Addition of about 1175 MW of new generating capacity during the period 1980—85. In addition the State will also get some allocation of power from the Central Sector Korba Super Thermal Power Station.

(ii) A number of steps are being taken to maximise generation from the existing installed capacity.

(iii) Efforts are made to put back the units under repairs as well as to stablise the newly commissioned generating units expeditiously.

Power shortage in Gujarat

2168. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Gujarat is facing grim power shortage and that it had to resort two days loadshedding in a week;

(b) reasons for such a drastic cut in the energy supply to various industries in Gujarat; and

(c) when is the situation likely to improve?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The Government is aware of the shortage of power in Gujarat.

(b) There are no energy cuts in power supply to any category of consumer in Gujarat. Only demand cuts have been enforced on account of loss in generation at Ukai hydro of 150 MW due to poor rains in the catchment area, loss of 320 MW due to outage of two thermal sets at Ukai, of which 200 MW has returned to service but not yet stabilised and loss of 80 MW from Tarapur Atomic Power project which is under refuelling.

(c) Power supply position in the State of Gujarat is likely to improve by May, 1981 .

Demand for take over of Metro Cinema, Calcutta

2169. SHRIMATI GEETA MUKERJEE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the present ownership position of Metro Cinema, Calcutta;

(b) whether Government are aware of the demand of the public as well as the employees for its takeover by Government; and

(c) what is the reaction of Government thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN. M. JOSHI): (a) The ownership of the Metro Cinema, Calcutta, is presently claimed by one M/s. Flavian Properties Ltd., Calcutta.

(b) and (c). Government of West Bengal have already initiated proceedings for the acquisition of the land on which Metro Theatre Building Calcutta is built under the Land Acquisition Act, 1894, for the public purpose, being a purpose of the Union, for the outlet of educational and instructional films for the people in general. These acquisition proceedings have been challenged in the High Court of Calcuta and the Court has issued interim stay. Government are pursuing the matter to expedite early hearing of the case and vacation of the stay order.

Proposal for Pooling Cost of Naptha and Gas

2170. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government received any proposal from the Government of West Bengal for pooling the cost of naptha and natural gas and fix an uniform price based on equivalent component;

(b) are Government aware that without this the naptha—based fertilizer and other petrochemical products plants would be at a comparative disadvantage; and

(c) if so, what is the reaction of Government to (a) and (b)?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) I have not received any such proposal.

(b) and (c). Do not arise.

Setting up of Small Hydro-Electric Power Stations

2171. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal of NHPC to build small hydro-electric power stations in Northern part of West Bengal including taking over some sanctioned hydro-electric projects in that part for execution.

(b) whether there are major/medium hydro-electric projects in West Bengal for execution by NHPC and if so, whether there is any proposal to take up the same; and

(c) whether any steps have been taken to remove imbalance between

thermal and hydro in West Bengal to ease out shortage condition arising from various factors including frequent outage of thermal stations caused by use of high ash context low grade fuel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). With a view to expediate the completion of Ramman Hydro-electric Project Stage II (4x12.5 MW), in April, 80, a formal request was made to the Chief Minister West Bengal to consider the possibility of entrusting this Project to Natjonal Hydro-electric Power Corporation for execution. There has been no response yet from the State Government in this regard. Excepting this, there is no other proposal to execute hydel stations in West Bengal in the Central Sector through National Hydro-electric Power Corporation.

(c) Presently, Jaldhaka He Project Stage-II (8MW) and Ramman St. II (50 MW) project are under execution in Northern part of West Bengal. Further, with a view to remove the imbalance between thermal and hydro generation, Central Electricity Authority has carried out an exercise to identify hydroelectric schemes yielding benefits during 1980—95. These schemes are:—

Ramman Sta e-I	30 MW
Teesta Canal F l'-	67.5 MW
Kishtobazar Pumped storage Scheme -	1050 MW
Ramman St. III & IV integrated -	63 MW
Ramman St. V & Rangit integrated -	420 MW
Balasun St. I	12 MW

In addition, with the commissioning of Chukha Hydel Project (4x84 MW) (Bhutan) power will be evacuated in 1985-90 India through eastern grid for distribution to the concerned States. In addition the Koel Karo HE Project (710 MW) which is essentially a peaking station is being taken up for execution in the Central Sector. This project will become operative in the same period (1985—90).

Super Thermal Power Station at Talcher

2172. SHRI GIRIDHAR GOMANGO:
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) is it a fact that the proposed Super Thermal Power Station at Talcher has been agreed to by his Ministry for execution in the Central Sector; and

(b) if so, when the investment decision is likely to be taken by the Government of India as the project has been included in Sixth Five Year Plan and when the work is expected to start?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). Agreement in principle has been conveyed to the Chief Minister of Orissa for taking up a regional super thermal power station at Talcher in Orissa in the Central sector. The feasibility report for the project has been prepared by the National Thermal Power Corporation and is presently under techno-economic appraisal in the Central Electricity Authority. The investment decision on the project is to be taken after techno-economic clearance is accorded to it by the Central Electricity Authority.

Development of Coal Mines in Orissa

2173. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the measures undertaken by his Ministry for the production of coal and development of coal mines in Orissa keeping the view on proposed Super Thermal Station and Captive Power Plant;

(b) the steps taken by his Ministry for stepping up the production of coal up to around eight million tonnes

per annum by 1985 from Talcher and Ib valley field so far;

(c) the total annual production of coal from Talcher and Ib valley at present separately; and

(d) the funds provided for the development of coal mines at both the places in the year 1979-80 and 1980-81 and the schemes and provision likely to be provided in sixth plan period and annual plan of 1981-82 therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKARM MAHAJAN): (a) to (c). It is proposed to increase the present production (1979-80) of 1.5 million tonnes in Talcher coalfield and 1.07 million tonnes in Ib valley coalfield to 3.45 million tonnes and 2.51 million tonnes in 1984-85 respectively.

To achieve this production target, it is proposed to open new mines and reorganise the existing mines, whereever possible.

During 1980-81 (April-December, 1980), coal production from the Talcher and Ib valley coalfields was 1.33 million tonnes and 0.89 million tonnes respectively.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Companies of Birla Group

2174. SHRI RAM VILAS PASWAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the names of the companies under the direct/indirect control-ownership of the Birla Group Members;

(b) what type of business is carried on by each concern; and

(c) the assets of each of these companies at the time of their beginning and at present?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). In the context of the present industrial licencing policy and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, only those companies are to be considered as companies of the Birla Group which are registered under section 26 of the M.R.T.P. Act as undertakings to which section 20(a) of the Act applies, and which at the same time either (i) figured in the list of companies identified by the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee as companies belonging to the large industrial house of Birla or (ii) are interconnected with such Birla companies.

The M.R.T.P. Act came into force with effect from 1-6-1970. The details o fassets of each company of the Birla group at the time of their beginning or at the commencement of the Act are not available. However the Statement laid on the Table of House gives the information regarding the nature of business carried on by each of such companies as per registrations under section 26 of the MRTP Act upto 31-12-1979 and the value of assets of each company for the years 1972 and 1979. [Statement placed in library. *See* No. LT-2012/81].

Petroleum Inventory

2175. SHRI B. V. DESAI:

SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether petroleum inventory in the country is proposed to be raised to 45 days during the next 2 or 3 years;

(b) if so, what was the present normal level;

(c) whether this will result in the increase of storage capacity;

(d) if so, whether Government will have to spend additional amount for constructing additional storage purpose;

(e) if so, whether it is also a fact that the total cost of additional 2 million tonnes tankerage will be around Rs. 100 crores;

(f) if so, whether any final decision has been taken; and

(g) whether decision in regard to the location of the storage point have been worked out?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) to (g). It is proposed to increase the petroleum inventory in the country suitably over the coming years. It would not be in the public interest to disclose further details.

Production of Bulk Drugs by Public Sector

2176. SHRI B. V. DESAI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether reservation for production of certain bulk drugs to the public sector may be done away with;

(b) if so, the main reason for the same;

(c) whether his Ministry has come to the conclusion that the sectoral reservation of bulk drugs production cannot be fully justified or rigidly enforced;

(d) whether the 1978 drug policy is likely to be revised or changed; and

(e) if so, the main changes proposed to be made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). At the time of announcing the 1978 policy, Government had decided that some flexibility would be necessary in up-dating or operating these lists from time to time keeping in view changes in technology as well as the need to ensure fair and vigorous competition while maintaining the quality of drugs at fair prices.

(e) One change has been made—Erythromycin has been changed from the public sector list to the Indian sector list which consists of drugs reserved for production by the public sector as well as the private Indian sector.

Import of Powerful Transmitters

2177. SHRI B. V. DESAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the AIR is importing two very powerful transmitters to make its external service broadcast less vulnerable to nature's vagaries;

(b) if so, the country from which these will be obtained;

(c) the total cost of the expenditure involved; and

(d) to what extent the external service broadcast will be improved after installing these transmitters?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b) Order for 2 Nos. of high power short wave transmitters has been placed. These are being imported from Switzerland.

(c) The total cost of the scheme is expected to be around Rs. 790.00 lakhs out of which Rs. 421.00 lakhs is towards the cost of transmitting equipment only.

(d) The two new transmitters would help A.I.R. to effect a substantial improvement in its external services. It is not possible to quantify the extent of improvement.

Collaboration from abroad for increasing production from Bombay High—setting up Petro-Chemical Complexes

2178. SHRI HIRALAL R. PARMAR: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had sought collaboration from abroad for increasing the yield from Bombay High and for setting up petro-chemical complexes in Gujarat and Maharashtra; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). In response to Government invitation from France, Italy and Romania the Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers recently visited France, U.K., Romania and Italy. Though the visit was not with the specific object of seeking any country's collaboration, Minister availed of the occasion to discuss cooperation in the field of oil exploration such as supply of equipment with concerned Governments. During his stay in France, he had detailed discussions with CFP (who are already collaborating with ONGC in the Bombay High) regarding further development of Bombay High.

Our interest in foreign collaboration was indicated when the subject of petro-chemicals come up for discussions. Both France and Italy have expressed interest in assisting us in setting up of the petrochemical complexes.

Cinema Houses

2179. SHRI HIRALAL R. PARMAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the total number of cinema houses in the country, State-Wise;

(b) the number of cinema houses in urban and rural areas, separately;

(c) the steps proposed for constructing more cinema houses particularly in rural areas; and

(d) the incentives proposed in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD JOSHI): (a) The total number of Cinema Houses in the country is 10,889. A Statewise list of Cinema Houses is attached.

(b) Approximate number of Cinema Houses in the urban areas is 3046 and in rural areas 7843.

(c) and (d). National Film Development Corporation advances loans on easy terms for construction of low-budget cinema houses in rural, urban and semi-urban areas.

Statement

Cinema houses in India as on 31st December, 1980

S. No.	State/Union Territory	Number of Cinema Houses
(1)	(2)	(3)
1	Andaman & Nicobar	2
2	Andhra Pradesh	1904
3	Arunachal Pradesh	2
4	Assam	205
5	Bihar	326
6	Chandigarh	8
7	Dadara & Nagar Haveli	1
8	Delhi	70
9	Goa, Daman & Diu	17
10	Gujrat	516
11	Harayna	111
12	Himachal Pradesh	30
13	Jammu & Kashmir	34
14	Karnataka	1021

1	2	3
15	Kerala	1122
16	Madhya Pradesh	481
17	Maharashtra	1064
18	Manipur	8
19	Meghalaya	7
20	Mizoram	2
21	Nagaland	6
22	Orissa	159
23	Pondichery	43
24	Punjab	158
25	Rajasthan	222
26	Sikkim	2
27	Tamil Nadu	1814
28	Tripura	6
29	Uttar Pradesh	909
30	West Bengal	659
	Total	10889

Use of Natural Gas of Bombay High

2180. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Governments of Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat have requested the Union Government t allow use of Natural Gas produced by Bombay-High for consumers in Bombay;

(b) what is the total availability of gas for consumers exploitation produced by Bombay High and the decision taken by Government thereupon;

(c) what was the total quantity of gas produced from Bombay High during 1978, 1979 and 1980 and how was it distributed; and

(d) what is the expected target of natural gas from Bombay High during 1981 and 1982?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). No requests for supply of Bombay High gas to domestic consumers in Bombay have recently been received from these States.

It may be stated that the Working Group set up in 1977 for studying the utilisation of offshore gas in Maharashtra had *inter-aia* recommended that the Government of Maharashtra should study the various issues connected with the proposal for the supply of offshore gas through a net work of pipelines to domestic consumers as well as to the 45 textile mills listed in the Group's report including the question of textile mills using a mixture of LSHS and fuel oil instead of gas for the purpose of reducing the level of pollution. The Maharashtra Government accordingly appointed a Study Group in September 1978 to undertake the required study. The report of the Study Group has not yet been received by the Central Government and further action in the matter will be taken on receipt of the report.

(c) The total quantity of gas produced and distributed during the last 3 years is given below:—

(In million cubic metres)

Year	Total gas Produced	Gas distributed			
		Supply to TEC	Supply to RCFL	Consumed by ONGC	Flared
1978-79	385.88	167.72	28.69	7.76	181.71
1979-80	541.69	190.54	172.65	8.69	169.81
1980-81 (Upto Sept. 1980)	306.84	95.82	96.12	4.21	110.69

(d) The targets for supply of gas from Bombay High for 1980-81 and 1981-82 are as under :—

Year	Supply of Gas
1980-81	514 million cubic metres.
1981-82	652 million cubic metres.

Transmission Losses in Power Stations

2181. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn towards increasing percentage of "Transmission Losses" in all power Stations including State-managed units;

(b) whether Government have compared and found reasons for lesser percentage of "Transmission Loss" in private power stations operated by Tatas, etc.;

(c) what is the total loss of energy through "transmission losses" in the country during the last three years; and

(d) whether Government have invited U.S.S.R. Energy Technologists to put into operation the Soviet method of reducing the "transmission losses"?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The Government is aware of the trend in the power system losses, in the country on account of transmission, transformation, distribution, and commercial causes (power losses due to reasons other than technical).

(b) The main reason for lesser system losses in power operations of the privately operated Tata, Ahmedabad, Calcutta etc. Electric Companies is that these are mainly serving concentrated load centres and in urban areas. In rural electrification, distribution lines are spread over a vast area causing substantial losses;

(c) It is not possible to segregate the transmission losses from those on account of transformation, distribution, and commercial. The All India figures of system losses, for utilities, during the past three years are as follows:—

1979-80	. .	20.45% (Estimated)
1978-79	. .	20.02%
1977-78	. .	19.26%

(d) In the Memorandum of Undertaking between representatives of India and USSR on issues of cooperation in the field of power production, signed in November, 1980, reference has been made to the desirability of exchange of experience and know-how in the field of power systems development between the two countries. Details in this regard have not yet been finalised.

Special Loan assistance to various State Electricity Loan

2182. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Centre has given special loan assistance to various States Electricity Boards, if so, the amount of assistance given during the last 5 years to SEBs State-wise;

(b) whether it is a fact that various SEBs, are not working efficiently and have incurred huge losses, if so a list of SEBs with the amount of losses as on 31-3-1980;

(c) how much power was distributed through Regional Electricity Boards working under Central Electricity Authority during the last 5 years!

(d) how much power through various systems of generation was produced by SEBs and Public Sector Power units during the last 5 years; and

(e) what are the national targets of total power generation through all sources for the 6th Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The Government of India do not make any investment directly in any State Electricity Board. Central assistance for power development is included as a part of the overall central assistance to the States' Plan.

(b) Ten SEBs have cumulative losses upto 31st March, 1979, after taking into account:—

(i) Provisions to be made for

(a) Interest on Government Loans;

(b) Depr eciation; and

(c) Other revenue deficits, if any;

(ii) Subvenions from Government for Rural Electrification etc. and

(iii) Revenue Reserves, viz.,

(a) General Reserves;

(b) Investment Allowance Reserves;

(c) Development Reserves;

(d) Tariff Reserves; and

(e) Loan Redemption Reserves.

Only six of them, however, continued to incur losses during 1978-79 computed on similar lines.

Excluding Assam, Jammu and Kashmir and Meghalya in respect of which 1978-79 accounts are not available, five SEBs have earned profits on a cumulative basis up to 31st March, 1979.

In all nine SEBs have not sustained losses during 1978-79.

Statement indicating profits/losses of SEBs are enclosed (Statement I & II).

(c) The Regional Electricity Boards working under Central Electricity Authority are associated only with the exchange of energy. They are not distributing energy as such. The quantum of Inter-state and Inter-Regional exchange of power is enclosed (Statement III).

(d) The details of Electricity generation from various sources by State Electricity Boards and other Public Sector units during the year 1975-76 to 1979-80 are furnished in the State (Statement IV).

(e) According to Planning Commission, the National target of total power generation in 1984-85 is kept at 191 billion Kwh as per the Sixth Five Year Plan 1980-85.

Statement

Losses of State Electricity Boards

(After taking into accounts subventions from Govt.)

(Rs. in lakhs)

State Electricity Board	A	B
1. Uttar Pradesh .	42271	9144
2. Punjab . . .	8655	X
3. Haryana . . .	5401	361
4. Bihar . . .	5294	..
5. Orissa . . .	4391	1668
6. Gujarat . . .	3730	392
7. Himachal Pradesh .	2494	435
8. Andhra Pradesh .	1801	X
9. Kerala . . .	1240	X
10. West Bengal . .	591	129
TOTAL . .	75868	12129
11. Meghalaya (Cumulative to and for the year ended 31-3-77 respectively)	1505	98

A=Cumulative to 31-3-1979.

B=For the year ended 31-3-1979.

X=Earned profits during the year ended 31-3-1979. Punjab=512; Andhra Pradesh=668; Kerala=2215.

Statement—II

Profits of State Electricity Boards

(After taking into account subventions from Government).

(Rs. in lakhs)

State Electricity Board	A	B
1. Maharashtra . .	7992	1139
2. Tamil Nadu . .	6914	598
3. Karnataka . .	3964	1463
4. Rajasthan . .	1611	1221
5. Madhya Pradesh .	1458	74
TOTAL . .	21939	4495
6. Assam (Cumulative to and for the year ended 31-3-1978 respectively).	1124	X

A=Cumulative to 31-3-1979.

B=For the year ended 31-3-1979.

X=Sustained losses during the year end 31-3-1978=331.

Statement—III

Inter-State and Inter-Regional exchange of Power

(Million Units)

Year	Inter-state	Inter-Regional
1977-78 . .	7731	891
1978-79 . .	7878	1142
1979-80 . .	6800	784
1980-81 (upto Oct., 1980) . .	3806	616

Statement

Electricity Generation by State Electricity Boards and Public Sector during 1975-76 to 1979-80

(IN GWH)

Item	Hydro	Steam	Diesel	Gas	Nuclear	Total
1975-76						
I. *Public Sector*						
(a) State Elecy. Boards .	24596.06	26474.38	28.67	482.76	..	51581.87
(b) Electricity Deptts/ Govt. Undertakings/ Corporations/Central Sector . . .	7327.89	9500.65	30.02	..	2626.51	19485.07
(c) Municipalities .	11.15	1492.82	0.65	..	..	1504.62
Sub-Total (Public Sector) .	31935.10	37467.85	59.34	482.76	2626.51	72571.56
II. Private Sector . .	1366.67	5292.20	0.49	..	..	6659.36
Total (All India) (I+II)	33301.77	42760.05	59.83	482.76	2626.51	79230.92
1976-77						
I. *Public Sector*						
(a) State Elecy. Boards .	26619.41	31959.69	20.84	446.04	..	59045.98

(b) Electricity Deptts/ Govt. Undertakings/ Corporations/Central Sector . . .	6874.77	11217.01	34.07	..	3252.28	21378.13
(c) Municipalities .	4.15	1568.46	0.14	..	..	1572.75
Sub-Total (Public Sector)	33498.33	44745.16	55.05	446.04	3252.28	81996.86
II. Private Sector . .	1337.80	4998.65	..	..	..	6336.45
Total (All India) (I+II)	34836.13	49743.81	55.05	446.04	3252.28	88333.31

1977-78

Item	Hydro	Steam	Diesel	Gas	Nuclear	Total
I. *Public Sector*						
(a) State Elecy. Boards .	30094.29	34028.04	29.00	470.24	..	64621.57
(b) Elecy. Deptts/ Govt. Undertakings/Corpns./ Central Sector . .	6492.48	9707.10	31.75	..	2272.17	18503.50
(c) Municipalities .	3.39	1591.26	1.94	..	..	1596.59
Sub-Total (Public Sector)	36590.16	45326.40	62.69	470.24	2272.17	84721.66
II. *Private Sector* . .	1417.00	5230.37	..	..	..	6647.37
Total (All India) (I+II)	38007.16	50556.77	62.69	470.24	2272.17	91369.03

1978-79

I. *Public Sector*						
(a) State Elecy. Boards .	38045.78	35516.51	21.05	514.94	..	74098.28
(b) Elecy. Deptts./Govt. Undertakings/Corpns./ Central Sector . .	7627.08	9697.84	31.17	..	2769.68	20125.77
(c) Municipalities .	..	1410.03	3.08	..	..	1413.11
Sub-Total (Public Sector)	45672.86	46624.38	55.30	514.94	2769.68	95637.16
II. *Private Sector* . .	1486.00	5399.36	..	..	..	6885.36
Total (All India) (I+II)	47158.86	52023.74	55.30	514.94	2769.68	102522.52

			1979-80			
I. *Public Sector*						
(a) State Elecy. Boards .	37180.10	39637.50	27.92*	499.98	..	77345.50
(b) Elecy. Deptts./Govt. Undertakings/Corpons/ Central Sector . .	7003.88	9380.36	24.68*	..	2876.59	19285.51
(c) Municipalities .	..	1465.38	1.38*	..	..	1466.76
Sub-Total (Pvt. Sec.) .	44183.98	50483.24	53.98	499.98	2876.59	98097.77
II. *Private Sector* . .	1308.00	5310.00	..	..	..	6618.00
Total (All India) (I+II)	45491.98	55793.24	53.98	499.98	2876.59	104715.77

*Figures Provisional.

Plan for free sale of non-coking and domestic coal

2183. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Coal India has drawn a plan for free sale of non-cooking and domestic coal;

(b) whether this would stop boarding of coal, black-marketing and bring down the prices of domestic and non-cooking coal;

(c) whether the free sale coal would be channelised for sale through co-operatives and Public Distribution System;

(d) whether it is a fact that some States have objected to the above proposal and wished to retain the power of issuing coal permits; if so, the names of these States; and

(e) whether Government propose allowing other States free sale of coal by opening dumps of Coal India for distribution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). Only non-coking coal from certain identified mines has been put on free sale with a view to pass on the benefit of improved production to the consumers.

(c) It will be sold direct to the purchaser.

(d) No Sir.

(e) Free sale of coal is done from the collieries and does not require the opening of dumps.

Suggestions made by Maharashtra Government at Information Minister's Conference

2184. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of demands and suggestions were made on behalf of Maharashtra Government in November, 1980, Conference of Minister of Information at Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) what action Government have taken or propose to take soon; and

(d) if no action has so far been taken or proposed, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). Suggestions from some of the State Governments including the Government of Maharashtra, and Union Territories were received for inclusion in the agenda of the Fifteenth Conference of State Ministers of Information held in New Delhi in November, 1980. The topics, in brief suggested by Government of Maharashtra were: Assistance for expansion of Community Viewing Scheme; Replacement of Community TV sets; Disparity in Advertisements Rates; State Quota in Central Information Service; PIB offices at Revenue Headquarters; Exemption of Excise duty on Documentary and News reels; Opportunity for participation in Film Festivals; Theatres for Bombay; Dubbing of State Governments Documentaries; Sales Tax Exemption on Raw Stock; State Government Censor Board; Coordination for Export of Documentaries; Mutual Exchange of Documentaries; and lastly Printer-Publishers Obligation.

(c) and (d). Keeping in view the wide range of topics received from the States/Union Territories, a comprehensive agenda for the said Conference was prepared which included items of common interest and importance such as: the Report of the Working Group on National Film Policy; Production and distribution of Films; Censorship Violations; Community Viewing/Listening Schemes; Setting up/Strengthening of Radio/TV transmitters; Liaison with State Governments and authorities of AIR and Doordarshan Kendras; Facilities to small and medium newspapers; Adverisements to Employment News; Strengthening/Shifting of Information Centres; Press Registration of Books Act, 1867; Coordination of Central and State media activities etc. After detailed discussions, decisions were taken on various issues by consensus. The minutes of the said Conference have already been circulated to all concerned for initiating further action.

Film on Veer Savarkarji

2185. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have undertaken to have a film on the life of Veer Savarkarji in the year 1978;

(b) what progress has been made in that respect;

(c) what is the financial estimate of the project; and

(d) when the project is likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) to (d). A film on 'Veer Savarkarji' was included in the Production Programme of the Films Division for the year 1977-78. The Film was, however, later dropped from the Production Programme because of high number of biographical films in the Programme. It is now proposed to consider the inclusion of this film in the Production Programme for the year 1981-82. The financial estimate of the project would be around Rs. 2,00,000/- to Rs: 2,50,000/-

Rated capacity and actual Generation of each Power Unit in Bihar

2186. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what is the last position with regard to the rated capacity and actual generation of each of the power units in Bihar including those based on diesel, coal, hydel; and

(b) what steps are being taken to ensure full capacity generation in Bihar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) The station-wise details about installed gen-

erating capacity gross energy generation and plant load factor of power stations of Bihar in January, 1981 is given below:

Station	Particular	January, 1981
Thermal		
Patratu	Capacity (MW)	620
	Gen. (Million Units)	157
	PLF (%)	34
Barauni	Capacity (MW)	145
	Gen. (Million Units)	37
	PLF (%)	34
Hydro		
Kosi	Capacity (MW)	15
	Gen. (Million Units)	2
Subernarekha	Capacity (MW)	130
	Gen. (Million Units)	8

The generation capacity of the diesel units in Bihar is negligible and these units are operated only for emergency supply to essential consumers and their operation is not being monitored by the Central Electricity Authority.

(b) The utilisation of hydel power stations depends on the design potential of the plant and the water availability. In order to improve the capacity utilisation of thermal power plant in Bihar, the following steps have been taken by the Government.

(i) A high level team from Central Electricity Authority NTPC & BHEL had visited Patratu & Barauni thermal power stations to make recommendations for improving the performance of thermal power stations;

(ii) Monitoring cells one each at Patratu and Barauni thermal power stations and Boards Head quarter have been formed to monitor effectively maintenance and construction works;

(iii) A spare parts cells has been created at Boards Head Quarters to survey requirement and identification of spares. Action is also being taken for procurement of adequate number of fast moving and slow moving spares;

(iv) For maintenance works of long duration, preparation of pertnet-works and micro-planning is being done and monitored to achive milestones by targets dates;

(v) Task force/teams have been formed at both the above thermal power stations to sudy and identify the problems related to generation. Constraints in the generating sets have been identified and action plan for removal of these constraints have been prepared.

(vi) All the tripping and outages are recorded and every outage and trippings is analysed now and where remedial measures are called for they are promptly attended to. Where outage and tripping are taking place on account of mal-operation, suitable action is being taken to ensure proper operation of the Units.

(vii) Action have been taken and are being taken to stock sufficient control and instrumentation equipments so that these may be used immediately whenever required.

राज्यों में खास कर राजस्थान में बिजली संकट

2187. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य गम्भीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस संकट में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ;

(ख) क्या बिजली संकट के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति गत वर्ष की तुलना में ज्यादा बदतर है ;

(ग) क्या सरकार को कृषि और उद्योग दोनों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के विस्तार की कोई जानकारी है; और

(घ) इस बिजली संकट पर काबू पाने के लिए निकट भविष्य में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा ऊत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य, दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य, पूर्वी क्षेत्र में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं ।

(ख) अप्रैल से नवम्बर, 1980 की अवधि के दौरान राजस्थान में विद्युत् की औसत उपलब्धता पिछले वर्ष की इसी अवधि की औसत उपलब्धता से लगभग 3.6 प्रतिशत अधिक थी । राजस्थान परमाणु विद्युत् संयंत्र की 220 मेगावाट की यूनिट सं० 1 में 18 दिसम्बर, 1980 से 28 जनवरी, 1981 तक बंदी हो जाने के कारण तथा इस वर्ष नदी अन्तर्वाहों के कम होने के कारण चम्बल तथा भाखड़ा-व्यास काम्पलैक्स से कम उत्पादन होने के कारण राजस्थान में दिसम्बर, 1980 में विद्युत् सप्लाई की स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी । 28 जनवरी, 1981 से राजस्थान परमाणु विद्युत् संयंत्र यूनिट सं० 1 के पुनः चालू हो जाने से राजस्थान में विद्युत् उपलब्धता में कुछ सुधार हुआ है ।

(ग) उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 50 से 70 प्रतिशत तक विद्युत् कटौतियां/प्रतिबन्ध लगाए गए हैं । तथापि, मध्यम और लघु उद्योगों पर अब कोई विद्युत् कटौती नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों को भी कम से कम 6 घण्टे प्रतिदिन विद्युत् सप्लाई की जाती है ।

(घ) 1980—85 की अवधि के दौरान राजस्थान प्रणाली में लगभग 496 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आशा है । इस के अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में 1980–85 के दौरान चालू होने वाली कुछ केन्द्रीय विद्युत् परियोजनाओं से भी राजस्थान को लाभ प्राप्त होंगे ।

Power Projects and rural electrification scheme of Rajasthan pending with the Centre

2188. PROF. NIRMALA KUMARI SHAKTAWAT: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the number and names of power projects and rural electrification schemes submitted by Rajasthan Government which are pending for approval of the Central Government;

(b) the time since when these schemes are pending; and

(c) the time by which these projects and schemes are likely to be approved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN) (a) to (c) The proposals for hydro and thermal power projects received from the Government of Rajasthan/Rejasthan State Electricity Board which are pending for clearance in the Central Electricity Authority and their present status are shown in Statement I. There are 62 rural electrification schemes involving loan outlay of Rs. 17.25 crores submitted by the Rajasthan State Electricity Board pending clearance in the Rural Electrification Corporation. The details of these schemes are shown in Statement II. 23 other rural electrification schemes involving loan outlay of Rs. 8.41 crores were received in the Rural Electrification Corporation but these have been referred back to the Rajasthan State Electricity Board for revision/clarifications. The details of these schemes are shown in Statement III. Clearance of the Rural electrification schemes by Rural Electrification Corporation is subject to their techno-economic viability and availability of funds. On the basis of the allocation of funds for disbursement as first year's instalment for new schemes, the Rural Electrification Corporation will be in a position to sanction more schemes involving a total outlay upto Rs. 2,00 crores during the current financial year.

Statement I

The Proposals for Hydro and Thermal Power Generation Projects received from the Government of Rajasthan, Rajasthan State Electricity Board which are pending in the Central Electricity Authority for clearance and their Present Status.

Sl. No.	Project	Installed Capacity (MW)	Estimated cost (Rs. in crores)	Date of receipt	Present status
1	2	3	4	5	6
1.	Right Main Canal (Chambal Project) Hydel Scheme.	4X2	5.58	February, 1980	The Project report was examined in the CEA/CWC and their comments have been sent to the project authorities whose replies are awaited.
2.	Mount Abu Hydel Scheme.	2X1.25	5.16	October 1979	The comments of CEA/CWC have been sent to the project authorities. The CWC has given the opinion that the project may be recast as multipurpose project taking into account the comments of CEA/CWC.
3.	Palana Lignite Thermal Project.	2X60	67.98	February 1979	The scheme has been given techno-economic clearance by CEA and is awaiting investment decision.

Statement II

Names of 62 Rural Electrification Schemes which have been submitted by the Rajasthan State Electricity Board and their present status.

Sl. No.	Name of the Scheme	Loan amount (Rs. in lakhs)	Date of receipt of scheme/revised scheme
1	2	3	4
1.	TRW at Bhratpur	15·550	21-10-80
2.	TRW at Kota	12·096	21-10-80
3.	Moondwa PS Nagur District	92·821	12-11-80
4.	Sankra Ps Jaisalmer District	29·493	20-1-81
5.	Sam PS Jaisalmer District	25·029	20-1-81
6.	Sultanpur PS Kota District	49·352	17-11-80
7.	Sagwara PS Dungarpur Distt.	60·358	17-12-80
8.	Chohtan PS-XX Barmer Distt.	90·749	19-12-80
9.	Chohtan PS-I Barmer Distt.	67·686	19-12-80
10.	Suratgarh PS Sriganganagar District	120·477	4-7-80
11.	Padampur PS Sriganganagar District	74·086	21-10-80
12.	Sangod PS Kota District	19·547	20-1-80
13.	Keshcreipatan PS Bundi District	83·738	26-2-80
14.	Talera PS Bundi District	17·335	12-11-80
15.	Garhi PS Banswara District	20·175	17-12-80
16.	Talwar a PS Banswara Distt.	14·119	17-12-80
17.	Ramgarh PS Alwar Distt.	46·450	20-12-80
18.	Bayana PS Bharatpur Distt.	54·798	23-12-80
19.	Jhunjhunu PS Jhunjhunu Distt.	12·527	23-12-80
20.	Raniwara PS Jalore Distt.	63·201	7-1-81
21.	Jaswantpure PS Jalore Distt.	11·965	29-1-80
22.	Dudu PS Jaipur District	52·586	24-1-81
23.	Sktora PS Ajmer District	37·971	24-1-81
24.	Pindwara PS Sirohi District	17·734	31-1-81
25.	Raipur PS Pali District	49·281	31-1-81
26.	Rijanbiri PS-I Nagur Distt.	36·684	29-12-80
27.	Rijanbari PS-II Nagur Distt.	49·876	17-1-81
28.	Bass PS Jaipur District	52·198	6-1-81

1	2	3	4
29.	Deogarh PS Udaipur Distt.	25·284	29-12-80
30.	Bhinmal PS Jalore Distt.	49·659	29-12-80
31.	Sumerpur PS Pali Distt.	17·653	29-12-80
32.	Khanpur PS Jhalwar Distt.	24·865	6-1-81
33.	Nadhai PS (South) Bharatpur district	51·668	6-1-81
34.	Nadhai PS (North) Bharatpur District	48·544	6-1-81
35.	Karanti PS S. Madhopur Distt.	29·887	6-1-81
36.	Jaitaran PS Jodhpur Distt.	49·859	24-1-81
37.	Shaoganj PS Sirohi District	15·308	24-1-81
38.	Nawalgarh PS Jhunjhuni Distt.	31·794	29-1-81
39.	Mahuwa PS S. Madhopur Distt.	0·526	1-9-80
40.	Todabhim PS Madhipur Distt.	0·338	1-9-80
41.	Karauli PS S. Madhopur Distt.	1·392	1-9-80
42.	Kekri REC s/Dajmer Distt.	0·943	12-6-80
43.	Bharatpur O & M S/D Bharatpur Distt.	2·767	20-6-80
44.	Deog O & M S/D Bharatpur Distt.	0·850	20-6-80
45.	Srimadhopur S/D Sikar District	0·787	20-6-80
46.	Shanpur S/D Bhilwara Distt.	0·365	19-2-80
47.	Degana REC S/D Nagpur Distt.	0·281	12-6-80
48.	Kankroli O & M S/D Udaipur Distt.	0·368	9-7-80
49.	Bhinder O & M S/D Udaipur Distt.	0·126	9-7-80
50.	Udaipur CSI-II Udaipur Distt.	0·290	9-7-80
51.	Banswara O & M S/D Banswara Distt.	0·430	9-7-80
52.	Biyanbari Mertacity-I Nagur Distt.	1·440	7-1-81
53.	Rijanbari Mertacity, II Nagur District	1·174	7-1-81
54.	Parbatsar Nagur District	1·333	7-1-81
55.	Deebwanar Nagur District	0·042	7-1-81
56.	Arain PS-I Ajmer District	0·236	7-1-81
57.	Arain PS-II Ajmer Distt.	0·264	20-1-81
58.	Parbatsar Nawa PS Nagur District	1·413	7-1-81
59.	Kuchaman City Nagur Distt.	0·202	7-1-81
60.	Railmangza S/D Udaipur Distt.	0·667	20-1-81
61.	Kankroli O & M S/D Udaipur Distt.	0·284	20-1-81
62.	Salumber & Cirwa PS Udaipur District	0·211	20-1-81
		1725·228	

Statement III

The names of 23 Rural Electrification Schemes received from the Rajasthan State Electricity Board but were referred back to the Board for revision/clarifications.

Sl. No.	Name of the Scheme	Loan amount (Rs. in lakhs)	Date of receipt in REC	Date of referred back to RSEB
1	2	3	4	5
1.	Phalodi & Bap PS Jodhpur District	33.171	31-10-79	16-9-80
2.	Rajeo & Gusaisar Churu District	33.972	31-10-79	16-9-80
3.	Rampura & Buchwas Churu District	32.261	31-10-79	16-2-8 o
4.	Dungla PS Chittorgarh District	57.854	22-9-79	1-8-79
5.	Chechat PS Kota Distt.	26.509	2-4-80	3-6-80
6.	Gangapur PS. S. Madhopur District	45.254	2-4-80	6-8-8 o
7.	Hindaum PS. S. Madhopur District.	39.762	7-7-80	5-8-8
8.	Baltora PS-I Barmer district	86.327	31-7-80	22-10-8
9.	Baltora PS-II Barmer District	52.235	2-9-80	22-10-80
10.	Mandore PS Jodhpur Distt.	17.341	28-5-80	5-9-80
11.	Reodhar PS Sirohi Distt.	23.190	6-6-80	13-11-80
12.	Tizara PS Alwar Distt.	15.077	9-9-80	6-1-81
13.	Kishangarh PS Alwar District	19.060	12-11-80	1-6-81
14.	Dausa PS Jaipur Distt.	49.348	12-11-80	6-1-81
15.	Kuchaman PS REC S/D Nagaur Distt.	47.635	15-11-80	7-1-81
16.	Kuchaman PS Makrana O & M S/D Nagaur District	32.147	27-11-80	6-1-81
17.	Jambaramgarh PS Jaipur Distt.	31.072	8-10-80	6-1-81
18.	Weir PS Bharatpur Distt.	29.427	8-12-80	12-1-81
19.	Roopwas PS Bharatpur Distt.	49.284	16-10-80	12-1-81
20.	Dhod PS Sikar Distt.	24.895	22-12-80	22-1-81
21.	Laxmangarh Sikar Distt.	23.528	29-12-80	22-1-81
22.	Jhalwar (SI) District	40.490	Dec., 78	Dec., 80
23.	Kankroli of Udaipur	32.010	March, 79	Dec., 80
		841.849		

Money advanced by F.F.C. and N.F.D.C. for film production

2189. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) how much money has been advanced during the calendar year 1980 by the Film Finance Corporation and by the National Film Development Corporation in the country;

(b) the names of the producers/directors who have received money and the terms on which the money has been given to them; and

(c) how many applications for loans are pending with Government and for what amount?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUD BEN M. JOSHI): (a) Loans sanctioned by FFC/NF DC are disbursed in instalments. For instance a loan sanctioned in 1980 may be released partly in 1980 and partly in the subsequent years. In the caledar year 1980 FFC/NFDC advanced loans of Rs. 26,16,696.50 to 24 producers/directors for production of films.

(b) A statement giving the names of producers/directors who received loans from FFC/NFDC during 1980 and the amount received by them is attached. The broad terms on which loans are sanctioned by the Corporation are (i) the loanees are required to furnish guarantee or security (collateral or otherwise) for payment of loan (ii) the corporation is assigned, in addition to the world rights, the first charge and paramount lien *inter alia* on the film, its picture and sound negative, rush prints, all sizes, including video rights, costumes, script, scenario, songs, copy rights etc; (iii) the money advanced is repayable in the case of feature films on the expiry of two years from the date of advance of the Ist instalment of loan or on the thirtieth day from the date of release of the film any where whichever is earlier, and in the case of documentary or short films the due date of repayment of loan is six months from the date of release of first instalment or thirtieth day of delivery of the documentary/short film to its sponsors whichever is earlier; and (iv) interest at the rate of 15 per cent per annum is charged.

(c) As on 31-12-1980, sixteen applications for loans of Rs. 59.61 lakhs were pending with the Corporation.

Statement

The names of producers/directors to whom loans have been advanced by FFC/NFDC during the Calendar year 1980.

Sl. No.	Name of the Producer	Name of the film	Amount Advanced
1	2	3	4
1.	Yukt Film Society Ltd.	Arivind Desai ki Ajeeb Dastan.	11,988.68
2.	Premsinh Varma	Tiger Uncle	15,255.61
3.	S. Sukhdev	Doc. on Meena Kumari	13,267.23
4.	N. Patwardhan	22nd June 1897	37,852.22
5.	KRSNA Movies	(Sanket) Askrosh	72,328 04
6.	Jahnu Barua	Aparupa	25,054.77

1	2	3	4
7.	Chitra Bharath	(Vizhippu) Sooravali	80,593.63
8.	Sanchr Film Co-op. Society Ltd.	Bhavani Bhaval	1,59,774.93
9.	Saeed Akhtar Mirza	Albert Pinto Ko Gussa Kyon Aata Hai.	1,13,053.49
10.	Kalinga Film International	(Garam Bhat Ya Bhoot ki Kahani) SHODH	89,259.60
11.	M. S. Sathu	Bara	2,14,182.23
12.	Bharat Chalchitra	(Harijan Cheupal) Naya Jeevan.	23,000.00
13.	Neo Films	Chakra	3,55,000.00
14.	Tanvir Ahmed Production	Chirutha	3,38,645.46
15.	Durga Khote Production	Abortion	38,910.25
16.	Vinod Chopra Production	Sajaye Mout	3,36,239.09
17.	Kavita Films	Pratishodh	74,863.15
18.	M. Sarkar Production	Aswamedhar Ghora	2,09,428.22
19.	Filmvalast	36 Chowringhee Street	2,25,000.00
20.	Balwant Gargi	Yamini Krishnamurthi	50,000.00
21.	B. D. Garga Production	Seepz	30,000.00
22.	Prakash Arora	Drop that Counts. (Petroleum Conservation)	5,000.00
23.	B. D. Garga	Pay your Tax & Relax	38,000.00
24.	Kalatmak	Pankaj Mallik	59,000.00
	TOTAL		26,15,696.50

Investment by public trusts in Industrial Undertaking

2190. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some Public Trusts are investing their funds in industrial Undertakings.

(b) if so, the names of Trusts with the names of the Trustees; and

(c) the total amount invested in each Industrial Undertaking?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement based on the information filed by the Trustees of these Public Trusts, where their investment in Companies, including industrial undertakings, exceeds the limits prescribed in the Companies Act, 1956, is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2013/81].

Observation made by Chief Justice of India at Allahabad

2191. SHRI R. L. BHATIA:
SHRI NAWAL KISHORE SHARMA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Justice of India while addressing the Allahabad High Court Bar Association on 1st January, 1981 *inter-alia* said that some members of the Bar complained to him that sons and daughters of judges who were practising in some of the High Courts were exploiting the position of their fathers in getting briefs;

(b) whether he also appealed to the judges whose children were practising in those High Courts where they were functioning that they should voluntarily offer themselves for transfer to other High Courts; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). According to the information furnished by the Registry of the Supreme Court, the Chief Justice of India addressed the members of the Allahabad High Court bar on January 1, 1981, and in his speech said that Judges themselves were not to be blamed but one could shut one's eyes to the fact that the close relations of Judges got some benefit by reason of their relationship. The Chief Justice of India also said in that speech that in the larger interest of the administration of justice, Judges whose close relations were practising in their courts, should come forward and opt for transfers to other High Courts voluntarily.

(c) If any Judge requests for transfer to other High Courts, his request will be considered sympathetically.

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम

2192. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार क, ख और ग राज्यों के लिए राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को यह कार्यक्रम नियमित रूप से प्राप्त होता है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1980 के लिए राज्यों की इन तीनों श्रेणियों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस कार्यक्रम की क्रियान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा प्रयास किए गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान राज्यों की इन सभी तीनों श्रेणियों में राजभाषा के रूप में हिन्दी के उपयोग में हुई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): (क), (ख) और (घ). जी, हां।

(ग) और (ङ). एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया। [देखिये संख्या LT—2014/81] जहां तक विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधीन अधिकारियों का सम्बन्ध है, राज्यवार जानकारी सभा के पटल पर रख दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । [देखिये संख्या LT—2014/81] कम्पनी कार्य विभाग के

अधीन अधिकारियों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Complaints of mismanagement in D.D.C.A.

2193. SHRI KAMAL NATH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether complaints have been received regarding mal-practices, mismanagement and manipulation of accounts against Delhi and District Cricket Association, which is registered as a Private Limited Company;

(b) nature of such complaints; and

(c) steps Government has taken or propose to take to rectify the same?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). The last complaint received against the company was in 1975. An inspection of the company under Section 209A of the Companies Act, 1956 was ordered and carried out during July, 1976. The report revealed certain irregularities which, *inter alia*, included:

(1) failure to submit annual account and balance sheet in time;

(2) wrong accountal of the rent received from the godown of the company;

(3) some violations under Section 211 read with Schedule VI in regard to certain receipts;

(4) failure to comply with the provisions of Section 297/301 in respect of hiring of a godown;

(5) some violations of the Objects Clause in regard to temporary members;

(6) improper maintenance of proxy register;

(7) certain advances being wrongly treated as "bad debts".

(8) default in realisation of advertisement charges. These findings are being pursued for suitable remedial action.

Aromatics complex at Cochin.

2194. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) when the Kerala State Industrial Development Corporation Limited had applied for a letter of intent for an Aromatics Complex at Cochin;

(b) Details of action taken by the Government of India on the application;

(c) is it not a fact that the site selection committee headed by Dr. Tilak appointed by the Government of India had recommended the location of the project at Cochin;

(d) if so, what is the reasons for the delay on the part of the Government of India in issuing the letter of intent; and

(e) when the Government of India propose to issue the letter of intent?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) In September, 1980.

(b) I has been decided to reject the proposal as the sources for the supply of base raw material has not yet been identified.

(c) The Site Selection Committee set up to make recommendations for the various locations on techno-economic considerations for setting up plants for the production of Aromatics has not yet submitted its Report.

(d) and (e). Do not arise.

Street light in R.P. block of Pitampura D.D.A. Colony

2195. SHRI KRISHNA PRATAP SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Officers of D.E.S.U. do not visit colonies themselves and leave the residents at the mercy of area inspectors who do not care for the welfare of the people;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) in case they visit, how many times they have visited the Pitampura Residential Scheme which is a very big D.D.A. colony and what steps they have taken to provide street lights on all poles fitted in the Block R-P, where only a very few poles have bulbs which lit in the night?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). DESU Engineers/Officials periodically visit the various colonies in connection with the preparation and execution of various electrifications schemes in Pitampura Residential Complex being developed by D.D.A. from time to time. 17 site inspections were also carried out by the Engineers of the Distribution Department during the last one year. In addition to the above visits, officers visit the various areas whenever there is an Emergency.

All the street lighting poles in pocket 'R'—Poorvi are reported to have been provided with street lighting fittings including tubes or bulbs etc. and Street Lighting System in this pocket is being maintained satisfactorily.

Vacant posts of Superintendents in Sessions Courts

2196. SHRI SATISH PRASAD SINGH. Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of posts of Superintendents in the Session's Courts are lying vacant and since when;

(b) the reasons for delay in filling up the posts; and

(c) by what time they are likely to filled up?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Vialation of companies Act by M/s. Perco Electronics Electricals Limited.

2197. SHRI H. N. GOWDA:
SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI N. E. HORO:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are some complaints/allegations against M/s. Perco Electricals Limited, formerly known as Phillips India Limited, Bombay regarding violation of Companies Act, 1956, etc. and if so, full details thereof;

(b) whether any investigation has been carried out by the Company Law Board and if so, details thereof; and

(c) action contemplated by the Government in the matter?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Evidently the Hon'ble Members wish to seek information about M/s. Perco Electronics & Electricals Ltd., Calcutta, formerly known as Phillips India Ltd. In respect of this Company, a complaint regarding contravention of Section 211 read with Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956, for non-disclosure of quantitative details in its Balance Sheet as at 31st December, 1978 was

received. The matter is under consideration.

Some complaints regarding delay in refunding share application money were also received but further inquiries did not reveal any violation of the provisions of Companies Act, 1956.

(b) and (c). An inspection in the usual course under Section 209A of the Companies Act, 1956 has recently been ordered by the Department and the report is awaited.

Allegations against Calcutta Chemical Company

2198. SHRI NIREN GHOSH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the serious allegations made against Calcutta Chemical Company, West Bengal in 'Dainik Basumati' dated November 4, 1980 December 5, 1980 and December 12, 1980 and 'Business Standard' dated October 10, 1980;

(b) if so, has any inquiry been instituted by the Company Law Board;

(c) whether any report has been submitted;

(d) if so, what are the contents of the Report;

(e) will the Report be laid on the Table of the House;

(f) if not, why; and

(g) will any action be taken on the basis of the Report?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIVSHANKAR): (a) Copies of 'Dainik Basumati' (published from Calcutta) of the issues dated 4th November 1980, 5th December, 1980 and 12th December, 1980 are not readily available but the 'Business Standard' dated 10th October, 1980 does not appear to contain any news report regarding this company. However, a letter dated 27th January, 1981 has been received in the Department from the Hon'ble Member drawing the attention of Government to the press reports referred to.

(b) to (d). An inspection of the books of accounts of the Company under section 209A of the Companies Act was ordered in December 1979 as a large number of complaints had been received in the Department from the shareholders and ex-directors of the company. The inspection report, (received in the Department on 30th October, 1980) revealed various irregularities and acts of mismanagement. The significant findings related to falsification of the published accounts and distortion of the working results of the company for the years ending 30th June, 1976, 30th June, 1977, 30th June, 1978 and 30th June, 1979 with a view to present a better financial position of the company, participation in the day-to-day management of the company of one Shri D. P. Barua, who was neither a director nor an employee of the company, as an invitee to the meetings of the Committee of Management; acquisition of shares by Shri D. P. Barua which could eventually lead to the change in the control and management of the company to its detriment; selling arrangements with M/s. Aparna Distributors Pvt. Ltd. and M/s. A. K. Pharmaceuticals Agencies Ltd., Nepal prejudicial to the company's interest, bulk purchases of sub-standard oil from M/s. Ganga Soap Factory despite its unsuitability; purchase of tallow during the years 1977-78 and 1979-80 at unduly high rates; serious shortage in the stocks and above all the finalisation of the accounts for the years 30th June, 1977 to 30th June, 1979, without depicting the true and fair view of the state of affairs of the company in contravention of the provisions of the Act.

(e) and (f). The answer to earlier parts of the question highlights, the main irregularities. However, it will not generally be in public interest to lay a copy of the inspection report(s) on the Table of the House not only because it might affect the free and frank expression of opinion by the inspecting officers but also because the

reports may contain one-sided views of the inspectors and the company inspected might not have had due opportunity to explain the points mentioned in the inspection report.

(g) On the basis of the findings of the inspection report, a show cause notice under section 408(1) of the Companies Act, 1956 had been issued to the company and all its directors by the Company Law Board as to why directors should not be appointed under the aforesaid provisions in order to prevent the affairs of the company being conducted either in a manner which is oppressive to any members of the company or in a manner which is prejudicial to the interest of the company or public interest. The reply of the company has since been received and the matter is under examination. Further, on the basis of a complaint under Section 409 of the Companies Act, 1956 by one of the Directors of the company, the Company Law Board by its order dated 19th December, 1980, directed that pending the completion of the enquiry under sub-section (1) of section 409 of the Companies Act, no resolution of the company or its Board of Directors passed or that may be passed or no action taken or that may be taken to effect a change in the Board of Directors after the date of complaint shall have effect unless confirmed by the Central Government. The enquiry under Section 409 is in progress.

उत्तर प्रदेश तथा बिहार विधान सभाओं में रिक्त स्थान

2199. श्री रामावतार शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार विधान सभाओं में कुछ स्थान रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्वाचन क्षेत्रों में उप-चुनाव कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त रिक्त स्थानों के लिए उप-चुनाव कब तक कराये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां। इस समय बिहार विधान सभा में पांच तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में सात स्थान रिक्त हैं।

(ख) बिहार राज्य विधान सभा के रिक्त स्थानों के लिए उप-निर्वाचन पहले इसलिए नहीं कराए जा सके क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ क्षेत्र पहले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित थे और राज्य सरकार के लिए वहां मतदान करना संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश विधान सभा के रिक्त स्थानों के मामले में राज्य सरकार ने सभी रिक्त स्थानों में मुख्य रूप से विधि और व्यवस्था के आधार पर उप-निर्वाचन कराने में असमर्थता व्यक्त की थी।

(ग) देश भर में जनगणना कार्य पूरा हो जाने पर निर्वाचन आयोग लम्बित उप-निर्वाचन कराने के बारे में विनिश्चय करेगा।

Social Security of Lawyers

2200. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that majority of lawyers at all levels are facing conditions of material provisions due to lack of briefs by paying clients;

(b) if so, the actual state of affairs and reaction thereon;

(c) whether any scheme of social security, provident fund, guaranteed briefs at Government cost, libraries, residential lands etc., is being contemplated, if so, details thereabout, if not, the reasons therefor;

(d) whether young Advocates of Chhapra, Madhubani and other districts of Bihar boycotted the courts on 24th January, 1981 demanding nationalisation of legal procession etc., if so, details of their demands and Government reaction thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). Government has not undertaken any survey of the economic and material conditions of members of the legal profession and as such has no clear information.

(c) No, Sir. Any scheme of social security launched by Government would have to be for the community as a whole and not for any limited section thereof.

(d) Government has no information whether young advocates of Chhapra, Madhubani and other districts of Bihar boycotted the courts on 24th January, 1981 demanding nationalisation of legal profession, etc., however, Government has received a copy of the resolution passed by the Sitamarhi Bar Association, Sitamarhi (Bihar) dated 20th February, 1981. The Association had passed two resolutions, the first resolution supports the demands of the District Young Lawyers Association, Madhubani, and by the second resolution it was resolved to boycot the courts on 24th and 25th February, 1981. Government has not received any letter of demand from advocates of Chhapra or Madhubani, but an appeal from District Young Lawers Welfare Committee, Goda (Bihar) has been received. The demands mentioned therein were:

(i) equi-distribution of cases among lawyers by the Government,

(ii) abolition of the system of government advocates, APP, etc., by substituting advocates from the Bar Associations,

(iii) providing facilities like housing, libraries, insurance, pension for old age and handicapped lawyers, and

(iv) appointment of Magistrates and Judges from among the advocates.

Government is not considering the nationalisation of the Legal Profession or regulating the distribution of briefs among Counsel other than those engaged by it.

---

12 hrs.

RE. SUPPLY OF BRIEFS TO MEMBERS BY MINISTRIES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, हमने एजोर्नमेंट मोशन दिया है कि श्री ज़ैल सिंह ने कांग्रेस (आई) के सम्बन्ध में होम मिनिस्ट्री के एडीशनल सेक्रेटरी को लिखा है कि वे उन को ब्रीफ करें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार और पार्टी में कोई अन्तर है या नहीं ? (व्यवधान) ...

MR. SPEAKER: Please listen to me. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am to decide it. I received this morning several notices drawing attention to the Press reports appearing today to the effect that the Home Minister is reported to have given directions for some briefs to be provided to some Members of the Ruling Party through the Party Office. This matter caused me concern and I took it up immediately with the Government. I have received a few minutes ago a letter from the Home Minister which is self-explanatory. The Home Minister has stated in his letter:

"On receipt of a letter from Shri Prakash Mehrotra, Secretary, Congress (I), dated the 9th February, 1981 asking for supply of background material for the use of Members on issues concerning my Ministry likely to come up in the Parliament, I had issued instructions to the Departments under my Ministry for necessary action in the matter. At that time I had thought that this would enable the Hon'ble Members to make useful contribution to discussions ...."

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Only to those belonging to the ruling party. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Why are you interrupting me? Let me complete.

"At that time I have thought that this would enable the Hon'ble Members to make useful contribution to discussions and debates in the Parliament on those issues. As a matter of fact, if a similar request had been received from the Opposition parties I might have given the same directions to the Departments."

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat) .... might have given...?

MR. SPEAKER: Yes, "might have given the same directions to the Departments."

"However, on careful consideration of the matter I found that this would lead to complications. Accordingly, I have since withdrawn these instructions. I may add that no such material has been supplied so far. Anticipating that the Hon. Members may raise this issue consequent upon a news item appearing in a section of the Press, I am bringing these facts to your kind notice."

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Does it not sufficiently show that all this has been done surreptitiously? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I need hardly stress that in such matters which affect the interest of Members, every care should be taken to see that Parliamentary conventions are duly observed. This is what I wanted to say.

श्री रामविलास पासवान : अखबार में यह बात आई, इसलिए हम लोगों की नालिज में यह बात आई .. (**व्यवधान**)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, on a point of order ....

MR. SPEAKER: We would have faced the situation as it comes. We would have crossed the bridge when it comes.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: Whatever the rules would have permitted, I would have taken decision accordinly.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: Not allowed.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: Nothing is going on record without my permission. I have not allowed any Member to speak.

(*Interruptions*)**

मैं यह कह रहा हूं कि आप चार-पांच बोलेंगे तो किसी को पता नहीं लग सकता कि आप क्या बोल रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूं ।

Why are you speaking without my permission when I am prepared to listen ....? You are also speaking without my permission.

(*Interruptions*)**

I can listen but not like this. Please sit down.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): आपने पहले मुझे बुलाया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका जवाब दे दिया है ।

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। इस प्रकार का डेमोक्रेसी में नहीं होता है । आप होम मिनिस्टर से माफी मंगवाइये, होम मिनिस्टर माफी मांगें । (**व्यवधान**) ।

MR. SPEAKER: I have done it; no hypothetical positions.

(*Interruptions*)

**Not recorded .

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): It is the right of member to ask for information; it is the right of a Minister to supply information. What is the breach of privilege? We do not agree to this at all. No question of privilege, no question of *mafi*. And, do not try to bully the Speaker.

MR. SPEAKER: Why are you doing this?

आप क्यों बोल रहे हैं ?

AN HON. MEMBER: They should be ashamed of it.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): We are not shamed of it. This is our right; this is our obligation. The question of privilege arises only when we ....

MR. SPEAKER: I have to decide that. Have you to decide that? Let them say; what is the harm?

SHRI C. M. STEPHEN: Then, it is all right.

MR. SPEAKER: How does it affect you? Why should you get agitated? (*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : आप माफी मंगवाइये ।

MR. SPEAKER: There is no question. (*Interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: We will continue to do that. My Ministry will supply the brief; it is my right and my obligation. (*Interruptions*).

SHRI SATYASADHAN CHAKARBORTHY (Calcutta South): It is the attitude of the elephant . . . . . (*Interruptions*).

SHRI C. M. STEPHEN: We can have a debate if you like.

SHRI VASANT SATHE: I will also supply the brief.

SHRI C. M. STEPHEN: We can supply the brief .... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I want to listen, but only if somebody allows that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order under rule 376. If the journalist concerned had not rendered this yoeman service,....

MR. SPEAKER: This is a hypothetical question; not allowed.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The second thing is, do you realise that if they had done it, it would have amounted to violation of Official Secrets Act?

MR. SPEAKER: When that comes, then I will see.

SOME HON. MEMBERS *ROSE* (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Have I allowed you? Not allowed. You have no permission of mine to speak.

(*Interruptions*)**

Not allowed. I will listen to you all . . .

SHRI JYOTIRMOY BOSU: My final submission is that Mr. Stephen in his wisdom has just now said ....

MR. SPEAKER: Nothing; over-ruled.

SHRI C. M. STEPHEN: I can answer that. You can bring a privilege motion. I consider it my obligation to brief the Members as to what is happening in my Ministry.... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Why are you agitated?

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: Mr. Somnath Chatterjee.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please....order.

(*Interruptions*)**

**Not recorded .

MR. SPEAKER: Why are you trying to be funny? Nothing is to go on record without my permission. Yes, Mr. Somnath Chatterjee. He has my permission.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sir, you were kind enough to observe just now that you really *suo motu* took action in this matter, because of its great importance; and you were kind enough to ask for information from the Home Ministry. And you have read out a letter. May I earnestly request you, because of the seriousness of the matter, for a *suo motu* intervention to enquire whether any other hon. Minister has issued such directives to his Ministry?

(Interruptions)

MR. SPEAKER: We will see when it comes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Unless you find out, it is not possible ....

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I will find out. Yes, Mr. Gupta.

(Interruptions)

SHRI INDRAJIT GUPTA: We appreciate very much the ruling which you have given. I heard you to say: it is of great importance that parliamentary conventions are observed. The difficulty that has arisen here—and that is why I am standing up and asking for your permission—is: either your ruling has to stand, or what some Ministers are now saying, has to stand. Both cannot stand.

MR. SPEAKER: No; I also understand that, I can rule on this also. I will see; whenever I find infringements of this convention taking place, I can take care of them.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Can your ruling be challenged? They are shouting here.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: No; that might be in a different context. I will see that. Yes, Mr. Shejwalkar.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Your ruling has been challenged. Two Ministers were shouting at the top of their voice. You should rebuke them for this.

MR. SPEAKER: I will see if they infringed. It might be something in another context. That might be under the rules. I cannot take anything for granted. Don't worry; I will look into it. Yes, Mr. Shejwalkar.

(Interruptions)

SHRI INDRAJIT GUPTA: They say: "We will do whatever we like".

MR. SPEAKER: It is on both the sides.

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): My point of order is this. I wanted to give notice; and I gave notice for privilege, for your consideration, on this very matter. To-day I gave it.

MR. SPEAKER: It has been disposed of.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Just hear me. Mine is a point of order. I know that it has been communicated to me. You have disposed it of. The point here is that so far as the question of fact is concerned, I was informed that the matter was being enquired into. There has been a letter from the Home Minister which confirms the charge which we have made, viz., some direction has been issued in contravention of....

MR. SPEAKER: That has been withdrawn. Nothing now.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Let me complete. I don't shout. I never rise. Let me make my point clear. You are free to decide. What I want to say is that according to me—what the reply says is this—they have said that they have withdrawn now. That means they had earlier issued the instructions for which you should ask them to...

(Interruptions)

MR. SPEAKER: There cannot be a withdrawal without an issue.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: My point is: now the matter has come before this House. Something has been done; and without apologizing —which we are demanding—it is upto you....

MR. SPEAKER: No; that does not come into it.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Technically, my submission is that there is a breach of privilege.

MR. SPEAKER: Mr. Faleiro.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: You give a ruling.

MR. SPEAKER: I have given it. Mr. Faleiro.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Kindly listen to me, Sir, carefully and patiently. This relates to the convention regarding the relationship between Members of Parliament and the Government. It is a standard practice that whenever the Members of Parliament ask for information from the Government, Government gives it, unless it is confidential. There is one exception. Members of Parliament are not expected to divulge this information outside, to interests which are against the Government and against Parliament. There has been a definite instance in this case. A Member of Parliament wrote to the Minister of External Affairs mentioning that a Bengali author had prepared a plan showing a portion of India as part of China and asked the Minister of External Affairs as to what his reaction was. The Minister of External Affairs said we were aware of this matter; we are seized of it; it is under consideration. The Member of Parliament divulged this information to the Chinese Embassy and it got.....

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I did it....

(*Interruptions*)

SHRI EDUARDO FALEIRO: This is a shameful thing. (*Interruptions*)

**(*Interruptions*) It is a shame to Parliament. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order, order.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): I have given another notice of privilege against the Minister of Finance regarding... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I had sent that. I will get the facts.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have asked for facts and then I will proceed.....

(*Interruptions*)

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): I am on a point of order. We are obliged to you for giving your ruling.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Under what rule, do you want to speak?

SHRI NIREN GHOSH: Under rule 376. But the point is the Minister only reacting to your ruling?

MR. SPEAKER: That has been done. It has been overruled.

SHRI NIREN GHOSH: You should reprimand those Ministers.

MR. SPEAKER: Overruled.

(*Interruptions*)

SHRI NIREN GHOSH: I want to know whether there will be a reprimand from the Chair.

MR. SPEAKER: I have already done what I could do.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: What I want to mention with your kind permission is important.

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. SPEAKER: Every member says something important.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I have learnt a lesson and you are very kind enough to teach us. The Speaker's Chair should be respected and we always abide by your ruling. This morning, Mr. Stephen openly violated your ruling.

MR. SPEAKER: No, not yet. I will look to that.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: This cannot be tolerated. (*Interruptions*) Will you allow me to speak? If I do something, will you allow me to do?

MR. SPEAKER: I will not allow you neither I will allow Mr. Stephen to go unchecked.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Rao Birendra Singh.

(*Interruptions*)

SHRI RASHEED MASOOD—rose.

MR. SPEAKER: What do you want?

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : जो शोर करते हैं उनको आप मौका दे देते हैं। मैं चुप बैठा था और मुझे नहीं दिया जा रहा है। प्रिवलेज का सवाल जो फेलीरो साहब ने उठाया है मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हू कि जो सीक्रेट मैटर्ज हैं उनके बारे में इनफर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए और मैं इससे मुत्तफिक हूं। मेरा आबजैक्शन यह है कि होम मिनिस्टर कांग्रेस आई के मैम्बर्ज को ही नहीं बल्कि जो भी मैम्बर इनफर्मेशन मांगे उसको दी जानी चाहिए।

MR. SPEAKER: That has been disposed of. You had not heard me.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Why don't you listen to me? Why did you not keep your ears open? If you had done it, then you would have listened to me. I have done it.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था। उसका क्या हुआ है ? आज देश के सारे अखबारों में यह फोटो छपी है और मोटे मोटे हैडिंग में यह चीज आई है।

MR. SPEAKER: No, no, I have already allowed it under 377. I would not listen.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरी बात सुन लीजिए।

MR. SPEAKER: Rao Birendra Singh.

(*Interruptions*)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उसको क्यों खारिज कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : खारिज नहीं किया है, 377 में एलाऊ किया है।

(*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I have already allowed it. Please sit down. Don't record.

(*Interruptions*)**

12.18 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

RICE-MILLING INDUSTRY (REGULATION AND LICENSING) AUDIT RULES, 1980

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRCULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): On behalf of Rao Birendra Singh. I beg to lay on the Table a copy of the Rice-Milling Industry (Regulation and Li-

**Not recorded.

censing) Amendment Rules, 1980 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 732(E) in Gazette of India dated the 31st December, 1980, under sub-section (4) of section 22 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958 [*Placed in Library. See No.* LT-1987$81]

INSURANCE CLAIMS BOARD (AMDT.) RULES, 1981.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): I beg to lay on the Table a copy of the Insurance Claims Board (Amendment) Rules, 1981 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 193 in Gazette of India dated the 14th February, 1981, issued under section 57 of the Displaced Persons (Debt Adjustment) Act, 1951. [*Placed in Library. See* No. LT-1988/81].

ANNUAL REPORT AND REVIEW OF INDIAN INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION, NEW DELHI FOR 1979-80 WITH STATEMENT FOR DELAY AND ANNUAL REPORT OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA ON 'PRESS IN INDIA, 1979'

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): I beg to lay on the Table:—

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 1979-80 along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Indian Institute of Mass Communications. New Delhi for the year 1979-80.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above. [*Placed in Library. See* No. LT-1989/81].

(3) A copy of the Annual Report (Part I) (Hindi and English versions) of the Registrar of Newspapers for India on 'Press in India 1979.' [*Placed in Library. See* No. LT-1990/81].

MR. SPEAKER: What do you want?

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing doing; no, no.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. Nothing will go on record without my permission.

*(Interruptions)***

12.20 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTEENTH REPORT

SHRI G. LAKSHMANAN (Madras North): I beg to present the Sixteenth Report of the Commitee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.20 1/2 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

INCREASING INCIDENCE OF ROBBERIES AND DACOITIES IN DELHI.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लूटपाट और डकैती की बढ़ती हुई घटनायें।"

**Not recorded.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Sir, with the strong measures taken by the present Government, during the last year, there has been a marked decline in the incidence of crime in the Union Territory of Delhi. Thirty-three cases of dacoity have been reported in the year 1980 as against 64 during the previous year. As regards robbery cases, 293 cases were reported during 1980 as against 621 cases in 1979. During the first month of the current year, no case of dacoity was reported and 17 cases of robbery were registered.

In fact, this welcome trend is discernible under other heads of crime also. This is mainly because of the specific steps taken by the Government to improve the operational efficiency of the Delhi Police. Some of these steps are as follows:—

(i) Since the beginning of 1980, 6 new Police Stations and 12 new Police Posts have been set up. In addition, the staff strength of the existing police stations have been enhanced.

(ii) With the purchase of new vehicles and replacement of old vehicles, the motor transport available with the Delhi Police has been substantially augumented.

(iii) 1776 posts, in various ranks, have been created for filling up of the existing vacancies as well as for strengthening the police force.

(iv) Also, with a view to ensuring better supervision, the Capital has been divided into two police ranges and each range has been placed under the charge of an Additional Commissioner of Police.

In addition to this, the Delhi Police has taken steps for improving the situation and bringing a feeling of confidence among the citizens. Some of these steps are as follows:—

(1) Anti-dacoity and anti-robbery partolling by wireless fitted vehicles including Motor Cycles has been intensified and 'Naka Bandi' at strategic points organised.

(2) Pickets have been posted at vulnerable points.

(3) Sources have been deployed to collect intelligence.

(4) Crime records have been consulted for interrogating criminals with known *modus operandi*.

(5) Round-the-clock patrolling is done and barriers placed at selected places, where during the night, vehicles are checked.

(6) About 2000 Home Guards are being utilised for patrolling duties.

As a result of the commendable efforts of the Delhi Police, the law and order situation in the Union Territory is well under control. However, there is no let up in our efforts and we expect still better results during the current year.

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा नजर आता है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में खास तौर से डकैतियों और लूटपाट की घटनाओं में पिछले एक साल में कमी हुई है ।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : कमी ? और कितनी गलत बात कह रहे हो ।

श्री नवल किशोर शर्मा : और इस कमी के बारे में हम संतोष कर सकते हैं । लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश के अनेक भागों में खासतौर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह डकैतियों की घटनायें बहुत बढ़ती जा रही हैं ।

MR. SPEAKER: Confine yourself to Delhi.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: I will. I am trying to be within the scope of the Calling Attention.

उनकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों में नेशनल हाई-वेज पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और वह चिन्ता का विषय है। राजस्थान की राजधानी . . .

MR. SPEAKER: Confine yourself to Delhi.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: I am confining.

श्री मनीराम बागड़ी : आप के राज्य में तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब अमन-चैन है।

श्री नवल किशोर शर्मा : जयपुर के आस पास पिछले कुछ दिनों में काफ़ी घटनाएं हुई हैं। ऐसा लगता है कि चाहे वह दिल्ली की घटनाएं हों, या दूसरे प्रान्तों की घटनाएं हों चम्बल के क्षेत्र में जो डकैतों की . . .

MR. SPEAKER: Why are you trying to refer to Chambal? You cannot; I cannot allow it.

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं।

My submission is, it is good that the Minister has taken precautionary measures and has strentghened the police administration. But unless you control the source, nothing would be done and the source is the Chambal ravines. Therefore, I am mentioning it.

MR. SPEAKER: I cannot allow it.

श्री नवल किशोर शर्मा : असल में इस देश में जो डकैतों का सब से बड़ा अड्डा दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र में है, वह चम्बल रेवाइन्स हैं। वहां के डकैतों को सैटल करने के बारे में, उन्होंने जो कुछ अच्छे आचरण करने के बारे में बात कही और कुछ लोगों ने सरण्डर किया, उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि प्रधान मंत्री ने राज्य के मुख्य मंत्रियों को मई में एक चिट्ठी लिखी थी और उसके जरिये उन्होंने लिखा था कि जिन डकैतों ने संरण्डर किया है, उनके रिहैब्लीटेशन के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहियें ? अगर उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी थी, तो उसके बाद कोई कदम उठाया गया है या नहीं ?

दूसरे यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो घटनाएं डकैती और रौबरी की होती हैं, इन घटनाओं के पीछे किसी विशेष गैंग का हाथ है क्या ? कौन से लोग इसमें सम्मिलित हैं ? क्या आपने इन डकैतियों और रौबरी की घटनाओं के बारे में यह जानकारी करने की कोशिश की है कि ये लोग कहां से आते हैं और उनको हथियार कहां से मिलते हैं ? क्योंकि अभी अभी पिछले दिनों में वैस्ट बंगाल में कुछ बन्दूकें पुलिस से छीनने की घटनाएं 22, 23 और 24 तारीख को हुई हैं। वैस्ट बंगाल सरकार उन बन्दूक छीनने की घटनाओं को रोक नहीं सकती है . . . . .

MR. SPEAKER: It does not concern this.

श्री मनीराम बागड़ी : तुम्हारा दिल्ली में तो दिवाला निकल रहा है, वैस्ट बंगाल में जा रहे हो !

MR. SPEAKER: I want you to confine yourself to Delhi. If you try to make a wider circle other than

[Mr. Speaker]

Delhi, I am going to over-rule it. Yesterday it was decided.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: I am only asking a question.

MR. SPEAKER: You cannot just go on a wild goose chase.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: I am asking whether the arms seized from West Bengal... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: How are you concerned with it? I am not allowing it.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: I leave it.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि दिल्ली में जो घटनाएं घटी हैं, उनमें से कितनी डकैतियों की और कितनी रौबरी की घटनाओं को अन-अर्थ किया है, कितना मालूमात किया है? इनके बारे में अब तक क्या हुआ है? इस के साथ साथ

अध्यक्ष महोदय: बस करिये अब ।

श्री नवल किशोर शर्मा: मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण हैं कि इन घटनाओं को हम पूरी तरह से इरैडीकेट नहीं कर पाए हैं? इसके बारे में मंत्री महोदय बतायें ।

श्री मनीराम बागड़ी: कांग्रेस सरकार का इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमन-चैन नहीं कर पा रही है ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The hon. Member has referred to inter-state dacoities. This is not the subject matter of today's calling attention. But he has put two questions regarding the Union territory of Delhi about which I would like to give the information to the hon. Member.

He wanted to know about unearthing of dacoities, robberies and other heads of crimes. During 1980 14 gangs of dacoities had been unearthed and 202 persons were arrested.

SHRI MANI RAM BAGRI: Where?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: In Delhi. 119 cases had been worked out. Property worth Rs. 1,32,050/- was recovered from them.

So far as robberies are concerned, 43 gangs had been unearthed and 139 persons were arrested. Property worth Rs. 7,79,603/- was recovered from them. 236 cases had been worked out.

Regarding other heads of crimes, if the hon. Member wants information I can give the information. It is available with me.

Regarding Khari Baoli case, the Police has been able to unearth and find out the culprits. The Delhi Police has recovered from them articles. Four accused namely Sudhir Kumar, Anwar, Hemraj and Balbir alias Billa alias Tiger have been arrested. Two other accused have also been arrested by the UP Police and articles have also been recovered from them. Rs. 7,600/- in cash could not be recovered from them as they have used it.

So far as inter-state dacoities are concerned, some gangs have been found out by the Delhi Police and they have been arrested. While Ambassador Car gang, safari suit gang and Ram Kishan's gang have been unearthed by the Delhi Police. They have been arrested. Property worth lakhs of rupees has been reserved from them.

There is a steep decline in the case of robberies in Delhi. It has come to 50 per cent.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत: (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से मुद्रा-स्फीति और मूल्य-वृद्धि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय लक्षण

हमारी अर्थ-व्यवस्था में आ गये हैं, उसी तरीके से कानून और व्यवस्था का प्रश्न, आर्थिक अपराधों का बढ़ना, कहीं राजनैतिक अपराधों और कहीं सामाजिक अपराधों का बढ़ना भी केवल डेवलपिंग कण्ट्रीज का ही नहीं है, बल्कि डेवेलप्ड कण्ट्रीज का एक आम लक्षण हो रहा है।

लेकिन जैसा कि हमारे गृह मंत्री ने कहा है, बहुत कुछ सुधार दिल्ली की कानून-व्यवस्था की स्थिति में हमारी सरकार के आने के बाद हुआ है। उसको दिल्ली के सब नागरिक महसूस करते हैं और उसके लिए मैं गृह मंत्री और दिल्ली प्रशासन को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि इससे आपोजीशन के हमारे मित्र भी सहमत होंगे। जो हमारी तरह सोचने वाली सरकारें हैं विभिन्न प्रान्तों में, जो नाक को सीधे हाथ से पकड़ना चाहती हैं, यदि वहां भी कहीं कहीं कानून-व्यवस्था की स्थिति में कोई ख़ामी है, तो जो लोग उलटे हाथ से, पीठ के पीछे हाथ घुमा कर, नाक पकड़ना चाहते हैं, उन के यहां भी ** में भी कानून-व्यवस्था की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : Not allowed. दिल्ली को लीजिए।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं तो जेनरल रेफ़रेंस में कह रहा था, मुझे तो उनकी बात से एक बात याद आती है। मैं आपकी इजाजत से एक उर्दू शेर की दो लाइनें कहना चाहता हूं :—

हम आह भी करते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम
वो कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होता।**

MR. SPEAKER: Not allowed. You limit yourself within the scope of the calling attention.

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत] **

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : हम अपनी बात को इलस्ट्रेट करने के लिए आम सन्दर्भ में भी बात को न कहें, ऐसी तो कोई बात है नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, छोड़िए साहब इस बात को।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं दो सवाल गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। एक सवाल तो यह है कि आर्थिक अपराध जो हैं, जहां तक मैं समझता हूं बिना पुलिस के मिले हुए ये नहीं होते हैं, तो यह जो आर्थिक अपराध हुए हैं जैसे डकैती, रौबरी, या छीनने झपटने वाली बातें हुई हैं, इन में जो पुलिस मैन इन्वाल्व्ड पाये गए, या जिस एरिया में ये चीजें हुई हैं उस एरिया के पुलिस मैन को या थाने के इन्चार्ज को कहीं कोई पनिश्मेंट दिया गया या नहीं दिया गया? जो आर्थिक अपराध हैं, जिस तरीके से कहीं डकैती पड़ी है, कहीं राबरी होती है, इस तरीके से जिस हलके में ये अपराध होते हैं, उस हलके में बिना पुलिस के मिले हुए ये अपराध नहीं होते हैं ... (व्यवधान) ....।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप दोहरा रहे हैं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत: इस में जहां गहराई से छानबीन की गई है वहां यह पाया गया है कि पुलिस ऐसे मामलों में शामिल रही है, तो क्या दिल्ली में जहां जहां इस तरीके के अपराध हुए हैं उस हलके के थाने के इन्चार्ज को कहीं दंडित किया गया, कहीं उन के उपर कोई स्टर्न ऐक्शन लिया गया? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं।

**Not recorded.

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

दूसरा यह है कि जो राजनैतिक और सामाजिक अपराध होते हैं जिन को कुछ राजनैतिक दल और ये लोग अपनी तरफ से इन्स्टीगेट करते हैं, बहुधा यह पाया गया है जैसे हम ने यू० पी० और बिहार में देखा . . .

MR. SPEAKER: Not allowed.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : यहां दिल्ली में भी हमारे मन में यह शंका है कि हम से पहले जो लोग थे उन्होंने इस प्रकार की भर्ती की है . . .

MR. SPEAKER: Not allowed. No, I have not allowed it. You confine yourself to Delhi. If you want to put questions, confine yourself to the main question. If you go beyond the scope of the question. I will not allow.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैंने जो बिलकुल साफ बात कही और जो आप की आज्ञा थी उस को शिरोधार्य कर के बात कह रहा हूं ।

तीसरी बात जो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं वह यह है, जैसा मैंने कहा, कानून और व्यवस्था की स्थिति में दिल्ली में बहुत सुधार हुआ है लेकिन उस में और भी सुधार की जरूरत है । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने भी पैट्रोलिंग इत्यादि कर के इस स्थिति में सुधार लाने में पुलिस की बड़ी मदद की है । तो क्या इस तरीके से और अधिक से अधिक पब्लिक के इन्वाल्वमेंट के लिए गृह मंत्रालय तैयार है ? इस तरीके की कोई योजना क्या गृह मंत्रालय के पास है कि दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन से यह कहा जाय कि वह अधिक से अधिक पब्लिक के लोगों को कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने में इन्वाल्व करे ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, there is only one question which you have allowed to the hon. Member, and that is regarding the action against police officers. Whenever any police officer is found guilty or involved in any case, action is taken against him.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था में व्यापक रूप से सुधार हुआ है । इस में दो राय नहीं कि दिल्ली की पुलिस को बड़े आड्स के सामने काम करना पड़ता है । दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है । . . (व्यवधान) . . दिल्ली में क्राइम के कण्ट्रोल के अलावा बहुत सी राजनैतिक घटनाओं से भी पुलिस को निपटना पड़ता है । आए दिन यहां धरना, सत्याग्रह, रैली ये सारी चीजें होती रहती हैं। (व्यवधान) . . मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं । आप क्यों परेशान हैं ? ऐसी हालत में यह सही है कि अगर हम पूरे देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखें (व्यवधान)

I am not saying anything about other places except Delhi.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Only Members on the list will be entitled to make any reference. Nobody else.

श्री जैनुल बशर : देश में जो दूसरे स्थान हैं वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति के कंपेरिजन में अगर हम दिल्ली को देखें तो हम संतोष की सांस ले सकते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां एक घटना भी हो जाती है तो वह राष्ट्रीय अखबार,

जोकि यहां से निकलते हैं, उनकी हेड-लाइन बन जाती है और उसकी बहुत चर्चा होती है जबकि दूसरे स्थानों पर ऐसी अनेकों घटनायें होती हैं वह अखबारों की हेड-लाइन नहीं बन पातीं और न ही पूरे देश में उन पर चर्चा होती है । इस कंपेरीजन में अगर दिल्ली को देखा जाए तो दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोष-जनक है ।

इस सिलसिले में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो सवाल करने की बात है ।

श्री जैनुल बशर : सवाल भी करूंगा । दिल्ली में पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन यह दुःख की बात है कि अभी तक पुलिस वालों की तनख्वाह अधिक नहीं बढ़ी है ।

MR. SPEAKER: What are you trying to do, Sir.

श्री जैनुल बशर : मैं सब्जेक्ट से बाहर नहीं कह रहा हूं । बड़े अदब से मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सब्जेक्ट से बाहर नहीं बोल रहा हूं ।

दिल्ली की पुलिस को 24 घण्टे काम करना पड़ता है, उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाना चाहिए । इस समय उनकी तनख्वाहें बक और एल आई सी के चपरासी से भी कम हैं । पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की तनख्वाह बैंक और एल० आई० सी० के क्लर्क से भी कम है इसलिए उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी ।

दूसरी बात यह है कि जो ऐन्टी राबरी, डकैटी स्क्वैड्स हैं उनमें आम तौर पर ऐसे पुलिस वालों को भेजा जाता है जिनको कि सजा देनी होती है । अच्छे अफसर उन स्क्वैड्स की पैट्रोलिंग में नहीं जाते हैं । इसलिए अच्छे अफसरों को वहां भेजा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें ।

श्री जैनुल बशर : मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं ।

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या दिल्ली पुलिस वालों की तनख्वाहें बढ़ाने का उनका विचार है— खासकर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के ग्रेड तक, जिनको कि 24 घंटे काम करना पड़ता है । इसके साथ ही साथ पुलिस कर्मचारियों के रहने के लिए, अपने परिवार रखने के लिए क्या अधिक से अधिक आवास सुविधा प्रदान करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बजट स्पीच में बोलने की बातें हैं ।

श्री जैनुल बशर : मैं सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं, सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूं । इस सब्जेक्ट पर आप इतने सेंसिटिव हैं, मुझे मालूम नहीं था ।

MR. SPEAKER: I want you to take up the problem.

SHRI ZAINUL BASHER: I am not taking the name of U.P., Madhya Pradesh or Rajasthan. I do not know why you are so sensitive.

MR. SPEAKER: I want you to confine it to a more constructive thing. These suggestions will be more...
(Interruptions)

श्री जैनुल बशर : मैं कांस्ट्रक्टिव थिंग्ज ही दे रहा हूं । मेरी समझ में नहीं आता आज आपका मूड कैसा है ? मैं बिल्कुल

[श्री जैनुल बशर]

कांस्ट्रक्टिव चीजें कह रहा हूं । क्या मंत्री जी पुलिस वालों को मकान, वर्दी और दूसरी सारी सुविधायें देने के लिए तैयार है ?

दूसरी बात यह है कि ऐन्टी स्क्वैड्स में जो पुलिस के लोग रहते हैं क्या उनको आप विशेष ट्रेनिंग देने की बात सोच रहे हैं ? आज कल जो क्रिमिनल्स हैं, उनके पास नए-नए टैक्नीक आ गए हैं और नए-नए तरीके से काम करना सीख गए हैं । उनके पास अच्छे-बढ़िया हथियार आ गए हैं । क्राइम का जो इन्टरनेशनल तरीका है, वह उनको मालूम हो गया है । क्या सरकार उससे निपटने के लिए गृह मंत्री जी हमारी पुलिस के लोगों को कोई विशेष ट्रेनिंग देने की बात सोच रहे हैं और क्या उन्होंने उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर रखी है ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The hon. Member has made several valuable suggestions. I have taken note of them.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: Nothing will go on record without my permission. No, he is not entitled.

Shri Mukunda Mandal.

(*Interruptions*)

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): First of all I would like to draw your attention to the information given by the hon. Minister yesterday and to-day. Yesterday, in the statement he....

MR. SPEAKER: No yesterday, only to-day.

SHRI MUKUNDA MANDAL: I can refer...

MR. SPEAKER: No.

SHRI MUKUNDA MANDAL: Yesterday, the figure given of robberies was 295, to-day it has been mentioned as 293. Dacoities committed were mentioned yesterday as 31, to-day the figure has gone up. It is 33. This is in regard to the year 1980. But how is it? I wanted to refer this only to get rectification.

MR. SPEAKER: It is only in the case of Delhi.

SHRI MUKUNDA MANDAL: Yes. In reply to the question the Minister stated that during the first five months of last year the position was—dacoities 118, murder 82, attempt to murder 120, rape 10. If you go through the newspaper you will find that every day the law and order position of Delhi is getting very serious. People of Delhi are very much upset. The people after evening cannot walk in the streets. This is more so in the case of women folk.

In the capitalist society, it is a must, haves rule the country and have not are exploited. That is why law and order position comes up and anti-social activities rise up.

In the police lock-up, the atrocities of the police go on...

MR. SPEAKER: It is simply in regard to dacoities. (*Interruptions*)

Please confine yourself to Delhi and put question in one minute.

SHRI MUKUNDA MANDAL: I want to ask the Minister—will be criminals be rehabilitated? Are proper steps being taken to frame rules to reform and rehabilitate the criminals? Mostly we find, once a criminal, criminal for generation. That is why rehabilitation of the criminals is essential. Is Government intending to adopt national policy to train police personnel so that they can deal with the accused and convicts properly as this training will help the criminals to become social afterwards? I want

**Not recorded.

to ask—will the Government reform the existing colonial type of jail system so that the criminals can regain social feelings and qualities? Will Government invite convention of all political parties to find out at least temporary solution because the problem cannot be solved totally? At least temporarily we can make co-ordinated efforts to liquidate gangs of all kinds without further loss of time. I also want to know whether the Government will allow the police personnel of Delhi to form democratic unions or associations so that they can have a free discussion of their problems.

Finally, I would like to know the measures taken by the Government for socio-economic development of the backward classes from where these people come.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The hon. Member referred to some figures given by me yesterday. I do not know which figures he is referring to. I did not make any statement in the House nor but I replied to any question in this House or in the other House. If the hon. Member obliges me to give the figures and the statement in which I have given those figures, I can clarify that.

He has put several questions. One is about the rehabilitation of criminals, about the reformatory punishment in jail and some training to the prisoners in jail so that after they come out of jails...

SHRI MUKUNDA MANDAL: I asked about training of police personnel.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I am coming to that. So far as the behaviour of the police is concerned, the Police Commission's report has suggested certain measures and new syllabus for the police training. We have taken sufficient care about the training of police personnel so that they behave properly with the public. So far as the improvement of jail system is concerned, we have already appointed a committee. The report on Tihar Jail is already with us. About other jails we are going to get reports later on.

Regarding unearthing of inter-State gangs. I have already stated that several gangs are unearthed in Delhi...

SHRI MUKUNDA MANDAL: I did not refer to inter-State gangs.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The last question of the hon. Member was by way of a suggestion. I have taken note of it.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आज कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं रह गई है...

श्री रणबीर सिंह (केसरगंज) : देश की नहीं, दिल्ली की बात कहिए।

श्री हरिकेश बहादुर। दिल्ली की ही बात कह रहा हूं, जो देश की राजधानी है। ...(**व्यवधान**)... आज यहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ऐसा लगता नहीं है कि देश में कोई गृह मंत्रालय है या किसी को कानून और व्यवस्था सम्भालने की चिन्ता रह गई है ... (**व्यवधान**)...

SHRI RAJESH KUMAR SINGH (Firozabad): He is saying about the nation. He is not referring to any State in particular.

SHRI HARIKESH BAHADUR: I am saying, Delhi is the capital of India.

MR. SPEAKER: That is a statement of fact.

SHRI HARIKESH BAHADUR: There is no law and order; there is no Home Ministry. The entire working of the Home Ministry is paralysed and deteriorated...(*Interruptions*)

[Shri Harikesh Bahadur]

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस लोक सभा के अध्यक्ष हैं ...

MR. SPEAKER: That is also a statement of fact.

मुझे आज पता लगा है। आज काम पक्का हो गया है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): So, you are confirmed.

श्री हरिकेश बहादुर : लेकिन, मान्यवर, मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी इस सभा के अध्यक्ष भी आज सुरक्षित नहीं हैं। आप राजस्थान गये थे . . . .

MR. SPEAKER: Please don't drag me.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): He says, there is no Parliament, there is no Home Minister. Whom is he going to put the question if there is no Parliament and there is no Home Minister? (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल को दिल्ली तक ही रखिए।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं।

**MR. SPEAKER: Confine yourself to Delhi. Nothing else will go on record.

श्री हरिकेश बहादुर : इस दिल्ली के अन्दर किस नीयत से एक अपराधी ने भारत सरकार के एक मंत्री के घर में जा कर उनके सेक्यूरिटी गार्ड की हत्या की और उनके घर में घुसा लूटने के लिए या वह किसी और काम के लिए गया था, यह बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना हुई है, जिस से न केवल दिल्ली के ही बल्कि पूरे देश के सारे नागरिक आतंकित हुए हैं। यहीं पर निरंकारी चोफ की हत्या की गई और आज तक सरकार अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। प्रधान मंत्री पर यहीं पर छुरा फैंका गया, इसी लोक सभा के परिसर के अन्दर। यह सारे काम इस सरकार की देखरेख में दिल्ली के अन्दर और संसद भवन तक के अन्दर हो रहे हैं। फिर हम यह कैसे मानें कि इस देश के अन्दर कोई सरकार है या कोई गृह मंत्रालय है जो कि कानून व व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। मान्यवर, अभी एक स0 पो0को किडनैप कर लिया गया, ऐसी रिपोर्ट अखबार में आई है। दो अखबार निकलते हैं 'स्वतन्त्र भारत' और 'पायनियर' और उनमें एक खबर यह निकली थी कि एक डाकू ने एक एस0 पी को किडनैप कर लिया। यह बात इन अखबारों में दी गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि आज आप के दिल्ली के अन्दर चारों तरफ सूबों के अन्दर जो डकैतियां हो रही हैं, वहां से वे डकैत यहां आ रहे हैं और खास तौर से**

MR. SPEAKER: No; not allowed; confine yourself to Delhi.

श्री हरिकेश बहादुर : उन के दिल्ली में आने की संभावना है। इसलिए यह सवाल उठा रहा हूं। क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से डकैत और अपराधी दिल्ली आ कर अपराध करते हैं? और ऐसी सूचना है तो उस का विवरण आप दीजिए और मैं आप को चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अन्दर जो भयंकर डकैतियां हो रही हैं, उन में भाग लेने वाले डकैत कहीं दिल्ली न आ जाएं।

अध्यक्ष महोदय : नो।

**Not recorded.

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि उन के यहां आने से और खतरा बढ़ जाएगा । इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं । अगर इस बात की जानकारी है, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है और मुख्य मंत्रियों से आप को इस दिशा में क्या सहयोग मिलने वाला है या मिल रहा है या आपने किसी सहयोग की याचना की है या नहीं ?

माननीय, मैं पुलिस की अक्षमता के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । जब आप ने यहां पर पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया, तो कम से कम 200 सीनियर पुलिस अफ़सरों को सुपरसीड कर के किया । इस से पूरा पुलिस फोर्स डीमोरेलाइज हुआ है । यही कारण है कि आज पुलिस ठीक ढंग से यहां पर कोई काम नहीं कर रही है और दिल्ली के अन्दर अपराध बढ़ रहे हैं । तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस अक्षमता को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? क्या भविष्य में फिर आप इस तरह से पुलिस अफ़सरों को सुपरसीड कर के नई नियुक्तियां करने वाले हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : टेक इट आल ।

श्री हरिकेश बहादुर : प्रदेशों की तो कौन कहे, विदेशों से अपराधी आए हैं । अभी माफिया किलर की बात हुई है । वह यहां पर ठहरा था और काफ़ी दिनों से ठहरा हुआ था । अगर इस तरह से प्रदेशों से और विदेशों से आ कर अपराधी दिल्ली में रहने लगेंगे, दिल्ली के संरक्षण में तमाम जगहों पर रहने लगेंगे, तो देश के अन्दर किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा । इसलिए माननीय मंत्री जी इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप को पुलिस अगर किसी को पकड़ती है, तो वह उस से हाथ जोड़ कर निवेदन करता है कि चितना चाहे पीट लो लेकिन अंधा मत बनाना । ऐसी स्थिति देश के अन्दर पैदा हो रही है । इसलिए पुलिस फोर्स को नियंत्रण में रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

13.00 hrs.

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने कई बातें जो कहीं तो वे तकरीर के तौर पर कही और कोई खास सवाल तो पूछा नहीं लेकिन उन्होंने यह कहा कि दिल्ली में कहीं बाहर से आ कर डेकायट्स और रोबर्स रहते हैं । इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े शहर में लोग आएंगे और जायेंगे भी । अब बाहर से कौन आता है और कौन जाता है, उस पर कोई चैकिंग नहीं रह सकती । लेकिन इतना जरूर है जो कि जो यहां बाहर से डकैत लोग आते हैं और रोबरी करते हैं, पुलिस उन पर बराबर नजर रखती है और उनको पकड़ती भी है । मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में बताया, जब एक आनरेबल मेम्बर ने प्रश्न पूछा था कि कई गैंग बाहर से आये और यहां पर गुनाह किया ? उनको पकड़ा गया, उनकी प्रापर्टी भी जप्त की गई, उन्हें जेल में भी भेजा गया : सब कुछ किया गया । यह सब बताने के बाद भी आनरेबल मेम्बर यह सब कुछ कह रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि मुख्य मंत्री का सहयोग नहीं है । हमें हर स्टेट के मुख्य मंत्री और हर स्टेट गवर्नमेंट का इसके बारे में सहयोग प्राप्त है । हमारी पुलिस राज्यों की पुलिस के साथ सहयोग करती है और उनका सहयोग लेती है ।

SHRI HARIKESH BAHADUR: What about the supersession of the Police Officers?

MR. SPEAKER: The House now stands adjourned till 2 p.m.

13.01 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are many hon. Members who want to speak on the Railway Budget. The Minister of Parliamentary Affairs thinks we can sit even after 6 P.M. I hope there is no objection.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

THE OIL AND NATURAL GAS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959."

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, this Bill has been brought to tackle those officials who are non-pliable and who are proving inconvenient to them in their operations to the interests of individuals and parties, etc. I shall show you, Sir. Let us go to the original Act. Section 5 of the ONGC Act, 1959 says:

"The term of office and conditions of service of the Chairman and other members shall be such as may be prescribed provided that the Central Government may if it thinks fit terminate the appointment of any member before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same."

Now, what does the satement of Objects and Reasons of the present Bill says:

"According to section 5 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959, the Central Government can terminate the appointment of any member before the expiry of his term of office only after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same. The business of oil has international repercussions and deals with matters which are very vital to the interests of the country. The working of the Commission has shown that it may be necessary in public interest to terminate the appointment of a member without giving show cause notice...

They want to dismiss an officer without giving him any show cause notice.

"It is, therefore, proposed to amend the section to enable the Central Government to terminate the appointment of any whole-time member who is not a servant of the Government after giving him a notice of not less than three months or in lieu thereof after making to him..."

Now, Sir, in this connection I would like to refer to Article 311, 312 and 319 of the Constitution. This is an atrocious move. They want to terminate a man if he proves inconvenient to them. What is the inconvenience at the present moment which has been caused? They are now in league with the French consortium called CFP. They know that the flow of oil between Bombay High and Gulf of Kutch would be about 22 million tonnes per annum.

Now this French company is about to enter into a joint sector technical agreement on reservoir management.

We agree that our scientists, although they have mastered many areas of the oil exploration technology, about reservoir management, they are not very confident. But they are bringing in this French consortium, this French company, in order to denigrate our scientists. The talk of self-reliance, the talk of banning importation of technical know-how which is available already in the country,—these are only myths. They say they had an old rate for granting technical know how and an extension was due for CFP. They want to add 4 per cent of oil bartering which will mean 4 times payment to the French consortium, of the Bombay High oil.

SHRI P. C. SETHI: May I bring to the notice of the hon. Member that he is opposing this Bill under the Rule 72? He is challenging the legislative competence of the Act. Let him speak on the legislative competence first. Then we will come to the other points.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I will tell you this. Is it a fact that the Minister cannot satisfy the House on these points? I have said, it offends Articles 309, 311 and 312 of the Constitution. This original Act which was passed by the House has got Section 5 which gives the right of natural justice to the workers. He has been in the trade union. Show-cause notice is a must. Here they want to do away with this show-cause notice. It is the fundamental right of any employee. Therefore, legislative incompetence is there. I will try to resume my seat by asking one question. Is it a fact that Mr. Venugopal and Mr. Woodward—one is Chairman and the other a Member—have become too inconvenient in the matter of concluding this additional concessional agreement with the French consortium CFP and that is the reason why you have brought this Bill to get rid of these people? I oppose this Bill..

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): What has that to do with the introduction of the Bill?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I oppose the Bill lock, stock and barrel. Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. George Fernandes—absent. Now, Mr. Mukunda Mandal. You should be very short.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Very brief; only two lines

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bosu has done well, I should say.

SHRI MUKUNDA MANDAL: Sir, my point is only this. I just want to say only two lines. I oppose the introduction of the Oil and Natural Gas Commission (Amendment) Bill, Sir, it is opposed to Article 14 and Article 19 of our Constitution. Number two: It is against the fundamental rights of the employees. This Bill is intended to curb the democratic rights of the employees. The Government can terminate at any time the appointment of any member who is in the service of the company. Therefore the Government is bringing in this Bill. They want to terminate the service of any employee who does not toe their line, who does not suit their interests. In this way, they are creating chaos in the whole administration. Sir, I wish to point out that this Bill is unconstiutional and illegal. Therefore I oppose the introduction of this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Harikesh Bahadur—absent.

Mr. Paswan—absent.

Now, Mr. Ajoy Biswas—Please be brief.

SHRI AJOY BISWAS (Tripura West): Mr. Deputy Speaker, Sir, I oppose the introduction of this Bill. Already Mr. Jyotirmoy Bosu and Mr. Mukunda Mandal have referred to certain points. This Amendment is against the Constitution of India. Every worker, whether he is in high position or he is in low position, has got the fundamental right of self-defence. But that right is being taken away by this Amendment. Therefore, it is unconstitutional. I oppose the introduction of the Bill.

[Shri Ajoy Biswas]

Then, my next point is this. We should see this. What is the need for it? Already the Government has entered into an agreement with 33 multinationals. They have been brought in to work in India. Here what is written is this: Sir, here it has been mentioned that this amendment is in the interest of the country. I say that this amendment will go against the interest of the country because the Government has entered into an agreement with 33 multinationals. The multinationals shall have the right of 25 to 30 per cent crude oil and they will take the crude oil out of the country. Some of the Members and the officials are not happy with this agreement. They are against this agreement and they think that it is clearly an agreement which will go against the interests of the country. So, this amendment should be withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: When the Government takes a decision, how can it go against the interests of the country?

SHRI AJOY BISWAS: But the agreement is against the interests of the country. This is the first time that Government has entered into an agreement which will help the multinationals to take out our crude oil. Some officials are not happy with this agreement. By bringing forward this amendment the Government wants to take the law into its hands so that they can take action against the officials. I would say that this amendment is a politically motivated amendment. I oppose the introduction of this Bill.

SHRI P. C. SETHI: This is a very simple amendment. The Oil and Natural Gas Commission Act was passed by the Parliament and therefore Parliament is absolutely competent to amend the Act. Sir, as far as the constitutional point is concerned, it does not affect the provisions of the Act which have been mentioned by the hon. Members. I am bringing to the notice of this House and also for the benefit of the hon. Members that such provisions already exist in so many other organisations, for example, the International Airport Authority has got this provision. The State Bank of India has got this provision and the Industrial Finance Corporation has got this provision.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: This is a mala fide provision because your price is $ 8 and the international price for this is 32 to 40 dollars. You want to give this to the French Consortium. That is why the officers are objecting to this. You are trying to get rid of them. (*Interruptions*)

SHRI ANAND GOPAL MUKHOPADHYAY (Asansol): Mr. Bosu must be knowing that the same practice of terminating the service of an officer without notice exists in the West Bengal State Government and particularly in the project under the State of West Bengal, namely, the Durgapur Projects Limited which is one of the biggest public sector projects under the State administration.

SHRI P. C. SETHI: Therefore, any amendment to the Clause 5 in not ultra vires of the Constitution. It is in natural conformity that this amendment is necessary. Already such provision exists in other organisations The question is that under this company the officers who are presently employed have got the freedom to give 3 months' notice and leave the company. But on a reciprocal basis, the Government is arming itself with a provision. (*Interruptions*) Now, you were saying that they were collecting the commission and now you are saying that we are collecting the commissions. You are not telling the truth as far as this is concerned, there is nothing new. We are trying to bring the ONGC Act on par with others.

With regard to the other points which have been made by the hon. Members, although they do not relate to opposition to the introduction of the Bill, which they are making, I would not allow them to pass unnoticed because they have already been recorded. I would like to say that the agreement with C F.P. has not yet been con-

cluded and it is wrong to say that Mr. Venugopal, Chairman of the ONGC and Mr. Woodward, Member (on share) are opposed to collaboration with C.F.P. Both of them and the O.N.G.C. as such have felt that collaboration with C.F.P., which is not a new company, where the collaboration already exists till April 6, is necessary.

As regards what share of the oil is to be given to them, this has not yet been finally decided. The C.F.P. team is visiting India on 12th and, therefore, it is premature to say that we have entered into any contract with them. I would like to correct the hon. Members by saying that no such agreement has been reached. I would also like to remind the hon. Member, Shri Biswas, that while he has objected to the collaboration which we are trying to have with the foreign companies with regard to oil exploration, it is strange that when China entered into such agreement with the foreign companies hon. Members did not oppose it. They are only trying to say that the officers.... (*Interruptions*).

As far as these collaborations are concerned, these are still to be negotiated. It is wrong to say that we are bartering away 25 to 30 per cent of oil to them. It is in the best interest of the country that we are deliberately taking a conscious decision to enter into collaberation with these companies. This is because we know that the oil consumption is going to be very high. By 1984-85, it is going to be 45 million tonnes; by the year 1989-90, it is going to be about 65 million tonnes. At present, we are producing only 14 million tonnes, and, therefore, we are draining foreign exchange through our nose at the rate of Rs. 5800 crores per annum at the present rate of OPEC prices. Therefore, it would be in the overall interest of the country to produce as much oil as we can. I can assure the hon. Members that we are also conscious of the national interest much more so than what they are, and much more than what the officers are. Officers and ourselves are working in absolutely fair terms with each other and in consultation with ONGC. And keeping their interest in view, we shall take a decision. It is too premature to say that we have entered into such an agreement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI: I introduce the Bill.

14.23 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Refusal to implement Palekar Award by Sakal Papers Private Lamited (Maharashtra)

SHRI V. N. GADGIL (Pune): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Sakal Papers Private Ltd., which publishes the daily Sakal from Poona, Mumbai Sakal from Bombay and Kolhapur Sakal from Kolhapur has declared a lockout which has affected a large number of working journalists.

The management has refused to implement the recommendations of Justice Palekar according to which Sakal falls in II Group since its gross revenue is between two crores and four crores. The management is trying to force recommendations relating to III Group on the ground that Sakal published from Poona, Bombay and Kolhapur are three independent units. All three of them have a common Board of Directors, their balance sheets are consolidated and their staff is transferable The Kolhapur Sakal has five employees including the resident editor on the pay roll of the Poona Sakal.

The stand taken by the management is contrary to the test laid down by the Tribunal on page 57:

"In spite of the paper's production from more than one centre, it is one newspaper establishment because it has several features which proclaim its functional integrity."

[Shri V. N. Gadgil]

The Government, therefore, should immediately intervene in the matter and ensure that the recommendations of the Justice Palekar Tribunal are implemented by the management.

(ii) PROBLEMS OF HANDLOOM INDUSTRY IN KERALA

*SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat): Sir, under rule 377, I wish to raise the following matter:

The handloom sector plays a very significant role in creating employment opportunities and easing foreign exchange in the fact of very stiff competition from many areas and in different ways in the de-centralized sector. This sector have given employment to two lakhs of people in Kerala alone.

The handloom industry in Kerala is facing a crisis to-day. Apart from the rise in prices and shortage of yarn and chemicals, accumulation of unsold stock of handloom cloth has really crippled this sector.

Rs. 7 crore-worth of handloom products are lying unsold, in Kerala alone. Incentive schemes like rebate etc., cannot help in selling the huge stock that has accumulated. Even the Handloom Development Corporation does not have the financial capacity to procure the entire stock. Thus there is very acute unemployment prevailing in this sector. What is urgently needed is the setting up of a National Handloom Development Corporation which can play a very important role in different aspects of this industry, such as production, marketing, distribution of raw materials etc. At the same time, the production of controlled cloth should be entrusted to the handloom sector, and market should be explored for the sale of the handloom production. The most important factor in regard to protection of hadloom is reservation in production. That is not being done fully. The State Governments which have the responsibility to ensure that reservation is implemented, do not show enough interest.

Another urgent step that should be taken is to bring down the price of yarn and remove its shortage. Kerala has to depend on other States for yarn. Therefore, making use of the additional looms that will be sanctioned during the 6th Plan, one spinning mill should be set up in Kerala. Since there is no control over the price or distribution of yarn, there is sudden fluctuation in the prices. Therefore, as a temporary measure, at least the price of yarn should be fixed by the Government. I request the Government that necessary steps may be taken to save this industry, which is a source of livelihood for lakhs of people.

(iii) STEPS FOR IMPROVING POWER SUPPLY IN RAJASTHAN

SHRI RAM SINGH YADAV (Alwar): Sir, under rule 377, I wish to raise the following matter:

The Atomic Power Project (Rawatbhatta), Kota, Rajasthan has got two units. The first was commissioned in the year 1973 and it is to generate 200 MW electricity. The second of the project has been commissioned in November, 1980, and its capacity to generate electricity is 200 MW. Unfortunately, these two units are not generating to their maximum capacity. Not only this, both the units have got a chequered career of shutting down because of frequent faults in their working. The days of the shutting down of these units outnumber the days of working. The shutting down of atomic power units has caused substantial loss to the crops of the farmers from the irrigation point of view, because of non-supply of electricity.

The Kota Atomic Power Plant, Unit 1 has to be shut down for maintenance work during this month, as reported in newspapers to-day.

Rajasthan has got a share in Gandhi Sagar Dam Hydel Project, Bhakra Nangal Hydel project and Vyas Hydel Project in Himachal Pradesh, but the State is not being given its proper

*Original speech was delivered in Malayalam.

share by the concerned project authorities. The thermal power project at Kota has not yet been commissioned. The project is yet incomplete, due to its slow working.

Minimum electricity requirement of Rajasthan is 180 lakh units, but during the period from July to February, the maximum supply of electricity has been below 80 lakh units. It can well be imagined how much losses have been sustained by the farmers and industrial units depending upon the availability of electricity.

22 districts of Rajasthan have got no assured sources of irrigation, and they depend upon ground water for irrigating their crops. Tube wells and cavity tube wells pump out water only with the help of electricity, motors and pump sets. As there has been no supply of energy to the electric motors installed in open wells and cavity tube-wells of the farmers, their crops have been badly damaged because of non-irrigation.

In view of the above existing conditions, I wish to make the following suggestions:

1. That Rajasthan should be supplied with more electricity from other States.

2. That the minimum charges of electricity fixed by the Rajasthan State Electricity Board should not be realised from the agriculturists of Rajasthan.

3. The agriculturists of Rajasthan whose crops have been damaged due to non-supply of electricity should be compensated.

4. A committee of experts and engineers of the Atomic Power Project should be appointed to investigate the causes of frequent shutting down of Rajasthan Atomic Power Project units at Rawatbhatta (Kota).

(iv) REPORTED DECISION FOR ALLOWING IMPORT OF PRE-PARTIALLY ORIENTED YARN FOR ACTUAL USERS.

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): On January 28, 1981, the Commerce Ministry announced the decision to allow import of prepartially oriented yarn for actual users. The State Chemicals and Pharmaceuticals Corporations of India has been appointed as the cancelising agency; imports to be initially allowed for a period of 3 months. The decision is said to be in violation of all established norms as laid down in the IDR Act and MRTP Act and would only help a few units in the cotton textile industry and nylon spinners.

In taking this particular decision the Commerce Ministry has completely ignored the advice of D.G.T.D. and the decision of P.A.B. that crimping is not a part of weaving. The D.G.T.D. which is the sponsoring authority for nylon filament yarn has also not been taken into account. What is more surprising is that polyster filament yarn producers have been recognised as actual users for import of partially oriented polyster yarn. The Textile Commissioner will certify their eligibility as nylon spinners for the purpose of import. The weavers have not been given an opportunity to import their requirements based on their capacity, but only to the extent they have crimping capacity. Hence, weavers as such are not eligible although the Import Trade Control Policy hitherto recognised them as actual users. In the past the weavers were permitted to import polyester staple fibre for conversion into yarn independently, for use in their undertakings.

The Arts Silk weaving industry naturally feels that the larger interests of the decentralised weaving community have been sacrificed at the alter of MRTP units belonging to the nylon yarn spinners and large cotton and arts silk sector, who would be the real beneficiaries of this decision.

The large organised cotton mills sector should not be allowed to encroach on the fields of production of small scale weavers as it would deliver a mortal blow at the decentralised weaving sector.

There should be an enquiry into the whole matter.

(v) CLEARANCE FOR NEW SIX HYDRO-ELECTRIC SCHEMES OF KERALA.

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): Project reports on the following 6 (six) new Hydro electric schemes of Kerala have been prepared and sent to Central Electricity Authority for scrutiny and clearance from the Planning Commission is awaited.

1. Lower Periyar Hydro-Electric Scheme. The project report was submitted to Central Electricity Authority in 1976 and sanction is awaited.

2. Kuriarkutty—Karapara Multipurpose Scheme. The project report on the scheme costing Rs. 4855 lakhs submitted to the Central Electricity Authority in 1978 for sanction. Sanction from Centre is awaited.

3. Kuttiadi Augmentation Hydro-Electric Scheme. The project report has been submitted to the Central Electricity Authority in 1976 and clearance is pending.

4. Kerala Pandiyar—Punnapuzha Hydro-Electric Scheme. The scheme report has been submitted to the Central Electricity Authority in 1972 and sanction is pending with the Centre.

5. Mananthedy Multi-purpose Scheme. The scheme report submitted to the Central Electricity in April, 1980.

6. Kallada Power Generation Scheme. The project report has been submitted to the Central Electricity Authority for sanction.

I request the Government to take early steps to sanction these schemes.

(vi) REPORTED KILLING OF A PERSON BY MEERUT POLICE.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): The Old and widowed mother of several children Ram Tharai has lost her son Ramesh (22 years) who was taken into custoday by Meerut Police on February 26. He is alleged to have not allowed a Police jeep to overtake his truck which was impounded. Cleaner Ravi says he saw Ramesh last, being brutally beaten by Police, and ran back to Delhi, Shahadara to inform his brother Kishanlal who could get from Meerut Police only the truck, transistor and Ramesh's watch which the 'Darogaji' was wearing. Ramesh was not traceable.

On the third day, i.e. March 1, having learnt that Meerut Police was about to dispose of an unclaimed body, Kishanlal again rushed to Meerut and got the 'unclaimed' body of Ramesh only after there was a public demonstration against the Police.

Has Ramesh been another victim of Police brutality inside a Police Station? An enquiry has been ordered to be conducted by the Meerut Additional District Magistrate (Eexutive). The Meerut Superintendent of Police has stated that "Ramesh committed suicide"—which is open to doubts on substantial grounds.

The Meerut *post mortem* report says that Ramesh died in the early morning of February 27 and Meerut S.S.P. says that Ramesh talked with a person in the late morning of February 27.

The Hon. Home Minister Giani Zail Singh has personally seen the victim's body yesterday and is said to have persuaded the U.P. Government for enquiry.

I appeal to the Hon. Home Minister to persuade again the U. P. Government to see reason, realise genuine public doubts and order a judicial enquiry by a High Court Judge for not only giving justice to the bereaved old mother Ram Tharai and clearing the public doubts but also for clearing the name of Meerut Police if there is nothing foul for the police to hide.

Further let the concerned Police persons be suspended and C.B.I. be asked to investigate to eliminate possibilities of interference in a judicial enquiry.

स्पाध्यक्ष महोदय, आज शाहदरा बन्द है और उन्होंने धमकी दी है कि वे कल जी० टी० रोड बन्द करेंगे.. (व्यवधान)..

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): The Home Minister is here. I also demand that he should make a statement. He is aware of the facts. (*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री जैलसिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, कल मेरे निवास-स्थान पर रमेश जी की लाश को ले कर कुछ लोग पहुंचे, उन में स्त्रियां भी थीं और मर्द भी थे। उन्होंने कहा कि यह साबित करने के लिए कि यह रेल के नीचे नहीं आया है, पुलिस ने मार दिया है, सब से पहले तो इसका री-पोस्टमार्टम कराया जाये। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इस की जुडीशियल एन्क्वायरी हो और कुछ ने कहा कि सी० बी० आई० इक्वायरी करे और पुलिस के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की जाये। उस के बाद मैंने कहा कि री-पोस्टमार्टम तो बहुत जरूरी बात है। मैंने उसी वक्त अपने अफ़सरों को कहा कि वहां के स्थानीय अफ़सरों से कहिये और यू० पी० गवर्नमेंट से कान्टैक्ट कीजिए कि री-पोस्टमार्टम करने के बाद इन की जो दूसरी शिकायतें हैं उन का निवारण करने के लिए उन्हें सुनें और अगर इस बात में थोड़ा-बहुत भी शुब्हा है कि पुलिस की वजह से इसकी जिन्दगी गई है तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर करने में दरेग़ न किया जाय। सी० बी० आई की इन्क्वायरी तभी हो सकती है जब स्टेट गवर्नमेंट इस बात को माने। इस के लिए हम ने स्टेट गवर्नमेंट को सुझाव दिया ....

श्री सूरजभान : आप मनवा सकते हैं।

श्री जैल सिंह : शाम तक मुझे चीफ़ मिनिस्टर नहीं मिल सके थे, लेकिन शाम को मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि री-पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अफ़सर मान गये हैं। और वे दिल्ली पहुंच रहे हैं और जो पहले पोस्ट-मार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट भी साथ ले आयेंगे। वे कल शाम यहां पहुंच गये थे।

मेरे पास दिल्ली प्रदेश कांग्रेस (आई) के प्रेसिडेण्ट श्री एच० के० एल० भगत दो बार—पहले एक डेपुटेशन ले कर और फिर दूसरा डेपुटेशन ले कर आए थे ... (*Interruptions*)

SHRI H. K. L. BHAGAT: The relations of the deceased were there.

श्री सूरज भान : आप उन्हीं के नाम से इन्क्वायरी करा दो।

SHRI H. K. L. BHAGAT: The deputation went to the Home Minister's house twice. He took a lot of interest. I also stand by the demand that an inquiry be conducted by C.B.I. (*Interruptions*)

श्री जैल सिंह : भगत जी ने अपने डेपुटेशन के साथ इस बात पर जोर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को आप मनवाइए और मनवा कर सी० बी० आई० एन्क्वायरी करवायें। उन्होंने बहुत जोर से कहा। मैंने कहा कि कायदे की बात यह है कि यह स्टेट की बात है, हम स्टेट को एडवाइज कर सकते हैं, स्टेट मान ले और हम से रिक्वेस्ट करे तो सी० बी० आई० की इंक्वायरी भी हो सकती है। उस डेपुटेशन में भी दो राय थीं लेकिन भगत जी ने जोर दे कर कहा कि सी० बी० आई० की इंक्वायरी हो ताकि जल्द से जल्द मामला निपट जाए और असलियत बाहर आ जाए। इनके कहने के बाद मैंने दो, तीन बार स्टेट गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया। जब सी० एम० नहीं मिले, तो हमारी होम मिनिस्ट्री के अफ़सर वहां के होम सेक्रेटरी और चीफ़ सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि जो री-पोस्टमोर्टम होना था, वह नहीं हुआ। इस के बारे में हमें अभी खबर नहीं मिली है

[श्री जैल सिंह]

मगर मैंने यह एडवाइज किया है कि इस लाश को, क्योंकि कई दिन हो गये हैं, किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाए ताकि खराब न हो और री-पोस्टमार्टम के काबिल रह सके और कल लाश को उठा कर पुलिस वाले, दिल्ली की पुलिस वाले स इरगंज अस्पताल में छोड़ आए थे और मेरठ की जो पुलिस है, उस के डिप्टी सुपरिण्टेंडेंट और कुछ और अफ़सर भी गये थे। मैंने कहा था कि आप भी सामने बेशक खड़े रहो और आप का जो पोस्टमार्टम का सर्टीफिकेट है, वह दिखला.ओ लेकिन दिल्ली में ही री-पोस्टमार्टम हो और मेरठ में नहीं। इस बात को भगत जी और डेपुटेशन वाले मान गये। हम चाहते हैं कि दिल्ली में री-पोस्ट-मार्टम हो और आयन्दा की जो कार्यवाही है, उस पर हम निगाह रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि उन को इन्साफ मिले।

(Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not allowing. This will not go on record. *(Interruptions)* **

(vii) REPORTED TERROR IN BHARATPUR (RAJASTHAN) DUE TO ACTIVITIES OF DACOITS.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Sir, through you I want to bring to the notice of the State Government of Rajasthan the following. There is a feeling of terror and shock in three tehsils of District Bharatpur of Rajasthan, namely, Kama, Nagar, and Deeg. There had been 13 dacoities in the last 21 days. People of villages in these tehsils are under terror of this particular gang of dacoits which is operating there. State Government has been informed but still effective action has not been taken so far. State Government should be asked to restore the confidence of the people in the area.

14.43 hrs.

RAILWAY BUDGET, 1981-82—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now resume the general discussion on the Railway Budget.

SHRI NITYANANDA MISRA (Bolangir): Sir, I rise to support the budget proposals presented by the Railway Minister. At the outset, I would like to congratulate the Railway Minister on the maturity of judgment he has exhibited in the framing of the budget and according priorities to the most vital and important sectors and for properly appreciating and tackling the issues and problems confronting the railways in a very realistic manner.

All of us know that the Indian Railways is a gigantic and massive organisation employing 17 lakhs of people, with a vast network of railways in every nook and corner of the country. The level of economic activity of the country and our economic progress and development to a large measure depend upon the efficient functioning, and better performance and systematic working of our railways. Unfortunately thirteen months ago when our Government took over, it was in a very bad shape and had sunk to a very low level of sluggishness and stagnation. It needed a great amount of tenacious and persistent effort to bring it out from the rot. It is a matter of satisfaction for everyone of us in the House that the railways have been restored back to the track again. Recently some improvements have been made which are very clearly perceptible and a part of the credit should go to the Railway Minister who has spared no effort in introducing these improvements within a brief span of three months.

I consider that it is a step in the right direction to give priority atten-

---

**Not recorded.

tion to freight transportation with a view to making available essential raw materials to our industries and thermal stations. This will ensure full capacity utilisation and higher productivity, which are our basic objectives. At the same time, the Railway will be able to strengthen and stabilise its own finance which is so vitally necessary for its efficient functioning and for its improvement.

A significant feature of the Budget is the thrust towards increasing the pace of electrification and retiring a large number of steam locomotives. It will enable the Railway to achieve better performance with lower cost. We welcome and commend the decision of the Railway Minister to constitute a high power committee of experts to examine the zonal and divisional systems and to go into the matter to make an indepth, thorough and detailed study as to how railways can adequately respond to the ever increasing demand of our expanding economy and how it can shoulder greater burden and heavier responsibilities in the Sixth Five Year Plan.

Criticisms have been levelled against the Railway Budget on the ground that the rise in freight rate would lead to inflationary pressure on the economy. Though to a certain extent it is true, yet its effect on the economy will be marginal. But the Government should be firm and determined in not allowing the prices to rise. Unscrupulous traders are always in the habit of increasing prices on some pretext or the other at the time of the Budget. It is necessary on the part of the Government to be very firm and not to allow any increase in the prices because there has been a slight increase in the freight rate.

I take this opportunity to speak a few words about my State. Orissa is an un-developed and backward State. Strangely enough though there are vast amounts of mineral resources in our State, they have remained untapped and unexploited. There are vast potentialities and possibilities which have not been realised. It is primarily because of the fact that we lack infrastructural facilities. There is no efficient communication system and we have been neglected by the Railway.

Now for any new railway lines to come up the Railway Ministry is insisting upon the adoption of the yardstick of cost benefit ratio, that is, the return that they will get on the investment which they make on the new railway project. If this new yardstick is rigidly and inflexibly adhered to in the case of new railway lines, an undeveloped area will continue to remain undeveloped for all times to come and it will have no scope for economic development. Therefore, I would request the hon. Railway Minister to be kind and generous enough to pay special attention to these areas, which remain economically backward and undeveloped over a number of years.

The regional imbalances and inequalities have been aggravating the social and political problems, and the railways can play a very vital role in removing these regional imbalances, if they decide to take up new railway lines in those areas which are undeveloped and economically backward.

I will give you a few instances. There is a proposal for a railway line from Banspani to Daitari, which will pass through an area which is inhabited by the Adibasis. This area has high potentialities because it is very rich in mineral resources. A sponge iron plant is coming up and a large number of industries will come up if there is a railway line. The survey for this line has already been completed, awaiting investment decision. I would request the Railway Minister to give top priority to this railway line, because it will fulfil the legitimate aspirations of the people by bringing about the economic development of that area and also of the State, which in turn will be able to bring about a substantial contribution to the development of the national economy as a whole.

[Shri Nityananda Misra]

There is another railway line, which has been surveyed, and that is from Sambhalpur to Talcher. Orissa has been divided into two parts, two water-tight compartments. One is western Orissa, which is very rich in minerals, in agricultural and forest resources, but which remains completely undeveloped, and the other part is the coastal area. There is absolutely no railway communication between Western Orissa and the coastal area, as a result of which the economic prosperity of the State has received a set back for a number of years. I would appeal to the Railway Minister to give top priority to this Sambhalpur-Talcher railway line so that the economic development of the State can be made possible.

Coming to my own constituency, there is a proposal for a railway line from Bolangir to Kurdha and another railway line from Kesinga to Koraput via Bhabanipatna in Kalahandi district. My district of Bolangir is the poorest district in the whole of Orissa. I would suggest that the survey for these lines should be conducted as early as possible. I would appeal to the Railway Minister to be kind and generous enough to pay special attention to this district, because it is the poorest area in the whole State.

Coming to the trains passing through our State, Neelachal Express is a super-fast long distance train. But there is, unfortunately, no pantry car arrangement in that train, as a result of which passengers are suffering. Further, since no security arrangement has been made in that train, dacoities are being committed. Members of Parliament have brought this fact to the notice of the hon. Minister several times. So, I would request the Minister to make suitable security arrangements in that train so that this problem can be solved.

DEPUTY SPEAKER: Do not make many demands of the Railway Minister. He will not be able to meet. One or two demands are enough.

SHRI NITYANANDA MISRA: And it is running three times a week. I would request the Railway Minister to make it daily.

There is another train, Kalinga Express, which is running once a week. This is serving not only the western part of Orissa, but also Madhya Pradesh. So, I request the Minister to make it tri-weekly.

14.56 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

These are some of my proposals. I hope the Railway Minister will be kind and generous enough to give priority to these proposals so that they will materialise in the near future.

With these words I once again support the Railway Budget.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को मैं असन्तुलित और अव्यावहारिक मानता हूं। इसका कारण यह है कि रेलवे बजटों के इतिहास में यह पहला बजट है जो 27 पन्ने का हो और उसके बावजूद भी सभी बातें सामने नहीं आ पाई है। इन्होंने माल भाड़े यात्री भाड़े आदि में वृद्धियां की हैं। यात्री भाड़े में दस प्रतिशत से ले कर पंद्रह प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। इनको नेट इससे जो इनकम है, शुद्ध जो आमदनी है वह 11.42 करोड़ की है। लेकिन खेद है कि थेफ्ट और पिलफ़ेजिज पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस पर करीब 25 करोड़ रुपया रेलवे का जाया हो जाता है हर साल। क्लम्ज पर करीब बारह करोड़ हर साल जाया हो जाता है। इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। लगता है कि मंत्री जी को स्केपगोट बनाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है। वास्तव में अधिकारियों ने जो बजट सामने प्रस्तुत किया है लगता है कि इन्होंने ज्यों का त्यों पढ़ दिया है। अगर

इन्होंने ध्यान दिया होता तो इस तरह की जो मुख्य बातें हैं वे नहीं छूट सकती थीं।

रिजर्वेशन चार्ज भी इन्होंने बढ़ाया है, सुपर चार्ज भी बढ़ाया है, एक रात से ज्यादा रातें होने पर जो चार्ज लगता है उसको भी बढ़ाया है। इस तरह से यह कुल मिला कर बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है, बजाय दस परसेंट के। गरीब आदमी को जो सैकिंड क्लास में सफर करता है अब बीस परसेंट अधिक देना होगा एक अप्रैल से।

एक अप्रैल से माननीय सदस्यों को भी यह बजट एडवर्सली एफैक्ट करेगा। सैकिंड क्लास ए सी सी में पंद्रह रुपये की एक हजार किलोमीटर तक और उससे ज्यादा पर पच्चीस रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। रेल अधिकारी मुझे बता रहे थे कि अगर हम कम्पैनियन को साथ ले जाएंगे, स्पाउज को साथ ले जाएंगे तो वे बिना सरचार्ज के नहीं उनको जाने देंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय की मंशा क्या है इसको भी वे साफ करें।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि वह चाहते हैं कि फ्रेट ओरिएंटिड साइकोलोजी मुल्क उभरे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि गुड्ज ट्रैफिक का मूवमेंट बढ़ा है, जो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन माननीय सदस्य और सारा देश जानता है कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी आज तक एक भी गाड़ी समय पर नहीं चल पा रही है। तो एक तरफ़ आप कहते हैं कि फ्रेट ओरियेंटेड साइकोलाजी होगी, तो दूसरी तरफ यह आपका सामाजिक दायित्व भी होता है कि कम पैसे पर लोगों को समय पर पहुंचायें। इस बात की आप पूर्ति करेंगे कि नहीं, इसका कोई जिक्र आपके बजट भाषण में नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संतुलन लाया जाय। ठीक है फ्रेट ओरियेन्टेड साइकोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं देश में, लेकिन साथ ही आप पेसेंजर गाड़ियों को नजरन्दाज नहीं कर सकते। मंत्री जी ने कहा कि रेलवे कमर्शियल आर्गेनाइज़ेशन है। तो बेसिक कामर्शियल बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती कि जहां कोई खरीददार ज्यादा चीज खरीदता है उसको छूट दी जाती है। यह व्यवस्था पहले थी कि ज्यादा दूर जाने वाले को छूट दी जाती थी। लेकिन इस बजट में आपने उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है।

15.00 hrs.

रेल किसी भी जगह की तरक्की का बड़ा माध्यम है, और इससे पहले भी एक यूनीफ़ार्म पौलिसी रेलवे की रही है कि बैकवर्ड रीजन में रिटर्न की बात नहीं की जाती है। अगर ऐसा करेंगे तो बैकवर्ड रीजन में रेल कभी नहीं हो सकती। वास्तव में बैकवर्ड रीजन को नेगलेक्ट किया गया है, जब कि सरकार बारबार कहती कि हम रीजनल इम्बैलेंस को दूर करना चाहते हैं। वास्तव में बैकवर्ड रीजन को नेगलेक्ट कर के सरकार ने रीजनल इम्बैलेंस को और बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए सरकार की पहले से ही जो ऐक्सेप्टेड पौलिसी रही है कि बैकवर्ड रीजन में रिटर्न आधार नहीं होगा नई लाइनें देने का, उस पर सरकार को अमल करना चाहिए। अगर बैकवर्ड एरिया को आपको आगे बढ़ाना है तो वहां नई रेल लाइनें दी जायें।

आज रेलवे में टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। यह बात इनका प्रशासन भी मानता है। गत एक साल में अफ़सरों की बढ़ोत्तरी हुई है। इनका मंशा एक ही था कि यह चाहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन हो और वर्किंग इम्प्रूव करें। आप इस बात को रिव्यू करें कि जब से अफ़सरों

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

की बढ़ोत्तरी की है और क्लास तीन और चार के पदों में कटौती की है तब से आपका परफ़ारमेंस इम्प्रूव किया है या गिरा है ।

रेलवे विभाग को रेल ऐक्सीडेंट का विभाग कहा जाता है । कोई गाड़ी समय पर नहीं आती है । इससे माना जायगा कि वास्तव में इसकी कार्यकुशलता घटी है । लेकिन चूंकि रिकमन्डेशन आई और इन्होंने मान लिया कि अफ़सरों को ऐकोमोडेट करना है । उसके आधार पर आपने 18 ऐडीशनल जो० एम० औरर् क डी० एस० की जगह 3, 4 डी एस बना दिये । मुझे अफ़सोस है कि अफसरों के बढ़ने के बाद भी किसी जोन या डिवीजन में या इंडियन रेलवेज ऐज सच में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि उसकी कार्यक्ष में गिरावटात आई है ।

मंत्री जी ने अपने भाषण में डीजलाइज़ेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कहीं है । उनका मंशा नेक है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस बदकिस्मत इलाके का क्या होगा जहां न डीजल की और न बिजली की गाड़ी चलती है,केवल कोयले से चलने वाली गाड़ियां ही चलती हैं । आपके पास 500 कोयले के इंजन हैं जिनको स्क्रैप डिक्लेयर किया जाना है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, ऐन० ई० जोन में वहां आज भी दर्जनों गाड़ियां रह पड़ी हुई हैं जिनको रेस्टोर नहीं किया गया है । इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए भी कुछ होगा कि नहीं ? आप डीजलाइज़ेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन जरूर करें, लेकिन दूसरी तरफ़ यह भी कहना चाहूंगा कि कोयले के इंजनों पर भी, जिनसे खास एरियाज में गाड़ियां चलती हैं, तवज्जह दें । उसका इम्प्रूवमैंट हो ताकि उस इलाके में भी गाड़ी ठीक से चल सके और वहां के लोगों को सुविधा मिल सके ।

आज रेल विभाग को यदि एक्सीडेंट्स का विभाग कहा जाये, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । उसके कुछ कारण हैं । आज डिब्बों की प्रापर मैन्टीनेन्स नहीं होती है, लेकिन पता नहीं प्रशासन के लोग क्यों उसको नज़रन्दाज करते हैं । वह कहते हैं कि हमें तो स्पीड चाहिए । मैं पूछता हूं कि क्या स्पीड सेफ्टी के कौस्ट पर उन्हें चाहिए ?

दूसरा कारण यह है कि सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं होता है । जो सेफ्टी रूल्स इन्होंने बनाये हैं, इसका मंशा है कि उसके हिसरत से सेफ्टी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन रूल्स में संशोधन लाये जायें । इनका अभी कहीं पूरी तरह पालन नहीं होता है । किसी कर्मचारी ने अगर पालन की बात कही तो वर्क टू रूल हो गया और रूल नहीं माना तो एक्सीडेंट हो गया । मैं जानना चाहता हूं कि जो रूल बनाये गये हैं, वह मनवाने की मंशा से बनाए गये हैं या न मनवाने की मंशा से ? मेरा कहना है कि रूल मानते हुए अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाये तो कम-से-कम कर्मचारी को दोषी न समझा जाये ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी नये मंत्री आते हैं, यह एक फैशन सा हो गया है कि वह कुछ नई गाड़ियां इन्ट्रोड्यूस करते हैं । लेकिन खुद उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि जो गाड़ी बढ़ाने जा रहे हैं उसके मुताबिक डिब्बे भी बढ़े हैं या नहीं । होता क्या है कि 2, 3 डिब्बे इस गाड़ी से काट लिए और 2, 3 किसी और से और इस तरह से एक नई गाड़ी बना दी । जो पूरी गाड़ी थी, उसमें डिब्बे कम हो गये और जो नई बनी है, उसमें भी पूरे नहीं हुए । यदि वास्तव में मंत्री जी चाहते हैं कि देश में गाड़ी बढ़ें, लोगों को सुविधा मिले तो डिब्बे भी बढ़ाए जाने चाहियें । अगर गाड़ियों में डिब्बे नहीं बढ़ाये जायेंगे, तो कोई फायदा नहीं

होना। कोई भी मंत्री आये और नई गाड़ी अपने देश में दे दी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

अभी अखिल भारतीय गार्ड काउंसिल की तरफ से एक सेफ्टी सैमिनार हुआ था। मैं यह मानता हूं कि ट्रेड यूनियन की मूवमेंट में यह पहला मौका है जब किसी आर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से पैसा खर्च कर के इस तरह का सैमिनार किया कि सेफ जर्नी कैसे हो। मंत्री महोदय ने इस सैमिनार का उद्घाटन किया था। उसमें कुछ सुझाव आये थे। मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाऊंगा कि उस पर अगर ध्यान दिया गया तो उससे एक्सीडेंट कम होंगे। अगर पूरे एक्सीडेंट्स खत्म नहीं भी होते तो इससे कम जरूर होंगे।

मेरा सुझाव है कि ट्रेन में आपरेटिंग स्टाफ की बढ़ोतरी होनी चाहिए, आप कमर्शियल के स्टाफ को बढ़ा रहे हैं लेकिन आपरेटिंग स्टाफ, जिनके माध्यम से ट्रेन अपरेट होती हैं, उनको बढ़ाना जरूरी है।

दूसरा सुझाव है कि कोई भी गाड़ी बिना अच्छे ब्रेकवान के न चलाई जाये। ब्रेकवान यदि अच्छा रहेगा तो गार्ड को रोका जा सकेगा, लेकिन आज तो हालत बड़ी खराब है, गुड्ज ट्रेन में अच्छे ब्रेकवान नहीं होते, आप उनको तेजी से चलाना चाहते हैं जिससे गुड्ज का मूवमेंट अच्छा हो सके, लेकिन इसमें अच्छे ब्रेकवान भी लगाये जायें ताकि जो कर्मचारी उसमें चलते हैं वह भी आदमी का जीवन बसर कर सकें और एफीशियेंसी उसमें हो।

गार्ड और ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं गाड़ी दो मिनट रुकती है, कहीं 3 मिनट रुकती है, संभव है कि किसी डिब्बे में कोई डिफिकल्टी हो, गार्ड के सामने या ड्राइवर के सामने दिक्कत आये तो वह आपस में कोई विमर्श नहीं कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि गार्ड और ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन हो सके।

कर्मचारी को केअर-फ्री अवश्य होना चाहिए। जब पीछे स्ट्राइक हुई थी तो किसी कर्मचारी के परिवार पर अत्याचार हुआ था, इसलिए स्ट्राइक हुई थी। जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, उसको विश्वास होना चाहिए कि उसके घर में उसका परिवार सेफ है, उसके लिए राशन-पानी की व्यवस्था है। आज जो महंगाई बढ़ रही है, रेल बजट ने और बढ़ाई है, मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारी केअर-फ्री नहीं हो पायेंगे। इस लिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कर्मचारियों को आश्वस्त करें कि उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी और उनके खाने-पीने का समुचित प्रबन्ध किया जायेगा।

कई गाड़ियां डबल क्रू के साथ चलती हैं, ताकि एक सरटेन डिसटेंस के बाद दूसरा क्रू टेक ओवर कर ले। लेकिन बदकिस्मती से क्रू के लिए रैस्ट वैन की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण वे लोग आराम नहीं कर पाते हैं और दोनों क्रू परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो एक कर्मचारी को लगातार सत्तर घण्टे तक काम करना पड़ता है। मंत्री महोदय को इस तरफ तवज्जुह देनी चाहिए।

मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में मीटरगेज को ब्राडगेज में कनवर्ट करने की बात को डेकाई किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे मुल्कों में एम जी पर गाड़ियां 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन मुल्कों में किसी दूसरे गेज की गाड़ियां भी चलती हैं? वहां पर केवल एक ही गेज की गाड़ियां चलती हैं। किसी भी मुल्क में यूनिगेज की जरूरत होती है, क्योंकि अलग-अलग

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

गेज होने से ट्रांसशिपमेंट की प्राबलम होती है और उसमें समय लगता है। एक तरफ़ तो मंत्री महोदय कहते हैं कि बी जी में कनवर्शन की जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ़ वह उसी पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। वास्तव में वह चाहते क्या हैं? क्या वह चाहते हैं कि मुल्क में एक ही गेज हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो? इसलिए यह बात कोई मानी नहीं रखती है कि दूसरे मुल्कों में एम जी पर गाड़ियां 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं, जबकि हम केवल 130 किलोमीटर की रफ्तार तक ही पहुंच सके हैं।

आज भारतीय रेलवे के जोन्ज़ को रीआर्गनाइज करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि जोन इतने लम्बे-चौड़े हैं कि जोनल हेडक्वाटर में एक जेनरेल मैनेजर के अलावा तीन एडीशनल जेनरेल मैनेजर्ज रहते हैं फिर भी मैनेज नहीं हो पाता। बिहार एक ऐसा बदकिस्मत प्रदेश है, जहां बहुत जोन्ज की गाड़ियां चलती हैं, लेकिन वहां आज तक एक भी ज़ोन की स्थापना नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ज़ोन की स्थापना हो।

हमें लगता है कि चूंकि रेल मंत्री महोदय बिहार से आते हैं, इस लिए वह बिहार को कोई सुविधा देने में थोड़ा एमबैरेस फ़ील करते हैं। एक दफ़ा रेल मंत्री स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र, बिहार के सांसदों से मिल रहे थे। लोगों ने कहा कि आप पूरे देश के रेल मंत्री हैं, आपको बिहार को कोई सुविधा देने में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की एक्सेप्टिड पालिसी है कि रिजनल इमबैलेंसिज को दूर किया जाये। यदि वास्तव में सरकार की यह नीति है, तो चूंकि बिहार को रेल की दृष्टि से कम सुविधाएं मिली हुई हैं, इसलिए बिहार को यह कहने का अधिकार है कि इसे वाजिब हिस्सा मिले। उसमें एमबैरेस फ़ील करने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं बिहार की उन मांगों के बारे में कहना चाहता हूं, जिनका मंत्री महोदय ने अपने बजट-भाषण में जिक्र नहीं किया है। बरौनी से कटिहार तक की लाइन को बी जी में कनवर्ट किया जाये, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने नहीं कहा है। फतुहा-इस्लामपुर रेलवे लाइन को टेक ओवर किया जाये। जमालपुर वर्कशाप की तरक्की के लिए कदम उठाये जायें, जहां लाखों लोग काम करते हैं। कोसी पर सरायगढ़ और निर्मली के बीच में पुल बनाया जाये, जो सहरसा और दरभंगा इन दो जिलों को जोड़ सकता है। ललित बाबू ने इसे शुरू किया था, लेकिन मालूम होता है कि आदमी बदलने के साथ पालिसी भी बदल जाती है। इस काम को पूरा किया जाये।

मेरे क्षेत्र में दौरम मधेपुरा से सिंहेश्वर तक की साढ़े नौ किलोमीटर की लाइन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसका बार-बार सरवे हो चुका है, जिसपर काफ़ी पैसा लगा है।

बिहारीगंज से सिमरी बख्त्यारपुर तक की लाइन के काम को भी हाथ में लिया जाये। उसका सरवे भी हो चुका है। मैं अपने यहां जाता हूं तो पटना से बरौनी में जा कर पांच घण्टे मुझे रुकना पड़ता है। मैं जाता हूं दानापुर-समस्तीपुर एक्सप्रेस से तो 8 बजे रात को पहुंचता हूं और 1 बजे रात में हमें फिर जानकी एक्सप्रेस मिलती है। पांच घण्टे में हम दूसरी गाड़ी से अपने यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन 5 घण्टे हमें वहां इंतजार करना

पड़ता है। इसलिए इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

मैं स्वागत करूंगा लोको कर्मचारियों का जिन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। लेकिन मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने बार-बार आश्वासन दिया है कि वह विडिक्टिव नहीं होना चाहते। मैं चाहता हूं कि वह उसी दृष्टिकोण से देखें, वह आप के ही कर्मचारी हैं। उनके ऊपर जो भी कार्यवाही हुई हो, अगर उन्होंने स्वतः हड़ताल काल आफ कर ली है तो उन को भी चाहिए कि उन्हें माफ कर दें क्योंकि वह उन्हीं के कर्मचारी हैं और बिना उनके वह काम नहीं चला सकते।

मंत्री जी, जो स्वयं भी ट्रेड यूनियन लीडर रहे और अगर वास्तव में यह चाहते हैं कि कि इंडस्ट्रियल पीस हो तो बार-बार यह बात आती रही है कि एक इंडस्ट्री में एक यूनियन हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि रेलवे की ट्रेड यूनियन्स के अन्दर भी डेमोक्रेटाइजेसन के दृष्टिकोण से भी उस को वह चाहे सीक्रेट बैलट के आधार पर ही कर लें, लेकिन एक यूनियन ही रहने दें तो मल्टिप्लिसिटी आफ यूनियन्स उनके सामने नहीं रहेगी। मेरा विश्वास है कि मंत्री जी खुद इस तरफ ध्यान देंगे तो इसे कर पाएंगे और इस में बहुत सारे विरोधी दल के लोगों का भी सहयोग होगा।... (व्यवधान)...

बहुत दिनों से रेलवे की और हमारी यह मान्यता रही है कि यह जो कैटरिंग चल रही है यह डिपार्टमेंट को दी जाय और उसमें जो कर्मचारी हैं उन को सुविधा दी जाये खासकर के वह यूनिट जो फायदे में चल रहे हैं। हमें खेद है कि अभी जयन्ती जनता में हम ने सुना है कि किसी प्राइवेट कांट्रैक्टर को यह काम दे दिया गया है जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनकी नौकरी खतरे में है। मैं आग्रह करूंगा कि इसको वह देखें। स्टीमर पर भी उन्होंने पटना में किसी प्राइवेट कांट्रेक्टर को दे दिया है। ये दोनों के दोनों आर्गेनाइजेशन मुनाफा दे रहे थे। ... (व्यवधान) ...

एक टाइम-टेबल की बात मैं कहना चाहता हूं। आप देखेंगे कि बहुत दिनों से एक आल इंडिया टाइम टेबल चलता था। पैसे के दृष्टिकोण से भी उस में फायदा था। अगर किसी को एक टाइमटेबल खरीदना होता था तो वह पूरा टाइम टेबल खरीद लेता था। अब हम को जोन-जोन के टाईम-टेबुल से कठिनाई हो रही है। हम को पूरे देश में चलना पड़ता है, अब हर एक जोन का इन्होंने अलग अलग दे रखा है, उस में से एक कहीं गुम हो गया तो बड़ी कठिनाई पड़ती है। जो एक मुख्य टाइम टेबल इनका है उसमें ब्रान्च लाइनों का कोई टाइम-टेबल नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस ओर वह ध्यान दें और देखें कि एक ही टाइम-टेबल हो जिसमें कि इन का भी फायदा हो और दूसरे लोगों को भी सुविधा हो।

श्री जे० सी० बर्वे (रामटेक) : सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने जो बजट 1981–82 का सदन के सामने रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो लोग 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक आते-जाते हैं उनको रेलवे मंत्री जी ने रियायत दी है, उसके लिए मैं उन का शुक्रिया अदा करता हूं।

रेलवे का जो मुहकमा है यह बहुत बड़ा मुहकमा है। इस की गतिविधियां अगर सही तरीके से चलें तो मेरा ख्याल है कि देश का उत्पादन बढ़ेगा और देशमें जो आने-जाने वाले लोग हैं जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जाते हैं उनको जाने-आने में सहूलियत होगी। माल डिब्बे की बात में कहना चाहूंगा, आज

[ी जे०सी० बर्वे]

हमारे पास जो माल डिब्बे हैं जिनमें लदान करते हैं और यहां से वहां माल जाता है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये तो अच्छा होगा । अभी तक इस प्रकार का नियम था कि माल ढोने वाले जो डिब्बे हैं, उनको दस रोज में डैमरेज देकर के छुड़ा सकते हैं । परन्तु अब एक ऐसा नियम विचाराधीन है कि उसको 20 दिन किया जाए । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उसको 20 दिन कर दिया जाएगा तो उसका वहां पर एक गोडाउन बन जाएगा और दूसरी तरफ वहां पर वेगन्स भी नहीं मिलते हैं । अगर इस प्रकार से पक्के माल को गोडाउन में जमा करके रखने के लिए 20 दिन की छूट दी जाएगी तो ठीक नहीं होगा । इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर ध्यान देंगे ।

मैं रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं । हमने बार-बार जनता पार्टी के टाइम में भी और कांग्रेस के टाइम में भी यह कोशिश की कि हमारे जो नरखेड़-अमरावती लाइन है, उसका जल्दी से जल्दी सर्वे कराया जाए और उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि नरखेड़-अमरावती का इलाका एक अरबन एरिया है । वहां होता यह है कि वहां पर जो माल तैयार होता है, पकता है, उस माल को पहले मध्य प्रदेश, मुलतायी स्टेशन पर, ट्रक से 80—90 किलोमीटर दूरी तय के, लाया जाता है और फिर उसको रेलवे द्वारा दूसरी जगहों पर भेजा जाता है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस लाइन को जल्दी से जल्दी हाथ में लेकर पूरा करायें, ताकि वहां जो संतरा पैदा करने वाले किसान हैं, उनको फायदा हो सके तथा उनको ट्रक से माल न ढोना पड़े और उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके ।

मैं माननीय मंत्री जी से सरचार्ज के बारे में कहना चाहता हूं । मंत्री जी ने पक्के माल पर सरचार्ज लगाया है, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु जैसे संतरा, केला आदि फल हैं, उन पर उन्होंने 15 टके सरचार्ज लगाया है, इससे किसानों के लिए और उत्पादक लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें और जो 15 टके सरचार्ज लगाया है, उसको रद्द करें—ऐसी मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं ।

अब कुछ बातें मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां छत्तीसगढ़ ट्रेन, छत्तीसगढ़ से होते हुए दिल्ली आती है, लेकिन यह ट्रेन कामटी स्टेशन पर दो मिनट के लिए भी नहीं रुकती है, जोकि मिलिटरी एरिया है, नागपुर जिले का दूसरे नम्बर का शहर है । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि मिलिटरी के आने-जाने वाले लोगों को उस छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस को रोककर के उनको भी फायदा दिया जाए । इसी प्रकार से नरखेड़ रेलवे स्टेशन है, जहां पर संतरे का बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन वहां सदर्न एक्सप्रस चाहे दिल्ली से जाने वाली हो या नागरपुर से दिल्ली जाने वाली हो, रुकती नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत कठिनाई होती है—उम्मीद है मंत्री जी इस पर भी ध्यान देंगे ।

सभापति महोदय, जब हमारे क्षेत्र में रेलवे का चलना शुरू हुआ तो सिर्फ एक दफा सवेरे और एक दफा शाम को रामटेक से नागपुर और नागपुर से रामटेक के लिए चलती थी, लेकिन अब भी उसी रफ्तार से रेलवे चलती है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर वहां पर बीच में एक दफा रेलवे और चलाई जाए तो वहां के लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां पर ट्रेफिक में भी कोई कमी नहीं है । वहां इस वक्त यह पोजीशन है कि बसों के किराये दुगने हो जाने के बावजूद बसों में जगह नहीं मिलती है ।

इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि दोपहर के समय में एक गाड़ी नागपुर से रामटेक और रामटेक से नागपुर के बीच में चलाई जाय ।

इन शब्दों के साथ माननीय रेल मंत्री जी ने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रणबीर सिंह (केसरगंज) : चेयरमैन साहब, मैं रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बड़ी अच्छी बात है—यादव जी रेल मंत्री जी के पास से उठ कर आ गये हैं, 40 मिनट तक तो यहां अपने भाषण में बतलाते रहे और फिर उनके लिए पास जा कर बतलाते रहे । अब मुझे मौका मिलेगा कि मैं भी कुछ कह सकूं ।

मैं, मंत्री जी, आपको आपके साहसयुक्त कदम के लिये बधाई देता हूं । जो विभाग आप को मिल रहा है, वह पिछले प्रशासन के समय में न केवल पटरी से उतर गया था, बल्कि रास्ते से भी हट गया था, पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया था, चरमरा गया था । हमारे पिछले शासन-काल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह थी कि गाड़ियां समय से चलती थीं और लोग अपनी घड़ियां उनसे मिलाया करते थे । हमने उस समय एक ऐसा उदाहरण देश के सामने रखा था कि हम जो वायदा करते हैं उसे पूरा करते हैं, समय से रेलगाड़ियां चला सकते हैं—लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं उसमें जाना नहीं चाहता । वाजपेयी जी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये, अन्य विरोधी दलों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिये, मैं उनकी यादों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं । रेलें उस समय समय से नहीं चलती थीं—इन यादों को वे अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो रखें, उनको वे यादें मुबारक हों ।

पिछले समय में जब हमारे उस समय के रेल मंत्री—श्री त्रिपाठी जी बोल रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक बहुत ही अनुकरणीय बात कही थी, जो हमेशा स्मरण रहेगी । उन्होंने कहा था—जब रेलें समय से चलती हैं, ठीक चलती हैं तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र समय से चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन जब वे ठीक नहीं चलती हैं, देर से चलती हैं तो यह मालूम होता है कि राष्ट्र ठीक नहीं चल रहा है, समय से नहीं चल रहा है । अपनी छोटी सी बुद्धि से मैं एक बात इस के साथ जोड़ना चाहता हूं—जब सवारियां डिब्बे के भीतर यात्रा करती हैं तो ऐसा लगता है कि अनुशासन हमारे हाथ में है, लेकिन जब डिब्बों की छतों पर बैठ कर चलती हैं तो ऐसा लगता है कि अनुशासन कूद कर, हमें छोड़ कर बाहर जा रहा है । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय दोनों तरफ़ ध्यान दें ।

पिछली दफ़ा जब प्रो० पाराशर भाषण दे रहे थे, तो उधर जहां वाजपेयी जी बैठे हैं, विरोधी दल के एक माननीय सदस्य महालगी जी आर्तनाद कर रहे थे । वे प्रो० पाराशर से बड़े दुख के साथ कह रहे थे—मैं वाजपेयी जी से कहना चाहता हूं, वे भी शायद उन की उस भावना में भागी होंगे—अब तो जनता पार्टी की बहुत बुराई कर चुके हो, कुछ आगे कहो, इस को जाने दो, मैं भी यही सोच रहा हूं कि अब इस के बारे में कुछ न कहूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की बहुत सतर्क आंखें हैं, वे हर बात को बहुत जल्दी देखते हैं—जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वे अपना भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि और-कोई उपलब्धि आप की हो या न हो, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप ने हाइजैकर्स को बहुत बड़ा स्थान दे दिया है । मैं मंत्री महोदय को एक बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं—आज हमारी कबिनेट

[श्री रणबीर सिंह]

में रेलों को डाइमानाइट से उड़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह गया है, वे अपनी रेलों को प्रगति के पथ पर बिना किसी भय के चला सकते हैं, उन को अब यह भय नहीं रह जाना चाहिये कि रेलें डाइनामाइट से उड़ाई जा सकती हैं ।

आप के पास इस समय लगभग 60 हजार रेलवे स्टेशन्ज हैं जिन में प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं । मैं कामना करता हूं कि आप उस कार्य-कुशलता से कार्य करें कि ये 60 हजार रेलवे स्टेशन आप की प्रशंसा के तीर्थस्थल हों और जो एक करोड़ यात्री आप की रेलों में यात्रा करते हैं वे आप की प्रशंसा के अनवरत समूह के रूप में कार्य करते रहें । रेल मंत्री जी ने तमाम कठोर कदम उठाए हैं रिन्यअल्स करने के, रिनोवेशन्स करने के और रेलवे लाइनें बदलने के लेकिन मैं रेल मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सब कुछ वे बदल सकेंगे लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उन को करना है और वह है विलटू वर्क' । पिछले कुशासन में जो हम ने खो दिया है, हमारी कार्य करने की इच्छा शक्त नष्ट हो गई है, उस की पुनः स्थापना करनी होगी । सब चीजें खरीदी जा सकती हैं लेकिन यह नहीं । गो स्लो, गो लेट, नेवर वर्क और रास्ता रोको, लोगों में जो यह प्रवृत्ति बीच में आ गई है, उस को खत्म करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करने पड़ेंगे लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारे रेलवे मंत्री जी जो रेलवे के प्रत्येक तंत्र से पूरी तरह से परिचित हैं, उस के मनोविचार से सही चिकित्सक हो सकते हैं और इस को आगे बढ़ा सकते हैं ।

आज कल हम विद्युतिकरण की बात कर रहे हैं, हम भाप के इंजन को छोड़ चुके हैं, डीजल से अभावगस्त हैं, बड़ी मुश्किल से वह मिलता है और उस की महंगाई से सारा देश पीड़ित होता है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा—हमारे ख्याल से वे दूसरों से बात कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी बातों पर भी ध्यान दे रहे हैं—कि वे विद्युती-करण की बात पर ज्यादा ध्यान दें और मैं यह चाहूंगा कि रेलवे विभाग को अपने पावर हाऊसेज चलाने चाहिए । और उन के पास पावर हाऊस होंगे, जिन में अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन होगा, तो मैं समझता हूं कि वे रेलें सही चला सकेंगे, उन को गति भी दे सकेंगे । आज वे स्थान जहां वेगन बना करते हैं, इस में भी उन का बड़ा भारी योगदान हो सकता है । विद्युतीकरण की जब बात आती है, तो लोग कहा करते हैं कि विद्युतीकरण बड़ा खर्चीला है लेकिन मैं इस का अध्ययन कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि अन्ततोगत्वा विद्युतीकरण से रेलें चलाना सही साबित होगा और वे कम खर्चीली होंगी । इसके अलावा उन में कार्यकुशलता आएगी और उन को हम अच्छी तरह से चला सकेंगे ।

जहां तक वेगनों की बात है, यह वाकई में एक अजीब सी बात है । अब रेलें खाली कोयला ही नहीं ढोती हैं । ये आवश्यक वस्तुएं ले कर जाती हैं और इस की कार्य प्रणाली सीमित नहीं है । इन के द्वारा हमें पूरे राष्ट्र का बाजार भाव एक करना है । जहां भाव बहुत ऊंचा है, वहां सामान पहुंचाना है और जहां नीचा है, वहां से ले जाना है । पिछली दफ़ा जब वेगन उपलब्ध नहीं थे तो जहां फारुखाबाद में आलू का गलेट हो रहा था, वहां आसाम और बंगाल, सभापति महोदय, आप के प्रदेश में, भाव बहुत ऊंचे थे । अगर वेगन उपलब्ध होते तो शायद ऐसी स्थिति न होती । यह भी कहा जाता है कि वैगनों की कमी भ्रष्टाचार का कारण है । माननीय त्रिपाठी जी ने कहा था कि पहले जब वैगनों की कमी थी तो लोग यह कहा करते थे कि पिछले शासन के जमाने में बड़ी मुश्किल से और बड़े भ्रष्टाचार के बाद वैगन मिलते थे

लेकिन त्रिपाठी जी ने इस को ठीक कर दिया था। जिस जादुई डंडे का प्रयोग त्रिपाठी जी ने किया था और इन की कमी दूर हुई थी और शीघ्र ही इस पर विजय वे प्राप्त कर सके थे, वैसा ही पांडे जी, आप करें।

जहां तक पुरानी लाइनों का प्रश्न है, श्रीमान्, मैं अब अपने उस स्थान पर आता हूं जहां पर वाजपेयी जी बार-बार गये है। उन्होंने भी उस को देखा होगा क्योंकि वह उनका बड़ा अच्छा कार्य स्थल रहा है। उन लाइनों को मैं ने देखा है और खास तौर पर मैं उस लाइन की चर्चा करने जा रहा हूं जो गोरखपुर से बहराइच होते हुए नेपालगंज जाती हैं और अब मेलानी तक जाती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि चाहे रजत जयन्ती मनी हो, स्वर्ण जयन्ती मनी हो और हरिक जयन्ती मनी हो लेकिन इन जयन्तियों का इस लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हैं। आप ने सुना होगा कि इस सदन में यह बात हो रही थी कि जब लाइनों में बहुत दिनों तक परिवर्तन नहीं किये जाते है, सुधार नहीं किये जाते हैं, तो फ्रेक्चर हो जाते हैं, मल्टीपिल फ्रेक्चर हो जाते है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं लेकिन उस लाइन में दुर्घटना नहीं होती है। दुर्घटना न होने का कारण यह नहीं है कि रेल की लाइन ठीक है बल्कि कारण यह है कि लाइनों के लिए जो इंजन दिये जाते हैं, वे बड़े पुराने महारथी हैं, जीर्णशीर्ण हैं, उपहा-संयोग्य हैं उपेक्षित हैं और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे ये कुम्भकरण के वंशज हैं और विश्राम में विश्वास करते हैं, गति में नहीं। जब मन में आया तो चल दिये और मन में आया तो विश्राम करते रहते हैं। आज तक हमारे क्षेत्र के लोगों को यह नहीं मालूम है कि रेलों की गति 80 किलोमीटर भी हो चुकी है। इस विपदा के साथ साथ एक विपदा और है। जब मैं किसी मंत्री जी से कहता हूं कि हमारे यहां की रेलों को थोड़ा सा दिखवा लीजिए, तो मंत्री जी कहते हैं कि मैं खुद आऊंगा। बड़े बड़े अधकारियों से कहा, तो उन्होंने भी यही वायदा किया। इस से हम भी खुश हो जाते हैं और अपने क्षेत्र में जा कर कह देते हैं लेकिन वे वहां जाते नहीं हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब तक रेल की गति नहीं बढ़ेगी, यह चीज जारी रहेगी। यह तो मैं नहीं जान पाता कि रेल की गति में सुधार होगा या नहीं लेकिन क्या आप मुझे वह बतायेंगे कि आप वहां जाकर उसे देखेंगे या नहीं। रेल की गति बढ़े या न बढ़े लेकिन आप जा कर देखें जरूर।

पिछले दिनों जो गीतांजली एक्सप्रेस चली उसी उम्मीद से मैं कह रहा हूं कि आप गोरखपुर से बहराइच और नेपालगंज के बीच और गोरखपुर से बहराइच होते हुए मैलानी होते हुए मथुरा तक गाड़ी चला दें। इस से राम और कृष्ण की जन्म-भूमियां जुड़ जायेंगी। पिछले वर्षों में जैसे प्रोफेसर मधु दंडवते ने गीतांजली चला कर उसकी प्रशंसा की यह उन्होंने उसकी प्रशंसा नहीं की बल्कि अपनी प्रशंसा की कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया कि एक अमर कवि की अमर कृति के नाम से एक रेल गाड़ी का नाम जोड़ दिया और यह गीतांजली कई स्टेटों से गुजरती है। देअरफोर इट इज ए सोर्स आफ नेशनल इन्टेग्रेशन। मैं जिन स्टेशनों के लिए गाड़ी चलाने के लिए कह रहा हूं वह गाड़ी हिन्दुस्तान से नेपाल को कनेक्ट करती है, देअरफार इट ईज ए सोर्स आफ इन्टरनेशनल इन्टेग्रेशन यह कहने का मुझे लालच हो रहा है। कम से कम यह बात हमारी मंत्री जी को स्वीकार करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि नेपाल की और जो इस क्षेत्र की विपुल सम्पदा है वह यहां से दूसरी जगह ले जायी जाती

[श्री रणबीर सिंह]

है । क्षेत्र में मछली इत्यादी हैं जो कि ट्रेन स जाती है । एक बात और है कि ट्रेन के डिब्बों में हम लिखा देखते है कि भारत के दो पर्यटक केन्द्र विश्वविख्यात श्रावस्ती और सय्यद सैलार राजी की मजार वहां है । यह पर्यटकों क लिए डिब्बों में हम पोस्टर लगे देखते हैं। लकिन बड़ी विडम्बना है कि डिब्बों में पोस्टर तो रहते हैं लेकिन रेल लाइन उधर नहीं जाती है। पर्यटकों की बड़ी दुर्गति होती है । इसी दृष्टिकोण से हमारे रेल मंत्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जो नहर निकल रही है, वह बड़ी भारी है। उसके लिए आवश्यक है कि वहां की जो उपज बढ़ेगी उसके लिए आप पहले से व्यवस्था कर लें ताकि वहां का उत्पादन दूसरी जगह भेजा जा सके ।

एक बात प्रोफेसर दंडवते साहब कह रहे थे कि रेलवे के ऊपर सोशल बर्डन होता है । चेअर मेन साहब, आप जानते हैं कि उन्होंने इस सोशल बर्डन को गीतांजली चलाकर और बम्बई के चारों तरफ ट्रेनें चला कर डिस्चार्ज किया था । अपनी कांस्टीच्युएंसी के चारों तरफ काम कर लिया और सोशल बर्डन डिस्चार्ज हो गया। मैं मंत्री जी से सोशल बर्डन डिस्चार्ज करने के लिए कहना चाहता हूं बिहार हम से दूर नहीं है । आप बहराइच की रेलवे को समस्या को सुलझा कर सोशल बर्डन दूर कर सकते हैं ।

एक बात मैं आऊट गोइंग प्रोजेक्ट्स क बारे में कहना चाहता हूं। बहुत बार कहा जाता है कि समस्तीपुर से बारा-बंको के बारे में लेकिन जनता पार्टी का प्रोमिज भी खत्म हो गया और जनता पार्टी भी खत्म हो गयी । आप इसे गति दें और शीघ्रता से इसके कन्वर्शन को पूरा करने के आप प्रयास करें। हमारे त्रिपाठी जी ने एक अच्छा काम किया था जिसको मधु दंडवते जी ने मटियामेट कर दिया वह था ए० टी० मेल के जरवल में रुकने का काम । प्रोफेसर दंडवते उसे बंद कर गये लेकिन त्रिपाठी जी ने आ कर फिर उसे कैंसिल कर दिया । मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि शाने अवध मेल को वे जरवल में रोकें ताकि वहां के लोगों को सुविधा हो सके ।

एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गोरखपुर से गोण्डा, बहराइच, मैलानी होते हुए बैगर किसी खर्चे के मथुरा तक एक गाड़ी चला सकते हैं । इसका प्रस्ताव आपके कार्यालय में है । वहां घोषणा भी हुई थी कि आप शीघ्र मथुरा के लिए गाड़ी चलाने वाले हैं । पता नहीं बीच में क्या हो गया । आप इस विषय में ध्यान दें ।

चेअरमेन साहब, हमने आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से नया कुछ नहीं मांगा है । एक नवीकरण का निवेदन किया है । आपका समस्तीपुर-बाराबंकी लाइन वाला तमाम सामान वहां बचेगा और उससे बहुत कम खर्चे में दिल्ली से मैलानी बहराइच होते हुए असम जाया जा सकता है । असम के लिए इससे छोटी दूरी कोई नहीं होगी और बहुत कम खर्चे में यह काम पूरा हो सकता है । अगर यह लाइन आप बिछा दें तो बड़ी सुविधा होगी। हम यह तो नहीं कहते कि आप हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक सब कुछ मिला दें लेकिन आपके थोड़े से प्रयास से यह राम और कृष्ण की जन्मभूमियां मिल जायेंगी और इसको कर के आप एक महान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं । इससे हिन्दुस्तान और नेपाल भी जुड़ जायेगा और गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। वहां की बेरोजगारी

की समस्या को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा ।

क्षेत्रीय असंतुलन जो हो गया है, उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में रेल डिब्बों में रेक्सीन की जगह टाट लगा हुआ होता है । किराया सबके लिए बराबर है लेकिन उस क्षेत्र में यह असतुलन है कि रेक्सीन की जगह टाट लगा हुआ है । उसमें भी खटमल और कीटाणुओं का प्रजनन केन्द्र बन गया है जिसके कारण यात्री अपना स्वयं स्तत प्रहरी बन कर अपनी सुरक्षा करता है, वैसे वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती है। अगर ये सब कार्य आप कर दें तो राम और कृष्ण के नगर को आप मिला देंगे, नेपाल और हिन्दुस्तान को जोड़ देंगे और दिल्ली के वैभव को गरीब पूर्वी भारत तक पहुंचा कर थोड़ा सा उन्हें भी अहसास करा सकेंगे । क्षेत्रीय असंतुलन को इससे आप धक्का देंगे, आज पूर्वी भारत सो रहा है उसे आप जगा देंगे और उसे विकास की ओर अग्रसर करेंगे ।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़े से खर्चे से महान् उपलब्धि हो सकती है, जिसका अवश्य आपको आकर्षण होगा और आप अवश्य ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हू और चेयरमैन साहब आपको धन्यवाद देता हू ।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Comrade Chairman... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: You are most welcome; please proceed.

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): There is nothing wrong in it .... (*Interruptions*).

SHRI A. K. ROY: 'Comrade Chairman' is absolutely parliamentary.... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: When I am on my legs, you are expected to take your seats. Many hon. Members have done that earlier; this is not the first time and if the Chair does not take exception to that, I do not think, the hon. Members should have any objection.

MR. ROY, please continue. (*Interruptions*).

SHRI K. A. RAJAN: Even Shri Jawaharlal Nehru has addressed like this; please go through the earlier proceedings... (*interruptions*).

SHRI JAMILUR RAHMAN (Kishanganj): You are setting wrong precedents. We will also address like Mr. Congress Speaker, or Mr. Congress Chairman.

SHRI A. K. ROY: Please do not be upset with the words.

Comrade Chairman, Shri Kedar Pandey, our good old colleague in the Bihar Assembly days, has the reputation of being a good man and a bad minister. That is why after his becoming a minister, the Minister of Railways, he has created both expectations and anxiety. The present Railway Minister had the distinction of claiming credit not only over the past Janta Ministry's performance, but also over his predecessors, the past Congress Ministers' performance. I would not like to compare the performance of the Congress Ministry's first year with the performance of the Janta Ministry's first year because Janta Party M.Ps. are capable of doing that.

In the last decade, only during four years the Railways produced a surplus and out of that, two years were in the non-Congress Ministry, that is the performance of the 1977-78 and 1978-79 with highest surplus and productivity, and that is still something which is to be surpassed. The performance of the Janta Government and the Congress Government is very evident. I do not like Janta Party

[Shri A. K. Roy]

also, but I liked their performance in Railways, at least as compared to the Congress Party. I would, however, like to compare the last three months performance with the previous nine months performance. That is more important. Some time back, the Consultative Committee meeting was held in Bangalore where the previous Railway Minister briefed the newsman about the achievements in the last eight months of the railways. and now, when the raiway budget was presented, we got the performance of the last three months. What was stated in the last Consultative Committee meeting? Four lakh tonnes more foodgrains, one million tonnes more coal moved compared to the last year; 161 pairs of cancelled trains restored, 51 new non-suburban trains including 16 mail express trains introduced, and runs of another 18 trains extended. In the last week of October, the total daily originating loading on the broad gauge was 24,000 wagons, and on metre gauge 5200 wagons. By calculation, it comes to this: goods moving per day would be 6 lakh tonnes. It means that the total performance should have been more than 220 million tonnes. But the Minister has placed before us the figure of 195 million tonnes. So, either the previous distinguished, and now extinguished, Minister has said something wrong or this Minister is telling something wrong. The only conclusion we could draw is that the performance during the last 3 months is extremely dismal even compared to his predecessor's.

There is another point to be clarified, viz. how the 6 months' performance speaks one thing; and one year's performance speaks another. There is a lecture by Mr. R. K. Hazari. He was the Deputy Governor of the Reserve Bank of India. He has said:

> "I started by emphasizing the Railways because we have reached a scandalous position of not even replacing the depreciated assets of the Railways."

This is the cause for late running, accidents and mishaps, for which poor railwaymen, workers and locomen are being victimized. The Minister has also said that they would invest this time more on repairs and replacements perhaps Rs. 450 crores out of Rs. 980 crores they have allotted for it. He should also enquire what happened to the earlier allotment, be cause Railways neither invest in repairs and replacements, nor do they add to their capacity. The rate at which Railways add to their capacity during this phase has gradually decreased. In 1965-66, 450 route Kms. were added. Now it has been reduced to less than 200 route Kms. So is the case with electrification. That rate has also been reduced—170 Kms. of line are now being electrified. In this manner, we will take 400 years to electrify the entire Indian Railways.

I would like to put certain specific questions. The Minister has talked of industrial relations in Railways. He has also claimed that in the Railways, they obey the Industrial Disputes Act. Government of India has reported to the International Labour Organization thus:

> "Government of India reports that workers in Indian Railways are covered by Industrial Disputes Act, 1947 which provides for settlement of unresolved disputes through conciliation; and when that is not possible, through arbitration and adjudication."

But in practice, whenever a dispute is raised before the RLG in respect of any case of dismissal of the workers or of victimization, they say: "We have got our own machineries. Disputes are referred to the machinery. So, they must not be referred to the industrial tribunals." This machinery operates for the recognized unions; but what happens to persons who are not members of the recognized unions, when they are the victims? Their cases are not referred to the joint machineries, nor to the industrial tribunals. They are also de-

barred from going to the tribunals under the Industrial Disputes Act. Normally, going to the industrial tribunals, under the Industrial Disputes Act, is a mandatory. That Act is mandatory for all work-men. The Railway Minister should clarify the position.

One more point: recently, we have seen the Kisan Specials. At the end of March and April, thousands of real kisans—they are not land-owning kisans, but landless kisans—migrate from North Bihar and Chhota Nagpur to Punjab. And what happens to them in the trains? (*Interruptions*) There is a paper called *Migrant Labourers in Rural Punjab*—Manjit Singh and K. Gopal Iyer, Department of Sociology, Punjab University, Chandigarh. How the railway men at Ludhiana Station tackle the labourers who are coming from North Bihar to work in Punjab? I am reading from the research paper from Punjab. It says as follows:

"The discussion under this section relates to the harassment meted out to the labourers when they got down from the various trains in Ludhiana and other stations like Khanna, Rajpura, Jullunder etc. However, what follows are base on the observations at Ludhiana railway station towards the end of March 1980 and the first two weeks of April, 1980. It coincides with the wheat harvesting and threshing period which is labour intensive operation. The trains through which is the labourers travel to Ludhiana are mainly Sealdah Express, Howra-Amritsar Mail, Howrah-Amritsar Express, Hardwar Express and Dehradun Express. The trains are full of labourers packed to the capacity inside the compartments, on the roof of the trains, and in-between the two compartments. The number of labourers who travel on the roof all along the distance from Bihar to Punjab are in as large numbers as those inside the compartments.

The "hawks" at Ludhiana Railway station consisting of the ticket collectors and railway police are on wait to plunder the innocent labourers. As soon as the arrival of the trains is announced, they take their positions. There is almost one ticket collector standing near each compartment along with policemen to get hold of the labourers who are supposed to travel without ticket. There are several instances when the labourers holding genuine tickets are also held by the ticket collectors and policemen and asked to pay the cost of the travel again. (*Hindi Tribune*), Oct., 17, 1980)."

MR. CHAIRMAN: Hon. members will not impute motive to the Chair; it is not fair.

SHRI A. K. ROY: It further says as follows:

"During each night between end of March to middle of April they get hold of 40 to 50 labourers each night and extract money from them. The unfortunate ones who are thus held are brought to the ticket collectors room which has a sign-board entitle, "May I help you." Such labourers who have money with them get freed after paying the amount demanded. Others are thoroughly searched even to the point of making them naked. Those without money become the object of sale to the employers who are assembled on large numbers at Ludhiana station with their trucks, tractors, buses etc. The labourers are sold to these employers at various rates even upto Rs. 60 per labourer. The labourers are also badly beaten on the railway station by the policemen."

On the basis of this paper, this matter should be enquired into and the hon. Minister should see that this is not repeated this year.

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Singh Yadav.

SHRI M. RAM REDDY (Nizamabad). As long as you are in the Chair, you behave like a judge. The moment you occupy your seat, you are a party men.

MR. CHAIRMAN: I am obliged to Mr. Reddy because he is trying to protect me.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, मैं रेल मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने इन बजट प्रस्तावों के माध्यम से रेलवे मंत्रालय को, रेलों को एक नई गति, नई दिशा दी है और नया कार्यक्रम दिया है जिसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं । आप जानते हैं कि एशिया में सबसे अधिक लम्बी रेल लाइनें भारत में हीं हैं और सारी दुनिया में रेल की दृष्टि से हमारा चौथा स्थान है, यही नहीं रेल मंत्री जी ने जो इन्नोवेशन्स और इमेजिनेशन्स इस बजट में दिये हैं और जो फ्रेट टैरिफ ओरियेन्टेड पोलिसी रखी है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । बहुत दिन से यह मांग रही है कि रेल मंत्रालय जब तक स्वयं में अपने रिसोर्सेज डेवलप नहीं करेगा तब तक वह जनरल बजट पर आश्रित रहेगा और अपने आप में एक आर्थिक क्षमता पैदा नहीं होगी । रेल मंत्री जी जो एक नई पालिसी ले कर चले हैं और फ्रेट टैरिफ को ले कर सामने आये हैं उसमें नये सुझाव दिये हैं, और अब तक जो केवल पैसेंजर टैरिफ की पोलिसी रही है उसको एक नई दिशा और रुख दिया है ।

आप जानते हैं कि जहां तक पैसेंजर ट्रैफिक का सवाल है उसने गत दिनों में 178 प्रतिशत की तरक्की की है, आगमेंटेशन हुआ है । और पिछले तीन साल के अन्दर ही केवल 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मैं कहना चाहूंगा कि देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आपको अगले वर्ष के बजट में इस दृष्टि से जो आपके रिसोर्सेज डेवलप हों तो पुनः सोचना होगा कि वास्तव में फ्रेट टैरिफ पौलिसी ही नहीं बल्कि पैसेंजर टैरिफ़ पोलिसी की तरफ भी फिर दोबारा ध्यान देना होगा । अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि जो रेल में सफर करने वाले हैं, वह केवल यात्री कम्पार्टमेंट में ही नहीं छत पर भी बैठते हैं । इसका कारण यह नहीं है कि वह छत पर बैठने में बहुत खुश हैं, उसमें केवल 1,2 परसेंट ऐसे होंगे जो छत पर बैठना चाहें, लेकिन जो रेल 1950 में केवल 32 करोड़ की दृष्टि से चलती थी वहां आज वह 70 करोड़ की आबादी के मुल्क में चल रही है । आपके द्वारा काफी कैपेसिटी बढ़ाने के बाद भी पेसेन्जर को एकमोडेट करने के लिये आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है ।

आप जानते हैं कि आपने जो कुछ भी मीटर गेज को ब्राडगेज में कन्वर्ट करने के लिये प्रयत्न किया है उसको और ज्यादा बढ़ावा आपको देना होगा। आज सारे मुल्क में केवल 51 प्रतिशत ब्राडगेज है और 42 प्रतिशत मीटर गेज है और सिर्फ 7 परसेंट नैरोगेज है । आपका यह कहना है कि ब्राडगेज में जितना भी माल ढोते हैं या पेसेन्जर्स ट्रैफिक को ले जाते है वह 77 और 80 परसेंट से ऊपर है । आपके प्रपोज़ल्स से मालूम होता है कि ब्राडगेज पर जो आपकी लागत है, उसका रिटर्न मीटर गेज के मुकाबले में ज्यादा हो गया है । आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा ।

आपने जो किताब पेश की है, उसके पेज 24 पर दिया हुआ है कि दूसरे मुल्कों में जो रेलें चलती हैं, वहां पर मीटर गेज की रफ्तार 150 किलोमीटर है, इसलिए उसके ब्राडगेड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं, इस को दोबारा सोचना चाहिये।

लांग रन में, आर्थिक दृष्टि से और उपयोगिता की दृष्टि से ब्राडगेज ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है, इसलिये इस पर आपको सोचना होगा । इस देश में आज रेल केवल आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । आज भी रेल की उपादेयता और उपयोगिता उस क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये उतनी ही अधिक है जितनी 1853 में थी जिस समय रेलों को प्रारम्भ किया गया था । मैं निवेदन करूंगा कि आपको अपनी पालिसी में, चाहे वह कन्वर्जन की पालिसी हो चाहे नई लाइन बिछाने की पालिसी हो, उसमें कुछ प्रायर्टीज तय करनी होंगी और इनको तय करने के लिये जैसे कि आजकल खास तौर से इंडस्ट्रियल ओरिएन्टेड पालिसी हो, एग्रीकल्चरल ओरिएन्टेड पालिसी हो, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको नई रेल कायम करने और मीटरगेज को कन्वर्ट करने के लिये देखना होगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बहुत बड़ी मांग इस सदन में आज से ही नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि दिल्ली से अहमदाबाद की मीटरगेज लाइन को ब्रोडगेज में कन्वर्ट किया जाये । यह केवल वहां के स्थानिय लोगों की मांग नहीं है, यह केवल गुजरात और राजस्थान के लोगों की ही मांग नहीं है बल्कि ऐसी मांग है, जिसको मैं कहूंगा कि नेशनल प्रोजैक्ट के रूप में आपको इसे स्वीकार करना चाहिये।

यह इसलिये कि आपको मालूम है कि एशिया में सबसे बड़ी नहर राजस्थान कैनाल है । उसका 9 करोड़ रुपया इसलिए काम में नहीं आ सका है कि आप वहां पर कोयला, लोहा और दूसरे इन्फास्ट्रक्चर नहीं दे सके हैं । इसका कारण यह है कि आपके पास रेल और रेल वैगन पर्याप्त रूप से नहीं है । इस बारे में आपको सोचना होगा ।

15.59 hrs.

[SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*]

राजस्थान में जो सीमेंट प्लान्ट लगाये हुए हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटि 3 मिलियन टन है । राजस्थान नहर का फर्स्ट फेज कंपलीट हो चुका है और उसकी वजह से राजस्थान में फूड-ग्रेन्स की पैदावार 5 मिलियन टन है । आप इस बात पर गौर कीजिये कि जहां पर केवल 3 मिलियन टन सीमेंट और 5 मिलियन टन फूडग्रेन्स और उसके साथ जितने भी मिनरल्ज हैं, चाहे सौफ्ट स्टोन हो, सिलीका सैंड या जिंक फास्फेट हो या दूसरा रा मैटीरियल हो—लाइम स्टोन, मारबल स्टोन, कोटा स्टोन हो उस सारे माल को ले जाने के लिये राजस्थान के अन्दर पर्याप्त साधन नहीं हैं । जितना माल राजस्थान में निकलता है, उतना हिन्दुस्तान के किसी और सूबे में नहीं है । इस सब के ट्रांस्पोर्ट के लिये आपको रेल की व्यवस्था करनी होगी ।

भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान के हिस्से में केवल सवाई माधोपुर तक ब्राडगेज की लाइन जाती है और कहीं दूसरी जगह नहीं है ।

जब पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी की सजा हुई तो उसने अदालत में एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने पाकिस्तान की सब से बड़ी सेवा यह कि है शाह आफ़ ईरान राजस्थान कैनाल को कम्पलीट करने के लिए भारत को पैसा देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और पैसा नहीं देने दिया, क्योंकि राजस्थान कैनाल सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परियोजना है ।

[श्री राम सिंह यादव]

16.00 hrs.

राजस्थान कैनाल की सहायता से हम फूडग्रेन्ज पैदा कर रहे है, दूसरे साधन पैदा कर रहे है, लेकिन जब तक वहां रेलवे लाइन नहीं होगी, तब तक वहां की पैदावार राष्ट्र के दूसरे हिस्सों में नहीं जा सकेगी । इसलिए राजस्थान में मीटर गेज का एक रेलवे जोन कायम करना चाहिए । जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा है, सारे देश में जो नौ रेलवे जोन्ज हैं, मंत्री महोदय को साइंटिफ़िक और जियोग्राफ़िकल दृष्टि से और इंडस्ट्रियल तथा एग्रीकल्चरल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए । यदि इस प्रकार जोनल सिस्टम का पुनर्गठन किया जायेगा तो रेलवे में एफ़िशेंसी और वर्कमैनशिप बढ़ेगी और रेगुलेरिटी तथा पंकचुएलिटी से काम होगा । जोनल सिस्टम को रिवाइज करने के बारे में बजट प्रस्तावों तथा सम्बद्ध लिट्रेचर में जो कुछ कहा गया है, उससे जाहिर होता कि मंत्री महोदय के पास इस महकमे को आगे बढ़ाने के लिए एक साइंटिफ़िक एपरोच और पोलीटिकल बिल है, और इसके लिए में उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

मंत्री महोदय ने जिन लाइनों का सरवे करने या जिन नई लाइनों के बिछाने की बात कही है, दिल्ली अहमदाबाद लाइन को उनमें शामिल नहीं किया गया है । मंत्री महोदय इसपर पुनर्विचार करें और इसको ब्राडगेज में कनवर्ट करें । इसका सरवे पूरा हो चुका है और प्लानिंग कमीशन के पास रिपोर्ट गई हुई है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रगति की नीति के अन्तर्गत इस लाइन को बनाने की घोषणा करेंगे और इसी बजट में इसके लिए रुपये की व्यास्था करेंगे ।

मीटरगेज की सब से अधिक किलोमीटर रेलवे लाइन राजस्थान में है, लेकिन वहां पर मीटरगेज का कोई जोन नहीं है । अजमेर और जयपुर सैंट्रली लोकेटिड प्लेसिज है, जो अहमदाबाद और दिल्ली दोनों से नजदीक हैं । इस लिए अजमेर या जयपुर में रेलवे जोन कायम किया जाये । इससे वहां को एफ़िशेंसी बढ़ेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

DR. B. N. SINGH(Hazaribagh): Sir, I have gone through the budget proposals of the Railway Minister very carefully. At the outset, I would like to inform him that the budget has not been very well received either by the travelling people or by the industrialists because of the rise in fares and freight charges or by the consumers who will be receiving the manufactured goods at higher prices or by even the politicians who are disappointed to read that only 171 KM of new routes are going to be opened during 1981-82. So much with regard to the reception of the budget. However, Sir, I would like to tell the Minister that he had certainly brought in certain innovations in the railway administration. He has infused new blood in his Ministry. With in three months he has shown certain results by improving the goods traffic trying to arrest the declining trend in the receipts from goods traffic.

Railway, as has been said by the Railway Minister, is the biggest single unit Government employer employing nearly 1.7 million workmen. This is a very gigantic organisation. According to the Chairman of the Railway Board about 60 to 65 per cent of the earnings of the Railway are being spent on salaries and emoluments and the welfare of the workmen. It must be admitted that the Railway Minister has not had the time to look into this gigantic affair of trying to introduce much needed administrative reforms and look to the man management of his department. He has also not been able to have the op-

portunity and the time to look into the distribution of duties and to see whether his department is ever-staffed and how best it can be pruned. He has nevertheless given some thought to it as appears from the budget proposals. He is going to appoint trained personnel managers to look into the affairs of the management on the personnel side with the workmen. He is also thinking of appointing an expert committee which will go into the general question of re-organisation of the Railway administration—strengthening and streamlining it. It must be clearly understood that unless the Minister is able to bring in certain reduction in the staff and try to prune it, because much of it is acting as dead weight, I doubt very much if he will be able to bring in the required economy and efficiency in the running of the Railway Ministry. I quite understand that a Government organisation cannot take ruthless steps to show profitability. But all the same it must be understood that unless the matter is looked into properly, wastages are controlled, pilferages are stopped and there is judicious intermingling of manpower with machine power. I do not think he will be in a position to bring in reform in the Railway administration. I know that prices of all inputs are going up. Wage bills are going up. Pension liability is increasing. All these effect the Railway. And despite the improvement in receipts from freight traffic and also the improvement expected from passenger fares, there is a yawning budgetary gap of Rs. 344.84 crores. The gap, in my opinion, should have been left for the time being, temporarily uncovered and in the meantime, the Minister should have gone and appointed the expert committee as he has mentioned in his Budget speech, giving them a time bound programme, specifically to examine one issue and that is to bring in reform in the administration, prune it wherever necessity arises, stop wasteful expenditure, stop pilferages and then, in my opinion, quite a substantial amount of the deficit if not whole, would have been covered. Instead of doing this, I am afraid the Railway Minister has succumbed to the bureaucratic tactics of rushing to adopt cut-short methods of cripling levies by increasing the passenger fares, by increasing the freight rate on traffic, thus netting for the railways a huge amount of Rs. 365.26 crores, which will give him a revenue surplus of Rs. 11.42 crores. These levies, coming soon after the hike in fare and freight rates, will have a very disastrous effect on the economy of the nation and it will have all-round cost-push effect, and I am afraid that the doctrine of diminishing returns will start acting. I am confident that by improving the man-power management he could have achieved the same results which he is trying to do through fresh levies. Though the hon. Minister is talking to Shri Chandrasekhar, I would like to invite his attention to this.

MR. CHAIRMAN: Probably they are discussing the issue which you are raising.

DR. B. N. SINGH: May be his mind is somewhere else, but I would like to have at least one of his ears.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDAY): I am quite attentive.

DR. B. N. SINGH: Whatever may be the justification of the Railway Minister, I would appeal to his generosity to look once again to charging a flat ten per cent increase in the second class fares. The second class is the lowest class in rail travel and it is only when there are some compelling reasons that people who can ill afford a journey travel in the second class. So, while replying to the debate, I would like him to spell out the Government's policy specifically on this issue. I do not mind his increasing the fares of air-conditioned or first class or air-conditioned sleeper. He may please himself by raising them. But, so far as second class fare is concerned, this increase should not be there. After all, only when there are compelling circumstances, people travel by second-class; not otherwise. He has given relief only for travel upto 100 km. This restriction on kilometers travelled should be removed.

[Dr. B. N. Singh]

Coming to freight, he has given exemption only to three items, namely, charcoal, fuel, wood and salt for domestic purpose. I would suggest that some more items should be included in this list like cereals, food articles which are carried by train.

MR. CHAIRMAN: You have congratulated him for his generosity.

DR. B. N. SINGH: While congratulating him for his generosity, I am requesting him to extend it further to items like meat, fish, vegetables, fruit etc. In fact, all perishable articles should be extempted.

MR. CHAIRMAN: He should conclude now.

DR. B. N. SINGH: I am yet to come to my main points. Sir, you realise that we come from a very backward region of Bihar.

MR. CHAIRMAN: So, I would suggest that you come to the main point straight.

DR. B. N. SINGH: Very good. But what I have mentioned is also very important.

I would request the Minister to extend the exemption to these items. Otherwise, it will adversely affect the economy of the country.

Then, Sir, I come to the question of the meagre mileage which he is adding to the national railways in 1981-82. It is only 171 km. If this is the speed at which the railways are going to break new ground, I do not know how many centuries they will need in trying to cover by railways the entire length and breadth of India, which is a subcontinent.

In the matter of selecting new railway lines backward regions are ignored and only such areas are taken up where there is political pull or where they fear political turmoil. In the process of laying new lines Chotanagpur is neglected. Perhaps the Minister knows that the per capita railway lines in our country is infinitismal. We have been hearing here from pre-Independence days that Hazaribagh will get railway connection. Unending chain of surveys have been going on, but a final route has not yet been selected. When our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, visited Hazaribagh, which is the Divisional Headquarters of North Chotanagpur, during April-May, 1980, she promised that Hazaribagh will soon be connected with railway lines. But unfortunately due to the apathy of the Railway Board nothing is done. Surveys have been going on since pre-Independence days. Only the other day, to a question put in this very House, the Minister replied that survey has been completed and the route selected in that survey is Ranchi-Hazaribagh Town-Koderma-Giridih. And to a Supplementary Question put by me on 11-12-80 he was good enough to answer and I quote his words in this very House.

The hon. Minister said:

"माननीय सदस्य ने यह सवाल रखा है कि वह पिछड़ा हुआ इलाका है। यह बात सही है कि वह ट्राइबल एरिया है और उस पर विशेष ध्यान है, सर्वे कम्पलेट हो चुका है और छठी पंचवर्षीय योजना में इनक्लूड होने जा रहा है"।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर): इन्कार कब किया है।

डा० बी० एन० सिंह: इन्कार किया है, वही मैं बताने जा रहा हूं।

It came as a great shock, a bolt from the blue, when I read his Budget proposal at page 85 that another route is being proposed to be surveyed. The route surveyed was this Hazaribagh-Koderma-Giridih-Ranchi and the route which is now proposed to be surveyed is Hazaribagh-Hazaribagh Road Giridih which was surveyed and rejected in 1975. So, we made a representation to the Minister on the 26th of February and he was good enough to see the hollowness, time consuming and money wasting proposal of

the Railway Board. The Railway Board has exposed him here. Innocently he read what had been given to him by the Railway Board.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDAY): I shall get this corrected. (*Interruptions*). And we told the hon. Member that this Hazaribagh Road will be excluded.

(*Interruptions*).

DR. B. N. SINGH: That is why I said he was good enough to see the hallowness. That is what I was saying.

MR. CHAIRMAN: The Minister has revised his opinion substantially.

DR. B. N. SINGH: He said that it would be included in the Sixth Five-Year Plan. A paltry sum has been provided in the Budget, i.e., Rs. 3,50,000 for survey against the estimated cost is Rs. 12 lakhs. Our Chief Minister, Dr. Jagannath Misra, is very keen that the railway line should be given to Chotanagpur and the area should be developed because it abounds in mineral wealth, but paradoxically enough, 70 per cent of the people of Chotanagpur live below the poverty line.

MR. CHAIRMAN: I think the paradoxical thing is that the two are not seeing eye to eye.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH (Banka): They are in perfect agreement.

DR. B. N. SINGH: I have convinced my Minister to see to it. At the same time, I request the hon. Minister....

(*Interruptions*).

I am saying.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): After all this is Bihar affair.... (*Interruptions*).

DR. B. N. SINGH: The triangle is complete. What I was saying is if the hon. Railway Minister approaches the Bihar Government, the Chief Minister is keen to develop this area. He will make a sizeable contribution and the final engineering survey can be completed within one year and as promised by the Minister on the floor of this House, the project of laying the Railway line be completed within 1981—85.

With these words and the suggestions given earlier I support the Budget.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति जी, लगभग एक वर्ष के भीतर किराये और माल भाड़े की दर में तीस फीसदी की वृद्धि की गयी है यह वृद्धि असाधारण है और मंत्री महोदय ने इसका औचित्य यह कर कर ठहराया है कि ईंधन का खर्चा बढ़ा है, कर्मचारियों को अधिक

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

भुगतान करना पड़ेगा । इससे इंकार नहीं कर सकते कि इंधन का खर्चा बढ़ा है लेकिन उसी मात्रा में रेलवे की अक्षमता और इनएफीशियेंसी में भी वृद्धि हुई है ।

एक बात जो मैं विशष रूप से उठाना चाहता हूं कि रेलवे में कोयले की खपत क्यों बढ़ रही है, कोयले का खर्चा क्यों बढ़ रहा है ? सारे प्रयत्न डीजेलाइजेशन और उससे आगे जा कर इलेक्ट्रीफिकेशन करने की ओर है । अगर हम आंकडे देखें तो यह पायेंगे कि कोयले का खर्चा पहले से बढ़ रहा है । यह कैसा रहस्य है ? इसका उद्घाटन आवश्यक है ।

सभापति महोदय, पर थाउजेण्ड ग्रोस किलोमीटर पैसेजर्स और गुड्स सार्विसिज के हिसाब से अगर आप कोयले का कंजम्प्शन देखें तो जो 1970-71 में पर थाउजेण्ड 59.0 परसेंट था वह 78-79 में 70.25 परसेंट हो गया । यह 22, 28 परसेंट इंक्रीम परसेंट सर्विसिज की है । यह कैसे हो सकता है । अब आप मालगाड़ियों के बारे में देखें । 1970-71 में 60.3 परसेंट थी और 1979-80 में 81 परसेंट हो गयी । इस तरह से 34.3 परसेंट कोयले का खर्चा बढ़ा है । मुझे तो कोयले में बड़ा गोलमाल दिखायी देता है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोयले की दलाली में कोई हाथ काला कर रहा है । इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मंत्री महोदय को आंकड़े दे कर यह सिद्ध करना पड़ेगा जब डिजेलाइजेशन की कोशिश हो रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम जा रहे है तो फिर कोयले का खर्च बढ़ने का औचित्य क्या है ?

इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हुई । 81-82 में हम 1418 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण करना चाहते हैं। पांच साल में आपको 45 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जरूरत होगी। हमारी क्षमता 300 या 350 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की है । इससे ज्यादा तैयार करने की नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी के लोकोमोटिव कहां से आने हैं या इनके निर्माण करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे है ? हो रही उलटी बात है । आप डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दे रहे है । इस में भी फिजूलखर्ची को टाला जा सकता है । अभी पटियाला में 30 करोड़ रुपये की लागत से डीजल कम्पोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है । मंत्री महोदय, इस बात की जांच करें कि वाराणसी में डी० एल० डब्ल्यु० कारखाने जिसमें कि अभी तक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है, क्या उसका लाभ उठा कर डीजल लोकोमोटिव्ज का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता ? क्या उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है ? फिर पटियाला के कारखाने को क्यों बनाया जा रहा है ?

सभापति महोदय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले सचिवों की बैठक हुई ।

उसमें यह तय किया गया था कि हमें जो उर्जा की नीति बनानी है उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रो लोकोमोटिव्स को हमें प्राथमिकता देनी है, विद्युतीकरण का हमें विस्तार करना है । लेकिन ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय ने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है । कहीं इसका कारण यह तो नहीं है कि रेलवे बोर्ड के सदस्य है वे मकेंनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के है । बिजली का सारा कार्य मकेनिकल इंजीनियरिंग के अन्तर्गत आता है । अब बिजली के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के है ।

विस्तार की बात होती है, चाहे वह इंजन बनाने की बात हो या विद्युतीकरण की बात हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेल मंत्रालय में जो परस्पर प्रतियोगिता चलती है, प्रतिस्पर्धा चलती है, विद्युतीकरण का सारा प्रोग्राम उसका शिकार बन जाता हो । यह सिफारिश की गई थी कि इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग का भी एक प्रतिनिधि रेलवे बोर्ड में होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उस सिफारिश का क्या हुआ लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के कारण डिपार्टमेंटल राइवलरी है और जो अलग-अलग विभागों को बांटकर देखते है, उसकी समग्रता को नहीं देखते वे रेलवे प्रशासन की सेवा नहीं कर सकते और न ही देश का कल्याण कर सकते हैं । इस प्रतिस्पर्धा को हमें समाप्त करना होगा मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, नई टेक्नालाजी हम लाना चाहते हैं । हमारा रेल मंत्रालय किस तरह से नई टेक्नालाजी ला रहा है इसका एक उदाहरण मेरे सामने लाया गया है । अमेरिका के कोलाबोरेशन से बंगलौर में कास्ट-स्टील-व्हील्स बनाने का प्लांट बना लिया, व्हील बनाने का फैसला कर लिया, मगर यह कास्ट-व्हील कहां काम में आएगा, इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है । क्या वह लोकोमोटिव्स.....।

सभापति महोदय : वह कौन सी चीज है जिसका पता नहीं चला ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सभापति महोदय, हम दो तरह से पहिए बनाते हैं । यह नई टेक्नालाजी में कास्ट व्हील तैयार किया जाएगा, लेकिन यह व्हील कहां काम में आएगा, यह अभी तक पता नहीं है । इस प्लांट पर 34 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया था । अब 132 करोड़ हो गए हैं और जब तक प्रोजेक्ट पूरा होगा तब तक खर्चा 200 करोड़ तक पहुंच जाएगा । लेकिन यह पहिया कहां लगेगा ? क्या इंजन में लगेगा ? इंजन में तो लगेगा नहीं । सवारी डिब्बों में भी नहीं लगेगा । मंत्री महोदय ने बाक्स वैगंस का उल्लेख किया है, उसमें भी नहीं लगेगा । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह कास्ट व्हील कहां काम में आएगा ? मुझे इसका उत्तर चाहिए ।

सभापति महोदय, गेज परिवर्तन की बड़ी चर्चा हो रही है । हमने तो यहां मंत्री परिवर्तन देखा है । पांच साल के लिए रेल मंत्रालय की गाड़ी पंडित कमलापति त्रिपाठी के गार्ड के रूप में चलेगी, हम तो यही समझते थे, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई । त्रिपाठी जी चले गए, पाण्डे जी आ गए । मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, मगर साल भर के भीतर यह मंत्रियों का परिवर्तन समझ में न आने वाली बात है । या तो त्रिपाठी जी को नियुक्ति गलत थी या उनको हटाना गलत था, दोनों बातें सही नहीं हो सकतीं । मगर मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, यह सत्तारूढ़ दल का घरेलू मामला है ।

एक **माननीय सदस्य** : आप चर्चा कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करना चाहते ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सभापति महोदय, थोड़ा-बहुत इशारा तो करना ही पड़ता है । मैं जो बात कह रहा हूं वह दूसरी है । मंत्री महोदय ने एक बड़ा ही साहसपूर्ण ऐलान किया है, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं कि मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए । देश के अनेक भाग ऐसे हैं जहां रेल लाइन नहीं है, वहां रेलवे लाइन ले जाना प्राथमिकता का काम है । हमें सड़क यातायात को बढ़ावा देना है । हमारे साधन सीमित हैं । मैं तो

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

समझता हूं कि यह नीति संबंधी फैसला हमने पहले क्यों नहीं किया? यह ठीक है कि यह फैसला लोक प्रिय होने वाला नहीं है। जिन क्षेत्रों में ब्राड गेज नहीं हैं और जो सदस्य या मंत्री वहां से आते हैं वे इसकी वहां के लिए मांग करेंगे—

सभापति महोदय : इसकी आलोचना हो चुकी है और आगे भी होगी। हिन्दू जैसे पत्र ने अपने सम्पादकीय में इसकी आलोचना की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो बड़े पंडित हैं और विद्वान भी हैं।

सभापति महोदय : पंडित नहीं हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, एक श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। श्रेय और प्रेय में लगातार संघर्ष चलता रहता है। मंत्री महोदय का कदम श्रेयपूर्ण है लेकिन वह प्रिय नहीं होगा। मैं अप्रिय बात कह रहा हूं। जब फैसला कर लिया है कि गेज परिवर्तन नहीं होगा तो फिर ग्यारह सैक्शंज में गेज परिवर्तन के वास्ते सर्वे कराने की क्या जरूरत है? क्या वह परस्पर विरोधी बात नहीं है? क्या राजनीतिक दबाव में ऐसा नहीं किया जा रहा है। मऊ शाहगंज सैक्शन का किस के दबाव में आ कर कराया जा रहा है? किस की चिट्ठी उसके लिए प्राप्त हुई है? क्या योजना आयोग ने स्वीकृति दी है? सत्तारूढ़ दल के एक माननीय मंत्री हैं—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता—वह इस कनवर्शन में रुचि रखते हैं और मंत्री महोदय को मानना पड़ा है। लेकिन रेल मंत्रालय ने, रेलवे बोर्ड ने या किसी दूसरे विभाग ने विचार नहीं किया है, कितना खर्चा पड़ेगा इसका अंदाज पत्रक नहीं बनाया। एक कनवर्शन और है बंगलौर से मैसूर तक का। वह भी राजनीतिक दबाव में हुआ है।

एक माननीय सदस्य : दंडवते जी ने यह किया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्ता धरता यहां बैठे हैं। लेकिन अब तो नीति नई बनी है। नीति में परिवर्तन की घोषणा भी है। लेकिन नीति का निर्धारण एक ओर है और आचरण दूसरी ओर है। इससे रेल मंत्री की विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी और न रेल मंत्रालय की। आप्रेशनल या फाइनेंशियल कारणों से गेज परिवर्तन की बात कही जाए तो मैं समझ सकता हूं लेकिन राजनीतिक दबाव से यह चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिये।

दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक सीकरी कमेटी बनी थी। उस ने सिफारिशें की थीं। उन पर अमल क्यों नहीं किया गया? क्या यह सम्भव नहीं था कि दो तीन जोनल रेलवेज में उन सिफारशों पर अमल करके देखा जाता? समिति ने दुर्घटनाओं की की चर्चा करते हुए एक टिप्पणी की थी। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर दिलाना चाहत हूं।

सभापति महोदय : इसी के साथ समाप्त कर दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खत्म कर दूंगा अगर बच गया तो।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : दुर्घटनाओं के ऊपर दूसरी दुर्घटनायें न करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सीकरी कमेटी ने यह लिखा था :

The Safety Organisation should be manned by Officers from any of the five major Departments namely, Operating, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Signal and Tele-Communication Engineering and Electric Section who are mainly concerned with safety in train operation.

अभी तक तो यह होता है कि सारे सेफ्टी के मामले ट्रैफिक ट्रांस्पोर्टेशन डिपार्टमेंट देखता है। सीकरी कमेटी की सिफारिशों के प्रकाश में क्या इस में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है? इस बारे में जो विभागीय प्रतिस्पर्धा है इसको हावी होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिये। रेलों में जो यात्रा करते हैं वे सुरक्षित पहुंचे—भले ही देर से पहुंचे—इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन हमारी रेलें इतनी क्षमता वाली हो गई हैं कि आप कहीं का टिकट लें, आपको पहुंचा कहीं और दिया जाता है। लेकिन ऐसी जगह न पहुंचायें जहां से वापिस आना असम्भव हो जाए, मुश्किल हो जाए।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : रेलवे बजट का समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मौजूदा रेल मंत्री महोदय राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी भी हैं और प्रगतिशील आदर्शों में आस्था रखने वाले भी। समयाभाव के कारण बहुत कुछ तो मैं नहीं कहना चहता लेकिन इसके पहले की मैं मूल विषय पर आऊं एक निवेदन करना चाहता हूं। डैमोक्रेटिक सोशलिज्म के आदर्श की बहुत चर्चा होती है और हमारी सरकार भी उस में आस्था रखती है। रेलवे पब्लिक सैक्टर की सब से बड़ी इंडस्ट्री है और सब से पुरानी इंडस्ट्री भी। और हमारे मौजूदा मंत्री महोदय समाजवादी भी हैं। तो क्या हम आशा करें कि जो कर्मचारी, जो श्रमिक रात दिन मेहनत कर के रेल के पहिये को, रेल गाड़ी को चलाते हैं उन श्रमिकों, मजदूरों का रेल के संचालन में कोई अधिकार है? या अंग्रेजों द्वारा बरासत में जो अफ़सरशाही रेलवे बोर्ड में बैठ कर नौकरशाही दृष्टिकोण से रेलवे को चलाती है वही चलता रहेगा, और इसी चलने का नाम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नई सभ्यता का रूप दिया जाएगा? मंत्री जी, आप अच्छे ट्रेड यूनियनिस्ट हैं इसलिये मैं आपके समक्ष विचारने के लिये रखता हूं कि रेल के प्रशासन में कोई परिवर्तन करने की आपकी योजना है या नहीं? और अगर है, तो उसमें रेल में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों को उसके प्रशासन में कोई हिस्सेदारी होगी या नहीं, इस पर आप रोशनी डालने की कृपा करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि हम समाजवादी भी हैं और ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है, पचीसों सदस्यों ने यहां कहा कि नेशनल इंटेगरेशन, इमोशनल इन्टेगरेशन का रेलवे बहुत बड़ा साधन है, और मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं एक उदाहरण रखता हूं। मैंने मंत्री जी से भी कहा है कि जब कोसी बैराज बीरपुर के पास नेपाल में बना, हिन्दुस्तान का कुछ हिस्सा इस प्रकार बंट गया कि अगर हम हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तान में जाते हैं तो 50 किलोमीटर नेपाल हो कर हमें गुजरना पड़ता है। हम संसद सदस्य हैं, हम उस क्षेत्र को रिप्रजेन्ट करते हैं, मुझ से पहले भी माननीय सदस्य उस कांस्टीच्यूएंसी को रिप्रजेन्ट कर चुके हैं, जहां हम नेपाल में प्रवेश करते हैं अपनी कांस्टीटयूएंसी में जाने के लिए तो हमारा ध्वज उतार लिया जाता है, हम झंडा फहरा कर नहीं जा सकते। अगर कोई संकट हो जाय और बिहार सरकार अपनी पुलिस या बी०एस० एफ० या सी०आर०पी० को भेजती है तो बीरपुर के पास बाराज के निकट हमारी फौज और पुलिस के जवानों को डिसआर्म कर दिया जाता है और नेपाल की मिलिट्री

[श्री कमल नाथ झा]

के संरक्षण में पूरे नेपाल क्षेत्र को हमारी फ़ौज के जवानों को पार करना पड़ता है । 90,000 करोड़ रु० की योजना बन रही है तो क्या हिन्दुस्तान इतना दरिद्र है, इतना अकिंचन है, ऐसा भिखमंगा है कि भारत से भारत में जाने के लिये वह यातायात का मार्ग नहीं बना सकता ? शायद दुनिया के किसी देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने देश से अपने देश में जाने के लिये 50 किलोमीटर दूसरे देश हो कर जाना पड़े और हमारा राष्ट्रीय ध्वज खोल दिया जाय, हमारी पुलिस और फ़ौज को डिसआर्म कर दिया जाये । एक कौसी के पुल के बिना । लैटरल रोड जो पश्चिम से आती है दरभंगा में रुक जाती है । और जो पूरब से आती है वह फारबिसगंज में समाप्त हो जाती है । उसी तरह नार्थ इस्टर्न रेलवे की लाइन सहरसा से आगे बढ़कर भपटिया ही (थरमिट्टा) में और दरभंगा से आगे बढ़ कर निमली में सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर कोशी पर एक पुल के अभाव में जुट नहीं पाती है । इस 13 कीलो मीटर की दूरी तय करने के लिये 450 कीलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है, रेल से या सड़क से । यह नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है । अगर आज चीन का हमला हो, उत्तर से आक्रमण हो तो एक दिन में पुल नहीं बनेगा, एक दिन में सड़क नहीं बनेगी । यह है यातायात का हाल । यह नेशनल इम्पलायर्टेन्स की बात है । इन्टेग्रेशन की हालत यह है कि हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तान में जाने के लिये कोई सड़क नहीं है, 5, 5 योजनाएं समाप्त हो गई और अब छठी योजना चल रही है । रेलवे से सामान और माल ढोना बड़ी चीज है, इस देश में सामान का मूल्य हो सकता है, माल का मूल्य हो सकता है, खान और खदान का मूल्य हो सकता है, लेकिन क्या इन्सान का मूल्य नहीं हो सकता है ? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल्य नहीं है ? क्या पिछड़े क्षेत्र के विकास का मूल्य नहीं है ? यदि भूगोल के विद्यार्थी को पूछें कि दुनिया की घनी आबादी वाला हिस्सा कौनसा है तो जवाब मिलेगा कि चम्पारन से लेकर सीतामढ़ी तक, दरभंगा और मधुबनी का हिस्सा है जहां कि 15 सौ आदमी एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं । सारण भी उत्तर बिहार में है । वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डैंसली पापुलेटेड और सबसे ज्यादा पिछड़ा एरिया है ।

यहां उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है, विकास की कोई चीज नहीं है । लेकिन उस एरिये की हालत यह है कि वहां 25 करोड़ का पुल पिछले 30 साल की आबादी के बाद भी नहीं बन सका है । मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट से, रक्षा विभाग से मिलकर एक ऐसी योजना बनायें जिससे हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तान में जाने के लिये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो, हमारी फौज की बन्दूकें और संगीनें रखवा न ली जायें और नेपाल की आर्मी के प्रोटेक्शन में हमारी फोर्स न जाये । हिन्दुस्तान का सबसे घनी आबादी वाला यह एरिया आगे अंडर-डैवलप न रहे । रेल तथा सड़क से हिन्दुस्तान के दो हिस्सों को जोड़ने के लिये निमली सरायगढ़ में कोशी पर पुल बनवाया जाये ।

एक लिंक ललित बाबू ने हमारे आदरणीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से छितौनी से बगाह के लिंक को जो गंडक ने तोड़ा था, आज जोड़ दिया और कोसी के लिंक को जो टूटा था, उस को जोड़ कर सम्पूर्ण उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधा जाये । तो फिर जम्मू से ले कर गोहाटी तक नेपाल की सीमा से सट कर सड़क और रेल मार्ग हो जायेगा । और विकास, सुरक्षा एवं नेशनल इनटिग्रेशन की योजना पूरी होगी । इससे उत्तर बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष हिन्दुस्तान का सब से पिछड़ा क्षेत्र है, वह एक जूट होगा और आगे बढ़ेगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप निमली में तुरन्त कोसी पर पुल बनाने

की घोषणा करें। अभी मुझ से पहले श्री अटल विहारी वाजपेयी जी ने कनवरशन तथा नानकनवरशन की नीति को एक सैद्धान्तिक जामा पहनाने का प्रयास किया। यह कोई इंटरनल सिद्धान्त नहीं है। नीति शास्वत नहीं होती है। वह रिलैटिविटी से गाइडेड होती है, सापेक्षता से गाइड होती है। आज जो नीति सही है वह कल पुरानी हो सकती है और बदल दी जाती है। इसलिए अगर रेल मंत्री जी ने कनवरशन के प्रश्न पर बहुमुखी नीति का अनुसरण किया है तो उस में विरोधाभास नहीं है। इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने सदन में जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं। विरोध पक्ष की ओर से रेल बजट के बारे में बहुत सारी बातें कही और सुनी गई हैं। यह बात ठीक है कि दूसरे में खोट निकालना बहुत आसान है, लेकिन खुद को उस के अनुरूप ढालना बहुत कठिन होता है। यदि विरोधी पक्ष के लोग आइने को सामने रख कर जनता पार्टी की सरकार और उसकी छवि को देखेंगे तो उस में अनुशासनहीनता, तोड़फोड़ और अराजकता तथा अव्यवस्था के अलावा कोई दूसरी छवि नजर नहीं आयेगी।

कुछ देर पहले श्री अटल विहारीजी ने अपनी बातें कहीं, लेकिन वह हम लोगों की बातें सुनने के लिये नहीं बैठे, क्योंकि वह सुनना नहीं चाहते, इसी तरह की श्री ए० के० राय ने बड़ी-बड़ी बातें कहीं और वह भी चले गये।

आप सभी जानते हैं कि 1974 में रेल कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल हुई और उन के कार्यकलाप जन-हित और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। उसके बाद भी हमारी सरकार ने, जिन्होंने थोड़ी बहुत गलती की थी, उनको तो नौकरी में वापिस बुला लिया लेकिन वह सारे ऐसे लोग जो राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे थे, जो कि जनहित में नहीं था, जो असामाजिक तत्व थे, जिन पर हिंसा, अपराध तोड़-फोड़ और अनुशासन-हीनता को फैलाने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों को पुनः नौकरी पर रख लिया गया। उसका मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव प्रशासन पर पड़ा। उन लोगों को उन बड़े पदाधिकारियों, उस सुपरवाइजरी स्टाफ, के अधीन काम दिया गया, जिसने उन के विरुद्ध शिकायत की थी। जिन लोगों ने राष्ट्र-विरोधी कार्य किये थे, उन्हें पुनः नौकरी पर रख दिया गया। इसलिए आज की अनुशासनहीनता की परिस्थिति के लिए जनता पार्टी के लोग, नेता और उस का प्रशासन उत्तरदायी है।

उन्होंने दावा किया है कि उनका 1977-78 का रेलवे का बजट सरप्लस था। वे दम भरते है कि वह बजट बचत का बजट था। लेकिन वे भ्रांति और ग़लतफ़हमी के शिकार हैं। भूतपूर्व रेल मंत्री और जनता पार्टी के नेता, श्री मधु दंडवते, इस बात का श्रेय लेना चाहते थे कि 1977-78 का बजट उनकी देन है। लेकिन उसका कारण हमारी सरकार द्वारा दिया गया मौमेंटम था, 1976-77 में हमारे सुदृढ़ प्रशासन का फल उन्हें मिला था। उसके बाद जब 1978-79 में उन्होंने दूसरा बजट प्रस्तुत किया, तो उनकी पोल खुल गई। उनका टारगेट 210 मिलियन टन माल-वहन का था, लेकिन वह 193 मिलियन टन पर आ कर ही अटक गया।

हमारे देश में करीब 110 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन रेल पर सवारी करते हैं। मंत्री महोदय ने यह महसूस किया कि इतने लोगों को कुछ मुट्ठी-भर कर्मचारियों का शिकार नहीं होने देना

[श्रीमती कृष्णा साही]

चाहिए। उन्होंने लोकों रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल का बड़ी मुस्तैदी के साथ और प्रभावकारी ढंग से मुकाबला कर के देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है।

देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अनाज, खाद, सीमेंट, इस्पात और दूसरी आवश्यक चीजें पहुंचाने का काम रेलों के जिम्मे है। जब देश में अराजकता बढ़ती है और अनुशासनहीनता होती है, तो सब से पहले रेलें ही उसकी शिकार होती हैं। रेल मंत्री का ध्यान इस तरफ है और इस बारे में मुस्तैद है।

सभापति महोदय : ऐसी बात आयें जिससे वह कुछ और मुस्तैद हों।

श्रीमती कृष्णा साही : जिस तरह से मुग़ल साम्राज्य में बाबर ने एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ शासन हुमायूं के हवाले किया, लेकिन हुमायूं ने अकबर को जो दिया, वह एक खोखला राज्य था उसी प्रकार जनता पार्टी ने हम लोगों के सुपुर्द जो कुछ किया है, आप देखते है कि उसकी वजह से हम कितनी परेशानी में पड़े हुए हैं।

किराये और माल-भाड़े में जो बढ़ौतरी हुई है, वह उचित नहीं है। हमारे यहां की आम जनता उसकी शिकार हुई है। जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, इस बढ़ौतरी का सीधा प्रभाव उन पर पड़ा है।

सभापति महोदय : यह भी बताइये कि रास्ता क्या था।

श्रीमती कृष्णा साही : उसमें कुछ कमी होनी चाहिए थी। यह ठीक है कि उनकी लाचारी थी क्योंकि रेल-संचालन के साधनों—ईंधन, कोयले आदि—के दामों में बढ़ौतरी हुई इस लिए कुछ न कुछ जरूर करना था। लेकिन मैं इसकी ताईद नहीं करती हूं कि यह बहुत अच्छा हुआ है। इस से आम जनता के ऊपर काफी इस का प्रभाव पड़ा है।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि हमारी ट्रेनों में सब से पहले मंत्री महोदय को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि समय की पाबन्दी होनी चाहिए। समय की पाबन्दी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक व्यक्ति या जो भी लोग जाते हैं एक निर्दिष्ट स्थान पर किसी प्रयोजन से जाते हैं और समय पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाते हैं।... (व्यवधान)... इस की ओर रेल मंत्री महोदय का ध्यान जाना आवश्यक है क्यों कि यह बात सब से आवश्यक है।

ट्रेनों में भोजन रोशनी और पानी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इस की ओर रेल विभाग कुछ उदासीनता बरत रहा है। इस को उन्हें देखना चाहिए क्यों कि गाड़ी चलती है और उस में पानी नहीं मिलता है। इस की ओर ध्यान देना होगा और समय की जो पाबन्दी है उस में कड़ाई बरतनी होगी। वहां पर अकसर ऐसा होता है कि कोलेज और स्कूलों के इतने लड़के चले आते हैं और वह कहते हैं, एक लड़का मेरे सामने हो कह रहा है कि क्या करेंगे, केदार पांडेय के बाप भी हम को नहीं रोक पाएंगे।..

सभापति महोदय : आप कृपया उस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं इसको वापस लेती हूं। मैंने कहा कि लड़के लोग ऐसा बोल रहे थे।

सभापति महोदय : आप को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्रीमती कृष्णा साही : उस को मैं विदड्रा करती हूं । मैंने ऐसे ही उन की बात कही कि वह कहते हैं कि मंत्री महोदय क्या करेंगे ?

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं– बहुत अरसे से बहुत सारी लाइनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है । अकसर कुछ दबाव में आ कर या हम लोग भी कभी कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि इस को कर दिया जाये तो उस का सर्वेक्षण हो जाता है लेकिन सर्वे करने के बाद बहुत दिनोंसे वह पुरानी फाइलों में पड़ा हुआ है । उस में एस्टैब्लिशमेंट कास्ट बढ़ती है और अनावश्यक परेशानी बढ़ती है । इसलिए मैं यह कहूंगी कि जो हमारे साधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो अधूरे काम हैं उन को पहले पूरा किया जाये और नये कामों को अभी न लिया जाये ।

रेल मंत्री महोदय की इस बात का मैं समर्थन करती हूं जो उन्होंने एक निश्चय लिया है और कहा है कि मीटर गेज से ब्राडगेज में कन्वर्शन की जो बात है उस में मीटर गेज में भी तेजी आ सकती है, उस लाइन का भी आधुनिकीकरण हो सकता है, मैं कहना चाहती हूं कि यह अच्छी नीति है और अपने साधन और आमदनी के स्रोत को देखते हुए यह करना चाहिए ।

इस के बाद मैं अब वह बात कहना चाहती हूं जो सब से ज्यादा आवश्यक है । बिहार हमारा बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है । आज रीजनल इम्बैलेंसेज की बात होती है । ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में बेगुसराय, बरौनी और क्यूल स्टेशनों की जो हालत थी आज भी वह उसी हालत में पड़े हुए हैं । . . . (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : बरौनी बदल गया ।

श्रीमती कृष्णा साही : जी नहीं । बरौनी का इंटरनेशनल महत्व है । वहां पर फर्टिलाइजर का कारखाना है, इंडियन आयल की रिफाइनरी है, वहां पर थर्मल पावर स्टेशन है, . . .(**व्यवधान**). . .मेरा बहुत सा समय तो इसी तरह बीच में चला गया है । मैं यह कहना चाहती हूं कि जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के टाइम में इन स्टेशनों का स्थान था, आज भी इन का वही स्थान है । उन का आधुनिकीकरण और एक्सपैन्शन किया जाये ।

एक बात और कहना चाहती हूं कि मन्दार हिल से बासी तक जो रेलवे लाइन है उस के ऊपर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए और कटिहार से जोगबनी की बात भी कही गई है । उस की तरफ भी उन को ध्यान देना चाहिए ।

इन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है, उस का भी मैं समर्थन करती हूं । वह कमेटी यह देखे कि कहां पर जोनल आफिस की जरूरत है, कहां पर रेलवे कमीशन की जरूरत है । मैं समझती हूं कि बहुत दिनों से पटना हैडक्वार्टर पर जोनल आफिस खोलने की चर्चा चली आ रही है । रीजनल इम्बैलेंस को समाप्त करने के लिए इस की बहुत आवश्यकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूं . . . .(**व्यवधान**). . . .

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने छठी योजना में 12 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन 5 हजार 100 करोड़ रुपये ही इन को मिले । तो ठीक है, साधन सीमित हैं, जो आर्थिक स्रोत हमारे हैं वह बहुत ही कम हैं । ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहती हूं, जो पुराने माल के डिब्बे हैं या जो यात्रियों के डिब्बे हैं वह सब पुराने हो गए हैं वह रिजेक्ट हो गये हैं, इस के लिए एक कारखाने का शिलान्यास अभी तिरुपति में उन्होंने किया है, लेकिन उस में तो बहुत टाइम लगेगा, उस के पहले इन को रेनोवेशन होना चाहिए, इस की बहुत आवश्यकता

[श्रीमती कृष्णा साही]

है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देती हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति जी, रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन की कुव्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत से सदस्य बोल चुके हैं, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इस अवसर पर रेलवे मिनिस्टर से कुछ अपील करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा पूर्वांचल प्रदेश देश का सब से पिछड़ा भाग है। इस में रेलवे लाइनों का ठीक से चलाना बहुत आवश्यक है। हमारे यहां से कल ही चिट्ठी आई है—हमारे पूर्वांचल में जितने भी स्टेशन हैं—उन में रिजर्वेशन के लिये किसी भी दिन जाओ, एक महीने आगे तक का रिजर्वेशन हो चुका होता है—ऐसा लोगों को जवाब दे दिया जाता है। वहां पर इतनी कम गाड़ियां चलती हैं कि भीड़ के कारण लोग उन में बैठ ही नहीं सकते। बहुत दफा ऐसा होता है कि स्टेशन पर आ कर जगह न मिलने के कारण लौट जाना पड़ता है। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा पहला अनुरोध यह है कि पूर्वांचल में जो गाड़ियां दिल्ली से आसाम की ओर जाती हैं उन की संख्या को बढ़ाया जाये ताकि लोगों को गाड़ियों में जगह मिल सके। इस के साथ ही हर स्टेशन पर रिजर्वेशन के लिये व्यवस्था की जाये तथा ज्यादा से ज्यादा स्थान दिये जायें।

मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे आंचल में बेलूर घाट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस का हैडक्वार्टर रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। वहां के लोगों ने अभी तक रेल गाड़ियों को नहीं देखा है। मेरा सुझाव है कि मालदा-बेलूर घाट होते हुए दिल्ली तक रेल लाइन से जोड़ा जाये। इस का तीन चार बार सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नही हुआ है।

इसी सम्बन्ध में मेरा यह भी निवेदन है कि "कैनिंग की गोलाबारी" तक तथा "कैनिंग से दागाखाली" तक रेलवे लाइन की व्यवस्था की जाये। इन का भी बहुत दिनों से सर्वे चल रहा है। मैं चाहता हूं कि इन पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मैं अब आप को कोई गाली नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि पहले ही बहुत से लोग आप को गालियां दे चुके हैं, परन्तु यह बात सही है कि रेलवे में कुव्यवस्था बहुत बढ़ चुकी है। आप ने पास होल्डरों को बहुत सुविधाएं दी हैं। जितनी सुविधाएं आज आप की तरफ से गवर्नमेंट एम्प्लाईज, मिनिस्टर्ज, एम० पीज, एम० एल० एज, को दी जा रही हैं, उतनी आम जनता को नहीं मिल रही हैं। आम जनता को सुविधायें देना सब से ज्यादा जरूरी है, पास-होल्डर्स को सुविधायें देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप से अपील करता हूं कि रेलवे में से फर्स्ट क्लास को बिल्कुल समाप्त कर दीजिए, रेलवे में केवल एक ही क्लास रहे। आप समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं इसलिये किसी को भी स्पेशल सुविधा गाड़ियों में नहीं दी जानी चाहिए।

मेरी दूसरी अपील यह है-- आप के रिकार्ड बतलाते हैं कि हमारे देश में 1979 तक 12 मिलियन एजूकेटेड-अनएम्प्लाएड थे। इन लोगों के पास कोई नौकरी या काम धन्धा नहीं है और सही बात यह भी है कि उन के पास पैसा नहीं है। वे नौकरी के लिये यदि कहीं से बुलाये जाते हैं तो पैसे के अभाव में वहां जा नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा निर्णय करें कि जब तक उन को नौकरी न मिले, रेलवे की तरफ से उन को पास दिया जाये।

हमारे हिन्दुस्तान में 70 प्रतिशत आदमी बिलो-पावर्टी लाइन हैं। हमारी स्टेट एक वेलफेयर-स्टेट कहलाती है, इसलिये

एक वेलफेयर स्टेट में जो आदमी बिलो-पावर्टी लाइन है वह रेल का किराया कैसे दे सकता है। इसी लिये मैं ने सुझाव दिया है कि ऐसे लोगों का फ्री पास दिये जायें ताकि वे रेलवे में मुफ्त यात्रा कर सकें।

हमारे यहां डिसएबल्ड पर्सन्ज बहुत बड़ी संख्या में हैं, जिन की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, मेरा सुझाव है कि उन को भी फ्री पास दिये जायें, तभी हम कह सकेंगे कि हमारी सरकार आम जनता की भलाई के लिये चेष्टा करती है, समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करती है। यदि आप ऐसी व्यवस्था कर दें तो आप पहले मंत्री होंगे जिन का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा कि हमारे रेल मंत्री पांडे जी रेलों में समाजवादी व्यवस्था को लाये, उन्होंने बेकारों के लिये, बूढ़ों के लिये, जो 60 वर्षा से ज्यादा उम्र के हो गये थे, बच्चों के लिये, पास का जुगाड़ किया। मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन पोलीटीकल लीडरों को आप ने पास ईशू किए हुए हैं, उन सब को रद्द कर दीजिए और इन लोगों को पास दीजिए जिन का मैंने जिक्र किया है।

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें पहले ही कही जा चुकी हैं।

17 hrs.

श्री प्रताप भानु शर्मा : (विदिशा) : माननीय सभापति जी, मैं रेल बजट 1981-82 का पुरजोर समर्थन करता हूं और आप के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस वर्ष के रेल बजट में रेलवे में व्यापक सुधार एवं विकास को प्राथमिकता दी है तथा देश की आवश्यकता को समझते हुए हर नये निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का संकल्प लिया है।

भारतीय रेल सेवा करीब 125 वर्ष पुरानी देश की एक प्रतिष्ठित एवं सबसे बड़ा संस्थान है, जो कि एशिया में सबसे प्रथम है और राष्ट्र की परिवहन एवं आर्थिक व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी के समान है विशेषकर जब पूरे विश्व में आयल एवं पेट्रोलियम की कमी के कारण ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है तब आधुनिक समय के इस यातायात एवं परिवहन के महत्वपूर्ण साधन को पूर्ण सक्षम बना कर राष्ट्र की प्रगति में पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

इस बजट में देश की प्रमुख लाइनों पर लगभग 1418 किलोमीटर विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है जो कि निश्चित ही स्वागत योग्य है। परन्तु यहां यह ध्यान देने की बात है कि पिछले वर्ष में सिर्फ 437 किलोमीटर का ही विद्युतीकरण हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है एवं प्रति वर्ष कम से कम 1,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण करने की बात कही गई है जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे रेल मंत्री की प्रशासनिक क्षमता और अनुभव से हम इन लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। पिछले 30 वर्षों में पेसेन्जर एवं वैगन ट्रफिक में 300 गुना वृद्धि हुई है जबकि कोच एवं वैगन की वृद्धि तथा उपलब्धि सिर्फ 100 प्रतिशत ही हो पाई है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि देश की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए इस को पूरा किया जाये। रेल विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारी बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिये हम को अगले 20 वर्षों में करीब 30,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अतः योजनाओं को बनाते समय इस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

वैगन ट्रैफिक एवं पेसेन्जर ट्रैफिक रेलवे की आय के प्रमुख स्रोत हैं। लगभग 60 प्रतिशत हमें माल भाड़े से होता है और 30 फीसदी आय पेसेन्जर किराये से होती है। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

हमारी सरकार को भाड़ा वृद्धि पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, वरन् हमको अपने वैगनों की उपलब्धि एवं गति में तेजी करनी चाहिए जिस से हम उपरोक्त साधनों का पूरा पूरा उपयोग कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि इन साधनों को गति देने से और मूवमेंट तेज करने से हम 25 परसेन्ट और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अभी वर्ष 1981–82 के लिए अनुमानित लदान 2150 लाख टन का माना है। यदि वैगन समय पर उपलब्ध हों एवं इन का मूवमेंट तेजी से हो, तो मेरा विश्वास है कि वर्तमान समय में ही हम 2500 लाख टन का लदान आसानी से कर सकते हैं और प्रति वर्ष हम इतना लदान कर सकते हैं।

स्टीम इंजनों को जल्दी से जल्दी फेज आउट कर के बिजली एवं डीजल के इन्जनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, जिस से वर्तमान गति एवं क्षमता दोनों को, हमारी बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सके। अभी जिस कोयले का उपयोग हम स्टीम इंजनों को चलाने में करते हैं, उस का उपयोग नये थर्मल पावर स्टेशनों पर किया जाना चाहिए, जिससे कि हम को बिजली मिल सके। जहां देश में हमें एक ओर बिजली का उत्पादन बढ़ाना है, वहां दूसरी तरफ हमें अपनी रेल व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी करना है। हमारे एक साथी ने सुझाव दिया है कि हमारे रेलवे विभाग के, हमारे रेल मंत्रालय के अपने पावर स्टेशन होने चाहिए। मैं उन के इस सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे रेलवे विभाग के लिए पावर स्टेशन बनाना जल्दी संभव न हो सके तो हमारे रेलवे विभाग को सतत ऊर्जा मंत्रालय के सम्पर्क में रहना चाहिए। जिससे कि हमारे अगले वर्षों की जो आवश्यकता है उस के अनुसार हम उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकें।

जहां तक आर० डी० एस० ओ० एवं आर० आई० टी० ई० का सवाल है दोनों की सेवाएं एवं कार्य हमारे लिए प्रशंसनीय रही है जिनमें भारतीय इंजीनियरों एवं तकनीशियनों ने अपनी कुशलता को नये अनुसंधान करने एवं रेलवे में सुधार एवं आधुनिकीकरण में उपयोग किया है। उन की यह सफलता निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।

अध्यक्ष जी, यदि रेल बजट पर चर्चा करते समय मैं प्रदेश की स्थिति से भी रेल मंत्री जी को अवगत नहीं कराऊं तो मेरी यह बात अधूरी रह जायेगी। मध्य प्रदेश एक विशाल एवं पिछड़ा हुआ प्रदेश है। जहां पर रेल लाइनों का समुचित इन्फ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण खनिज एवं वन-सम्पदा पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। रेलवे के विकास के बारे में जो स्थिति मध्य प्रदेश की सन् 1956 में थी लगभग आज भी वही स्थिति बनी हुई है। जहां देश भर में 60,691 किलोमीटर रेल लाइन है वहां इस प्रदेश में केवल 5,715 किलोमीटर रेल लाइन है जिसका औसत प्रति सौ किलोमीटर सिर्फ 1.3 किलोमीटर ही आता है जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति सौ वर्ग किलोमीटर 1.9 किलोमीटर है।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत का 13.4 प्रतिशत है। वहां पर उच्च कोटि के लौह अयस्क डिपाजिट्स 30 प्रतिशत हैं, बाक्साइट खनिज 44 प्रतिशत हैं और कोयला 36 प्रतिशत है एवं वन-सम्पदा 22 प्रतिशत है। परन्तु रेल लाइनों की सुविधा के अभाव में हम इन विशाल सम्पदाओं का उपयोग राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए नहीं कर पा रहे हैं।

उपरोक्त आंकड़े बताने का मेरा तात्पर्य यह है कि मेरे प्रदेश में रेलवे का समुचित विकास एवं विस्तार सिर्फ प्रदेश

के लोगों की ही आवश्यकता नहीं है वरन् यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है जिस की शीघ्र पूर्ति होनी चाहिए । इतने बड़े रेल बजट में मध्य प्रदेश में कोई नये सर्वे या नई रेल लाइन निर्माण की बात नहीं कही गयी है जो कि दुखद एवं आश्चर्यजनक है । जबकि रेल मंत्री जी ने स्वयं अपने पत्र में कहा है कि गुना-सिरोंज-विदिसा,-रायसेन, नरसिंहपुर की 330 किलोमीटर की लम्बी रेल लाइन की आवश्यकता है । अतः उनसे मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम इस नयी लाइन के सर्वे को तो इस वर्ष के बजट में जोड़ लें । बड़ी कृपा होगी । आशा है शीघ्र इसका सर्वे कराया जायगा ।

इसी प्रकार देश के हर प्रदेश की राजधानी को दिल्ली से जोड़ने की हमारे रेल मंत्री जी ने योजना स्वीकार की थी । उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी भोपाल दिल्ली से जुड़ा हुआ नहीं है जब कि हर प्रदेश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है । अतः भोपाल-दिल्ली के मध्य चलने वाली सांची एक्सप्रेस जो कि 6 मास से प्रतिक्षित है को शीघ्र ही चलाया जाना चाहिए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा का नाम छात्र उपद्रव एवं रेलों पर पथराव के लिए जोड़ा जाता है और ऐसा कई बार हो भी चुका है । परन्तु इस का मूल कारण क्या है ? उसको समझ कर उस को दूर करने का प्रयास रेल विभाग द्वारा नहीं किया गया है । विदिशा स्थित इंजीनियरिंग कालेज एवं अन्य सभी कालेज नगर के बाहर रेल लाइन के उस पार हैं जिस के कारण छात्रों को लगातार रेलवे स्टेशन एवं गेट क्रासिंग पर से आना-जाना पड़ता है । परन्तु आज तक उन स्थानों पर एक फुट ब्रिज एवं एक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया है । अतः मेरा सुझाव है कि इन स्थानों पर एक पुल का निर्माण बहुत ही आवश्यक है । प्रदेश सरकार से आप के पास प्रस्ताव आ चुका है कि वहां पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है । अतः मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें ।

अन्त में मैं सदन में प्रस्तुत रेल बजट 1981–82 का जोरदार समर्थन करता हूं और मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि उनके द्वारा अनुमानित शुद्ध लाभ 49.89 करोड़ रुपए इस वर्ष अवश्य ही रेलवे को प्राप्त होगा । इस के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री रणजीत सिंह (चतरा) : सभापति महोदय, मैं इस रेलवे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बजट से विकास की नई दिशा दिखाई पड़ रही है, इसमें बहुत से प्रोग्रेसिव प्लान दिए गए हैं । जितना 1979–80 के वर्ष में यातायात से भाड़ा मिलना चाहिए था उतना भाड़ा न मिलने की वजह से 6624 करोड़ का घाटा दिखाया गया है । इसी तरह से माल भाड़े में भी घाटा हुआ है । इस घाटे की पूर्ति के लिये मंत्री महोदय द्वारा कुछ प्रभार रखा गया है, जिस का मैं समर्थन करता हूं । अब आमदनी नहीं होगी तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति कैसे होगी । अपोजीशन के लोग इस की शिकायत कर रहे हैं । वे लोग गलत समझ रहे हैं । बिना पैसे के रेलवे मंत्री के पास ऐसा कौन सा रास्ता है, जिस से रेलवे में प्रोग्रेस करवा दें ।

सभापति महोदय, राजस्व संभार पिछले वर्ष में 1996 लाख की तुलना में घटकर 1931 लाख रुपए रह गया और इसी तरह से जनता पार्टी के शासन काल में माल ढुलाई में भी कमी आई थी । यातायात राजस्व में भी कमी आई थी । रेलवे लाइनें भी कम बिछाई गई थीं । अब छठी योजना में वर्ष 1980–81 में रेलवे की उन्नति के लिए 5100 करोड़ रुपया रखा गया है जो कि 1978–79 की तुलना में काफी अधिक है । उस समय 3.47 करोड़ रुपया रखा गया था :

[श्री रणजीत सिंह]

सभापति महोदय, इस सब के बावजूद, प्रशासनिक खर्च के अनुपात में योजनागत व्यय में कमी आई है, यह चिंता का विषय है। वगन की बढ़ोतरी का काम भी पिछड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि अगर प्रशासनिक खर्च इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो प्रोग्रेसिव काम नहीं हो पाएंगे।

सभापति महोदय, योजना के अन्तर्गत 14 हजार किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान है। एक लाख वैगनों का और 5680 यात्री डिब्बों, 1990 विद्युत और 780 डीजल, बिजली के इंजनों का निर्माण किया जाएगा। 2200 किलोमीटर लाइन के विद्युतीकरण का योजना है। इस वर्ष 1880 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई जाएंगी और 934 किलोमीटर लाइनों को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदला जाएगा। 1415 किलोमीटर लाइनों को डबल करने की योजना है। 1981-82 में योजनागत खर्च को बढ़ा कर 9 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इन सब योजनाओं को देखने से पता चलता है कि रेल मंत्री महोदय छठी योजना में भारत में रेल के विकास के लिए बहुत अधिक खर्च करने जा रहे हैं। इन योजनाओं से लोग कम खर्च में यात्रा कर सकेंगे। नई लाइनें बिछाने के लिये और मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने के लिये कई जगह सर्वेक्षण किए जा चुके हैं और काम भी शुरू हो चुका है। 1980-81 में अब तक 126 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई है। गेज बदलने के 13 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। रेल मंत्री का यह दावा अक्षरशः सत्य है, 1980 के पहले सात महीनों में औसत लदान की मात्रा में नवम्बर, 1980 में 161.9 लाख टन, दिसंबर 1980 में 178.2 लाख टन और जनवरी, 1981 में 1980 लाख टन हो गई है। पहले सात महीनों के दैनिक औसत लदान की तुलना में वर्तमान रेल मंत्री जी के आने के बाद नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के महीनों में लदान बढ़ता गया है। इस तरह से रेल मंत्री जी ने रेलों को एक नई दिशा दी है।

इस बार इस बजट में पहले के बजटों की अपेक्षा बहुत अच्छी योजनाएं शामिल की गई हैं। इसलिए मैं इस का समर्थन करता हूं। कर्मचारियों के वास्ते क्वार्टर बनाने के लिए भी इस में काफी धनराशि का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल बनाने के वास्ते भी इस में अच्छी अच्छी योजनाएं रखी गई हैं। इन सबसे कर्मचारी वर्ग को बड़ा लाभ होगा।

मेरा क्षेत्र चतरा है जो बिहार में है। हजारी बाग गया और पालामऊ, इन तीनों जिलों में बिहार में यातायात के कोई साधन नहीं हैं, यहां एक भी रेलवे लाइन नहीं है मैंने इसके बारे में मंत्री जी से बात भी की थी और उन को एक पत्र भी दिया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि शेरघाटी से ले कर चतरा और चतरा से हजारीबाग और चतरा से पलामऊ तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह काम आज तक नहीं हुआ है। सरकार की यह घोषित नीति है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां यातायात के कोई साधन नहीं हैं, वहां यातायात के साधन सुलभ करने की कोशिश की जाएगी। हमारा क्षेत्र पूर्णतया आदिवासी और हरिजनों से भरा हुआ है। वह जंगली इलाका है। वहां कोई यातायात के साधन नहीं हैं। बसें भी नहीं चलती हैं। मजदूर लोग, आदिवासी लोग पैदल आ जा कर ही अपना काम चलाते हैं। उधर रेल मंत्री जी का ध्यान नहीं है। उधर उनका ध्यान जाना चाहिए। चतरा में इमामगंज क्षेत्र से पार करने वाली लाइन जो हजारीबाग जाने वाली थी और जिस का सर्वेक्षण भी हुआ था उसकी प्रगति भी नहीं हुई है और कोई काम वहां शुरू नहीं किया गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उस ओर भी ध्यान दिया जाए। हमारे

वर्तमान रेल मंत्री योग्य हैं, बिहार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, बिहार के कोने कोने को जानते हैं। वहां उन का प्रशासन भी बहुत अच्छा था। वह रेलवे प्रशासन पर भी नजर रखें जिस से चेनपुलिंग न हो, चोरियां न हों, घाटा न हो।

चौधरी सुलतान सिंह (जलेसर): इस रेलवे बजट के सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। यह बजट गरीबों का शोषण करने वाला है और अमीरों को राहत पहुंचाने वाला। आए साल रेलों का किराया भाड़ा बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहूदी चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं उसी तरह से ये भी ले रहे हैं और उन से भी ये आगे बढ़ चुके हैं।

जब तक चोरियां बन्द नहीं होती हैं रेलों का घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता है। जब तक फर्स्ट क्लास और एयर-कंडिशंड क्लास को हटा नहीं दिया जाता है और एक ही क्लास नहीं बना दी जाती है तब तक घाटा ही घाटा रहेगा। इन क्लासिस में पासहोल्डर ही बैठते हैं या एम पीज, एम एल एज और मिनिस्टर आदि बैठते हैं या कुछ हद तक व्यापारी वर्ग बैठता है जो इनकम टक्स से छूट पा जाता है। अगर एक ही क्लास कर दी जाए तो अरबों खरबों का फायदा रेलों को हो सकता है। देखने में आता है कि दो हिस्से गाड़ी फर्स्ट और एयरकंडिशंड की ही होती है। इन में कुल चार यात्री बैठते हैं और चार उनको पंखे मिले होते हैं। सैकिंड क्लास में एक यात्री को एक फुट जगह भी प्राप्त नहीं होती है जब कि फर्स्ट क्लास में एक यात्री को लगभग बारह फुट जगह दी जाती है। इस हिसाब से उनका किराया बारह गुना होना चाहिए जब कि होता है चार गुना ही। फर्स्ट क्लास की गैलेरी खाली पड़ी रहती है जबकि सैकिंड क्लास में यात्रियों को खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। फर्स्ट क्लास में चार यात्रियों का दो पंखे और चार बत्तियां प्राप्त हैं जबकि सैकिंड क्लास के पचास यात्रियों को एक पंखा और एक बत्ती ही प्राप्त होती है जो कभी कभी जलती भी नहीं है या पंखा चलता भी नहीं है। एयर कंडिशंड डिब्बे बिल्कुल खाली जाते हैं या उन में पासहोल्डर जाते हैं। टिकट वाला कोई नहीं जाता है। या व्यापारी वर्ग जाता है जो इन्कम टैक्स में उस किराये पर छूट लेता है। इसलिए क्लास बना दी जाय और चोरी बन्द कर दी जाय इससे रेलवे को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि ए० सी० सी० और फर्स्ट क्लास के गुसलखाने में दो बत्तियां हैं जब कि सेकेण्ड क्लास में यह सुविधा 250 यात्रियों को मिलती है। फस्ट-क्लास और एयर कण्डीशण्ड डिब्बों की हर बड़े स्टेशन पर सफ़ाई होती है लेकिन सेकेण्ड क्लास के डिब्बों में साल में एक आध बार ही सफ़ाई होती होगी। फ़र्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्री अगर जंजीर खींचे तो उस पर कोई जुर्माना नहीं होता, लेकिन सेकेण्ड क्लास में अगर कोई जंजीर खींचे तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। जैसा मैंने पहले कहा यह किराया बढ़ाने का चक्कर चक्रवर्ती ब्याज की तरह से चल रहा है। इसी तरह से फ़र्स्ट क्लास के रिजर्वेशन पर शायद अब कुछ बढ़ाया है सेकेण्ड क्लास के यात्री पर बठने के रिजर्वेशन चार्जेज को 8 आने से बढ़ा कर 1 रु० कर दिया है और हर रात का सोने के चार्जेज 6 रु० 50 पैसे कर दिये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किराया तो बढ़ा रहेहैं लेकिन सेकेण्ड क्लास के यात्रियों के लिए आपने क्या सुविधायें बढ़ायी हैं? सेकण्ड क्लास के डिब्बों में लोग जमीन पर और छत्तों पर बैठ कर चलते हैं। उसको आप कौन सी क्लास मानेंगे। जितनी सुपर और मेल गाड़ियां हैं यह सब बड़े आदमियों के लिए हैं। गरीबों को इनसे

[चौधरी मुलतान सिंह]

कोई फायदा नहीं है । 90 प्रतिशत जनता आज भी पैसेंजर गाड़ी से चलती है । जितनी पसेंजर गाड़ियां 1937, 1947 में चलती थीं उतनी ही आज भी चल रही हैं । दिल्ली से अहमदाबाद और टूंडला से इलाहाबाद एक पैसेंजर गाड़ी चलती थी वही आज भी चल रही है । इसलिए जो मेल और ऐक्सप्रेस ट्रेन्स हैं इनको कम कीजिए और पैसेंजर गाड़ियों की तादाद बढ़ायें । क्योंकि जनता दुखी है, किराया भी देती है फिर भी बैठने को जगह नहीं मिलती ।

एक और झंझट है सुपर ट्रेन आपने चलाई है जिसमें बिना रिजर्वेशन के कोई आदमी बैठ नहीं सकता । मेरी मांग है कि हर सुपर फ़ास्ट और मेल ट्रेन में दो, दो जनरल डिब्बे लगाये जायें । एक और बात है कि नार्दर्न रेलवे में अगर कोई यात्री टिकट ले कर बैठ जाय और रिजर्वेशन न कराये तो 11 रु० पैनल्टी ले कर और उसको धक्का दे कर बीच में ही उतार दिया जाता है । ऐसा शायद और किसी रेलवे में नहीं है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा तो नहीं है ।

चौधरी मूलतान सिंह : ऐसा ही होता है । इसलिए मेरी मांग है कि पसेंजर ट्रेन्स की तादाद बढ़ाई जाय । रेलवे में करीब 300 आदमी मरे दिखाए हैं, 600, 700 घायल दिखाये हैं एक्सीडेंट्स में । उनको सिर्फ 5 लाख रुपया मुआवजा दिया बताते हैं । वह भी माननीय मंत्री जी के बजट में है । मैं पूछना चाहता हूं कि हवाई जहाज में मरने वाले को तो एक लाख रुपया दिया जाता है, फर्स्ट क्लास में मरने वाले को 50 हजार रुपया दिया जाता है और सैकिंड क्लास में जो मरता है उसको 20 रुपये में ही टाल दिया जाता है । इसकी क्या वजह है ? क्या वह इंसान नहीं है, वह अपने मां-बाप का बच्चा नहीं है, क्या उसके मां-बाप को उससे प्यार नहीं है ? क्या उसको गरीब के हिसाब से ही देंगे । मैं सुझाव दूंगा कि जो हवाई जहाज में मरता है या रेलवे के फर्स्ट क्लास या सैकिंड क्लास में मरता है, सब को एकसा मुआवजा दिया जाये ।

हमारे यू० पी० के पहाड़ों में, नाम बताने में समय लगेगा, सन् 1928 में सर्वे हुआ था, कि रेलवे लाइन बिछाई जायेगी, लेकिन आज तक वह सर्वे धरा ही है । पहाड़ी क्षेत्र है, टिहरी, गढ़वाल, नेपाल के बार्डर और चाइना के बार्डर से मिलता है, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं है हालांकि वहां के 2, 3 मुख्य मंत्री रहे हैं ।

मेरा सुझाव है कि टूंडला से एटा होते हुए कासगंज तक एक लाइन बिछाई जाये । आगरा से वाह होते हुए लखनऊ तक लाइन चलाई जाये । वहां पैसेन्जर ट्रेन नहीं है । वाह से भिंड और शिकोहाबाद के लिए रेल चलाई जाये । भिंड डकैतों का क्षेत्र है, इसमें अगर आप रेलवे लाइन बिछा दें तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है ।

टूंडला स्टेशन पर पुल को ढका जाये । साहिबाबाद का पुल तो ढका हुआ है, क्योंकि वहां पर सेठ लोग बैठते हैं, इनकम टैक्स देने वाले, ** लेकिन टूंडला का स्टेशन जो करीब करीब आधा मील लम्बा है, सर्दियों से 5, 6 लाइनें वहां से जाती हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि यह एक औपचारिक डिबेट होती है, किसी की कोई बात सुनी नहीं जाती है । लेकिन आज तक पुल को कवर नहीं किया गया । वेटिंग रूम के बारे में कहा गया,

लेकिन वह नहीं बनाया गया । पसेन्जर्स के लिए पानी पीने की जगह नहीं है, बाहर इन्क्वायरी नहीं है । फाटक एक बड़े आदमी ने मिल कर एतमादुदौला के पास टूंडला के पास बनवाया । हाई कोर्ट में किसी ने रिट कर दिया, अफसर मिल गये और उसे बन्द करा दिया । इधर के मुर्दे उधर रहते हैं और उधर के मुर्दे उधर रहते हैं, वहां जमना घाट है ।

मैंने चार-पांच साल पहले भी सुझाव दिया था, लेकिन यह लगता है कि औपचारिक होता है । हमारे सभापति जी बार बार घण्टी बजा रहे हैं, सारी बातें कहीं नहीं जा सकतीं । मैं माननीय मंत्री जी को अपने सुझाव भेज दूंगा, यहां कहने का तो समय नहीं रह गया है ।

MR. CHAIRMAN: I hope the hon. Member has used some words. We shall see to it.

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसको एक्सपंज कीजिए, ** कहा है ।

MR. CHAIRMAN: We shall see to it. Deputy Minister.

चौधरी मुलतान सिंह : आपको नहीं कहा है । मैंने कहा है कि जहां पुल ढका हुआ है, वहां ** हैं । जहां भले आदमी बैठते हैं, वहां नहीं ढका हुआ है । मैंने इस में क्या कह दिया है ? **

सभापति महोदय : आप बैठिये ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): I shall not take much time of the House.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We shall continue the debate after his speech. He is only invervening.

MR. CHAIRMAN: We shall sit. It is an intervention. Why are you worrying?.. (*Interruptions*)

The hon. Deputy Minister is intervening only. It is not reply. You will get a chance. Why are you worried about it.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): I shall not take much time of the House because I understand and appreciate the feelings of the hon. Members.

Railways is vital infrastructure in building the nation's economy. Since it has a role to play in building the nation, I can appreciate the agony expressed by the hon. Members on various points and also the appreciation made by them. It is true, the punctuality performance is not only agitating the minds of the hon. Members in this august House but also outside the Parliament. But adequate steps are being taken by the railway administration. I desire that the august House should also appreciate that.

The punctuality of trains does not merely depend on the functional integrity of the railways. It has also got some relationship with the people who are not connected with the railways. In the recent past, it has been a bad experience of lawlessness, particularly people indulging in chain pulling, taking away coulings and thereby becoming a great hindrance in the smooth movement of trains. So, even when the train starts from the originating staton in time, it becomes difficult to reach the destination in time. Deliberate attempts are being made by a particular section of society, anti-social elements and irrespon-

**Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Mallikarjun]

sible people, without realising that passengers who travel on trains are travelling with great difficulty to reach their destination to attend to their various works. This august House should also condemn such an irresponsible attitude on the part of particular section of society. It is not merely for the sake of criticism that one should be criticised and take such an attitude. It is everybody's responsibility to appreciate the reality that exists. If we desire the goods to be delivered to the best satisfaction of the people, it becomes necessary that the society should also realise various lacunae that are there.

As I mentioned earlier, the railways is one of the important undertakings in the country. I do appreciate that when a passenger travels by train, he does desire to have comforts and necessary amenities. It is our constant effort to provide the necessary amenities. It is not that because somebody is telling us, we are realising it. From he very inception of the railways, it has been the constant feeling of the railway administration to provide the necessary amenities to the travelling passengers.

Just now, the hon. Member spoke about non-availability of water. It is totally wrong. In summer, we have got special arrangements to provide water to passengers. Apart from summer, throughout the year, there are facilities for providing water. Being a vast organisation, the amenities may not be there to the best satisfaction of passengers.

श्री दौलत राम सारण (चुरू): कई सटेशनों पर पयाऊ नहीं है (व्यावधान)

SHRI MALLIKARJUN: I ignore what the hon. Member says for the simple reason that because he is sitting in the Opposition, he speaks of non-availability of water. Necessary directions have been given to all General Managers and, in turn, they have issued instructions to their Divisional Managers to see that passenger amenities are properly provided for. We do allocate certain amount for providing minimum amenities which a passenger desires to have during his travelling period.

Another essential point is that it is not only passenger traffic which is important but equally important is the goods traffic. At the same time, we also look after the goods traffic.

I will speak about the core sector, about thermal power stations which generate power and about coal later.

As regards the functioning of railways, we can never fail to appreciate the fact that today more than 32,000 wagons are transporting essential commodities and other things which are vitally needed for the society.

But still, industry is suffering for want of steam coal. The Hon. Member Shri Vajpayee has, while appreciating the performance of the Railways also made a point. The point he made is that coal consumption is going up in Railways. (*Interruptions*) Inferior service comes in, when a superior service goes up! Coal consumption in Indian Railways increased. The steam coal that Indian Railways need is about 12.5 million tonnes per annum. Even if the Railways are the carriers and distributors of coal, coal supply to industries is cut and the industries like the Small-scale industry, the paper industry, the textile industry pottery, glasses and so on and so forth are suffering. Therefore, we imposed a voluntary cut on the consumption of steam coal by Indian Railways and we divert that coal to these industries. Every Hon. Member knows this fact. We need steam coal to he tune of 31,100 wagons per day. But, we cannot afford to consume so much coal. We do not have so much coal in stock. In any case, today, we transport more than 2,000 wagons of steam coal. We impose a voluntary cut on our own consumption of coal and consequently some passenger and goods trains are

cancelled. This is because we have to look to the maintenance of other industries also. It is a well-known fact that M.P.s lodge frequent complaints about the non-maintenance of other industries. I need hardly reiterate this fact.

You will be interested to know that as a result of this voluntary imposition of a cut in coal consumption by Indian Railways, 282 pairs of trains were cancelled before 5th of February.

It will be astonishing to this august House to know that by 25th of February, 173 pairs of trains have been restored.

One may bring in issues like Kisan Rally and other issues and go on criticising. That is an entirely different thing.

You must know that in this period itself, 175 pairs of trains have been restored. I say this without any ulterior motive. By 26th of February, 107 trains are cancelled due to the lack of steam coal. This is the position.

We are conscious of our duty towards the society. As regards the coal supply to the thermal power stations, we are loading nearly 4,000 wagons per day. Today if you go to Barauni, you will appreciate that 29 days' coal stock is there. In Patratu 29 days' coal stock is there. In Chandrapura about 28 days' coal stock is there. In Talcher about 35 days' coal stock is there. In Busawal about 13 days' coal stock is there. In my own State, in Ramagundam, about 17 days of coal stock is there. In Vijayawada, 14 days' coal stock is there. (*An hon. Member: What about Bhatinda*)? In Bhatinda, 2 days' stock is there. Sir, if I may say so, Bhatinda and Badarpur are always living from hand to mouth. Badarpur has only one day's stock. This is the coal position of the thermal power stations. Power is an essential input for various industries and coal is rushed in for these thermal stations so that electricity generation is not affected. In the Northern Railway we are loading 1200 wagons per day of sponsored foodgrains to be sent to various parts of the country. Therefore, I would respectfully submit that the performance of the Railways should be viewed in the proper light. Hon. Members have spoken about construction of New Lines and conversion of lines. Now, in all these matters, one should appreciate that we have got limited resources. When you have limited resources, you find it very difficult to go in for a new line or conversion of line except in a phased manner.

Mr. Chairman, in your own State, from Jagpura to Daitari we have got a new line of 33 K.M. It is almost completed. As a consequence of this line, Mr. Chairman, export of Iron ore from Paradip port would be made much more easier. You know how much benefit it will render to the country as a whole.

There is another line from Apta to Pen in the Konkan Railway which is about 20 KM. This line has been completed. This will help in the rapid development of the whole area.

So far as resources are concerned, the Planning Commission has allotted to us only Rs. 5,000 crores during the whole Plan period. There are number of surveys which have to be conducted. Proper examination has to be done in respect of various projects. One finds that the Planning Commission does not always give the clearance. They go into various factors and then they decide. Progress cannot be achieved all of a sudden. Progress has to be achieved in a phased manner in a developing country like ours.

Sir, I don't want to take more time of the House. I re-emphasise the position of the Government in this regard. The apprehensions of some members of the opposition that coal is available in the pit-head only and wagons are not available to remove them or that wagons are there, but coal is not there, are not correct. All these apprehensions are unfounded. Railways are the greatest ingredients

[Shri Mallikarjun]

for national development as a whole. I would like to reiterate that there should not be such apprehensions in their minds. There is proper co-ordination in Government. We have all got collective responsibility. We are all part and parcel of the Government and as a Government we perform our duty to the nation, not in the way that the hon. Members opposite imagine.

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK (Anantnag): Mr. Chairman, we have disinherited the British imperial system politically but we have inherited two notorious institutions, that is, bureaucratic system and the system of having a separate budget for Railways. We have never thought of re-orientating the Railway system on national lines. We are expecting the Railways to serve the needs of the economy, the society and what not. But we do not share its burden. I would suggest that the Railway budget should be made a part of the General Budget. The whole country is inter-linked in one way or the other in which Railways have to play a vital role. It should be treated as a national problem because it concerns the whole country.

Railways have ignored Jammu and Kashmir State. So far as the Jammu and Kashmir State is concerned, the railway line has not been extended beyond Jammu to link the valley of Kashmir. I would request the hon. Minister to consider that, it is a national issue and see that new railway links are introduced in the State. The problem of Railways is compared to that of an heart patient. But we are trying to cure it with some pills which can just remove the ailment of headache. But the disease is there. We have to think of carrying out an operation for this disease. Then only we can expect the Railways to cater to the needs of the people, fare crisis of this country and the demands that we make in this House from Railways. The Government should give top priority to extend the railway line to the valley of Kashmir.

Now, in this budget, I can see that it is just a start towards new direction and discussions. But it has to be followed up in a big way to achieve the real objectives. We expect that the budget should not be a deficit budget, but it had to be done because the Government had to remove the disparities or meet some urgent needs in the matter of railway network and meet urgent demands in some States. In this connection, I would like to refer to one more point, that is, with regard to my State. I would say that my State has not only been ignored but no serious attention has been given in the matter of construction of new Railway lines in my State beyond Jammu to the valley of Kashmir. You have not extended the railway line from Jammu to other strategic points in the Kashmir Valley. The State has highly sensitive areas where the means for swift movement of our security forces should take the highest priority especially in the present context when China, Russia and Pakistan are knocking at our doors. The amount that we are spending only for the transportation of essential goods to cater the military forces or their movement by transport buses and trucks consuming diesel or petrol whose prices have short up could have easily been considered, that would have answered the question of urgency of constructing the line extending it to Kashmir valley. The whole amount that would involve for this purpose could easily be realised within one year not to speak of through other commercial goods that are transported from Jammu and Kashmir to other parts of India. We must have a second line of communication. At present we have only one communication line and that is, road communication. That is very dangerous from the strategic point of view. Tourist traffic now is more than three lacks annually from commercial point of view also and from strategic point of view also., railway link is a must. It must be given a national priority due to overall development of the State. Even during the British time they had made a survey for linking the Valley of Kashmir with the rest of India and that survey was adjudged as

most feasible. It is only a matter of having a few tunnels from Khud to Kazigund that the rail connection to Kashmir is possible. This would also strengthen the emotional and national integration from Kashmir to Kanyakumari. We are always in danger. If not, from the commercial point of view, at least from the strategic point of view, this suggestion must be considered by the Government. Even Juring the British regime, a survey was conducted to have a railway link from Jammu to the Kashmir valley, and that survey is there, but so far implementation has not been effected on that. What does it matter, if we incur a sum of Rs. two crores on this. Annually, about Rs. five hundred crores are spent on military vehicles apart from other things. This area is important from the tourism point of view also. From the commercial point of view also, about 8000 tonnes of fruits are sent annually from Kashmir to other parts of India. That alone would give the railways the total amount that would be invested on this project.

I hope, the hon. Railway Minister, being in the know of everything in Kashmir would give top priority to this demand from the people of Jammu and Kashmir State.

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय चेअरमैन साहब, मुझे खुशी है कि मुझे भी बोलने के लिए समय मिल गया । जो हमारे माननीय मंत्री जी ने इस माननीय सदन में रेलवे बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

जहां तक मुखालिफ पार्टी के लोगों का सवाल है, प्रोग्राम तो उनके पास कुछ है नहीं । पिछले तीस महीनों में उनका यही काम रहा था कि उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब किया, ला एण्ड आर्डर को खराब किया । रेलवे में डाके पड़े और उस ढंग से पड़े जैसे कि पुराने जमाने में लूटपाट होता था । यही काम उनके जमाने में चल रहा था।

आज जो रेलवे की लाइनों में गड़बड़ी पैदा करते हैं ये वही लोग हैं जो पहले भी रेलवे में गड़बड़ पैदा करते थे । मैं आप के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 1975–76 में रेलवे में जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ी पैदा की और मुल्क के अन्दर एकता नहीं रहने दी, उन्हीं लोगों के लीडर आज यहां नुमाइन्दगी करते हैं । ये भी उस वक्त की गड़बड़ी में इन्वाल्व थे । इसलिए आज भी वे गड़बड़ी पैदा करते हैं । जहां ये यह कहते हैं कि इन्होंने अपनी हुकूमत में बहुत काम किया वहां मैं नहीं समझता कि जनता पार्टी के मंत्रि मंडल ने देश के लिए कुछ काम किया हो । इन्होंने केवल एक काम किया कि आपस में लड़ाई पैदा की । न कोई सड़क बनायी न कहीं कोई रेल पहुंचाई ।

सभापति महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं । हमारे यहां ब्रिटिश टाइम्स से रेलवे बनी हुई है । अंग्रेजों के समय में शिमला रेल पहुंची थी । उसके बाद से एक फुट लाइन नहीं बन पायी है ।

जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है उसका एक सर्वे तलवाड़ा से हुआ था और उसका उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री जी ने किया था । वह भी कम्पलीट नहीं हुआ है । इसी तरह से जगाधरी, पौण्टा के लिए रेलवे लाइन का सर्वे करने की बात थी । पिछले मंत्री जी ने पत्र द्वारा मुझे सूचित किया था कि उसका कम्पलीट सर्वे करने का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा । मैं अर्ज करूंगा कि जहां हिमाचल प्रदेश में इण्डस्ट्रीज, उद्योग लगाने का बड़ा भारी स्कोप है, वहां खेती की उपज बढ़ाने का भी बड़ा स्कोप है । हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर सेब पैदा होता है, आलू पैदा होता है । उसके लिए हमें माल गाड़ियां नहीं मिलतीं, आनन्दपुर से नहीं मिलतीं, पौण्टा से नहीं

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

मिलतीं, कालका से नहीं मिलतीं । हमारी सारी प्रोडक्शन जो है वह काम में नहीं आती और हमारे लोग सफर करते हैं। इस से हमारी माली हालत पिछड़ी हुई रह जाती है ।

हमारी भारत सरकार के रेल मंत्री बिहार को बिलोंग करते हैं । वहां पर भी सड़कों की बड़ी भारी कमी है जिसके लिए बहुत काम हुए हैं । अभी कोसी के पुल की बात कही गयी । सभापति महोदय, रेलवे बजट में 5–7 किलोमीटर रेलवे लाइन किसी क्षेत्र में दे देने से किसी क्षेत्र का भला नहीं होता है। इसलिए कम दूरी की रेलवे लाइनों के बजाए लम्बी दूरी की रेलवे लाइनें बिछाने की योजना बनानी चाहिए । हमारा पहाड़ी क्षेत्र तिब्बत से चाइना के बार्डर से लगता है, वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है । शिमला से रामपुर सर्वे ब्रिटिश टाइम में हुआ था, लेकिन उस पर आज तक कार्य शुरू नहीं किया गया है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में भी कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है । मेरा निवेदन है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी, जो कि अब मंत्री नहीं हैं, ने वादा किया था कि कालका से परमाणु तक सर्वे हो चुका है और शीघ्र ही काम शुरू करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और शीघ्र ही काम शुरू करवाएंगे । इसी प्रकार तलवाड़ा से भी एक लाइन का सर्वे कम्पलीट हो चुका है । इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे पहाड़ी क्षेत्र की ओर ध्यान दें ।

हिमाचाल प्रदेश में सेब अधिक मात्रा में होता है, इस पर बड़ी हुई दर माफ होनी चाहिए । इसी प्रकार आलू, टमाटर केला, संतरा जो ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, इन पर भी बड़ी हुई दर में छूट दी जानी चाहिए । ये चीजें अगर ट्रकों से लाई जाती हैं तो दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, कई मौतें होती हैं । अभी रामपुर के पास 34 आदमी मर गए हैं। गाड़ी का सफर सब लोग पसन्द करते हैं। मैदानी इलाके में तो चोरी डकैती का डर रहता है, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाके में चोरी डकैती का कोई डर नहीं है । हमारे अन्य साथियों ने भी सुझाव दिए हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन निर्माण के बारे में ध्यान दिया जाए । हिमाचल प्रदेश में रेलवे का विकास कर प्रदेश की आर्थिक हालत सुदृढ़ की जा सकती है ।

पंजाब में अनाज अधिक पैदा होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां से अनाज के लिए भी बढ़े हुए भाड़े में छूट दी जाए ताकि लोगों को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सके । इसी प्रकार फर्टिलाइजर की ढुलाई पर भी छूट दी जाए ताकि किसानों को इस का लाभ मिल सके और उत्पादन में वृद्धि हो ।

पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जगाधरी से पोण्टा, जोगिन्दर नगर से मण्डी, रोपड़ से नालागढ़ रेलवे लाइन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। इस से पहाड़ी क्षेत्रों को लाभ होगा । पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक इंच भी रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें ।

माननीय वाजपेयी जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार रेलवे के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है । वाजपेयी जी तो विदेश मंत्री थे, बाहर ही घूमते रहे, हिन्दुस्तान में कहां-कहां रेलवे-लाइन बिछाई जानी चाहिए, इस का उन्हें पता नहीं है । श्री

रामावतार शास्त्री जी के भाषण में भी बे-बुनियाद बातें कही गई, उन सब बातों का मैं खण्डन करता हूं और इस रेल बजट का समर्थन करता हूं ।

18 hrs.

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं । मैं अपने सुझाव संक्षेप में रखना चाहता हूं ।

खंडवा दोहद मार्ग के लिए सर्वेक्षण करने की काफी समय से मांग की जा रही है । ये आदिवासी जिले हैं । इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए वनों के विकास के लिए और वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस मार्ग का सर्वेक्षण कराया जाए ।

पूना-जेहलम चलने वाली जेहलम एक्सप्रेस को बरहनपुर में रोका जाना चाहिए । श्री त्रिपाठी जी के समय से यह मांग चली आ रही है । मुझे पूरा विश्वास है कि इसको वहां रोकने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

बम्बई-लखनऊ एक्सप्रेस को हुसूर में रोकने की व्यवस्था की जाए । बम्बई वाराणसी जो गाड़ी चलती है उस का टाइम टेबल इस तरह से नियोजित किया जाए ताकि बरहनपुर से दिल्ली आने वाले यात्रियों को इटारसी में जी टी एक्सप्रेस मिल सके ।

कांचीगुडा एक्सप्रेस जो पानी लेने के लिए तुकाईथड़ रेलवे स्टेशन पर रुकती है वहां टिकट इशू नहीं किए जाते हैं । तुकाईथड़ रेलवे स्टेशन से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों के लिए वहां पर कांचीगुडा एक्सप्रेस के लिए टिकट देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

खंडवा इंदौर जो शटल चलती थी और जिस को बन्द कर दिया गया है उस को फिर से प्रारम्भ किया जाए ।

कोयले की कमी बता कर हमेशा पैसेन्जर गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं । इटारसी–भोसावल को भी बार बार रद्द कर दिया जाता है और अब भी वह बन्द है । उसे फिर से चालू किया जाए ।

एक पैसेन्जर इटारसी से झांसी पहले चलती थी । उसे फिर से चलाया जाए ताकि गरीब लोगों को लाभ हो ।

बरहनपुर नगर में सिटी रिजर्वेशन आफिस की बहुत आवश्यकता है । बरहनपुर प्लेटफार्म को चार ट्रैक का बनाया जाए, उसको चौड़ा किया जाए । यह बहुत जरूरी है । सुपर फास्ट ट्रेनों को इस वजह से काफी देर तक वहां रुकना पड़ता है । निम्बोलाग्राम के पास स्टेट हाईवे पर ओवर ब्रिज बनाना भी बहुत जरूरी है । यह मांग भी बहुत समय से की जा रही है और इस को पूरा किया जाना चाहिये ।

18.02 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के वास्ते सुविधाओं की बड़ी कमी है । कल महा शिवरात्री है । आज बहुत शुभ अवसर है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय घोषणा करें इन सुविधाओं के बारे में । पीने के पानी की वहां कमी है, ठहरने के शेड की बड़ी मांग है । समय समय पर रेल अधिकारियों को इन कमियों के बारे में अवगत कराया जाता रहा है । इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए ।

केला मध्य प्रदेश के बरहनपुर, महाराष्ट्र के भोसावल और जल गांव तथा मध्य प्रदेश के खंडवा जिलों से आता है । आप ने पन्द्रह परसेंट का सरचार्ज लगाया है । हिमाचल के सेब के बारे में वहां के माननीय सदस्य ने जैसे कहा है और रामटेक के संतरे के क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह से मांग की है उसी तरह से मैं भी पुरजोर

[श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर]

मांग करता हूं कि यह सरचार्ज केलों पर न लगाया जाए, इस को वापिस लिया जाए।

बरहनपुर में, दाघोड़ा में, निम्मोरा में, सावदा रोवर में अधिक से अधिक वैगंज दी जाएं। केला एक पैरीशेवल कमोडिटी है। इस को दिल्ली जाने में काफी समय लग जाता है। इस को जल्दी पहुंचने के आदेश दिए जाएं।

गुना से इटावा तक रेलवे लाइन प्रदान की जाए और ग्वालियर से इंदौर वाया भोपाल के लिए भी एक नई यात्री गाड़ी प्रारम्भ की जाए। भोपाल से दिल्ली आने वाली जी टी एक्सप्रेस में एक यात्री बोगी लगाई जाए ताकि भोपाल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को लाभ पहुंच सके।

इटारसी से झांसी के बीच आप ने इलैक्ट्रिफिकेशन किया है जिस के लिए हम आप के बहुत आभारी हैं। साथ ही निवेदन है कि भुसावल इटारसी सैक्शन का भी आप इलैक्ट्रिफिकेशन करें ताकि रेलों में गति आए और खर्चा भी कम हो।

उपाध्यक्ष जी, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि गाड़ियां लेट हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि जो असामाजिक तत्व गाड़ियों में चेन पुलिंग कर के उन को लेट करते हैं उन के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाये ताकि अन्य यात्रियों को परेशानी न हो। टर्न राउन्ड में जो 16 दिन का समय वैगन्स लेते हैं उनको सख्ती से एन्फोर्स कराया जाय और इस समय को कम किया जाय वरना माल ढुलाई पर इस का असर पड़ता है जिस से हमारी आय भी कम होती है और यही कारण है कि 21 करोड़ 40 लाख टन माल ढोने का जो हमारा लक्ष्य है उस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस के लिये आवश्यक कार्यवाही करें ताकि वैगन्स का इस्तेमाल शीघ्र माल ढुलाई के लिये बढ़े। 18,000 वैगन्ज बेकार पड़े हैं और 35,000 वगन्ज को मरम्मत की आवश्यकता है। इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दें जिस से उन को ढुलाई के काम में लाया जा सके।

दूसरे जो प्रगतिशील देश हैं वहां रेलों को नो प्रोफिट नो लास के आधार पर चलाया जाता है। परन्तु हमारे रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट से सामान्य बजट के भार को भी कम किया है यह बधाई की बात है। मैं रेल मंत्री जी और अधिकारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। रेलवे की वर्किन्ग में भी काफी सुधार आया है। हमारे देशवासियों को रेल मंत्रालय से काफी अपेक्षाएं हैं।

अन्त में मैं पुनः कहूंगा कि झेलम एक्सप्रेस को बुरहनपुर में रोका जाए।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा (आरा): उपाध्यक्ष जी, मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। यह बजट देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को डगमगा देगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और इस प्रकार देश के लोग तबाह और बर्बाद होने वाले हैं। सारे देश के लोग इस बजट से परेशान हैं। सरकारी पक्ष के सदस्यों ने भी इस बढ़ोतरी का विरोध किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री एम० एस० गुजराल ने भी इसको स्वीकार किया है और कहा है कि इस तरह का बजट कभी नहीं आया था जिसमें इतना ज्यादा यात्रा भाड़ा बढ़ा हो और माल किराया बढ़ा हो। उन्होंने कहा है : The price increase in the rail passenger and freight rates was the highest single dose ever proposed.

आज काफी किराया बढ़ गया। यदि इस पूर समझदारी से काम लिया गया होता तो इतना किराया बढ़ाने की

जरूरत नहीं थी । फिजूल खर्ची को कम करने से काम चल सकता था । तीन महीने पहले की बात माननीय पांडे जी ने उठायी है कि उसके पहले रेल की हालत बहुत खराब थी और इन्होंने इनके अनुसार रेल का परिचालन फिर से पटरी पर ला दिया है । उपाध्यक्ष जी, रेल पटरी पर अभी नहीं आयी है । यदि आयी होती तो कर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज हड़तालें नहीं होती, दुर्धटनायें नहीं होतीं । आम जानता को 356 करोड़ 26 लाख रु० कर के रूप में देने पड़ेंगे । इस तरह का बजट कभी नहीं आया था जिसमें जनता को इतना भार उठाना पड़ा हो। काफी दुर्धटनाएं हुई हैं । त्रिपाठी जी के समय में तो दो गाड़ियां लड़ती थीं, लेकिन इनके समय में एक साथ तीन गाड़ियां लड़ती हैं । तीन ट्रेनों की दुर्धटना एक साथ हो गई ।

MR. DEPUTY SPEAKER: If Shri Kamlapati Tripathi had continued, this accident would not have taken place?

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : बजट भाषण में कहा गया हैं कि भिन्न-भिन्न भागों में कम्पनी स्वामित्व वाली 6 निजी रेलें चल रही हैं । शायद मंत्री जी को यह मालूम होगा कि उपरोक्त 6 निजी रेलें अलग-अलग करारों पर भारतीय रेल द्वारा चलाई जाती हैं । लेकिन एक ही ऐसी रेलवे है-फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे, जिसे स्वयं एक कम्पनी चलाती है । इस तरह की और सभी रेलों को भारतीय रेल द्वारा चलायी जा रही है । इसका भी सबसे पहले राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ऐसी दो रेलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जो भारतीय रेल द्वारा चलाई जा रही थीं । इस लाइन की हालत बहुत खराब है, मजदूरों को वेतन 6 महीने से नहीं मिल रहा है, इनकी हालत बदतर हो रही है । 60 से लेकर 250 रूपये तक ही वेतन इनको मिलता है । साल में 15,20 लाख रुपये सरकार उस रेल लाइन को चलाने के लिये देती है, जो रेल वास्तव में पटरी पर नहीं चलती है । पांडे जी जानते हैं, इन्होंने एक आम सभा में हाल ही में कहा था कि इस रेल लाइन का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य है । आज भी वह समझते हैं कि अनिवार्य है, लेकिन किया नहीं । इसका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । जो रेल भारतीय रेल द्वारा चलाई जा रही थी उनका राष्ट्रीयकरण इतना आवश्यक नहीं था, जितना इसका आवश्यक है ।

जब तक आप इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करते, हम चाहेंगे कि यहां के मजदूरों को आप एबजार्ब कर लीजिये, जैसा कि आरा-सासाराम लाइट रेलवे के मजदूरों का हुआ है । अगर ऐसा कर लेंगे तो इन का कल्याण हो जाएगा । जब तक यह मजदूर एबजार्ब नहीं होते हैं, तब तक इन रुपयों को आप सीधे कंपनी को न दीजिये, जो दानापुर में आप का मंडल कार्यालय है, उस को दे दीजिये जिस से कम-से-कम इन रुपयों में से इन लोगों को वेतन तो मिल जाये । अगर उस में से कुछ रुपया बच जाये तो आप इन को दे सकते हैं। लेकिन इन लोगों के वेतन का प्रबन्ध भारतीय रेल को करना चाहिए ।

आरा-सासाराम लाइट रेलवे के बारे में कहा गया है कि इस का सर्वेक्षण हाथ में है । यह बहुत दिनों से हाथ में है, एक साल से अधिक हो गया । आप से हम आग्रह करेंगे कि इस का सर्वेक्षण शीघ्र करा दीजिये, ताकि यह जो उपजाऊ इलाके से लाइन चलती है इस से काफी लोगों को फायदा हो सके । यह दक्षिण और उत्तर बिहार को मिलाने वाली लाइन है ।

[श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा]

विगत वर्ष भी मैं ने कहा था कि बक्सर से पटना, मोकामा से पटना, पटना से जहानाबाद के एरिया को 'सबर्बन एरिया' घोषित कर दीजिये, इस से काफी लोगों को लाभ होगा। आज जो इस इलाके में आप को चेन-पुलिंग की कठिनाई हो रही है, वह आगे नहीं होगी क्योंकि उस इलाके से काफी लोग आते हैं, सिर्फ आम यात्रीगण ही नहीं, बिहार और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी आते जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी इन इलाकों से पटना आते-जाते हैं। इस इलाके को सबर्बन एरिया, अर्द्धशहरी क्षेत्र, घोषित करने से सरकार को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि उन लोगों को रहने का किराया नहीं देना पड़ेगा।

पटना-गया लाइन बिहार की राजधानी को औद्योगिक केन्द्र से जोड़ने वाली लाइन है और यह सिंगल लाइन है। काफी दिनों से इसे दोहरी लाइन करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। इस काम को शीघ्र करने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि पटना में दीघाघाट के पास गंगा नदी पर रेलवे पुल बनाया जायेगा। शायद सेन्ट्रल वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना से इस के बारे में नेगेटिव उत्तर आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस के बावजूद यदि वहां कहीं खामी हो, यदि पटना कटने का कोई डर है, तो उस कमी को दूर कर के इस पुल को बनाया जाये, वर्ना उत्तर और दक्षिण बिहार में यह अन्तर बना रहेगा।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : नेगेटिव उत्तर नहीं आया है, पाजीटिव उत्तर आया है। जो साइट सादाकत आश्रम की तरफ थी, उस को उन्हों ने ऐप्रूव नहीं किया है। जो रोड ब्रिज बन रहा है, उस से 200 मीटर डाउन दि करेंट की साइट को उन्हों ने ऐप्रूव किया है।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : धन्यवाद। लेकिन दीघाघाट वाला साइट अच्छा था।

पटना से बक्सर और पटना से मोकामा तक गाड़ियों की बहुत कमी है। गाड़ियों की कमी की वजह से लोग सुपरफास्ट गाड़ियों की भी जंजीर खींच कर उतर जाते हैं और चढ़ जाते है। ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि वहां पैसेंजर गाड़ियां अधिक चलाई जायें और समय पर चलाई जायें। यदि वे समय पर नहीं चलेंगी, तो फिर वही हालत होगी।

आरा, बिहटा और पटना शहर स्थित राजेन्द्र नगर में यात्रियों के आने-जाने की सुविधा के लिए रोड ओवरब्रिज की आवश्यकता है। शायद यह स्वीकार भी हो गया है। अब इस काम को शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए। पटना में एक ही ब्रिज है, जिस से लोग आते जाते हैं। इस से लोगों को बहुत असुविधा और क्षति होती है।

कर्मचारी जीवन भर रेलवे में काम करने के बाद जब रिटायर होते हैं, तो उन के परिवार के एक भी आदमी को नहीं लिया जाता है। यह अच्छा नहीं है। यह आवश्यक है कि जिस रेलवे कर्मचारी ने अपना पूरा जीवन रेलवे की सेवा में लगाया है, उस की रिटायरमेंट पर उस के परिवार के एक सदस्य को तो कम से कम सेवा में ले लिया जाये। इस बारे में बहुत दिनों से विचार हो रहा है। हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में निर्णय लें।

प्रति दिन गाड़ियों में लूट-पाट, डकैतियों और हत्याओं की खबरें मिल रही हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी घटनाओं की रोक-थाम के लिए अभी तक कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया है। इस बारे में कड़ाई और सख्ती से कदम

उठाये जाने चाहियें । नहीं तो इस से आगे आने वाले दिनों में भारी खतरा होने वाला है ।

पटना से हावड़ा के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है । लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि वहां एक सीधी गाड़ी चलायी जाय । लोकल गाड़ियां जो चलती हैं उस में न पंखा होता है और न कोई और सुविधा होती है । पाखाना इतना गन्दा रहता है कि दुर्गन्ध के मारे उस डिब्बे में बैठना मुश्किल होता है । इसलिये लोकल गाड़ियों में सुधार किया जाय ।

पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में हम चाहते हैं कि कुल्हड़िया और नेऊरा स्टेशनों पर प्लेटफार्म को ऊंचा कर दिया जाय क्योंकि वहां यात्री बहुत ज्यादा संख्या में चढ़ते-उतरते हैं । उन की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि इन स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को ऊंचा कर दिया जाय। कोइलवर, कारीसाथ और कुल्हड़िया में एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वहां एक पुल की आवश्यकता है जिस से कि दुर्घटना न हों । कोइलवर में तो यह बहुत जरूरी है । बगल में सोन नदी पर पुल है और लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है ।

सोन नदी पर एक रेलवे का पुल बना हुआ है । वह बहुत पुराना हो गया है । अंग्रेजों के समय का ही बना हुआ है । जैसी कि हम को खबर मिली है, उस में कई खामियां हैं । यदि उस पर तुरन्त कोई कार्यवाही नहीं की गई तो दुर्घटना हो सकती है । इसलिए हम चाहते हैं कि कोइलवर का जो पुल है या तो उस की अच्छी तरह से मरम्मत हो या इस को और आधुनिक ढंग से बनाया जाय

पटना जिले में बिहटा से अनुग्रहनारायण रोड तक एक नई रेलवे लाइन की योजना बनायी जानी चाहिये । यह इलाका बहुत ही सघन कृषि का इलाका है और इन लोगों को काफी कठिनाई होती है ।

एक नई लाइन वहां बनाने की आवश्यकता है ।

कुछ दिनों पहले जब मंत्री महोदय पटना स्टेशन पर गए थे और वहां एक आम सभा थी तो उस में उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि पटना में एक जोन स्थापित करेंगे । बिहार में रेलवे का एक जोन आवश्यक है । अभी कलकत्ता में उस का मुख्य कार्यालय है । बिहार के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है । यहां बिहार में काफी रेलवे लाइन्स हैं । इसलिए मैं उन से आग्रह करूंगा कि यहां एक जोन वह बनाएं ।

आरा से छपरा को एक बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है । यदि यह काम हुआ तो बहुत फायदा इस से होगा । सीधे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का रास्ता खुल जाएगा । यह बहुत ही अच्छा है । उस में सिर्फ यह है कि गंगा पर पुल बनाना होगा और उस में खर्च तो होगा लेकिन लाभ बहुत होगा ।

सीतारामपुर पटना मोगलसराय लाइन के विद्युतीकरण की तुरन्त आवश्यकता है । आप ने किया भी है । इस के लिए आप को बधाई है ।

दानापुर मंडल में आरा और बिहटा दो बड़े स्टेशन हैं । इन की हालत बहुत खराब है । इन स्टेशनों को आधुनिक ढंग से बनाने की जरूरत है । उस पर अच्छी तरह से सोच विचार करने की आवश्यकता है ।

रेलवे में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । जाली टिकट बेचने वालों का तो तांता लगा हुआ है । अभी हाल ही में अखबारों में आया था कुछ समय पहले कि जाली टिकट बेचने वाले पकड़े गए और वह जेल में हैं । वह जमानत

[श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा]

पर छूट गए हैं। लेकिन उन पर ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिस में कि इस तरह का काम आगे न चले। इस से बहुत घाटा हो रहा है। बहुत जगहों पर जाली टिकट चल रहे हैं।

रेलवे में खान-पान की व्यवस्था दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस बात को यहां पर कहा है इसलिए इस में सुधार लाने की बड़ी आवश्यकता है।

आप ने सोनभद्र एक्सप्रेस चलाई है। यद्यपि आप ने इस का सोनभद्र नाम रखा है लेकिन आप इस को सोन वाले इलाके में रोकते नहीं हैं। मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप सोनभद्र एक्सप्रेस को सोनभद्र के इलाके में, आरा में रोकने की व्यवस्था करें।

पूर्व रेलवे में वालंटियर असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क कार्यरत हैं जिन्हें एक रुपया प्रति घंटा दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप उन को स्थायी रूप से रख लीजिए क्योंकि वे रेलवे एम्प्लाईज के लड़के ही हैं। मेरा आग्रह है आप यह अवश्य करें।

आप की दस हजार किलोमीटर रेलवे लाइन खराब है। इस के कारण एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। आप उस को ठीक करवाने की व्यवस्था करें। यदि आप उस को ठीक करवा लेंगे तो काफी लाभ होगा।

इतना कहने के बाद मैं पुनः प्रस्तुत रेल बजट का घोर विरोध करता हूं।

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): Sir, I have been listening to the hon. Members on the other side of the House expressing serious doubts about the justification of the increase in railway fares and freights in the Railway Budget.

I will now deal with some of the salient points on this issue. Ours is the largest railway system in entire Asia. Almost one sixtieth of our population daily moves in our trains covering about 60,000 kilometres spreading all over the country. Among the State-owned railways, ours is the second largest, next only to Russia. This national enterprise consists of a work-force of 17 lakhs and it is one of the largest in the world under one organisation. The reason for my giving these basic features of our railway system is that with this characteristic feature of largeness in terms of geographical spread, total length of railway, total operations and the total number of staff, our railway system is not simply an organisation which can become an island of efficiency standing out defferent from what is happening to our whole economy and the whole of our society. Thus it forms an integral part of our economy. The factors that influencing the whole economy are bound to exercise similar influence on the railway system. In fact, the increase in fares and freights so far in various railway services has not kept pace with the increase in the costs of inputs in our railway system. This is a visible feature particularly fater 1966. The result is we are not able to provide enough funds for repairs, maintenance and particularly for further development of our railway system. Consequently, the whole system has become not viable in the sense that our railways are not able to earn enough to pay for the dividends on the capital at charge. Apart from this, the Rail Tariff Inquiry Committee had made two important observations while submitting its Report in April, 1980. The first observation is that the funds provided in the past for repairs, maintenance and particularly for the development of our railway system were not adquate and the second and equally important observation made by the Rail Tariff Inquiry Committee is that the financial viability of our railway system

can be re-established only by permitting substantial increases in fares and freights. This objective has been empasised with an intention to make our railway system more effective in ensuring efficient functioning of our national economy and finally in serving the interests of the common man.

In spite of the existence of these influencing factors for raising substantially fares and freight charges, our Railway Minister has exercised commendable restraint in not touching some of the important areas of rail traffic. For instance, there is no change proposed in the existing rates of monthly season tickets for suburban rail traffic. Apart from this he has given further concessions in the monthly season tickets from 33 1/3 per cent to 50 per cent to all the students of Calcutta at par with the students of Bombay. Besides, it is most gratifying to note that 6 per cent concession on the freight charges on all goods traffic to and from all the North Eastern States of Assam, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, is really commendable. When I went to these States in a Parliament Committee I could see in them a sense of discrimination and neglect. This kind of concession is really very welcome particularly in view of their crippled economy due to their agitation which is going on there. I shall be happy if this concession is increased from 6 per cent to 10 per cent. Apart from it, it is gratifying, that the Minister has exempted some of the items of basic needs from surcharge of 15 per cent for instance, salt for domestic purpose consumption, charcoal, fire wood. Here I would like to make one suggestion for the sympathetic consideration of the hon. Minister that the salt may be exempted completely because it is the cheapest and seasonal product wherein lakhs of people belonging to the backward classes and weaker sections have been employed for their livelihood. Therefore, it requires to be completely exempted.

There is one other item in which lakhs of women and un-skilled workers are employed for their livelihood. That is coconut fibre and coconut yarn. In fact the Rail Tariff Enquiry Committee has strongly recommended for the exemption of coir yarn and coir fibre from this surcharge.

Before going to another important aspect I would like to cite one observation made by the Rail Tariff Enquiry Committee as a justification in requesting for reduction in the passenger fares.

> "In case of passenger services, the revenue from ordinary second class passengers should cover the direct costs of this service and revenue from the mail and express services should not only cover their fully distributed costs but also make up shortfall in the ordinary service so that the passenger services taken as a whole meet their share of total costs."

Now, in the light of with this observation I would like to make one suggestion for the consideration of the hon. Minister, that the proposed surcharge of 10 per cent on ordinary second class fares which has been exempted for journey upto 150 kilometres, may be exempted completely. Persons who travel in the ordinary second class would do so only when it is unavoidable and very necessary. In view of their financial position, therefore, there is every justification for this concession.

In the Sixtyninth Report of the Estimates Committee of Parliament it has been clearly emphasised that—

> "Rail links to the backward and thiokly populated areas without proper communication facilities would greately help their development and also balanced growth of the nation."

This has been suggested in view of the fact that the people there, if unconnected with the rest of the country, would develop a sense of discrimina-

(Shri Kusum Krishna Murthy)

tion and sense of neglect which slowly leads to migration of metropolitan cities and that this leads to further troubles. Therefore, the policy of extending railway line should be based on balanced growth of rail links. In fact, the Britishers followed the policy of convenience and profit and they never treated our Railways as an instrument of national integration. I am afraid our Railways are still following the same policy. After all our Railways are run as an instrument of national integration and not with profit motive. Therefore, the balanced growth of the nation depends on the balanced growth of the Railways and money should not be diverted to the cities at the cost of the rural areas. Therefore, I would like to make an important suggestion that the study of this urgent problem of balance growth of the Indian Railway lines should be taken up immediately in order to diversify the rail lines properly and evenly. Therefore, Rail Line Expansion Committee may be consituted to study this problem. That Committee would specifically make suggestions for the balanced growth of our rail lines.

I now come to an important problem which relates to my area and in support of my point, I would like to cite an important observation from the Rail Tariff Enquiry Committee which strongly recommended that—

> "Whenever possible, development should take the form of alternative routes and bye-pass instead of doubling and tripling along the existing routes."

I am giving a glaring example of my district of East Godavari in Andhra Pradesh. A rail cum road bridge has been constructed a few years ago in parallel to the old rail bridge at Rajahmundry. This is an important step taken and it is quite justifiable. The road-cum-railway bridge was constructed as a substitute for the existing old bridge. But recently it has been decided to construct another bridge by investing crores of rupees, of course to replace the old bridge.

No doubt, it is always advantageous to have a double line. But in view of the observations made by the Railway Tariff Enquiry Committee that we should preer alternative routes or bye-passes instead of doubling or tribling the existing line, I strongly feel and contend that if the same amount is diverted by adding a little more, if necessary, the entire island of Konaseema, popularly known as Amlapuram Parliamentary constituency, with more than 10 lakhs of neglected people, can be connected with main line. The amount earmarked for the second railway bridge at Rajahmundri can be safely diverted to construct a road-cum-rail bridge at Kotipalle to connect Amlapuram. Upto Kotipalle, from Kakinada, there was a rail connection existing from 1928 to 1940. During the Second World War, it was removed by the Britishers. The Britishers always followed the path of convenience and profitability. They never treated the railways as an instrument of national integration. The moment the purpose was served they removed the railways.

Then, I asked for some relevant information about this removed rail line and the authorities of the South-Central Railway were kind enough to supply me the information immediately. I am reading out some of the relevant facts for the information of the hon. Railway Minister. I am not pleading for a new line. The Deputy Minister of Railways while intervening in the debate said that in view of the constraints of funds, they are not able to take up new lines. But I am not making a case for a new line; I am making a case only for the restoration of the removed railway line which can be taken up at a minimum cost. The relevant facts from the note given by the South Central Railway authorities are:—

> "(1) The removed rail line from Kakinada to Kotipalle is 40 kms. only.

(2) Most of the embankments are reported to be in existence.

(3) Most of the land is still with the Railways.

(4) Approximate cost to restore the removed rail line between Kakinada and Kotipalle would be Rs. 6 crores.

(5) A more realistic cost can be given only after the survey is made."

Therefore, I would like to request the hon. Minister to order for an immediate survey. If a survey is made, the work on the removed line can be taken up. Apart from this, if you divert the funds earmarked for the second railway bridge at Rajamundri to construct a road-cum-rail bridge at Kotipalle to connect Amlapuram, the entire 10 lakhs of neglected people of Kanaseema can be connected at an appropriate point of feasibility to the main line so that they can be connected finally with the rest of the country. Thus the second rail line instead of going again through Rajamundri, it can be diverted from Kakinada *via* Kotipalle to Amalapuram from there to Nursapur to connect the main line.

Then, in the last Railway Budget, the hon. Minister had made an important observation that the cooperation of the employees is an important factor for the efficient running of the railways. There are about 3,13,000 employees belonging to SCST in the Railways. This is the biggest undertaking giving opportunities to the largest number of people belonging to SCST. The Railway Ministry has taken all possible steps to implement the reservation quota for SCST people. But in regard to checks and balances, there are serious lapses. When late Shri L. N. Mishra was the Railway Minister, on the floor of this House, made an important proposal for manning the cell at the national level. He made the opportunities to man this cell to keep open to any employees of any railway zone, without confining tham to the Railway Board alone. This is a cell for the entire nation and it functions through the Railway Board which is not being properly manned. After the Janata Party came to power, the system has been changed and the opportunities to man the cell were restricted only to the employees of the Railway Board. This leads to downgrading even the existing grades. Therefore, you are not able to keep these opportunities open to all the employees from different zones. In fact, this cell is not confined to the Railway Board. It is a cell at the national level. So, this defect should be rectified forthwith.

Apart from this, there is another commitment made by the hon. Minister to the parliamentary committee on the welfare of SC and ST officers on duty, one at Bombay and another at Calcutta, are to be created and manned by one S.C. and another by S.T. respectively. The officer on duty at Calcutta has not been appointed though the financial approval has also been given. The post belongs to S.C. During the two crash propommes, these officers made a commendable progress in wiping out the back-log in the services. This lapse should also be rectified, immediately so that the provisions of reservation in the services can be effectively and properly implemented.

With these words, I congratulate the hon. Minister for bringing such a progressive budget and I conclude.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Alleppey): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am unable to support this Railway Budget because that is going to further enhance the increasing prices. That will have an adverse effect on our economy as a whole. Whatever little benefit the Finance Minister has given to middle class employees will be taken away by the enhanced ticket charges imposed by the Railway Minister. So, the people are not going to get any relief and this budget is actually

(Smt. Susheela Gopalan)

an anti-people in character. Even the members from the ruling party Benches have expressed this opinion that these enhanced fares-freights should not have been there, because they are also facing opposition from people.

With regard to the workers' problem, I was amazed to hear the speech of the Railway Minister. He was saying that the workers' relations in Railways were cordial throughout the year. It reminds me of Nero fiddling veena while Rome was burning! The Economic Survey placed before the Parliament repudiates the statement (*Interruptions*) of the Railway Minister. On page 70 para 4 of the Economic Survey, it is said:

> "There has been a significant decline in industrial discipline, persistent agitations and go-slow affecting work and productivity."

When more than 30,000 locomen were already on strike and the station masters had assembled before the Boat Club to burn the misfit uniforms and to press their demands, it is the height of callousness to say that the relations with railwaymen were cordial. (*Interruptions*).

There has been agitation by Carriage and Wagon staff, Watch & Ward staff, commercial clerks, office clerks, Ticket checking staff and tele-communication staff during 1980. There were several petitions before the Parliament. They are pending before the Lok Sabha Speaker and I think he has passed them on to the Petitions Committee. This is because it is not possible for one-third of the workers to ventilate their grievances. There are no avenues for them to have a discussion with the Railway Ministry.

Our Railway Ministry has no respect even for the court judgements. In Palghat division five Assistant Station Masters' salary was much lower than that of the junior officers. Therefore, four Assistant Station Masters, asked the Railway Board to at least to bring their salary on par with junior officers. But, they did not pay heed to their request. They went to the court. Then, the court asked them to revise the salary. The junior officers salary was reduced. Again, both had to go to a court and the court held that this was not the correct thing. The court ordered for revision of the salaries. But the Railway Board did not do it. Again, they had to go to court. The case is pending for the last one year before the court. The railway board is not taking care even to implement the verdict of the courts. They are careless about it.

What about the tribunal awards? Even when negotiatiions are going on and the dispute is pending before the industrial tribunal, the officers are being transferred and dismissed. This is what actually is happening.

Last time when I spoke, I referred to the contract labour. I received a letter from the Railway Ministry saying that they cannot be absorbed in regular service because they are only doing contract work. So, they are not able to take them into regular service. This is their reply. But is the contract labour governed by the Contract Labour Regulations in Railways? I want to ask the Minister whether any one of the contract labourers is governed by these contract Labour Abolition Act. None of the workers is getting the benefit of this Contract Labour Abolition Act.

When they complain you give them the reply that they are governed by the contract labour laws. But these laws have not benefited these poor workers.

Sir, I have no time to go into details. The Railway Minister has declared a war against these poor workers. Let there be a ceasefire. If you

want to carry on the administration in a better way, you should have cordial relations with the workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the first speech delivered by Shri A. K. Gopalan as Leader of the Opposition, he mentioned that the President's Address was a declaration of war against the people of India. Now you have said, Railway Budget is a declaration of war against the railway workers. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): Railway workers are our workers. We are treating them properly. We are part and parcel of the people. We are placing the realities before the people.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: What has been the demand of the locomen? From 1967 onwards they have been demanding that you should reduce their working hours from the limit of 14 hours. It was reduced to 12 hours in 1973 and an agreement was signed for implementing 10 hours' work. For that they had to go on strike. When they complain, you go on penalising them. So, they had to resort to strike. You have now introduced these jumbo wagons. These poor railway workers have to work for 14 hours or even 16 hours continuously. If they stop work, you take action against them. If they complain that their wives were raped, you take action against them. That is why these people get frustrated and they resort to strike. This is what we see after 34 years of independence. Sir, I do not want to go into details.

The Railway sector is a sector where there is abundant opportunity for the Government to provide more employment. In a country like ours, where unemployment is mounting up, what should be your policy? It should be to get more and more people employed. But what you are doing is that you are bringing the third generation and the fourth generation computers. You introduced the second generation computers some three years back. What has been the result of it? 10,000 workers are affected.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: I would like to point out to the Hon. Member that there is no retrenchment at all due to the introduction of computers. We are giving them alternative jobs and training them. We are absorbing them in the best possible way. There is no retrenchment on account of introduction of computers. Nobody is removed from the services on that score.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: This is a field where you could have provided more employment to the poor people in this country. In these three years ten per cent more workers could have been employed. This should not be your policy. Lakhs of people are going to be unemployed because of this policy.

Then, Sir, I wish to point out that Kerala has always been neglected. This Budget also does the same thing. No fresh proposal is there in the Railway Budget so far as Kerala is concerned. In the present year, for Railway construction for Alleppey line, what is the amount allotted? Only Rs. 2 crores. What is the total amount? Rs. 7 crores. By about 1983 you want to complete the work. How is it possible? Next year you propose to allow Rs. 4 crores. This is only duping the people; we have no belief in that. We have no doubt whatsoever that this project will get more and more delayed. you have ordered for two surveys to satisfy the people of Kerala. In your own report you have stated that the surveys would be conducted. But there is no possibility of taking up this project in the near future.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Kerala should be thankful to it is full of broad gauge lines.

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor): The entire railway line in my constituency is of meter gauge line.

SHRIMATI SUSHELLA GOPOLAN: It is true that the railway lines were constructed during the British time. You could not destroy them. Now, about the opening of a Railway Workshop in my State, you have not done anything. There is not even a workshop in Kerala at present. I would request the hon. Minister to tour the Malabar area and see the conditions of railway stations there. They are very old and they are in a dilapidated condition. There are no proper roads leading to the railway stations. At places like Neeleswar one has to walk for more than two furlongs to reach the railway stations since the roads are very badly maintained. If it was under the State Government they would have at least constructed it well.

Sir, you will know that Kerala is producing electricity in abundance. But there is no proposal in the budget for electrification of some of the railway lines in Kerala. Why cann't you electrify at least one railway line to start with?

Now, with regard to the allotment of wagons, every day we have to approach the Minister. Now leaves for the manufacture of bidis have to be brought from Orissa. We represented several times for the allotment of wagons for transportation of these leaves from Orissa. But the position has not improved, with the result that the price of bidi leaves has gone up.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: We have taken action.

SHRIMATI SUSHEELA GOPALAN: Now, in the tile industry about one lakh people are unemployed because of the lack of transportation facilities. For transportation of tiles, special types of wagons are required. Now, we are producing cash crops. But we are depending on other States for rice.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: You please advise the workers to keep on working and increase the production so that we can reach you.

SHRIMATI SUSHELLA GOPOLAN: You will get their cooperation. You should not take such an attitude. You should not ask them to work for 14 hours. Now, from so many States, we have to purchase rice. The question is how these things to be transported to Kerala. Now, the price of rice has gone up. The excess distribution of 5 K.G. besides rice ration has to be contnued.

Another point I would like to make is that Keralites are serving in various industries, in both private and public sectors, spread all over the country. These people are facing a lot of difficulties to visit their native places in Kerala once a year or so. In this connection, I have also requested the hon. Minister to consider attaching some coaches in the Navjeevan Express starting from Ahmedabad so that the Keralites working in that part can reach Kerala and visit their native places without being held up at Arkonam. From Jaipur also I got a letter from the Malayalee Association. I represented to the Minister. I got the letter that he will consider it, yet consideration till now. They want that at least 5 berths to be allotted in Kerala bound trains from Delhi. From Bhilai also, they want that some berths to be allotted in the Express trains from Nagpur for people travelling to Kerala from Nagpur. It is very difficult for them to travel. These are all minor things, but even in these things, the Government is very callous, and no attention is paid to these things. That is our experience. I would request the hon. Minister to go into all these matters and take necessary action. As I said, the neglect of Kerala State should also be stopped.

With the words, I conclude.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): वैस्टर्न रेलवे का जो डिवीजन है उस में जो जिले पड़ते हैं, जो इलाका पड़ता है वह बहुत बैकवर्ड है । वहां ज्यादा से ज्यादा लाइनें बिछाई जानी चाहिये । हम बराबर इस के बारे में निवेदन करते आ रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मेरा पहला सुझाव यह है कि वैस्टर्न रेलवे जो घाटे वाली रेलवे नहीं है और बहुत ज्यादा मुनाफा देती है इस का सैपरेट जोन बनाया जाय । ऐसा किया गया तो नई लाइनें बिछ सकेंगी और इस बैकवर्ड एरिया का बहुत तेजी से विकास हो सकेगा । इस मीटर गेज का अलग जोन वैस्टर्न रेलवे का बनाया जाना चाहिये जिस में राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ इलाका गुजरात का हो । इस के बारे में हम बराबर निवेदन करते रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इस से इस पिछड़े हुए इलाके की उन्नति हो सकेगी ।

वैस्टर्न रेलवे और नार्दर्न रेलवे राजस्थान में से हो कर गुजरती हैं । दोनों की पब्लिक सर्विस कमिशंज अलग अलग हैं । एक की बम्बई में और दूसरी की इलाहबाद में है । राजस्थान तथा अन्य प्रान्तों को इससे बहुत घाटा होता है । वहां के लोगों को निश्चित तौर पर नहीं लिया जाता है । जहां पर हैड-क्वार्टर होता है , पी एस सी होती है वहीं के लोग ले लिए जाते हैं और दूसरे प्रान्तों के लोगों को आने का मौका नहीं मिलता है । बम्बई वैस्टर्न रेलवे के एक किनारे पर है और वहीं पी एस सी का हैड-क्वार्टर है । राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रान्तों के लोगों को भरती होने का अवसर नहीं मिलता है । मेरा सुझाव है कि वैस्टर्न रेलवे की पी एस सी का हैडक्वार्टर अजमेर किया जाए जो कि बीच में पड़ता है और इससे सब लोगों को लाभ मिल सकता है ।

नार्दर्न जोन का जो हैडक्वार्टर है इसको या तो बीकानेर में या जोधपुर में रखा जाए ताकि यहां के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा भरती के अवसर मिल सकें । वैस्टर्न रेलवे का जो नया जोन बने उस को अजमेर या जयपुर में स्थापित किया जाए ।

हम दस बारह साल से अहमदाबाद और दिल्ली को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की मांग करते आ रहे हैं । इस के अभाव में जो ट्रांसशिपमेंट की दिक्कत होती है, सामान को इधर उधर ले जाने की जो दिक्कत होती है और उस में जो बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है उस से बचा जा सकेगा । ब्राड गेज न होने की वजह से उद्योगपति भी यहां उद्योग स्थापित नहीं करते हैं । इस वजह से राजस्थान तथा अन्य इलाके पिछड़ गए हैं । अगर ब्राड गेज हो जाए तो पिछड़े हुए क्षेत्र काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं । इस के बारे में पिछली बार भी मैं ने कहा था । तब कहा गया था कि यह मामला प्लानिंग कमीशन में पड़ा हुआ है । 10, 12 साल हो गये प्लानिंग कमीशन में और उस पर रेल मंत्रालय तथा प्लानिंग कमीशन कोई निर्णय नहीं लेते जिस की वजह से सारा का सारा इलाका पिछड़ा हुआ रह गया है और जिस प्रकार का वहां विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है । इसलिए नितांत आवश्यक है कि रेल मंत्री जी इसकी कोशिश करें और प्लानिंग मिनिस्टर से बात कर के इस ओर ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दिलायें ताकि इस रेलवे लाइन की वहां स्वीकृति हो और सारे क्षेत्र का विकास हो सके । इस प्रकार की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए ।

19 hrs.

आप ने टोडा रायसिंह से नाथद्वारा, कोटा से देवगढ़ और लाम्बिया से त्यावर रेलवे लाइन के सर्वे की स्वीकृति दी है जिसके लिये आपके हम आभारी हैं । मगर यह सर्वे

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

सालों तक न चले, बल्कि एक साल के अन्दर इस का सर्वे पूरा हो जाना चाहिए । क्योंकि आप ने माना है कि राजस्थान का भीलवाड़ा चित्तौड़, टौंक और उदयपुर जिले यह सारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है जिस का निश्चित रूप से डेवलपमेंट होना चाहिये । इसीलिये आप ने दोनों लाइनों के सर्वे की स्वीकृति दी है । मगर सर्वे होने के बाद निश्चित रूप से इस क्षेत्र की तरक्की के लिए इन लाइनों को जल्दी से जल्दी बिछा कर वहां के लोगों को राहत पहुंचायें । हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप ने सर्वे की प्रार्थना स्वीकार की है उसी प्रकार से इन लाइनों को बिछाने की भी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे ।

एक और मांग है और रेल मंत्री महोदय ने भी सुबह कहा था कि राजस्थान कैनाल के पैरलल रेलवे लाइन बिछायी जाय । क्योंकि राजस्थान कैनाल एक नेशनल प्रोजक्ट है जिस का फर्स्ट फेज पूरा हो गया है, लेकिन सेकेन्ड फेज बनने में कठिनाई आ रही है क्योंकि न सीमेंट और न कोयला पहुंच पाता है और इस के कारण इतना बड़ा प्रोजक्ट सालों से रुका हुआ है । राजस्थान कैनाल का सेकेन्ड फेज तीसरी और चौथी योजना काल में पूरा हो जाना चाहिए था, मगर छठी योजना में भी राजस्थान कैनाल पूरी नहीं हुई है । उस का मुख्य कारण यह है कि वहां रेलवे की व्यवस्था नहीं है । अगर राजस्थान कैनाल के पैरलल रेलवे लाइन बिछा दी जाय तो उस से कैनाल भी जल्दी बन सकेगी और हम अपने डिफेंस का मसला भी हल कर सकेंगे । क्योंकि राजस्थान कैनाल बिल्कुल बोर्डर लाइन पर जायगी, रेलवे लाइन हो जाने से अपने डिफेंस को मजबूत बना पायेंगे तथा मिलिट्री को भी जल्दी से जल्दी पहुंचा सकेंगे तथा उन के लिये आवश्यक साधनों को भी जल्दी पहुंचा सकेंगे । इसलिये हमारे लिये, डिफेंस के लिये और उस क्षेत्र के विकास के लिये, यह नितांत आवश्यक है कि कैनाल के पैरलल रेलवे लाइन जल्दी से जल्दी बिछायी जाय, इस की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाय ताकि हम अपनी सारी व्यवस्था को मजबूत बना सकें ।

जयपुर से सवाई माधोपुर तक बड़ी लाइन बिछा दी जाय । यहां आज मीटर गेज लाइन है जिस के कारण काफी कठिनाई पड़ती है और वहां का विकास नहीं हो रहा है । सवाई माधोपुर से ले कर कोटा बूंदी, झालावाड़ तक सारे इलाके में लाइम स्टोन के भंडार हैं और इस कारण पांच साल के अन्दर निश्चित तरीके से 15, 20 सीमेंट के कारखाने वहां लगने वाले हैं । अगर यहां बड़ी रेल लाइन हो जाती है तो सीमेंट के कारखानों से होने वाले उत्पादन को हम देश के कोने कोने तक आसानी से भेज सकेंगे और हमारी जो विकास की गति रुकी हुई है सीमेंट के अभाव में उस को भी पूरा कर सकेंगे ।

हम ने कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भी कहा है । पर किन कारणों से इस लाइन को स्वीकृति नहीं दी यह समझ में नहीं आता । मैं फिर निवेदन करूंगा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच में बहुत ही विकसित क्षेत्र है तथा बड़े बड़े उद्योग यहां लगे हुए हैं इसलिए बड़ी लाइन से अगर जयपुर को मिला दिया जाता है तो उस क्षेत्र का बहुत विकास होगा और तेजी से उद्योग बढ़ेंगे । इसलिए यह लाइन ब्राड गेज में परिवर्तित कर दी जाय, इस से बहुत बड़ा लाभ होगा ।

मैं एक बात मीनाक्षी ट्रेन के बारे में कहना चाहता हूं जो अजमेर से काछीगुडा चलती है और हफ्ते में दो दिन चलती है । और कोई फास्ट ट्रेन अजमेर से काछीगुडा खंडवा के लिये नहीं है । बार बार निवेदन किया है, कंसल्टेटिव कमेटी में भी कहा है, लेकिन जवाब मिला है कि लोड बहुत है, इसलिये संभव नहीं है कि इसे रोजाना में कर दिया

जाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्रमें इसके अलावा और कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, इस को डेली कर दें तो वहां के पैसेन्जर्स को ज्यादा लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र को ज्यादा तरक्की का अवसर मिलेगा ।

मैं ने भीलवाड़ा स्टेशन के बारे में भी निवेदन किया था । यह एक लाख की आबादी का शहर है । जब पहले स्टेशन बना था तो मुश्किल से यहां की आबादी 5, 7 हजार थी, लेकिन उस में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । केवल 40, 50 फुट का एक शैड जरूर बनाया गया है । 1 लाख की पाप्युलेशन के लिये जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, जो साधन होने चाहियें, उन को पूरा करना जरूरी है, एक छोटा सा वेटिंग रूम वहां बना रखा है, उस में 50, 40 फुट का शैड है । यह सारे स्टेशन को कवर नहीं करता है, अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त है कि वह इस सम्बन्ध में जरूर तय करें ।

भीलवाड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है, तरह तरह की इंडस्ट्रीज वहां पर बराबर सैट होती जा रही हैं, इसलिए इस स्टेशन को माडर्नाइज करने और डैवलप करने के लिये मेरा ख्याल है माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे । इससे वहां के बिजनेस मैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स पब्लिक और दूसरे मजदूरों को भी सुविधा मिल सकेगी ।

इसी तरह गुलाबपुरा और रायला स्टेशन भी उसी क्षेत्र में पड़ते हैं, उन को भी पूरा स्टेशन बनाने के लिये कहा था । वहां भी दो-दो तीन-तीन इंडस्ट्रीज हैं लेकिन वहां फ्लैग स्टेशन ही बना रखे हैं, उसकी वजह से लोडिंग और अन-लोडिंग में हर प्रकार की कठिनाई होती है । बराबर निवेदन करने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । जब भी निवेदन करते हैं, आप भी कह देते हैं कि हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन कोई भी सुविधा वहां नहीं है । इसलिए इन को पूरा स्टेशन बनाया जाये । यह दोनों मंडियां हैं, इससे इस क्षेत्र को ज्यादा लाभ मिल सकेगा । इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है । हमें उमीद है कि माननीय रेल मंत्री जिन्होंने सर्वे की व्यवस्था की है, वह इन छोटी-छोटी मांगों पर निश्चित तरीके से कार्यवाही करेंगे ।

मेरा एक छोटा-सा सुझाव और है, जिसको पहले भी मैंने कहा था । आपने सैकिंड क्लास पर सरचार्ज लगाया है, 150 किलोमीटर तक इसे छोड़ दिया है । मेरा कहना है कि सैकिंड क्लास में गरीब लोग सफर करते हैं, आपने जो 10 परसैंट सरचार्ज लगाया है, इसमें कुछ रियायत देने की कृपा करें, क्योंकि गरीबों के प्रति आपके दिल में कुछ हमदर्दी है । इसी के साथ साथ फेट पर जो आपने 15 परसैंट सरचार्ज लगाया है उसको भी किसी तरीके से कम करने की व्यवस्था करें ।

लोको के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की हड़ताल के बारे में आपने बहुत मजबूती से उसे फेस किया है, इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इस बात को भी देखिए कि रेलवे में जो तोड़फोड़ करने वाले संघ हैं, वह सी० पी० एम० के द्वारा चलाये जाते हैं, यह जार्ज फर्नाण्डीज की यूनियन है । इस प्रकार की यूनियन को अगर बढ़ावा मिलता है, तो उससे हमारी रेलवे की प्रापर्टी को नुक्सान होता है । आपने देखा है कि जार्ज साहब ने कितनी रेल लाइनें उड़ाई हैं और किस तरीके से उन्होंने सैंकड़ों आदमियों को नुक्सान पहुंचाया है । ऐसी यूनियन को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो निश्चित तरीके से हमारी रेलवे को कभी लाभ नहीं मिल

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1974 की जो रेलवे की हड़ताल हुई थी, उसमें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से काम किया, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय नहीं था। जो रेलवेज के लायलिस्ट्स थे, जिन्होंने उस खतरे में रेलवे को मजबत बनाने के लिए काम किया, जब कि लोग-बाग उन्हें जान से मार सकते थे, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। लेकिन जिन अधिकारियों ने जार्ज फर्नाण्डीज की यूनियन के साथ मिल कर उस हड़ताल को मजबूत बनाने के लिए काम किया, उनको प्रोत्साहन मिला। जो लोग हमारी मदद करते थे, जिन्होंने चौबीस चौबीस घंटे काम कर के रेलें चलाईं, उनको किसी प्रकार प्रोत्साहन नहीं मिला। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलाना चाहिए, बढ़ौतरी मिलनी चाहिए, पदोन्नति मिलनी चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए,। जो लोग रेलों में तोड़-फोड़ करते हैं, उनको प्रोटेक्शन न मिले। जो लोग रेलवे को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनका ख़याल मंत्री महोदय के दिलो-दिमाग़ में होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं रेल-बजट का नसमर्थन करता हूं।

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Mr. Deputy-Speaker, I rise to support the Railway Budget. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will call every Member who is present.

SHRI K. MAYATHEVAR: I welcome the Budget. But I am demanding certain concessions on behalf of the people, not only the people of Tamil Nadu, but the people of India. The Railways should achieve maximum efficiency at minimum cost. This is what we are reading in newspapers and hearing in public statements. One more thing I want to request the Minister for Railways. We have been pressing for the construction of new lines. Secondly, we are pressing for conversions from metre gauge to broad guage and we are pressing for doubling of lines. These are three proposals which we are making or improving the Railways, for providing conveniences and facilities to the people. I request the Government to implement all these three proposals as expeditiously as possible in the interest of reducing the cost on the running lines, because the cost if implementations is double; sometimes it is three times or even four times. Therefore, the expeditious execution of all these three proposals is in the national interest and I request the Minister and the Government to issue strong instructions to the concerned officials to implement with maximum efficiency and minimum cost in the interest of national economy.

The people of Tamil Nadu have been demanding for the construction of a broad gauge line from Karur-Dindigul-Tuticorin for the last 25 to 30 years. Other hon. Members from the Congress Party and DMK have already mentioned about this and the hon. Minister and the hon. Minister of State and above all the hon. the Mother of India our beloved Prime Minister also were pleased and graciously pleased and I am satisfied—to hear from the hon. Minister and hon. Prime Minister that they are considering this new line, Karur-Dindigul line for execution in the Six Five Year Plan. I demand, I request, I insist again and again, on behalf of the people of Tamil Nadu that this new line should be given priority because this will benefit not only the people of Tamil Nadu and it will go a long way to help the industrial development of the region. I request the Minister to implement it and execute it in the Sixth Plan.

We are also demanding the inclusion of a new broad gauge line from Tirunelveli to Kanyakumari also. The Minister is laughing because he knows why I am speaking about it, or why I am demanding it. The total length of this line is 159 kilometres and nearly 128 kilometres is in Tamil Nadu and the remaining 31 kilometres is in Kerala. If this line is included it will help the economic development of Tamil Nadu and it is a legitimate right of the people of Tamil Nadu to claim the inclusion of this line. Even geographically we are speaking of connecting Kashmir and Kanyakumari. Kanyakumari lies within Tamilnadu; it is the southern-most tip of India. So, geographically also we are having a legitimate right to demand it. Culturally, economically, socially, politically and even morally also we have a right to have that line, which should be included in the Madurai division. The Minister came to Madras and met my leader, Kalaignar Karunanidhi and I was an eye-witness. The Minister should not forget that I am a lawyer. I was an eye-witness and he should not drive me to the court. Of course, we are not going to the court to give evidence. That is not the case. But I was an eye-witness to the fact that the Minister of State came to Madras and promised to the people of Tamilnadu that the Government will consider favourably and include the Nellai-Kumari line in the Madurai division.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): I promised that father and mother should be together.

SHRI K. MAYATHEVAR: Unless they are divorced, father and mother are always together, as long as there is no trouble, giving birth to a lot of children and giving trouble to the country! That is a different matter. We are not going to the court for divorce.

Even the predecessor to the present Minister promised to me, my party leaders and Tamilnadu MPs to include this under the Madurai division. The Minister of State knows that trains in Tamilnadu were not running for a week or ten days. He came and pacified the railway workers who were on strike, because their claim is legitimate and right. Therefore, you should not drive the people of Tamilnadu to go on strike again for demanding the inclusion of this new line. It is the heart-line of Tamilnadu. I said that the Dindigul-Karur line is the life-line for the people of Tamil Nadu. This Nellai-Kumari line is the heart-line for the people of Tamilnadu and the people of the South within Tamil Nadu. So, request that this should be included under as you promised to my leader, Kalaignar Karunanidhi, at Madurai.

You have been giving promises to convert the Beach-Tambaram electric line into B.G. The officials in the Madras Southern Zone with whom we had some discussion told us that they have recommended to the Railway Board and the Government for considering the conversion of this MG line to BG. But I am shocked to hear the speech of the Railway Minister that Government is going to get proposals from the officials for conversion and for survey also. I have been told by your own Southern Zone General Manager and other officials at Madras two weeks back that it was already surveyed and they have submitted a report to the Government for conversion into BG. I request the Minister to look into the matter as expeditiously as possible, because the population is very tense in Madras and the present MG trains are unable to cope up with the demands of Tamilnadu for transport facilities.

Our railway department has allotted only Rs. 50 crores for this financial year for metro railway development in various cities like Bombay, Calcutta and other cities. It is a very negligible amount in view of the heavy load

[Shri K. Mayathevar]

of work to be completed by the railway department. For Madras we have been demanding metro line development for a very long time. The Government are promising to implement the metro line for Madras city. But unfortunately, I am sorry to state that it has not been taken up in this financial year or in the sixth plan. I request the Government to have a re-consideration on this point and allot more funds. I request the hon. Minister to allot more money and take up metro project for Madras city also.

Officials from the World Bank seemed to have come to Tamil Nadu for having first-hand knowledge and assessment to start another Integral Coach Factory at Madras. They have made an estimate of Rs. 200 crores to be spent for starting another ICF in Madras. Officials of the World Bank were convinced with the environment of Madras. But the Government of Tamil Nadu did not take any steps for this project. I congratulate the people of Kerala and MPs from Kerala as they are having two Chief Ministers—one Chief Minister at Madras and another their own from Kerala itself. My Chief Minister is helping Kerala. I do not have any grudge against the people of Kerala. But he should not betray** the people of Tamil Nadu who have voted him to power. He betrayed the people of Tamil Nadu and acted against their welfare. The Congress(I) and DMK MPs are here to fight for the people of Tamil Nadu. Therefore, you please consider to put up another ICF in Tamil Nadu. You should not take into consideration the Government of Tamil Nadu. We feel that we do not have a politically known person leading us in Tamil Nadu. He is not a politician. He does not know abed of poltics and administration.

There are six privately owned railways in the Eastern Railway which have not been nationalised even after 34 years of our independence. It is high time that the Government should nationalise these six companies immediately.

As per facts and figures, the Railways are having about 1.5 million employees who are working on permanent basis.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDAY): 1.75 million permanent workers.

SHRI K. MAYATHEVAR: According to your report 2.35 lakh workers are working on temporary basis even now. Khalasis are working on temporary basis. Certain workers have been working for more than 25 and 30 years. Workers from Stores Department of ICF have given a petition to me stating that they have been working for the last 25 years but they have not been regularised and their basic seniority has also not been fixed. I request the hon. Minister to consider their cases and make them permanent so that they can get some benefit at least at the time of retirement. Suppose, they die now, their families will not get any benefit.

I do not have any complaint regarding freight rate. I am only requesting the hon. Minister to consider reducing second class fare which has been raised at the rate of 10 per cent, and thus give relief to the poor down-trodden and middle class people. We are having so many accidents in the railways. To avoid them we have been demanding for the last 25 years that in every unmanned gate we should post gate-keepers. Though all the MPs and all the leaders have been demanding this, it has not been done so far.

Coming to level crossings, in every area people want level-crossing. In my constituency also people have been demanding level-crossings. But the railways demand Rs. 40,000 for every

**Expunged as ordered by the Chair.

level-crossing. What is the justification for such a big amount? The local panchayats are unable to pay Rs. 40,000 to 50,000. Either you give some concession or you pressure the State Governments to bear it. Because, so far as Tamil Nadu is concerned, the DMK or Congress MPs cannot approach the State Government, as it is run by some other party. Therefore, we are unable to help our constituency by opening more level crossings. Kindly do something in the matter.

Then I come to the suggestion for a road over-bridge in Dindigul, which is a headquarter, next to Madurai, one of the biggest towns in Tamil Nadu. When we wrote to the Railway Board, they gave a positive reply that they are ready to bear 50 per cent, provided the State Government bear 50 per cent of the cost. When I wrote to the State Government in the matter, they did not reply to me. It is the custom and convention of the Tamil Nadu Government not to reply to the letters of MPs, MLAs or other representatives of the people. Since we have no way of solving this problem, I would demand that it is high time a directive is given to the State Government to construct all those over-bridges in Tamil Nadu. You should also appoint gate-keepers at every unmanned level crossing to avoid accidents.

In the ICF there are 14,000 employees and they are manufacturing 750 coaches every year, earning a foreign exchange of Rs. 35 crores. It is one of your units which is doing highly profitable business. Therefore, I would suggest that more money should be allotted to them to manufacture more coaches so that we can export more and earn more foreign exchange.

Now there is only one train which is going to Rameswaram. It is being apprehended that it is likely to be stopped. There is a fear that the railways are going to stop this train. I would request the Railway Minister not to stop it, because this is the only train which is going to Rameswaram. Sir, you know the importance of Ramayana and Rameswaram.

SHRI KEDAR PANDAY: Has that train been stopped?

SHRI K. MAYATHEVAR: The railways are considering a proposal to stop it. It should not be stopped.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Since that is the only train going to Rameswaram the Railway Minister will not stop it.

SHRI K. MAYATHEVAR: Now the Tamil Nadu Express runs only thrice a week both ways. It has been the unanimous demand of the MPs and the people of Tamil Nadu that it should be made daily to meet the very great demand. Similarly, KK Express should also be made daily.

Then, the name of the Grant Trunk Express should be changed into "Bharathi Express." After all, it will not entail any expenditure. It should be done to respect the "Revolutionary National Poet."

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the name of Subramaniam Bharathi from Tamil Nadu.

SHRI K. MAYATHEVAR: Bharatiyar is a national poet. His poems have been translated into all the languages.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the name you want? Bharathi Express?

SHRI K. MAYATHEVAR: Yes, "Bharathi Express."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Our Minister knows that he is a national leader.

SHRI K. MAYATHEVAR: I support the budget. I welcome the budget and I congratulate the Minister for the efficient implementation of various proposals. At the same time, I would say that he should do more for the people of Tamil Nadu as done to the people of other States.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Krishna Pratap Singh may now speak. I very much request that every hon. Member may take 5 minutes. We will have to adjourn the House at least at 8 o'clock.

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं — 4–5 घण्टे इन्तजार के बाद आप ने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया। ठीक इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, हम को एम० ई० रेलवे में चढ़ने के लिए इन्तजार करना पड़ता है। कभी भी स्टेशन जाने पर गाड़ी समय से नहीं मिली। परन्तु इस बात के लिए मुझे खुशी है —मैं इस बात के लिए रेल मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं — कि बाराबंकी, लखनऊ से ले कर सोनपुर तक आप ने उस लाइन के मान-परिवर्तन का काम तेजी से कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस से मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, उत्तर बिहार के रहने वाले सभी लोग आप को हृदय से धन्यवाद देते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उस लाइन का मान-परिवर्तन हो जाने के बाद हरी झण्डी दिखा कर आप हमें दिल्ली से ले कर समस्तीपुर तक बड़ी लाइन की गाड़ी में चढ़ने का अवसर देने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे के सम्बन्ध में काफी अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं। मैं नहीं समझता हूं कि उन सुझावों के बाद कोई विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है या कोई विशेष सुझाव देने की आवश्यकता है। लेकिन मैं दो बातों की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे भी माननीय मंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। व बिहार राज्य के मुख्य मंत्री थे, उस समय विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपनी कार्यक्षमता और दक्षता से जिस काम को अपने हाथ में लेंगे निश्चित रूप से उस को पूरा करेंगे। उस समय, उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में परीक्षायें बहुत भारी चिन्ता का विषय थीं, उन में काफ़ी अनियमिततायें होती थीं, लेकिन आप के आने के बाद उन पर ऐसा नियन्त्रण हुआ कि आज तक बिहार के लोग मंत्री जी का नाम याद करते हैं। उसी तरह से मेरा आप से अनुरोध है कि आप रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कीजिए। भारतीय रेलें एक ऐसी संस्था है जिस पर हमारे भारतवर्ष की पूरी इकानामी आधारित है, निर्भर करती है। हमारी इकानामी तभी सुदृढ़ हो सकती है जब रेलों की कार्य-क्षमता बढ़े, दक्षता बढ़े, इस में विकास हो।

इसी सन्दर्भ में मैं दो बातों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक—मैटीरियल मैनेजमेण्ट और दूसरा—परसोनल मैनेजमेण्ट। आप जानते हैं—रेलवे कितनी भारी मात्रा में सामान खरीदता और निर्माण करता है, लेकिन क्या उस का हम सही-सही उपयोग कर पाते हैं। जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है उस को समय पर पहुंचा पाते हैं? नहीं पहुंचा पाते हैं। आज हम बार-बार कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं लेकिन जितने साधन हैं उन का उपयोग हम किस हद तक कर पाते हैं? इसलिए सब से जरूरी बात यह है कि आप मैटीरियल मैनेजमेण्ट की तरफ़ ध्यान दें।

मेरा दूसरा सुझाव —मैन मैनेजमेण्ट के बारे में है। आप ने कहा है कि इस समय रेलवे में 17 लाख लोग काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस देश में किसी संस्था में इतने लोग काम करते होंगे। आप के बजट भाषण में मैंने देखा कि आप ने उनकी सुविधाओं के लिए, मनोरंजन के

लिये, खेल के लिए, चिकित्सा के लिए भारी रक़म की व्यवस्था की है । लेकिन इस के बावजूद भी क्या कारण है कि हमारे कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है ? हमें इस की गहराई तक जाना होगा । मात्र पैसा बढ़ा देने से, चिकित्सा और मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा देने से, मैं नहीं समझता हूं कि उन की कार्यक्षमता में कोई परिवर्तन आयेगा । जब तक रेल कर्मचारियों को एक-सूत्र में नहीं बांधेंगे, वे जिस अन्तर को महसूस करते हैं—छोटा कर्मचारी और बड़ा कर्मचारी, बड़ा अधिकारी और छोटा अधिकारी— जब तक इस भावना को नहीं मिटायेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि हम मैन-मैनेजमेण्ट कर पायेंगे तथा जो हमारे 17 लाख कर्मचारी हैं उन की शक्ति का भरपूर उपयोग कर पायेंगे—रेलों के चलाने में, माल के ढोने में । इसलिए मैं यह मांग मंत्री महोदय से करूंगा कि आप मैन-मैनेजमेंट के लिए इस तरह की व्यवस्था करें । केवल कुछ अफ़सरों का तबादला कर देने से या कुछ परिवर्तन कर देने से काम नहीं चलने वाला है जब तक कि ऊपर से नीचे तक आप इस में सुधार नहीं लाते हैं और मैं जानता हूं और मुझे भरोसा है कि आप इस काम को कर के दिखायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं कुछ बातें अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा । मेरा हैडक्वार्टर महाराजगंज है, जो कि एन० ई० रेलवे पर पड़ता है । आप मान-परिवर्तन करने जा रहे हैं मीटर गेज से ब्राड गेज में लेकिन यह 4 किलोमीटर का टुकड़ा है । महाराजगंज एक बहुत पुराना बाजार है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है । इस के मान-परिवर्तन का प्रस्ताव भी आया था और आप ने भी इस के परिवर्तन का निश्चय किया था । मैंने एक पत्र भी पंडित जी को इस के बारे में लिखा था कि इस का मान-परिवर्तन होना चाहिए । उन्होंने जवाब दिया था कि इस के निर्देश दे दिए गये हैं कि बाराबंकी से ले कर सोनपुर तक मान-परिवर्तन किया जाए । मेरा कहना यह है कि आप दारोदा से महाराजगंज तक मान-परिवर्तन करा दीजिए । सुनने में यह आया है कि यह कहा जा रहा है कि यह अनएकोनोमीकल है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो गाड़ी है, वह ठीक समय से नहीं चलती है । अगर समय से माल नहीं पहुंचेगा, तो फिर इस गाड़ी का उपयोग क्या रहेगा । मेरा यह दावा है कि जो गाड़ी चलती थी, उस का समय ठीक नहीं था और इस वजह से जो गाड़ी से आने-जाने वाले लोग हैं, वे भी उस से नहीं जाते थे । आज भी वह रेल लाइन है और आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश रीजीम से वह रेलवे लाइन है और हमारी मांग यह है कि उस का मान-परिवर्तन मंत्री महोदय करवाएं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री सत्य देव सिंह ने छपरा और सीवान पर ओवर ब्रिज के लिए कहा है । ये दोनों जिले संयोग से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं । दोनों जिलों के बीच से एन० ई० रेलवे जाती है और उस पर ओवरब्रिज बनाने के लिए कई बार कहा जा चुका है । मैंने इस के बारे में एक प्रश्न भी किया था और मुझे यह एसोरेंस दिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर पार्टीसिपेशन हो, तो ओवरब्रिज बना देंगे ।

श्री कहार पाण्डेय : इस में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ़ से अगर प्रस्ताव आए, तो उस को बनाने में हमें कोई कठिनाई नहीं है । पैसे की कमी इस के लिए नहीं है ।

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस को बनवा दें ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : ठीक है, इस के लिए हम प्रयास करेंगे राज्य सरकार से। अब जो मानपरिवर्तन आप करने जा रहे हैं और जो रेलवे की मीटर गेज की लाइन है, आप वहां से कहां ले जाएंगे, उस का उपयोग कहां करेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप ने ठीक कहा है कि मीटरगेज अनुपयोगी नहीं है। इस का भी उपयोग किया जा सकता है। इस के लिए मैं यह आग्रह करूंगा कि आप जो मीटर गेज से ब्रोड गेज में परिवर्तन करेंगे, तो मीटर गेज की जो पटरी है, उसका उपयोग नजदीक में कीजिए। इसी संदर्भ में एक निवेदन और करना चाहूंगा और मैंने इस बारे में पत्र भी लिखा है कि महाराजगंज से मसरिख तक जो लाइन है, इसका विस्तार किया जाए और मीटर गेज की लाइन, जो छपरा से गोरखपुर जाती है और वहां शूगर फैक्टरी है, उससे इस को अगर आप कनेक्ट कर देंगे, तो हम समझते हैं कि यह उपयोगी हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं पुन: निवेदन करता हूं कि बाराबंकी से जो सोनपुर तक ब्रोड गेज बनाने की बात आप कर रहे हैं और सीतारामपुर, पटना और मुगलसराय में जो विद्युतीकरण करने का काम आप ने हाथ में लिया है, इस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

आप ने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं और पुन: मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, कई घंटे बैठने के बाद आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

रेल बजट में द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए जो वृद्धि की गई है उसका मैं विरोध करता हूं और अपील करता हूं कि उसके भाड़े में वृद्धि नहीं की जाए। आशा है इस पर मंत्री जी सोचेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने रेलवे में प्रबन्ध को सुधारने के विषय में काम तो जरूर किया है लेकिन जितना काम किया है उससे रेलवे के आम वर्कर्स में यह प्रेरणा पैदा नहीं हो रही है कि रेलवे राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उसके विकास में उनका भी योगदान होना चाहिए। लोकोमेंस ने अपनी हड़ताल तो वापस ले ली है लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। उनकी मांगें पूरी करने की दिशा में भी मंत्री जी काम करें। मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि उनके साथ बदले की भावना से काम नहीं लिया जाए।

बाराबंकी, गोरखपुर, छपरा, सोनपुर को बड़ी लाइन में कंवर्ट करने में लगे हुए साढ़े सत्तरह हजार कर्मचारियों ने गोरखपुर में प्रदर्शन किया था। मंत्री जी उनकी मांगों पर ध्यान दें। उनकी मांगों के बारे में मैंने आपसे भेंट भी की थी और आपने आश्वासन दिया था कि आप उनकी मांगों को हल करेंगे। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा।

मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद दूंगा कि लगातार 1967 से 1980 तक मैंने जबर्दस्ती रेल बजट पर बोल कर और सभापति जी से विशेष आज्ञा मांग कर यह मांग की है कि मुजफ्फरपुर से बड़ी लाइन नरकटियागंज तक जाए। आपने इस बजट में उसके सर्वेक्षण का प्रावधान किया इस से मेरा पुराना चला आ रहा स्वप्न साकार हुआ। लेकिन आगे के लिए भी मेरी मांग थी और वह मांग भी मैं उसी समय से कर रहा हूं कि एक ब्रांच

लाइन खोली जाये जो हाजीपुर से बेतिया तक जाए जिसका हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, साहबगंज, केसरिया, अरेराज, पहाड़पुर, हरसिद्धि, नौतन मार्ग हो। यह हमारे ही जिले की मांग नहीं है और न ही हमारे क्षेत्र की ही मांग है। इसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण भी पड़ते हैं यानी पूरा गण्डक कमान एरिया पड़ता है। आपके लिहाज से भी वहां रेलवे लाइन बनाने में आपको कोई घाटा नहीं होगा क्योंकि लालगंज, हाजीपुर और केसरिया व्यापार के केन्द्र हैं जो कि इस लाइन से सम्बन्धित होते हैं। साथ ही हिन्दुस्तान में प्रथम रिपब्लिक अर्थात् प्रथम जनतंत्र की राजधानी वैशाली जो कि बौद्ध और जैन काल में रही है, वह भी उपेक्षित पड़ा हुआ है। वह भी इस से सम्बन्धित है। आप धर्म पर विश्वास करने वाले हैं। वहां के अरेराज के महादेव के स्थान पर जाने के लिए यात्रियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है, वह भी इस लाइन से सम्बन्धित है। इसलिए इस लाइन पर ध्यान दीजिए और इसका सर्वेक्षण कराइये।

मेरी आपसे दूसरी मांग है कि मोतीहारी, बेतिया, सोन, नरकटियागंज पर इन क्षेत्रों के लिए जयन्ती जनता में कोटा बढ़ाइये। अभी तक कोटा नहीं है। इससे जयन्ती जनता में जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो सकेगी।

मेरी तीसरी मांग है जिसके लिए आपको बार-बार लिखा भी है कि मुजफ्फरपुर से असाम मेल में जो बोगी जोड़ी जाती है उस बोगी की अवस्था बहुत बुरी है उसको ठीक किया जाए। न उसमें पानी, न पाखाने की, न लाईट की, न पंखे की व्यवस्था रहती है। उसका फाटक भी बहुत खराब रहता है और न उसकी कोई वास्ता करने वाला होता है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए और जो बोगी जोड़ी जाए वह सही बोगी हो।

मेरी चौथी मांग है कि छितौनी पुल के निर्माण में शीघ्रता लाई जाए जिससे चम्पारण और उत्तर प्रदेश का सीधा रेलवे सम्बन्ध हो सके।

मेरी पांचवीं मांग है कि जयन्ती जनता को सप्ताह मे तीन बार चलाया जाए।

मेरी छठी मांग है कि मोतीहारी में ओवरब्रिज बनाना नितांत आवश्यक है। उसका निर्माण कराइये। मेहसी स्टेशन पर रेलवे शेड बनाने की भी परम आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अन्तिम मांग है कि पटना में रोड कम रेल ब्रिज बनाया जाए। यह अकेले उस क्षेत्र की मांग ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की मांग है। इस मांग को पूर्ण किया जाए। इस प्रकार मोतीहारी स्टेशन को पूर्ण स्टेशन बनाया जाए, इससे पूरे चंपारण को लाभ होगा। इससे पूरे चंपारण क्षेत्र की आशाएं पूर्ण होंगी और पूरे चंपारण में आपका यश फैलेगा।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are about 8 Hon. Members to speak. I would like that every one of you should speak because this is an important Railway Budget. I would only suggest that every Hon. Member shall put forth the problems of his Constituency, the main points, so that the Minister may note them and he will reply to them. Therefore, I will give three minutes to each Member to make his speech and only the problems of his Constituency should be put forth.

[Mr. Deputy Speaker]

Please help me. Now, I will call Mr. Rawat. I will call everybody. I do things in an All India manner.

SHRI ERA ANBARASU (Chengalpattu): I want to fulfil my responsibility by voicing the sentiments of the people of Tamilnadu.

I would like to mention here that my Hon. friend Mr. Harish Rawat is not taking part in the discussion. Therefore, I would request that I may be allowed to take some more time.

I rise to stand here to support the Railway Budget. It is very commendable in many respects. However, I have to say that the Railway Minister resorted to additional freights and fares. Instead, the Railway Minister should have concentrated more on keeping the existing railway fare. It is very easy to present a deficit Budget, keeping the fare as it is and claiming credit, as was done by the former Railway Minister.

But here we should appreciate the fact that the Hon. Railway Minister has also admitted that 30 per cent of the wagons remained sick. We should also appreciate the assurance given by the Hon. Minister that proper steps are being taken to improve their condition.

I was rather surprised and astonished when the Railway Minister read out that there was no project for Tamilnadu. No suggestion or setting up any new project, any new railway line, has been made. There was no provision in the Budget. This august House will be surprised to know that after independence, no new project, no new railway line, was laid in Tamilnadu. Even during the last session, I raised a query about double track from Tambaram to Chingleput. I was given to understand that the plan had been approved and execution of the project would be taken up. I was assured that it would be taken up shortly. But, when I saw the Railway Budget, I did not find any provision in the Budget! And, therefore, I insist that this line from Tambaram to Chingleput should be laid.

For the path leading from Mahabalipuram to Kalpakkam, a new track should be taken up immediately in this Budget itself. It is very important because nearly 50,000 season ticket-holders are travelling from Chingalpattu to Tambaram apart from the other railway passengers. Bridges have been already constructed. No acquisition of land is involved or there is any other complicated procedure for having this double railway track from Tambaram to Chingalpattu. Therefore, I request the Hon. Minister to take up the execution of this project immediately.

The U.P. hills is also a neglected area. Nearly 8 districts in U.P.—I am speaking on behalf of my friend Shri Rawat as he is not likely to take part in the discussion—have no railway line at all. It is surprising how nearly 35 lakhs of people are left uncovered by Railway net-work and neglected without transport facility! If these two new lines namely, Tanakupur Ghat-Bageswar and Ramnagar Via Bhikisen Chaukhutia are taken up, they will cater to the needs of 35 lakhs of people. Hence, I demand the Hon. Railway Minister to concentrate more on these new railway lines.

I like to refrain from speaking on the frequent occurrence of accidents on railways. I suggest that the administration should be toned up effectively. Sir, the hon. Minister is aware of the serious accident that took place recently at Vaniyambadi. The unfortunate passengers who met with this catastrophe could not get any medical aid for a long time. They have to wait for hours together. Some medical cell from Madras or from Vellore had to arrive there to attend to these injured persons. What I suggest is this. In every region there should be an accident cell or emergency cell. If the distance between one station and another station is far away then, in between, there should be one medical cell which should be set up to attend

to this emergency work. I have personally visited the Integral Coach Factory at Madras. I have gone to Arkonam. I have visited the workshop there. I have visited the Carriage Works at Madras. The miserable condition of the workers there is really pitiable. The workers who are working near the fire-spot are not being provided with any proper or special or fire-proof dress. They are not being given any special allowance or any such thing. Their condition is really horrible. They have to work for long hours. Therefore, I request the Minister to take some special interest in providing them with extra benefits.

Then, my next point is this. Flood advance is being given in the Southern Railway only to those people who are residing in Madras city limits. It is not given to those who are residing outside the city limits. I made a representation also to the General Manager about it. I request the hon. Minister to look into it. I request him to see that this flood advance is given to those people who are working in Madras Railway units outside the city limits if the loss incurred by them is actually *bonafide*. This is my request to the hon. Minister and I request him to consider this suggestion with sympathy because they are also equally affected.

Then, Sir, I wish to say a word about bonus. Bonus is being given only to the employees. It is not being given to the officers, those who are working in the production units. I wish to submit that this is utterly unfair. Production is being maintained by these officials who are working in these units. They should be granted Bonus just like other workers. So, I request the hon. Minister to consider this point.

When I visited the ICF Madras I found how enormous things were being wasted there. I want to know what is the pricing policy followed by the Railway Ministry. I understand reliably that the overhead charges are very much more than what they should really be or what is justified. That is why the cost of a coach is enormous. It is quite unreasonable. Therefore I request the Minister that he should try to reduce the overhead charges and thereby reduce the cost of production of railway wagons. In this way we will be able to earn more of foreign exchange also by selling these wagons to foreign countries at a cheaper rate. So, he should evolve a new pricing policy in this respect.

Now, coming to the question of labour unions in the Railways, Sir, there are already two recognised unions in the Southern Railways and recently about 5 splinter groups forming themselves as unions have sprung up in Madras. All these splinter group unions have come together and merged as one single Union named as Southern Railway Employees' Congress. This Union is committed to the smooth administration of the railways, committed to the welfare of the people and committed to the welfare of railway workers. There are nearly a lakh of members who have enrolled themselves as Union members. But this Union has not been recognised so far. You have given recognition to the Union headed by Mr. George Fernandes who is always instigating the labour to resort to violence and all sorts of unlawful activities. Recently in a meeting he told the workers that if they struck work for 21 days, the whole country would be paralysed and the entire economy of the country would come to a standstill. Does it behove of a leader to utter such things which cut across the very root of the Indian economy? I would like to ask whether you want to encourage such leaders who act against the interests of the country. Democracy does not mean that there is freedom to instigate people to indulge in nefarious activities. I would therefore request the hon. Minister that he should evolve a rule for all these unions. If any union indulges in such unlawful activities, recognition to that Union should be withdrawn immediately. Of course, the *bona fide* demands of the union can be considered favourably. The hon. Minister is aware that in 1974, the country faced a difficult situation on account of the strike by the railway wor-

[Shri Era Anbarasu]

kers. To avoid recurrence of such a situation, recognition to various unions should be reviewed. Therefore, I would request that recognition to union headed by Shri George Fernandes should be withdrawn immediately and the recently formed union called the Southern Railway Employees' Congress should be given recognition forthwith.

Sir, I understand that in the Railway stations and platforms licence for selling some eatables and drinks by the poor venders is being withdrawn and in their place contractors will sell those things in the railway stations and platforms. There are now about 25,000 poor vendors who are engaged in this small and petty business and they are earning their livelihood. If they are being replaced by the contractors, only the rich people will take over this busines and these poor people will be thrown out of their job. Therefore, I would request that the present arrangement may be continued so that the poor vendors would be able to earn their livelihood in this small and petty business.

In this connection, I would submit that the quality of the food stuff supplied in the long-distance trains should be improved. The quality of food supplied in the Tamil Nadu Express and the G.T. Express is very very poor. I do not know why proper action has not been taken against those who are responsible for supplying such a poor quality of food in these trains. I understand that the same contractor for the supply of food in these trains has been continuing for the last so many years and that is why the quality of food supplied by him has become very poor. My suggestion is that for every two or three years, the contractor should be changed. The same contractor should not be allowed to continue the supply the foodstuff. Otherwise what they do is that they would try to satisfy the bureaucrats by some way or the other in order to cling themselves on to this business and thus they will continue unperturbed to supply very poor quality of food. Therefore, to improve the quality of food supplied in the trains, there should be a change effected in the contract once in two or three years.

Sir, I support my friend's suggestion for calling the G.T. Express as Bharati Express. The G.T. Express should be named as Bharati Express. Sir, as you know very well, the Tamil Nadu Express has been running to capacity since its introduction. At present, this train is running between Delhi and Madras thrice in a week. I would request the hon. Minister kindly to consider running this train daily so that the travelling public need not wait for many days to get their seats in the Tamil Nadu Express.

With these words, I support the Railway Budget and I congratulate the hon. Railway Minister for that. I do not know whether he will consider my suggestions or not. In spite of that, it was my duty to bring to his notice the various suggestions that I wanted to make. I congratulate him once again for having presented such a good budget.

20 hrs.

श्री तरेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय मैं पहले आपको ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर से ही सही, लेकिन आपने मुझे समय दिया है, मैं अपनी बात को जल्दी ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा क्योंकि जैसी मुझे व्यग्रता थी, वैसी हमारे मित्रों को भी होगी।

मैं सर्वप्रथम इस रेल बजट पर, जो हमारे रेल मंत्री श्री पांडे जी ने प्रेजेण्ट किया है, उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने रेल बजट बहुत अच्छा प्रेजेण्ट किया है। जब से उन्होंने रेल मंत्रालय का प्रभार लिया है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि रेलवे के काम में काफी प्रगति है और सुधार हो रहा है।

रेल मंत्री ने जो अपना भाषण दिया है, जो बजट में समावेश किया है, उससे ऐसा लगता है कि उनका ध्यान रेल के हर विभाग की ओर गया है, वह हर चीज में सुधार करने के लिए प्रयत्न शील हैं। बजट और उनकी स्पीच के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की ओर उनका ध्यान है और उन्होंने पूरी मजबूती से काम करना शुरू किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, वह एक कर्मठ और एफीशियेन्सी क्रिएट करने की मैंटेलिटी के व्यक्ति हैं। मैं अपनी और से पांडे जी को धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही जो रेलवे के प्रशासन में गोलमाल करने वाले लोग हैं, वह आपके सामने सदन में कुछ बोलते हैं और बाहर जा कर गोलमाल कराते हैं। पांडेय जी ने इस बारे में जो सख्त रास्ते का अवलम्बन किया है, इसका भी मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और आश्वासन देता हूं कि हमारा उनको सहयोग प्राप्त होगा

इन चन्द शब्दों के साथ मैं 2, 4 सुझाव भी देना चाहता हूं।

एक तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा है कि रेलवे के एम्पलाईज की हाउसिंग की प्रावलम है, मैं चाहता हूं कि उनको रिपीट न करूं। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस बात को सदन के सामने रखा है। इह हाउसिंग की प्रायलम को सौल्व करने के लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी का ध्यान है और इस बारे में जो उन को फाइनेन्शियल डिफीकल्टीज हैं, उनको दूर करने के लिए वह को-आपरेटिव बनाना चाहते हैं। को-आपरेटिव्ज के सिद्धान्त में ये विश्वास करते हैं। मैं चाहूंगा कि को-आपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर के हाउसिंगकी प्रावलम को हल करें,इसके लिए लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो बैंक से भी लोन मिल सकेगा।

इसके अलावा बड़ी-बड़ी बातें इस हाउस के सामने कही गई हैं। एक तरफ विरोध-पक्ष के भाई कटु आलोचना करते हैं किराये और माल-भाड़े में वृद्धि की और दूसरी तरफ वहीं इस बात की चर्चा करते हैं कि रेलवे के एम्प्लाईज जो कि लगभग 17 लाख और ढाई लाख कैजुअल हैं, लगभग 20 लाख लोग हैं वह इससे वेतन पाते हैं और 20 लाख ही नहीं इससे भी बहुत ज्यादा संख्या है उन लोगों की जो भारत के जन-जीवन में रेलवे के काम से, दूसरे विजनेस से और दूसरे तरीकों से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। जब इसमें किराये की वृद्धि होती है तो वह एफीशियेन्सी की मांग करते हैं, चाहते हैं कि जो काम करने वाले हैं, उनको सुविधाएं बढ़ें, उनकी तनख्वाहें बढ़ें, बोनस ज्यादा मिले। जब रेलवे के बजट में नहीं देखते हैं कि वृद्धि हुई है तो कहते हैं कि यह बड़ा गलत बजट है, यह जनता का शोषण करने वाला बजट है। लेकिन उनकी आलोचना के बारे में मैं मानता हूं कि विरोधी पक्ष है, उनको विरोध में कुछ बोलना है, इसलिए बोलते हैं। रेल मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि सैकंड क्लास के किराये में जो वृद्धि हुई है, उस पर वह पुनर्विचार करें और उसमें जो कमी वह कर सकते हैं, वह करने की चेष्टा करें।

एक अत्यन्त आवश्यक विषय की ओर मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले बजट सत्र में भी मैंने अपने भाषण में इस बारे में कहा था। रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि आरा से सासाराम तक रेल लाइन बनेगी। सदन में सब सदस्यों ने कहा है कि यहां से वहां तक रेलवे लाइन बननी चाहिए, उनके क्षेत्र में बननी चाहिए, उनके राज्य में बननी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आरा-सासाराम रेलवे लाइन 1910–11 में ब्रिटिश साम्राज्य

[श्री सर्वेश्वर सिंह]

ने बनाई थी। आप यह जानकर चकित होंगे कि जनता पार्टी की सल्तनत ने 1978 में सौ किलोमीटर लम्बी उस रेलवे लाइन को बन्द कर दिया। कांग्रेस पार्टी की सल्तनत तो सबसिडी दे कर उस रेलवे को चलाती थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार और उसके मंत्री ने उसको केवल बन्द करने का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि उसकी सारी सम्पत्ति बेच देने का आदेश भी दिया। आज जनता की आंखों के सामने रेल की पटरियां बिक रही हैं, रेल के स्टेशन बिक रहे हैं और रेल की जमीन बिक रही है।

जिस इलाके के लोगों ने कभी रेलवे लाइन नहीं देखी है, उनकी मांग तो जरूरी है, लेकिन जिन लोगों की पांच जेनीरेशन्ज 78 साल तक रेलवे लाइन पर चढ़ती रहहैं, उन्हें उस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। इस रेलवे लाइन के बन्द होने से लगभग एक करोड़ लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में भी कहा है, पिछले बजट-सत्र में भी कहा गया, कि इस रेलवे लाइन का सरवे कराया जा रहा है। जब श्री जगजीवन राम रेल मंत्री थे, तब भी इसका सरवे कराया गया था। लेकिन अभी तक इस सरवे का काम नहीं हुआ है। मेरा आग्रह है—कनसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भी मैंने कहा था— कि सरवे का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये, ताकि उस क्षेत्र की जनता आश्वस्त हो कि उनके क्षेत्र में ब्राडगेज रेलवे लाइन बनने की तैयारी हो रही है।

मैं रेल मंत्री से कहना चाहता हूं कि सर्वेक्षण करने वाले लोग इकानोमिक वायेबिलिटी की बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री महोदय स्वयं इस मामले को देखें। हमारा केस दूसरे केसिज से बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहां के लोगों ने 78 बरसों से जिस रेलवे लाइन का प्रयोग किया है, जनता पार्टी के राज्य में उसको छीन लिया गया। हम चाहते हैं कि जनता पार्टी के राज्य में जिस रेलवे लाइन को छीन लिया गया था, उसको रेस्टोर किया जाये।

बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि दानापुर या पटना में एक रेलवे पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। वहां के लोगों को पहले कलकत्ता जाना पड़ता था। अब मुजफ्फरपुर में रेलवे का पब्लिक सर्विस कमीशन है। बिहार देश में यू0 पी0 के बाद दूसरी बड़ी स्टेट है। मैं चाहूंगा कि दानापुर में कमीशन की स्थापना की जाये।

हम बहुत दिनों से यह मांग करते आ रहे हैं कि आरा, सासाराम और डेरी-आन-सोन में रेलवे क्रासिंग्ज पर ओवरब्रिज बनाये जाये। इस बारे में कई बार जांच की जा चुकी है और सरकार की ओर बताया गया है कि इन्हें बनाया जायेगा। वहां ट्रेफ़िक काफ़ी है और गाड़ियां भी बहुत चलती हैं, इसलिए बहुत लोगों को असुविधा होती है। मैं मांग करता हूं कि वहां पर ओवरब्रिज बनाये जायें।

सोनभद्र एक्सप्रेस दिल्ली से एक ट्रेन चलती है। नाम तो बड़ा सुन्दर रख दिया गया। सोनभद्र बिहार की एक बड़ी इम्पार्टेंट नदी है। लेकिन आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि जहां से सोनभद्र बहती है वहां यह सोनभद्र एक्सप्रेस चलती रुकती नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि सोनभद्र एक्सप्रेस को सोनभद्र के किनारे आरा जो भोजपुर का मुख्यालय है, वहां अवश्य रुकवाइए।

कोआपरेटिव सेक्टर के अन्दर प्रोडक्शन-कम-डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो हमारी है उस से कन्ज्यूमर्स को काफी सहायता दी

जाती है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत बड़े पैमाने पर एन सी सी एफ, नेशनल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव फेडरेशन और नाफेड की ओर से मदद मिलती है । लेकिन रेलवे में उस को (सी) प्रायोरिटी दी जाती है सामान को ढोने में, चाहे वह फूड ग्रेन्स हों, चाहे फर्टिलाइजर्स हों या चाहे और कन्जम्पशन के आइटम्स हों । मैं आप से आग्रह करूंगा कि उस को (बी) प्रायरिटी दिलवाइए ताकि वह लोगों की सहायता और मजबूती के साथ कर सके ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Every body should get a chance to speak. Others should not be deprived of speaking. Everybody would like to say something on the Railway Budget. You can speak next year. You can send your points to the Railway Minister also. He belongs to your State. (*Interruptions*) That is what I am requesting him. You also make a request.

श्री तपेश्वर सिंह : एक बात और कह कर समाप्त कर रहा हूं । रक्सौल—बेतिया—बनियारपुर—नैनी—छपरा नई लाइन की जो मांग प्रोफेसर सत्यदेव सिंह ने की है उस का मैं समर्थन करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल मंत्री महोदय को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rameshwar Nikhra. You take only 3 minutes. We have to adjourn the House at 8-30 p.m. You have to co-operate. Other things you can give to Mr. Mallikarjun or to the Minister. It can be treated as if you have spoken here.

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि दस घण्टे के उपरान्त आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया है । एक मिनट एक घण्टे का दिया जाता तो भी दस मिनट होता । तब भी चार मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट संसद् में पेश किया है उस के लिए वह बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं । जहां एक ओर जनता पार्टी के शासन में रेलवे प्रशासन पूरी तरह से ठप्प हो चुका था, चारों ओर अराजकता का वातावरण था, पूरी रेलवे की आय समाप्त होती जा रही थी । उस व्यवस्था को फिर से बनाने और उस को आगे ले जाने का काम इस बजट के माध्यम से उन्होंने किया है । मैं बहुत थोड़े से शब्दों में अपने सुझाव देना चाहता हूं ।

भोपाल में उन्होंने रेल मंडल बनाने की घोषणा की है । इस घोषणा के कारण सरकार का करीब-करीब 60 करोड़ रुपया अनावश्यक रूप से खर्च हो जायगा । मैं भूतपूर्व रेल मंत्री महोदय से मिला था, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिला था और वर्तमान रेल मंत्री जी से भी मिला था और उनसे अनुरोध किया था कि भोपाल की जगह यह रेल मण्डल इटारसी में स्थापित किया जाय । इटारसी में स्थापित करने से निश्चित ही जो बहुत बड़ा खर्च इस पर होने वाला है उसमें बचत होगी । उसका कारण यह है कि इटारसी में मार्शलिंग यार्ड है करीब दस करोड़ का, डीजल का कारखाना दस करोड़ का है । वहां पर पचास एकड़ जमीन रेलवे की पड़ी हुई है । इन सारी बातों की व्यवस्था उन को भोपाल में करनी पड़ेगी जिस से रेलवे प्रशासन का करीब 50 करोड़ रुपया और खर्च होगा । मेरी उन से पुरजोर प्रार्थना है कि इसे इटारसी में स्थापित किया जाय । वह इस बात के औचित्य को स्वीकार करते हैं । उन्होंने मुझ से कहा था कि यह बात तो सही है । जब वह इस बात के औचित्य को स्वीकार करते हैं

[श्री रामेश्वर नीखार]

तो क्यों इटारसी में रेल मंडल की स्थापना नहीं की जा रही है ? मैं ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसी जगह रेल मंडल बनवा लेते हैं, जैसे मुगलसराय में बन गया, समस्तीपुर में बन गया, वहां पर अधिकारी लोग जाते नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक छोटी सी जिद के कारण यह अनावश्यक रूप से रेलवे पर 50 करोड़ रुपये का भार बढ़ रहा है ।

रेलवे के अन्दर कैंटीन की व्यवस्था हर ट्रेन में की जाती है, हर स्टेशन पर की जाती है तो उस ओर उन का ध्यान अवश्य ही जाना चाहिए । मुझे विश्वास है कि जितने डायनेमिक तरीके से और जितने जोरदार तरीके से उन्होंने रेलवे प्रशासन को सुधारने और उस को बढ़ाने की तैयारी की है, जो बात मैं बोल रहा हूं उस पर भी वह उसी तरीके से ध्यान देंगे । रेलवे कैण्टीन्स की व्यवस्था बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दी जाती हैं और वह ठेकेदार स्टेशन्स पर छोटे छोटे सामान बेचने वालों, मिठाई बेचने वालों, पुस्तक बेचने वालों, फल बेचने वालों और चाय बेचने वालों को सबलेट कर देते हैं और 50–50, सौ-सौ रुपया रोजाना उनसे वसूल करते हैं ; जब कि रेलवे प्रशासन से केवल 1200 रुपये में वे पूरी कैंटीन का ठेका ले लेते हैं । यही कारण है कि स्टेशन पर सामान भी महंगा मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है । जब बड़े ठेकेदार केण्टीन को सबलेट ही कर देते हैं तो मेरा सुझाव है कि रेलवे प्रशासन इसका अध्ययन कराकर समस्त स्टेशन पर उन बड़े ठेकेदारों को ठेका न देकर डायरेक्टली पान वाले, फल वाले, पुस्तक वाले, मिठाई वाले जो हैं उन्हीं को ठेका दे दिया जाए । इस प्रकार से बेरोजगारी भी दूर होगी और रेलवे में कैन्टीन लेने में नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार होता है वह भी समाप्त हो जायेगा ।

इसी प्रकार से मेरा अनुरोध है कि छठी योजना में जो वैगन बनाने का कारखाना रेलवे द्वारा प्रस्तावित है उस के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होशंगाबाद का सोहागपुर नगर है क्योंकि वहां पर हजारों एकड़ जमीन उपलब्ध है, पानी की व्यवस्था है तथा लकड़ी भी वहां पर उत्पन्न होती है । यदि वहां पर रेलवे वैगन का कारखाना खोल दिया जाता है तो उस क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा क्योंकि वहां पर कोई एण्डस्ट्रियलाईजेशन नहीं है । वह देश के बीचों-बीच है, चारों तरफ वहां से रेल वैगन को भेजा जा सकता है । वह बहुत पिछड़ा एवं गरीब क्षेत्र है ।

इसी प्रकार से मैं कुछ और भी सुझाव देना चाहता हूं । हर प्रदेश की राजधानी से एक ट्रेन दिल्ली को जोड़ती है परन्तु अभी तक भोपाल के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है । मेरा सुझाव है कि भोपाल से 50 मील दूर इटारसी से एक ऐसी रेलगाड़ी नई दिल्ली के लिए चलाई जाए ।

इसी प्रकार से कुछ छोटी छोटी समस्यायें हैं जो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं । महानगरी एक्सप्रेस और गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो चलाई जाती हैं वह जबलपुर और इटारसी में तो रुकती हैं लेकिन बीच में जो बड़ी बड़ी अनाज मण्डियां हैं जैसे नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, पिरिया, सोहागपुर, सितनी मालवा—इन स्थानों पर इन गाड़ियों के न रुकने से लोगों को बड़ी परेशानी होती है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इन स्टेशन्स पर दोनों गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था की जाए ।

गाड़ियां जो लेट चलती हैं उसका एक कारण प्रशासनिक क्षमता का दोष भी हो सकता है परन्तु साथ ही साथ आर० एस० एस० के लोगों को जानबूझ कर बिठाया जाता है जो कि गाड़ियों की चेन खींचते हैं ताकि रेलवे प्रशासन बदनाम हो सके। ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी सेकड़ी कार्यवाही करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

इसी प्रकार से अभी हमारे जबलपुर डिवीजन में बीना इटारसी तक एक पैसेंजर चलती है उसको फास्ट पैसेंजर बना कर भोपाल तक बढ़ा दिया जाए । इससे जबलपुर से भोपाल तक के पैसेंजर्स को बहुत बड़ी सुविधा हो जायेगी । इसमें कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं करना पड़ेगा और कोई नई गाड़ी भी नहीं चलानी पड़ेगी ।

इसी तरह से एक सब से बड़ी समस्या जबलपुर से गोंदिया नैरो-गेज की है । इसका सर्वेक्षण हो चुका है । इसको जल्दी से जल्दी ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाए ।

सेण्ट्रल रेलवे का जो मेन आफिस है वह बाम्बे में है । उसके एक कोने में होने की वजह से यहां के लोगों को किसी प्रकार की नौकरी की सुविधा नहीं मिलती है। मेरा सुझाव है कि सेण्ट्रल रेलवे का आफिस जबलपुर में, जो कि देश के मध्य में है, स्थापित किया जाए जिससे कि हमारे यहां की प्रतिभाओं को स्थान मिल सके तथा रेलवे प्रशासन में भी सुधार आ सके ।

इन शब्दों के साथ ही मैं प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सुन्दर शर्मा (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनेक सुधार रेलवे बजट में प्रस्तावित हैं, उसके लिए तो मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं । लेकिन एक उलाहना देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश रेलवे बजट में कहीं नहीं है । कारण क्या है —यह समझ में नहीं आता है । अनेक विद्वानों ने यह कहा है कि अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है, तो आवागमन के साधन परमावश्यक हैं । मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े प्रान्त में जहां कि जंगल और पहाड़ बहुतयात से हैं, अगर वहां आवागमन की सुविधा न हो तो उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है । मध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में हैं कि यदि वहां पर आवागमन की सुविधा को ठीक कर दिया जाए तो उस क्षेत्र का विकास हो सकता है ।

जैसे अभी श्री निखरा जी ने कहा कि जबलपुर से गोंदिया, जो नैरो-गेज लाइन है, वह ऐसा इलाका है, जहां कोयले का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है । इस स्थान से अन्य क्षेत्रों में कोयला जाता है, बिजली के लिए, औजार बनाने के लिए और इस्पात कारखानों के लिए—लेकिन उस क्षेत्र में आज भी ब्रिटिश जमाने से नैरो-गेज लाइन ही है । इस सम्बन्ध में कई बार यहां प्रश्न उठाया गया, तो उत्तर दिया गया कि जांच हो रही है, लेकिन अभी तक यह निश्चय नहीं है कि जांच कहां तक हुई है और कहां तक नहीं हुई है । इसलिए राष्ट्रीय-हित में और विशेषकर उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए यह परमावश्यक है कि जबलपुर और गोंदिया लाइन, जो कि नैरो-गेज है, उसको ब्राड-गेज में परिवर्तित किया जाए— यह बहुत ही आवश्यक है ।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक नियम बना लेना चाहिए कि जितने भी जिले मुख्यालय हों, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हों, यह क्राइटेरिया बना कर चलना चाहिए कि उनको रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाएगा । अगर

[श्री सुन्दर शर्मा]

जिलों के मुख्यालय ही रेलवे लाइन से हीं जोड़े जायेंगे, तो जिलों की उन्नति कैसे हो सकती है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं, जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, जैसे सतना—रीवा—सीधी होते हुए मिर्जापुर चाहे वाराणसी से मिलाया जा सकता है। इसी तरह से भोपाल राजधानी को पटना राजधानी से मिलाने की भी बात है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत लोग भोपाल में काम करते हैं। मध्य प्रदेश में विशेषकर भोपाल को यदि पटना लाइन से मिला दिया जाता है, किसी भी रास्ते से ले जा कर, तो वह जनहित में होगा और उस क्षेत्र का भी विकास हो सकेगा।

इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश को दक्षिण से मिलाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, जो जबलपुर से त्रिवेन्द्रम या अहमदाबाद जाती हो। जैसा कि कहा जाता है कि वहां का मार्केट बहुत सस्ता है अन्य मार्केटों की अपेक्षा, यदि इसको जोड़ दिया जाएगा तो न केवल आवागमन की सुविधा होगी, बल्कि व्यापार में भी सहूलियत मिल सकती है। विशेष कर केरल और गुजरात के लोग, वहां पर अत्याधिक रहते हैं। वे लोग मांग करते हैं कि इस लाइन को जोड़ना परमावश्यक है।

अब मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। रेलवे महत्वपूर्ण विभाग समझकर ही इसको आम बजट से अलग रखा गया है—इसलिए वित्त मंत्रालय को भी और मंत्रिमंडल को भी रेलवे विभाग को अधिक से अधिक पैसा देना चाहिए, क्योंकि इसमें राष्ट्र की उन्नति सन्निहित है। इसके साथ ही साथ आमदनी बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जो इसमें चोरियां होती हैं, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत ही आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोयले की चोरी की तरफ अत्याधिक ध्यान देने की जरूरत है। न जाने हमारा कितना पैसा इसमें बर्बाद हो रहा है।

जनहित में रिजर्वेशन की जो प्रणाली है, उस में विशेष कर आम जनता को महान कष्ट हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि बम्बई अथवा अन्य स्थानों के चाट पर लिखा रहता है कि जगह 15—20 दिन पूर्व रिजर्वेशन के लिए, लेकिन कोई उस दिन भी जाता है, तो उसको कुछ पैसा खर्च करने पर रिजर्वेशन मिल जाता है। यह हमारे लिए भी रेलवे मंत्रालय तथा शासन के लिए और अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उधर भी अवश्य ध्यान देंगे। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, मैं आपको कल का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं —जब मैं भोपाल से जी० टी० एक्सप्रेस से चला, तो कुछ लड़के आ कर बैठ गए। उन्होंने मिलिटरी के डिब्बों में भी प्रवेश किया और उनसे झगड़ा कर लिया। मिलिटरी वालों को हमें अधिक से अधिक सुविधा देनी चाहिए। लड़कों ने झगड़ा ही नहीं किया, बल्कि वे महिलाओं के डिब्बों में भी घुस गए और महिलाओं के आभूषण छीन लिए, कान के टॉप्स उतार लिए। उनके कान से खून बहता हुआ देखा गया। केवल लड़के ही नहीं, बल्कि रेलवे के कर्मचारी प्रथम श्रेणी में बैठ जाते हैं, पुलिस के भी कान्स्टेबिल बैठ जाते हैं, फर्स्टक्लास के डिब्बों में और कहने से उतरते नहीं हैं। कुछ गुण्डे और बदमाश लोग चढ़ आये थे। लेकिन जो लोग पैसा दे कर आप की रेलों में चढ़ते हैं उन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप की है, उन को अधिक से अधिक सहूलियत मिल सके, इस की तरफ आप को ध्यान देना चाहिए।

बहुत से क्षतिग्रस्त डिब्बे आप की रेलों में चल रहे हैं। जब आप जनता से किराया लेते हैं तो आप को यह भी देखना चाहिए कि ठीक डिब्बे गाड़ियों में लगाये जायं।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि गाड़ियां समय पर चलाई जायं। आप ने भी इस बात का उल्लेख किया है और मैं भी इस का समर्थन करता हूं। आप चाहें जो उपाय करें—रेल कर्मचारियों को इस काम के लिए पुरस्कार दें या दण्डित करें, लेकिन गाड़ियों के समय पर चलाने की व्यवस्था करें, इस से आप बहुत ज्यादा प्रशंसा के पात्र होंगे और जनता को भी इस में बहुत सहूलियत मिलेगी।

मैं भी यही कहूंगा—यदि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को रेल भाड़े में आप कुछ राहत दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। हम लोग जो इधर बैठते हैं उनको देखने में, उपाध्यक्ष जी, आप को थोड़ा कष्ट होता है, मंत्रियों की भी पीठ हमारी ओर होती है, फिर भी आप ने हमारी तरफ़ देख लिया और हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप को धन्यवाद।

श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के हित में टनकपुर-घाट-बागेश्वर तथा रामनगर-भीखियासेन-चौखटिया—इन दो लाइनों के निर्माण का कुछ प्रबन्ध कर दें। इस वर्ष यदि यह काम नहीं हो सकता है तो कम से कम उस के सर्वेक्षण की घोषणा अवश्य कर दें।

दूसरी बात—लखनऊ से काठगोदाम के लिए इस समय एक गाड़ी चलती है, यदि वहां दो गाड़ियों की व्यवस्था हो जायं तो उससे बहुत सहूलियत हो जायगी। उस लाइन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस लिए इस तरह की व्यवस्था की तुरन्त जरूरत है।

टनकपुर से पीलीभीत तक के लिए नैनीताल एक्सप्रेस में जो बोगी लगती है उस में पिथौरागढ़ जिले के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन एक बोगी बिल्कुल अपर्याप्त है, कम से कम दो बोगियां लगाई जायं। इस में एक तो थ्री-टायर की व्यवस्था कर दीजिए, दूसरे—4 बर्थ का फर्स्ट-क्लास का कूपे लगवा दीजिए। इस से उस जनपद के लोगों को बहुत लाभ होगा। उस के आरक्षण की व्यवस्था पिथौरागढ़ में एक आउट-एजेन्सी खोल कर करवा दीजिए, साथ ही अल्मोड़ा में भी उस की व्यवस्था करा दीजिए।

बरेली से काठगोदाम तथा मुरादाबाद से रामनगर को बड़ी लाइन में बदलने की घोषणा आप ने की है इस के लिए बहुत धन्यवाद। कृपा कर इस काम को जल्दी करवा दीजिए।

श्री भोला राउत (बगहा) : उपाध्यक्ष जी, आपने भले ही थोड़े समय के लिए मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मैं इस के लिए आप का आभारी हूं। मैं रेलवे बजट को अपना समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं साथ ही मैं कुछ जरूरी सुझाव नट-शेल में आप के सामने रखूंगा। हमारे माननीय रेल मंत्री जी का क्षेत्र मेरे क्षेत्र से सटा हुआ है, इसलिये मुझे अपनी बातों को रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मंत्री जी उन को स्वयं भी जानते हैं।

मेरे क्षेत्र में 9 लाख आदमी रहते हैं, जिन में 6 लाख ऐसे हैं जिन को रेल सेवा से कोई फायदा नहीं है। वे ऐसी-ऐसी जगहों में रहते हैं जहां से 20-30 किलो-मीटर आने पर ही उन को स्टेशन नजर

[श्री भोला राउत]

आता है और बड़ी मुश्किल से वे गाड़ी पकड़ते हैं। हमारा क्षेत्र ऐसा है जिस के एक तरफ़ यू० पी० बॉडर है और दूसरी तरफ नैपाल की तराई का इलाका है। इस क्षेत्र में बीकर सेक्शन के लोग ज्यादा रहते हैं। आज सरकार की यह नीति है कि बीकर सैक्शन और पिछड़े वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाय। माननीय मंत्री जी का जहां घर है—रामनगर क्षेत्र में, उस रामनगर क्षेत्र में ही—वह जानते हैं—"दोन" इलाका ऐसा है जहां सब पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वहां बस भी नहीं जाती है। इसलिए मैंने मंत्री जी से कहा था कि बगहा से लेकर दोन साइड से डिगनाठोरी तक लाइन दे दें, ताकि बीकर सेक्शन्स के लोग, कमजोर वर्ग के लोग उस साइड में जा सकें। दूसरी तरफ़ खासकर पांडे जी जिस कांस्टीटुयेन्सी से अभी चुने गये हैं और जहां से वे 15 वर्ष तक एसेम्बली के मेम्बर थे, नोतन-बोरिया में एक इंच भी रेलवे लाइन का दर्शन नहीं है। वहां के लोगों को 15–20 किलोमीटर चल कर बेतिया स्टेशन जा कर गाड़ी पकड़नी पड़ती है। मधुकर जी ने ठीक ही कहा है कि हाजीपुर से एक रेलवे लाइन लाल गंज, नोतन-बेरिया, नवलपुर बाजार, पतिलाड़ होते हुए बगहा तक मिला दी जाए। इस से हमारा जो बेकवर्ड एरिया है, वह कवर हो जाता है और पांडे जी का क्षेत्र जो है, वहां के लोग भी परेशानी महसूस करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि वहां पर रेलवे लाइन होनी चाहिए। मुझे हैरत इस बात की है कि रेल बजट जो पेश किया गया है, उस में मंत्री जी ने कोई गुंजाइश उस लाइन के लिए अभी भी नहीं रखी है और मैं यह चाहूंगा कि कभी कोई और मौका आवे, तो उस क्षेत्र के लिए लाइन के बारे में मंत्री जी विचार करें।

अब मैं छतौनी ब्रिज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज से पांच वर्ष पहले हमारी लीडर माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस का फ़ाउण्डेशन ले किया था और जनता पार्टी के रीजीम में उस का सर्वे भी हो गया था और जो थोड़े गार्डर उस समय गिराए गए थे वे भी अब खत्म हो हो गये हैं। पांडे जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि उस को बनाया जाएगा लेकिन मैं समझता हूं कि अब तक प्रत्यक्ष रूप से उस का काम नहीं लगा है। सिर्फ सर्वे हुआ है और देखने के लिए कुछ बोर्डर हैं लेकिन प्राथमिकता के साथ उस का काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसी रीजीम में उस ब्रिज को पूरा कर के स्वयं पांडे जी उस का उद्घाटन करें, तो बहुत बड़ा क्रेडिट उन को मिलेगा। इन्दिरा गांधी जी ने उस का फाउण्डेशन दिया है और इन को वाह-वाही मिल जाएगी लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि वहां जिस तरह से यह काम चलता है, उस से मालूम पड़ता है कि इस रीजीम में वह पूरा नहीं होगा। इसलिए इस तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

एक चीज के ऊपर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि क्लास 4 में जो एपाइण्टमेंट होता है, उसमें बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उस में कुछ छुआछूत तो दूर हुआ है लेकिन जो हरिजन मजदूर हैं वे इस तरह से छुआछूत से जकड़े हुए हैं कि सफ़ाई पेशा करने वाले हरिजन मजदूर चाहे मेट्रीकुलेट हों, वे अगर क्लास 4 में चले जाते हैं तो उन को सफ़ाई की ही नौकरी में लगाया जाता है, सफ़ाई पेशे में ही लगाया जाता है। कई जगहों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं। मैं अपने रेल मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर वे सफ़ाई पेशे में एक दफ़ा चले जाते

हैं, तो फिर जिन्दगी भर सफाई पेशे में ही रहते हैं और उन की तरक्की का कोई रास्ता नहीं है, किसी तरह की तरक्की उन के लिए नहीं है। इस तरह के 50 हजार आदमी रेलवे में हैं, जो सफ़ाई पेशे से सम्बन्धित कार्य में कार्यरत हैं और उन लोगों की जिन्दगी बिल्कुल डूम्ड हैं। उनकी तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। आज ही मैं ने एक चिट्ठी लिखी है कि 19 वर्ष से काम करने वाला सफ़ाई मजदूर जो मेट्रीकुलेट है, वह वहीं पर है। रेलवे में जो डिपार्टमेण्टल परीक्षा होती है, हर साल लोगों को कुछ मौका मिलता है प्रोमोशन के लिए बैठने के लिए लेकिन सफ़ाई मजदूर वर्ग को उस का मौका नहीं दिया जाता है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक डेपुटेशन पांडे जी से मिलने वाला है इसके मुताल्लिक और वह डेपुटेशन अपनी मांगें मेमोरेण्डम में रखेगा।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह एन० ई० रेलवे से सम्बन्धित है। एन० ई० रेलवे के लिए अगर कहा जाए कि वह निगलेक्टेड है और रिजेक्टेड है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां पर रेल गाड़ियों में कोई सुविधा नहीं है। काठ की पटरी बैठने के लिए है। न पंखा है, न बत्ती है और न बाथरूम की कोई सुविधा है और बरसात में वह चूता है। तो इस तरह की सब रेल गाड़ियां इकट्ठी कर के एन० ई० रेलवे में दे दी जाती है और उनमें कोई सुधार नहीं होता है। नयी रेल गाड़ियों का तो वहां दर्शन ही नहीं होता।

अधिकतर देखा जाता है कि दूसरी श्रेणी का भाड़ा बढ़ा दिया जाता है लेकिन उसके यात्रियों को सुविधाएं क्या दी जाती हैं। आप जरा पटना जंक्शन पर खड़े हो कर देखिए, वहां पर जितनी गाड़ियां आती-जाती हैं उन पर लोग छतों पर बैठे रहते हैं।

एक तरफ सरकार से आज्ञा की जाती है कि संसद् सदस्यों की अमेनिटीज को बढ़ाया जाए और दूसरी ओर रेल मंत्रालय ने जो हम लोगों को ए० सी० सेकिंड क्लास के टु-टायर में जाने की सुविधा दे रखी है उसके लिए रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने पांडे जी को सुझाव दिया है कि वह सुविधा हमें न दी जाए। यह हमारे हक पर कुठाराघात किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे हक को खत्म न किया जाए और हमारी यह सुविधा बरकरार रहे।

मैं पांडे जी को अन्त में कहूंगा कि कम से कम चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने इलाके में रेल लाइन का विस्तार करना चाहिए जिससे कि 6 लाख लोग जो बीकर सेक्शंस के वहां रहते हैं जिनको कि रेल लाइन की सुविधा नहीं है, उनको आने-जाने की सुविधा मिल जाए। वह लाइन हाजीपुर, लालगंज, नौतन होते हुए बगहा जा कर मिल जाए। इससे बहुत बड़ा एरिया वहां का कवर हो जाएगा।

आशा है मंत्री जी मेरी इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

श्री शान्तूभाई पटेल (साबरकंठा): मैं रेल बजट का स्वागत करते हुए रेल मंत्री जी को सुझाव दूंगा। रेल मंत्री जी ने, नडियाद-कपड़वंज मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने का और पकड़वंज से मोडासा को ब्राडगेज नई लाइन बनाने का जो काम दो साल से चलता है उस काम में 5–6 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है लेकिन अभी तक दो सालों में इन कामों पर एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है और इस साल के बजट में हमने देखा है कि सिर्फ दस लाख रुपये का प्राविजन किया गया है। इस बारे में मैं रेल मंत्री जी से विनती करता हूं कि इस ढंग से तो काम

[श्री शान्तूभाई पटेल]

बहुत सालों में भी पूरा न होगा। सौ किलोमीटर से ऊपर का काम है जिसमें कंवर्शन होना है और नई लाइन बनाने की मंजूरी की गई है। अगर इस ढंग से काम चलेगा तो मेरे ख्याल से 20–25 साल तक भी यह काम पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है कि इसके लिए ज्यादा रुपये का प्रोविजन किया जाए और जल्दी से जल्दी काम पूरा किया जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि इस काम के लिए जो लोहा और दूसरा मेटीरियल लाया गया था उसे दूसरी जगह पर ले जाया गया। गये साल के बजट में इस काम के लिए जितना प्रोविजन किया गया था वह पूरा पैसा इस काम पर खर्च नहीं हुआ। इस साल भी इस काम के लिए केवल दस लाख रुपये को प्राविजन किया गया है। दस लाख रुपये में तो एक ब्रिज भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है कि इस काम के लिए ज्यादा पैसे की मंजूरी दें और इस काम को जल्दी से जल्दी और तेज गति से पूरा करें जिससे कि उस पिछड़े इलाके के पिछड़े लोगों का विकास हो सके। और पिछड़े इलाके के लोग इसका उपयोग कर सकें।

हमारी गुजरात गवर्नमेंट ने अहमदाबाद से खेड़रम्मा (ए० पी०) मीटर गेज लाइन पर हिम्मतनगर के पास में स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के क्रासिंग पर एक ब्रिज बनाने का प्रपोजल सेण्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा है। मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि इस बारे में भी वे गौर करें। यह रास्ता अम्बाजी तक चलता है और यह यह बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार से अहमदाबाद-उदयपुर वाया हिम्मतनगर जो लाइन है, उस लाइन को मोड़ासा से सामराजी लाइन को मिलाने हेतु सर्वे का काम चल रहा है, उसको जल्दी से पूरा किया जाए। इसी तरह से मेरी एक विनती और है कि ए० पी० मीटर गेज लाइन पर जो गाड़ी चलती है वह कभी राइट टाइम नहीं चलती। महीने में दो-चार दिन ही सही समय पर चलती होगी। इसका मेंटिनेंस भी सही नहीं होता है। न पंखे चलते हैं, न लाइट जलती है, दरवाजे भी नहीं खुलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ताकि जनता की तकलीफ दूर हो सके।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उनका प्राक्कलन किया जाए। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री काली चरण शर्मा (भिण्ड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और मैं मंत्री जी को इस सुधारवादी बजट के लिए बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से समय में कुछ मुद्दे माननीय रेल मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश के एक कोने में है। यहां पर गुना, इटावा, भिण्ड ब्राड गेज लाइन का काम जल्दी ही पूरा होने की स्थिति में है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक तो उस क्षेत्र में आबादी घनी है और दूसरा ट्रेफिक भी ज्यादा है। इधर चंबल के इरीगेशन की वजह से गल्ले का सरपलस भी है, इसलिए उसको जल्दी ही बजट के अन्तर्गत लाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को लाभ हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि दतिया जिला हैड-क्वार्टर है और झांसी के पास है, उस पर पूर्वी साइड में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म या यार्ड नहीं है। इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से मंत्री महोदय को लिखकर दूंगा।

मान्यवर, भोपाल से कोई रेलवे लाइन दिल्ली के लिए सीधी नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि दिल्ली, भोपाल और इंदौर के लिए एक फास्ट ट्रेन चलाई जाए। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि द्वितीय श्रेणी का जो किराया बढ़ाया गया है, वह सुविधाओं को देखते हुए अधिक है। इससे मध्यम श्रेणी के लोगों को कठिनाई होगी। गाड़ियों में भीड़ बहुत होती है। इन सब बातों को देखते हुए इसमें कमी हो सके तो काफी अच्छा होगा। इसी प्रकार माल भाड़े के बारे में सब्जी और फ्रूट्स पर जो भाड़ा बढ़ाया गया है, इसमें भी छूट दी जाए।

अंत में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कई स्थानों पर चेन पुलिंग की वजह से आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक विशेष फोर्स बनाया जाये जो समय-समय पर ऐसे स्थानों पर जा कर इस को देखें, जिस से आम जनता को सुविधा मिल सके। इसी प्रकार छात्रों द्वारा स्टेशनों पर किए जाने वाले उधम पर भी रोक लगाई जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली-बांबे लाइन पर गाड़ियों की सब से ज्यादा कमी है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस लाइन पर झांसी और भोपाल होती हुई एक राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाए।

अन्त में मैं प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री महोदय के कार्यकाल में सुधार होगा और मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी। मध्य प्रदेश को कोई नई रेलवे नहीं दी गई है और न ही सर्वे जो होना है उस में इस को कोई स्थान दिया गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उस को इस बजट से अलग ही रख दिया गया है। वह सबसे बड़ा प्रदेश लम्बाई में है। खनिज और वन सम्पदा से वह भरपूर प्रदेश है। हम मध्य प्रदेश के एम पी उन को एक मैमोरेंडम भी देने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश को अछूता छोड़ दिया गया है उसकी ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे और उस को भी रेल बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : अजीब भाग्य की विडम्बना है कि मैं बंजारा कौम में पैदा हुआ हूं और मेरे बाप दादा बैलों से माल एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम किया करते थे। इस रेलवे बजट पर बोलने के लिए खड़ा मैं हुआ हूं। हम को रेलों को आने के बाद अपने धंधे से उखाड़ा गया है और आज मैं इसी रेलवे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा भी हो रहा हूं। समर्थन करते हुए मुझे बड़ी खुशी का अनुभव भी हो रहा है।

मुझे दुख है कि महाराष्ट्र के साथ इस बजट में बड़ा अन्याय किया गया है। शुरू में रेलें मीटर गेज, नैरो गेज और ब्राड गेज बनाई गई थीं। हमारे मीटर गेज को ब्राड गेज बनाने का वादा किया गया है। यह वादा तीन साल पहले किया गया था, तब इसका आगाज किया गया था। मैं मनमाड और औरंगाबाद के बीच की लाइन की बात कर रहा हूं। इस साल बहुत ही कम रकम इस के लिए रखी गई है। इस को देख कर बड़ी शर्म आ रही है। अगर आप इस को करना नहीं चाहते हैं तो इस का मैंशन भी आप को नहीं करना चाहिए था। मैंशन कर के आप

[श्री उत्तम राठौर]

असन्तोष ही फैला रहे हैं लोगों में। मेहरबानी कर के आप चाहते हैं तो आप इस काम को जल्दी करें और काफी पैसा उस के लिए मुहैया करें।

दूसरी वर्ल्ड वार और उस के बाद जब रिफ्यूजी आए उस की वजह से रेलों का काम बिल्कुल चौपट हो गया था। उस को सुधारा गया। यह खुशी की बात है कि वैक्यूम ब्रेक का सिस्टम शुरू हुआ है, वैगंज, लोकोमोटिव्ज और पैसेंजर बोगीज बढ़ाई गई हैं। यह सब होते हुए भी मैं चाहता हूं कि जो इलाके अभी भी पिछड़ हुआ हैं जहां रेलों की अभी भी या तो व्यवस्था नहीं है या है तो वे बहुत स्लो चलती हैं उन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे एक किस्सा याद आ गया। श्री एस के पाटिल उस जमाने में रेल मंत्री थे। मेरे एक दोस्त जो इंगलैंड में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए और जो उनकी हर वक्त प्लेन में ही देखा करते थे आखिर उन से एक बार पूछ बैठे, माफ कीजिए, क्या आप एस के पाटिल हैं? उन्हों ने कहा जी हां। तब उन्होंने पूछा कि क्या आप रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा जी हां। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि मैं देश भर में घूमता हूं लेकिन आप मुझे रेल पर कभी नजर नहीं आए? यह बात नहीं होनी चाहिए। पांडे जी, मल्लिकार्जुन साहब, जाफर शरीफ साहब को चाहिये कि वे सबर्बन ट्रेंज में चलें, देहातों में और पिछड़े एरियाज में जा कर हालात को देखें। मुतखेड़—आदिलाबाद, खंडवा-हिंगोली सैक्शन की क्या हालत है जा कर देखें। जी एम तीन तीन साल तक नहीं जाते हैं। डिवीजनल मैनेजर जिस का नाम आप ने बदल दिया है उस को भी एक एक साल तक जाने का मौका नहीं मिलता है। बोर्ड के चेयरमैन को बदल देने से ही मामला नहीं बन जायगा। आप को उन लोगों को भी मजबूर करना पड़ेगा कि वे इस तरह के इलाकों में जा कर देखें। जिस तरह से तहसीलदार होता है और वह गांवों में बीस दिन बिताता है उसी तरह से आप को भी लोगों की वहां जा जा कर तकलीफों को देखना चाहिये और उन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

तीन महीने पहले हमारे कमला पति त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे। आज कमल नाथ जी से मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त मैंने एक लैटर दिया था जिस का मुझे जवाब प्राप्त नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है? आप ने तीन महीने में अच्छी काम किया है खुशी की बात है। मराठावाड़ा का जो पूर्णा डिवीजन है उस की मांग को मैंने उठाया था। मनमाड से निजामाबाद और पूर्णा से ले कर खंडवा जो कि सेन्ट्रल रेलवे के तहत है और जिस के पास न तो रेलें हैं और न लोकोमोटिव्ज हैं उस को आप सेंट्रल रेलवे से निकाल कर के पूर्णे को दे दें तो आप की बड़ी मेहरबानी होगी। वह पिछड़ा हुआ इलाका है। मेहरबानी करके उस को आप हम को दे दें और नया डिवीजन बना दें तो बहुत अच्छा होगा। इस के बारे में मैं आप को एक महीना पहले लिख भी चुका हूं। एक महीने पहले मैंने लिखा है जिस का उत्तर मुझे मिलना है।

छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि यहां उन का महत्व कम है। एक रोड सिरली-चौंडी स्टेशन है जो पूर्णा और हिंगोली सैक्शन में है जिस पर एक लेविल क्रासिंग सिर्फ 500 रु० में बनना है। लोकल बोर्ड ने मेटल्ड रोड बना दी है लेकिन लेविल क्रासिंग इसलिए नहीं बना क्योंकि 500 रु० किसी ने नहीं दिये, न लोकल बोर्ड ने और न जिला परिषद् ने। तो 500 रु० के लिये आप इस काम को न रोकिये।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : वह क्यों नहीं भरवाते लोकल आदमियों से।

श्री उत्तम राठौर : वह भी चिट्ठी आपने त्रिपाठी जी के लिये आप के हाथ में ही मैं ने दी थी ।

रेल मंत्री (श्री केसरी पांडे): आप उस को भरवा दीजिये, 500 रु० मैं आप को दे दूंगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can yourself do it. Why don't you do it? Have it done.

श्री उत्तम राठौर : हिंगोली से खंडवा लाइन जो है इस के बारे में मैं ने सवाल पूछा था कि 33 पौइंट समथिंग जो ज्यादा चार्ज किया जा रहा है वह किसलिये ? क्या वहां के लोग पिछड़ेपन का टैक्स दे रहे हैं । इस में उन का कोई कसुर नहीं है । उन लोगों को आप ने पीछे रखा है । वह रेल लाइन इसलिये आप ने सोची थी कि दक्षिण से उत्तर तक मीटर गेज की आप को लाइन बनानी है । इसलिये उस की तरफ अब आप तवज्जह दीजिये, और लोगों से पैसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए । छोट स्टेशनों का इलैक्ट्रिफिकेशन कीजिये । जो लोग आप की मदद करना चाहते हैं, उन की मदद को आप क्यों नहीं स्वीकार करते । जैसे करखेली के लोग हैं ....

MR. DEPUTY-SPEAKER: As soon as you write a letter, you meet the Minister also for follow-up action.

श्री उत्तम राठौर : वहां करखेली के लोगों ने कहा कि इंजन के लिये हम पानी सप्लाई करने के लिए तैयार हैं । काचीगुडा, मनमाड लाइन पर पानी की कमी होने की वजह से इंजन रुक जाते हैं । जब लोग पानी देने के लिये तैयार हैं तो उस को ले कर लाइन को चलाइये । करखेली लेविल क्रौसिंग इस समय अनमैन्ड है, उस को मैन्ड कीजिये ।

रेल में लिखा जाता है कि यह भारतीय जनता की प्रौपर्टी है । एक मेरे जैसा शरीफ पहुंच गया उस ने कहा कि ठीक है, पंखा निकाल दिया और लिख दिया कि मैं अपना सैंपर ले जा रहा हूं । इस को आप रोकिये । इतना ही कहूंगा । मुझे आशा है कि आप के जमाने में पूर्णा डिवीजन बनेगा और जो मराठावाड़ा की ब्रौडगेज की मांग है वह पूरी होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं ।

DR. GOLAM YAZDANI (Raiganj): Sir, I like to draw the attention of the Hon. Minister to the very pathetic condition of West Dinajpur district in North Bengal in the matter of Railways. When the partition of the country took place, this West Dinajpur district was deprived of the main railway line from Sealdah to Siliguri via Parvatipur and only one railway line metre gauge from Barsoi to Radhikapur existed. This is of little use to people at present. There was a proposal to connect Balurghat, the district headquarters of West Dinajpur, by railway line from Ekklakki in Malda district to Balurghat. This proposal was considered but not yet materialised. I do not know the reasons for it.

Now, as this line may not be viable, I would like to make a fresh proposal. This line should be from Ekklakki to Balurghat to *Hilli* via Buniadpur and from Buniadpur Point, a link line should be made up to Kalyaganj station on the metre gauge. This metre gauge could be converted into broad gauge later on. The main connection from Balurghat will be up to Barsoi *via* Buniadpur, Kaliaganj and Raiganj on one side and the other side through Buniadpur to Eklakki in Malda. If this fresh proposal is implemented, this line will be viable. I, therefore, make this modified proposal. Please have the proposal surveyed and take necessary steps in this regard. This is my request.

Now, Sir, I want to draw your attention to the fact that in Malda station the waiting room is very narrow. I request you to broaden this waiting room at Malda Station.

There is one station named Bhalukha road on Katihar-Malda line. There

is no overbridge here. The bazar is on the other side of the Railway station. The passengers have to cross the railway line and then only they can go to the other side. For the benefit of the public there should be one overbridge here. Also, there should be over--bridges at Dalkola and Siliguri level crossings. In these places the traffic is getting jammed at these level crossings. It takes many hours for the traffic to get cleared up.

In Malda district there are two places called Gour and Pandua which are very famous. There are Mohammaden shrines at Pandua. One month before the Ramzan the annual Urs festival takes place there—Thousands of people go over there during the Urs. There is no special train provided for this occasion, nor increased number of coaches are provided for and passengers face great difficulties. I request you to increase the number of coaches and to run more trains in this line in between scheduled timings of regular trains, so that the passengers who want to go to Pandua shrine during Urs are not inconvenienced in any way. I would like to draw the attention of the hon. Minister to one other point. If you go to Malda you will find that late running of trains is a usual occurrence. In the Darjeeling Mail, Kamrup Express and NJP passenger, decoities frequently occur. Only recently near Katihar one dacoity took place in one coach meant for down Darjeeling mail. The dacoits came into the train and they were armed with fire-arms. They injured the passengers and looted their properties.

Sir, the passengers of West Dinajpur go to Calcutta *via* buses or by train. They have to travel for 9 hours or 10 hours, if they go by bus. If they come to Malda station to get the train, many times they do not at all get the accommodation there. Again for the people who come to Delhi, the first class quota here is only two which is always full. It is really very difficult for the people to travel by Tinsukia mail and come to Delhi. I myself do not get from Malda stations first class accommodation at many times and my name is put in the waiting list. I have then to travel on the mercy of the T.Ts. I request the hon. Minister that the quota of first class accommodation should be increased at Malda station and special attention should be given to Malda station to improve its present condition.

With these words I conclude my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Hon. Minister will reply on the 5th instant.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDEY): Yes, I will reply on the 5th.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House stands adjourned to meet at 11 A.M. on the 5th March, 1981.

21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 5, 1981/Phalguna 14, 1902, (Saka).

GMGIPMRND—L—4089 LS—25-4-81—890.